पूर्णचन्द जैन द्वारा युगान्तर प्रेस, जयपुर में मुद्रित तथा कांग्रेस
स्वागत समिति के प्रधान मंत्री द्वारा प्रकाशित

विषय-सूची

भाग १ — पृष्ठ संख्या

भाग २

भाग ३

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

जिनके स्वर्गारोहण के बाद होनेवाले इस प्रथम अधिवेशन के लिए
जयपुर के पास के एक जंगल में निर्मित विशाल नगर
का नाम 'गांधीनगर' रखा गया

राष्ट्रपति
THE CONGRESS PRESIDENT

डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया

भारत के नेता एवं प्रधान मन्त्री
माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू
(खुले अधिवेशन में भाषण दे रहे हैं ।)

India's Leader and the Prime Minister
Hon. Pt. Jawaharlal Nehru
(Addrening the open Session)

भारत के नेता तथा उपप्रधानमंत्री
मानतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल
(विषय निर्वाचिनी का भाषण देते हुए)
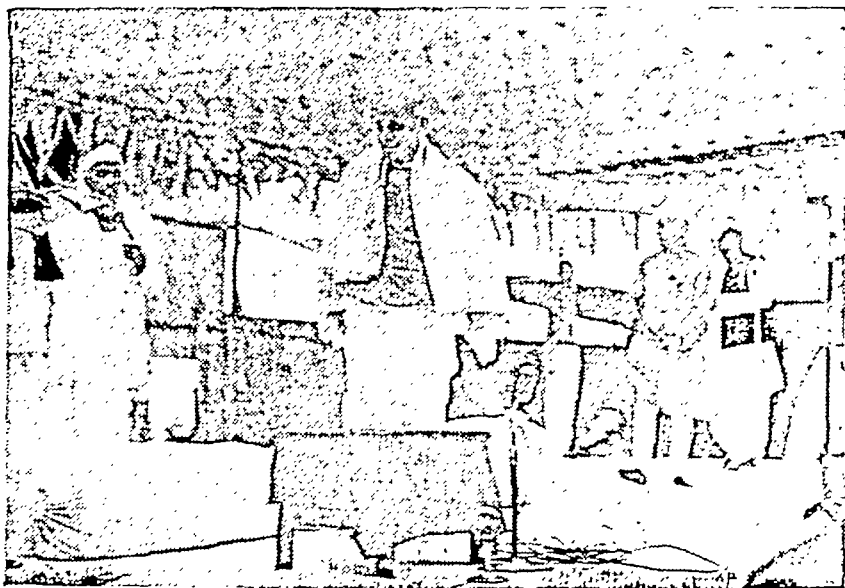
India's leader and Deputy Prime Minister.
Saradr Ballabh Bhai Patel
(Addressing the subjects Committee)

—अखिल भारतीय—

कांग्रेस स्वागत समिति

[५५ वां अधिवेशन (जयपुर) दिसम्बर, १९४८]

कार्यविवरण

१. निमंत्रण

हरिपुरा अधिवेशन के निश्चयानुसार यद्यपि कांग्रेस ने अपने आपको तत्कालीन देशी राज्यों की राजनीति से अलग रक्खा था पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के रूप में बने हुए रियासतों के राजनैतिक संगठन के साथ उसका सम्बन्ध चला आ रहा था । १९४७ में देश की राजनैतिक स्थिति में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बाद अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने अप्रेल १९४८ को बम्बई बैठक में "देशी राज्यों' को भी अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करने का निश्चय किया । कांग्रेस के इस निर्णय के बाद देशी राज्य लोक परिषद ने भी अपना स्वतन्त्र संगठन बनाये रखना अनावश्यक समझकर अपने आपको कांग्रेस में मिला देने का निश्चय किया । लोक परिषद के इस निश्चय और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मार्गदर्शन के अनुसार लोक परिषद की राजपूताना प्रान्तीय सभा ने ता० २६ जून १९४८ को अपनी भरतपुर की बैठक में अपने आपको राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के रूप में परिवर्तित कर लिया और उसे अ० भा० राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का एक अंग होने का नया गौरव प्राप्त हुआ ।

उन्हीं दिनों कांग्रेस के आगामी अधिवेशन की चर्चा चल रही थी। अ० भा० कांग्रेस की कार्यकारिणी की १ जलाई १९४८ को होने वाली बैठक के कार्यक्रम में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के स्थान का प्रश्न भी था और उसके लिए विभिन्न प्रान्तों के निमन्त्रणों पर वर्किंग कमेटी द्वारा विचार होने वाला था । नवनिर्मित राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस की भरतपुर बैठक के सामने आगामी अधिवेशन राजपूताना में करने के लिए निमन्त्रण भेजने का विचार आना स्वाभाविक था । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

"राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी निश्चय करती है कि अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन राजपूताना में किये जाने के लिए वर्किंग कमेटी को सादर निमन्त्रण किया जाय।"

कांग्रेस के ६१ वर्ष के पिछले इतिहास में होने वाले उस समय तक के ५४ अधिवेशन विभिन्न प्रान्तों में हो चुके थे और इस सम्मान के लिए कई गांवों व शहरों को एक से अधिक बार भी मौका मिल चुका था। पर राजपूताना रियासती प्रदेश होने के कारण अब तक इस प्रान्त में अधिवेशन होना सम्भव नहीं हुआ था। हमारे सौभाग्य से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ता० १ जुलाई १९४८ को राजपूताना का उपरोक्त निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और इस प्रकार पहली बार इस प्रान्त में कांग्रेस अधिवेशन होने का अवसर आया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेन्द्र बाबू ने अधिवेशन की तारीखें १७, १८, व १९ दिसम्बर, १९४८ घोषित की। इस प्रकार अधिवेशन की तैयारी के लिए स्वागत समिति को कुछ ही महिनों का समय मिला।

२. जयपुर अधिवेशन का महत्त्व

रामगढ़ के अधिवेशन (१९४०) के बाद कांग्रेस को द्वितीय विश्व महायुद्ध के समय स्वातन्त्र्य संग्राम की अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ा था जिसके कारण ६ वर्ष तक कोई अधिवेशन नहीं हो सका। अप्रेल १९४७ में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पर उसके महत्व को उस समय फैली हुई साम्प्रदायिकता की आग ने फीका कर दिया था। इसलिए गत आठ वर्ष से प्रचलित पद्धति के अनुसार धूमधाम और समारोह के साथ कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होने पाया था। इसी बीच विश्व और भारत के राजनैतिक वातावरण के साथ २ कांग्रेस की स्थिति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुके थे। १५ अगस्त १९४७ को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त होकर देश का शासनसूत्र कांग्रेस के हाथ में आ चुका था। साथ ही साम्प्रदायिकता की बलिवेदी पर देश का विभाजन हो गया था। विभाजन के फलस्वरूप न केवल लाखों नागरिकों को अपने घरबार छोड़ने और इधर से उधर जाने पर बाध्य होना पड़ा बल्कि राष्ट्र के निर्माता महात्मा गांधी को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। भारतीय राष्ट्र के इस महान् संकट की घड़ी में भी उसके रियासती क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे।

माननीय सरदार पटेल की प्रेरणा और प्रभाव से भारत की बिखरी हुई ६०० रियासतों को शासन की बड़ी इकाइयों में पिरोया जा रहा था। सौराष्ट्र, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पटियाला व पूर्वी पंजाब रियासती संघ के अलावा राजपूताना में "मत्स्य" और "संयुक्त राजस्थान" संघ बन चुके थे और इस तरह जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि बड़ी रियासतों के इन दोनों के साथ मिलकर एक वृहत्त राजस्थान के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी।

ऐसे समय में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन देश के लिए अपना विशेष महत्व रखता था। कांग्रेस को अपने मार्गदर्शक (महात्मा गांधी) के अभाव में अपना मार्ग खोजना था और स्वतन्त्र भारत जयपुर अधिवेशन में देश को आजाद करने वाले संगठन कांग्रेस से एक नया संदेश सुनने की आशा रखता था। एक लम्बे अरसे के बाद स्वतन्त्र भारत में पहली बार होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण अधिवेशन का आयोजन करने का गौरव एवं सौभाग्य राजस्थान को प्राप्त हुआ था। पिछली अर्ध शताब्दी से विदेशी साम्राज्यशाही का मुकाबला करते हुए भी कांग्रेस के ५४ अधिवेशन जिस शान शौकत तथा उत्साह के साथ सम्पन्न हो चुके थे उससे लोगों में इस कल्पना का जाग उठना स्वाभाविक था कि नई परिस्थितियों में राजपूताना के सुन्दर शहर जयपुर में होने वाला अधिवेशन न केवल उसके राजनैतिक महत्व बल्कि उसकी सजावट और शान शौकत में भी अद्वितीय होगा। इस कल्पना को साकार रूप देने के लिए राजपूताना के लोग अधिवेशन की तैयारी में जुट पड़े।

३. स्वागत समिति का निर्माण तथा प्रारंभिक तैयारी

साधारणतया आगामी कांग्रेस अधिवेशन के समय और स्थान का निर्णय पिछले अधिवेशन में ही कर लिया जाता था जिससे अधिवेशन की तैयारी के लिए प्रायः कम से कम साल भर का समय मिल जाता था पर ऊपर बतलाये अनुसार जयपुर अधिवेशन की तैयारी के लिए केवल ५ महीने का समय मिला।

तारीखों का निश्चय होते ही अधिवेशन की तैयारी का काम तुरन्त हाथ में लिया गया। स्वागत समिति का निर्माण करने के लिए ता० १४ जुलाई १९४८ को प्रान्तीय कांग्रेस कार्य समिति की एक आवश्यक बैठक जयपुर

में हुई जिसमें प्रान्त की जिला कमेट्रियों के अध्यक्षों तथा मन्त्रियों के अलावा अजमेर मेरवाडा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को भी निमन्त्रित किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था के सिलसिले में चर्चा के उपरान्त अधिवेशन जयपुर में करने तथा अस्थायी समिति व स्थायी स्वागत समिति के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किए गए।

१. "राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति निश्चय करती है कि राजपूताना प्रान्त के लिए निमन्त्रित कांग्रेस का आगामी अधिवेशन जयपुर में किया जाय।"

२. "राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति जयपुर में होने वाले कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) के आगामी अधिवेशन की व्यवस्था करने के लिए एक अस्थाई समिति नियुक्त करती है जिसे स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी आदि का चुनाव होने तक अधिवेशन की व्यवस्था सम्बन्धी कारवाई करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट, प्रधान मन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री तथा अर्थ मन्त्री श्री कमलनयन बजाज होंगे। समिति की बैठकों का कोरम ११ सदस्यों का होगा।"

३. "कार्यसमिति ने निश्चय किया कि स्वागत समिति का सदस्यता शुल्क २५ रु० रखा जाय और स्वागत समिति के कम से कम २५० सदस्य बन जाने पर ता० २२ अगस्त, १९४८ को स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी आदि का चुनाव किया जाय।"

स्वागत समिति के सदस्य बनाने का कार्य ता० १४ जुलाई से ही तुरन्त चालू हो गया और सदस्यता शुल्क की रसीद की कापियां प्रान्त के सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं तथा कलकत्ता, आसाम आदि स्थानों में प्रवासी राजस्थानियों को सदस्य बनाने के लिए भेजी गई।

श्री गोकलभाई भट्ट

स्वागताध्यक्ष

SHRI GOKULBHAI BHATT
Chairman Reception committee

४. स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी का चुनाव

पूर्व निश्चय के अनुसार ता० २२ अगस्त १९४८ को राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की साधारण सभा हिन्द होटल, त्रिपोलिया, जयपुर में हुई जिसमें कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था के लिए स्वागत समिति निर्माण करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

"कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन राजपूताना प्रान्त में करने का अपना निमन्त्रण स्वीकार किये जाने पर राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हर्ष और आभार प्रकट करती है। अधिवेशन की तैयारी के लिए अस्थाई स्वागत समिति के निर्माण तथा स्वागत समिति के संगठन के सिलसिले में प्रान्तीय कार्यसमिति के द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई को स्वीकार करते हुए कमेटी प्रान्त के प्रत्येक निवासी से तथा प्रवासी भाइयों से भी अपील करती है कि वे सब अपने प्रान्त में होने वाले इस अधिवेशन को सफल बनाने और हिन्दुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले महमानों के आतिथ्य में तन मन धन से पूरा सहयोग दें।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी श्री काशीनाथ गुटगुटिया एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को स्वागत समिति का हिसाब निरीक्षक नियुक्त करती है।"

स्वागत समिति के हिसाब की जांच के लिए विधान के अनुसार प्रान्तीय कांग्रेस ने श्री के० एन० गुटगुतिटिया एण्ड कम्पनी, को आडीटर नियुक्त किया।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की उपरोक्त बैठक के बाद तुरन्त उसी समय वहां पर कांग्रेस स्वागत समिति की पहली बैठक हुई जिसमें राजस्थान के सभी क्षेत्रों से बने हुए स्वागत समिति के कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी सदस्य उपस्थित हुए। इस बैठक के सभापति का आसन प्रान्तीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट ने ग्रहण किया। स्वागत समिति ने नीचे लिखे अनुसार अपने पदाधिकारी निर्वाचित किए।

१. श्री गोकुल भाई भट्ट — अध्यक्ष
२. श्री श्री कृष्णदास जाजू — उपाध्यक्ष
३. श्री हरिभाऊ उपाध्याय — ,,

४. श्रीमती जानकीदेवी बजाज ,,
५. श्री माणिक्यलाल वर्मा ,,
६. श्री भागीरथ कानोडिया ,,
७. श्री हीरालाल शास्त्री प्रधान मन्त्री
८. श्री जयनारायण व्यास दलपति
९. श्री कमलनयन बजाज कोषाध्यक्ष
१०. श्री सिद्धराज ढड्ढा संयुक्त मन्त्री

स्वागत समिति ने अधिवेशन की तैयारी सम्बन्धी कार्य के लिए ५१ सदस्यों की एक कार्यकारिणी नियुक्त की जिसे अपनी सदस्यता में आवश्यकतानुसार ५० और सदस्य अर्थात कुल १०१ की सदस्य सख्या तक वृद्धि करने का अधिकार दिया गया। इस निश्चय के अनुसार कार्यकारिणी ने समय २ पर सदस्य कोआप्ट किए। स्वागत समिति की कार्यकारिणी के कुल सदस्यों की सूची परिशिष्ट सं. १ में दी गई है। इस कार्यकारिणी को कांग्रेस के विधान तथा उसके तत्सम्बन्धी आदेशानुसार स्वागत समिति की ओर से अधिवेशन के सब आवश्यक तैयारी, अर्थ संग्रह आदि कार्य करने का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया। कार्यकारिणी का कोरम १५ सदस्यों का रखा गया।

५. संचालन समिति

कार्यकारिणी ने अपनी ता० २९ अगस्त, १९४८ की बैठक में स्वागत समिति के रोजमर्रा के काम को प्रगति देने के लिए एक संचालन समिति के निर्माण का निश्चय किया। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

"स्वागत समिति की कार्यकारिणी निश्चय करती है कि समिति के रोजमर्रा के कार्य संचालन के लिए एक संचालन समिति नियुक्त की जाय जिसमें स्वागत समिति के सब पदाधिकारी तथा विभिन्न कमेटियों के संयोजक सदस्य होंगे। संचालन समिति कार्यकारिणी के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगी। संचालन समिति का कोरम ७ सदस्यों का होगा।"

इस समिति में पदाधिकारियों के अलावा समय २ पर बनाई गई सब समितियों के संयोजकों को मिलाकर कुल २६ सदस्य थे (देखिए परिशिष्ट सं.२)

श्री पं हीरालाल शास्त्री

प्रधान मंत्री

SHRI Pt. HIRAL SHASTRI

General Secretary
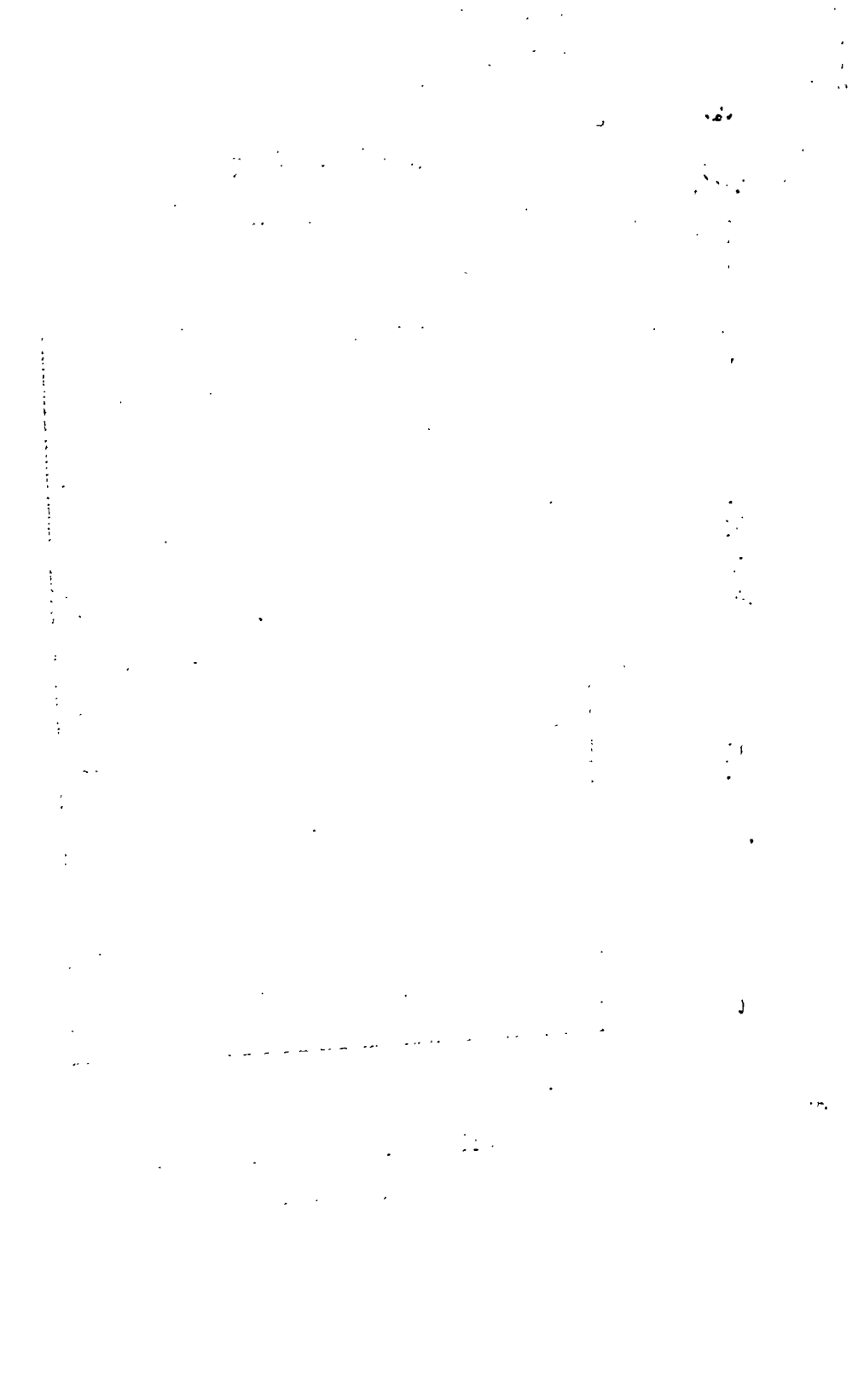
श्री जयनाराण व्यास दलपति

एवं

संयोजक—स्वयं सेवक समिति

Shri Jainarain Vyas

G. O. C.

&

Convenor Volunteers Sub Committe

६. उपसमितियों का निर्माण

स्वागत समिति की २२ अगस्त, १९४८ की बैठक में निर्माण समिति, भोजन समिति तथा सामग्री संग्रह समिति बनाई गई। इन समितियों के अलावा आवश्यकतानुसार और समितियां बनाने तथा संयोजक चुनने का अधिकार कार्यकारिणी को दे दिया गया।

स्वागत समिति की कार्यकारिणी की ता० २९ अगस्त, १९४८ की बैठक में स्वागत समिति द्वारा बनाई गई उपरोक्त तीन समितियों के अलावा प्रदर्शिनी एवं प्रचार प्रकाशन समिति सहित ५ अन्य समितियों का निर्माण हुआ। समितियों के संयोजकों को आवश्यकतानुसार अपनी २ समिति की सदस्यता में वृद्धि करने का अधिकार दे दिया गया। स्वयंसेवक समिति के संगठन का कार्य श्री जयनारायण व्यास, दलपति स्वयंसेवक दल, तथा अर्थ समिति का निर्माण श्री कमलनयन बजाज, कोषाध्यक्ष की सलाह से करने का निश्चय किया गया।

ता० १२-९-४८ की कार्यकारिणी की बैठक में पण्डाल, निवास, सजावट, बाजार विज्ञापन, प्रवेश नियन्त्रण, सफाई, रोगोपचार, रेलवे यातायात, जुलूस तथा स्वागत सत्कार आदि के लिए अलग २ समितियां बनाने का तै किया गया। कार्यकारिणी ने इन समितियों के संयोजकों को निर्वाचित किया और अपनी २ समिति बनाने का भार उन पर छोड़ा गया। ता २ अक्टूबर की बैठक में सवारी समिति का निर्माण किया गया तथा अधिवेशन के बाद ता० २०-१२-४८ को बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करने, मांगे हुए सामान को वापस लौटाने तथा व्यापारियों के माल का निरीक्षण करके गेट पास द्वारा जाने देने की आवश्यक व्यवस्था के लिए सामान समेट समिति का निर्माण किया गया।

इस प्रकार स्वागत समिति की ओर से कुल २० समितियों का निर्माण हुआ (समितियों के संयोजकों तथा सदस्यों की सूची के लिए देखिए परिशिष्ट सं ३।

स्वागत समिति के मन्त्रीगण पदेन इन सभी समितियों के सदस्य माने गए तथा कार्यालय 'सहायक और प्रचार प्रकाशन सहायक को कार्यकारिणी और संचालन समिति की बैठकों के अलावा हर समिति की बैठक में भी उपस्थित होने का अधिकार दिया गया।

स्वागत समिति के बचे हुए सामान की बिक्री का भार स्वागत समिति की कार्यकारिणी की ता० २६ दिसम्बर १९४८ की बैठक में स्वागताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट पर छोड़ा गया। उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी संयुक्त मन्त्री श्री सिद्धराज ढड्ढा की देखरेख में श्री भँवरलाल भदादा को सौंपी। उपरोक्त समितियों के रूप में अलग २ विभागों में बटा हुआ स्वागत समिति का काम शीघ्र ही गति पकड़ता गया। अधिकांश विभाग में सैंकड़ों वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यकर्ता काम में लगे।

७. स्थान का चुनाव तथा निर्माण कार्य की शुरुआत

राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की ता० १४-७-४८ की बैठक में अधिवेशन जयपुर में करने के निश्चय के साथ ही उसके लिए जयपुर में उचित स्थान चुनने का प्रश्न उठा। इस काम के लिए शहर के दक्षिण में "मोतीडूंगरी" के पीछे की जमीन सुझाई गई। उपस्थित लोगों ने बैठक के तुरन्त बाद उस स्थान का निरीक्षण किया। अस्थाई स्वागत समिति की ता० २८-७-४८ की बैठक में अधिवेशन के स्थान के बारे में मोतीडूंगरी के पीछे के स्थान के अलावा जयपुर स्टेशन के पास बेनीबाग के लिए भी सुझाव आया। इन्जनीयरों व विशेषज्ञों से सलाह लेकर स्थान का अन्तिम निर्णय करने का भार एक समिति पर छोड़ा गया। इस समिति ने सभी दृष्टियों से विचार करने के बाद मोतीडूंगरी के पीछे के मैदान को ही अधिवेशन के लिए उपयुक्त माना।

अधिवेशन के नगर निर्माण का काम अस्थायी स्वागत समिति द्वारा श्री दौलतमल भण्डारी को सोंपा गया जिन्होंने अपनी सहायता के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई। बाद में ता० २२ अगस्त को स्वागत समिति की बैठक में निर्माण समिति का नियमित रूप से संगठन हुआ। इस निर्माण समिति ने मोतीडूंगरी के पीछे के मैदान के टीबों को साफ कराने के लिए जोधपुर व बूंदी राज्यों तथा भारत सरकार से 'बुलडोजर' मंगवाकर तुरन्त काम चालू कर दिया।

८. कांग्रेस नगर का नामकरण तथा शिलान्यास

ता० २९ अगस्त, १९४८ की कांग्रेस स्वागत समिति की कार्यकारिणी की पहली बैठक में निश्चय किया गया कि कांग्रेस नगर का नाम "गांधीनगर"

गांधीनगर-शिलान्यास

(आचार्य श्री विनोबा भावे द्वारा ता० २ अक्टूबर १९४८ (गांधी जयन्ती) को प्रातः ८ बजे 'गांधी नगर' का शिलान्यास किया जा रहा है।)–पीछे की तरफ सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी श्री जानकी देवी बजाज बैठी हैं।
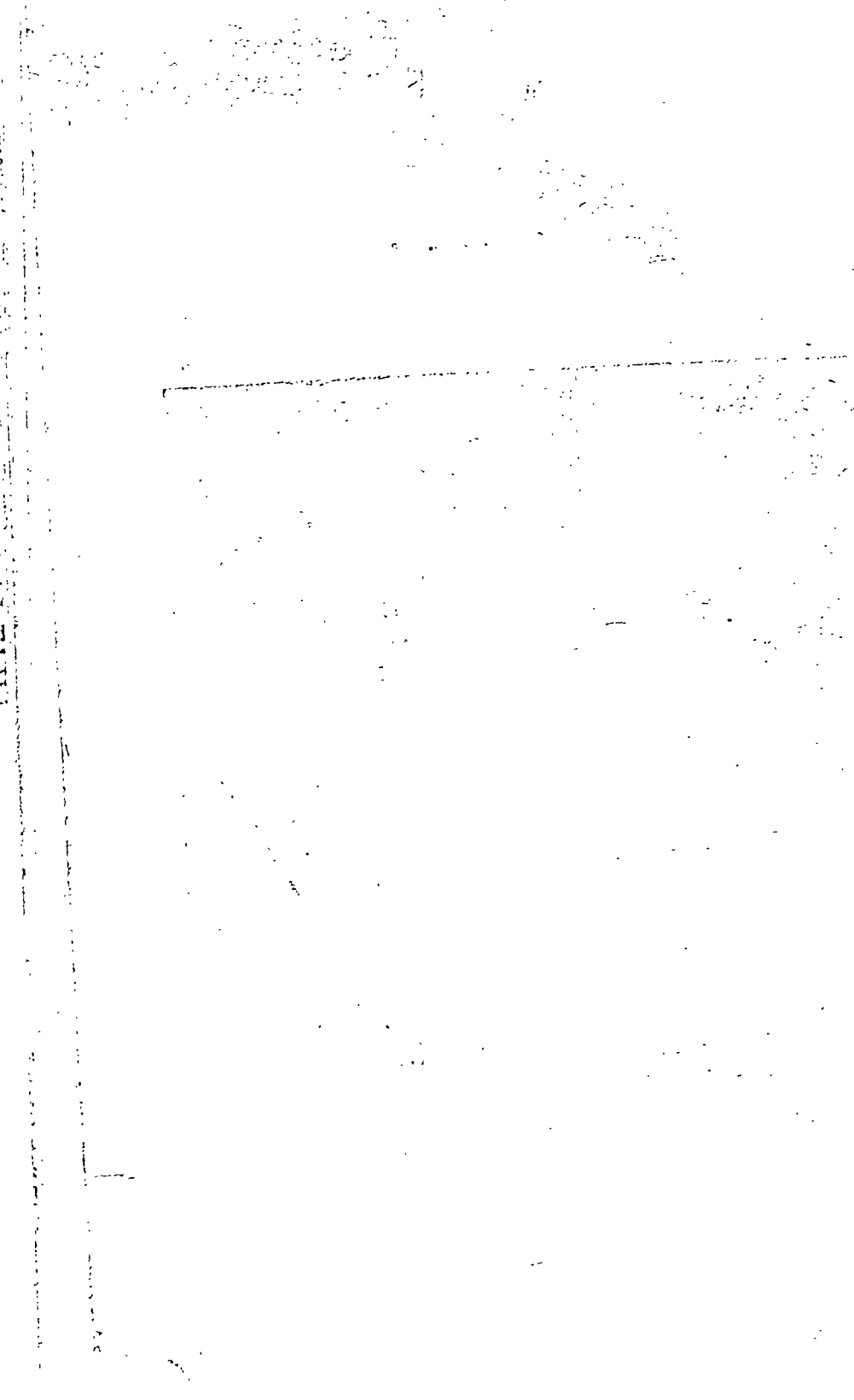
रक्खा जाय और उसका शिलान्यास २ अक्टूबर, १९४८ को गांधी जयन्ति के अवसर पर कराया जाय। इस निश्चय के अनुसार ता० २ अक्टूबर को आचार्य श्री विनोबा भावे द्वारा गांधीनगर का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर भाषण देते हुए श्री विनोबाजी ने कहा "गांधीजी कांग्रेस को शहर से देहात में ले गए थे, परन्तु जयपुर में कांग्रेस करने का अर्थ उसे वापस शहर में लाना नहीं है। जयपुर देशी राज्यों के रेगिस्तान का एक हिस्सा है। अतएव कांग्रेस के यहां आने का उद्देश्य इस हिस्से को सजल और सफल बनाने का ही हो सकता है।" कांग्रेस अधिवेशन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए श्री विनोबाजी जी ने यह भी कहा कि उसे हमारी देहाती सभ्यता का जीताजागता प्रदर्शन होना चाहिए। जहां तक सम्भव हो उसमें ग्रामोद्योग की वस्तुओं का उपयोग ही किया जाय।

गांधीनगर के शिलान्यास के बाद उसी दिन गांधीनगर में स्वागत समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें निर्माण समिति के संयोजक श्री दौलतमल भण्डारी ने कार्यकारिणी के विचारार्थ गांधीनगर का प्रस्तावित नक्शा पेश किया। अधिवेशन के लिए निर्मित नगर का नक्शा परिशिष्ट सं० में दिया गया है। (निर्माण के काम के ब्योरे के लिए देखिए, निर्माण समिति का कार्य विवरण)

८. कार्यालय का स्थान

स्वागत समिति के कार्यालय के लिए शहर में चौडा रास्ता स्थित "हिन्द होटल" में स्थान चुना गया। तिलक जयन्ती के शुभ अवसर पर ता० १ अगस्त १९४८ को ठीक सूर्योदय के समय पं० हीरालाल शास्त्री द्वारा स्वागत समिति कार्यालय का उद्‌घाटन हुआ और उसके बाद कार्यालय के विभिन्न विभागों तथा समितियों के लिए आवश्यक कार्यकर्ता जुटाये गये। ज्यों ज्यों कार्यकर्ता बढ़ते गये स्थान की तंगी महसूस होती गई और कार्यालय के लिए किशोर निवास व उणियारे का बाग भी काम में लिए गए। निर्माण समिति का कार्यालय शुरू से ही गांधीनगर में रखा गया। ता० १५ नवम्बर को स्वागत समिति का सम्पूर्ण कार्यालय गांधीनगर में ले जाया गया जो वहां ता० ५ जनवरी १९४९ तक रहा। अधिवेशन के बाद फिर सब काम हिन्द होटल कार्यालय में हुआ। (कार्यालय के काम के लिए देखिए कार्यालय विवरण)

१०. अर्थ व्यवस्था

कांग्रेस स्वागत समिति की २२ अगस्त की बैठक में बैंकों में स्वागत समिति के खाते खोलने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

"स्वागत समिति ५५वां कांग्रेस अधिवेशन, जयपुर के नाम से यूनाइटेड कामर्शियल बैंक तथा दी बैंक आफ जयपुर लिमिटेड की जयपुर शाखाओं में तथा कार्यकारिणी द्वारा समय पर स्वीकृत किये गये अन्य बैंकों में खाता खोले जाय। स्वागत समिति श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री कमलनयन बजाज व श्री सिद्धराज ढड्ढा इनमें से प्रत्येक को उपरोक्त खातों में आवश्यकतानुसार रुपया जमा कराने तथा निकालने का अधिकार देती है।"

जिस पैमाने पर कांग्रेस नगर के निर्माण का काम हाथ में लिया गया था तथा चीजों की जो अत्यधिक मंहगाई थी उसके कारण स्वागत समिति के काम के लिए तुरन्त लाखों रुपयों की आवश्यकता थी। ता० १२ सितम्बर १९४८ की बैठक में कार्यकारिणी ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वागत समिति के मन्त्रियों को आवश्यक रकम उधार लेने का अधिकार दिया। बैंक आफ जयपुर लिमिटेड तथा यूनाइटेड कामर्शियल बैंक व बैंक आफ बीकानेर लि० ने देश के विभिन्न स्थानों से स्वागत समिति के नाम आये हुए चैकों का कलैक्शन तथा बाहर रकम भेजने का काम बिना कमीशन चार्ज किए करने के लिए अपनी सेवायें अर्पित की।

अर्थ संग्रह के लिये प्रान्त के प्रवासी भाइयों ने बम्बई और कलकत्ते में कमेटियों का निर्माण किया। अक्टुबर के पहले सप्ताह में अर्थ संग्रह के काम के लिए स्वागत समिति की ओर से सर्व श्री लादूराम जोशी तथा नरोत्तमलाल जोशी ने बंगाल और आसाम का दौरा करके स्वागत समिति के सदस्य बनाये। इसके अलावा संयुक्त राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य व सिरोही की सरकारों से भी क्रमशः २,००,०००, १,०० ०००, १,००,०००, २५,०००, १२,१०१ रु० की सहायता प्राप्त हुई। इस सबके अतिरिक्त तत्कालीन जयपुर सरकार से, बैंकों से तथा अन्य मित्रों से समय समय पर स्वागत समिति को काफी रकम उधार भी लेनी पड़ी।

श्री सिद्धराज ढड्ढा, (संयुक्त मंत्री)
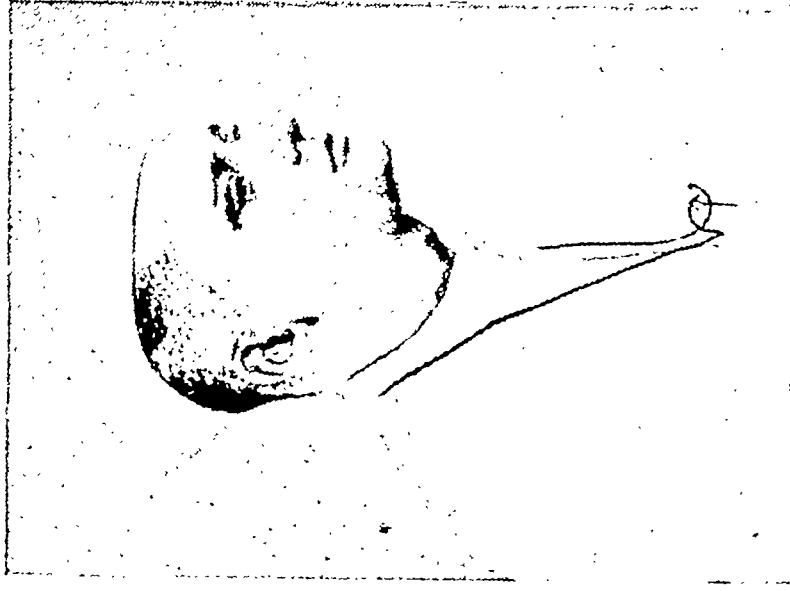
SHRI SIDDHARAJ DHADDHA
(Joint Secretary)

श्री कमलनयन बजाज
(कोषाध्यक्ष)

SHRI KMALNAYAN BAJAJ
(Treasurer)

एक ओर तो जिस पैमाने पर अधिवेशन के लिए सारी व्यवस्था की गई उसके कारण खर्च काफी हुआ और दूसरी ओर जितनी आमदनी की आशा की गई थी वह अपेक्षाकृत उससे बहुत कम हुई। अधिवेशन के तुरन्त बाद ही तत्कालीन स्थिति के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि अधिवेशन के काम में स्वागत समिति को दस और पन्द्रह लाख के बीच में घाटा रहेगा। ता० २१ दिसम्बर की बैठक में स्वागत समिति की कार्यकारिणी ने इस घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी समिति के प्रधान मन्त्री पं० हीरालाल शास्त्री पर छोडी। श्री हीरालाल शास्त्री ने इस घाटे की पूर्ति के लिए तत्कालीन जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर की सरकारों से बातचीत की। बीकानेर तथा जोधपुर की सरकारों से चार चार लाख रुपये की सहायता की व्यवस्था हुई। उस वक्त के अन्दाज से कुल घाटा करीब १४ लाख तक जाने की सम्भावना थी पर चूंकि अन्त में रहने वाले घाटे की निश्चित मात्रा का तखमीना पूरे सामान की बिक्री हो जाने तक लगना सम्भव नहीं था अतः शेष घाटे की पूर्ति के लिए जयपुर सरकार से यह तै किया गया कि वे तत्काल ६ लाख रुपया सहायता के रूप में दें, पर यदि स्वागत समिति को अन्त में घाटा इससे भी अधिक रहा तो उतनी रकम सरकार और दे देगी। इसके खिलाफ कदाचित घाटा कम रहा तो उतनी रकम सरकार को लौटा दी जायगी। इस व्यवस्था के अनुसार सामान बिकने तथा देन लेन की स्थिति अधिक निश्चित रूप में सामने आने के बाद कुल रु० ३,४७,००० की रकम, जो जयपुर सरकार को लौटानी पडती, वह इस बीच जयपुर के राजस्थान में शामिल हो जाने से, राजस्थान सरकार को वापस जमा करा दी गई है।

११. स्वागत समिति की सदस्यता

ता० १४ जुलाई, १९४८ की प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक में स्वागत समिति की सदस्यता का शुल्क २५ रुपया रखने का निश्चय किया गया था। प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रवासी राजस्थानियों को स्वागत समिति का सदस्य बनाने का अवसर देने के लिए प्रान्त की कमेटियों तथा कलकत्ता, आसाम और बम्बई में स्वागत समिति सदस्यता शुल्क की रसीद बुकें भेज दी गई थीं। स्वागत समिति के सदस्य बनने की अन्तिम तारीख ३०-११-४८ निश्चित की गई। ता० ४-१२-४८ को स्वागत समिति की सदस्यता का

रजिस्टर बन्द कर दिया गया। स्वागत समिति के कुल सदस्यों की संख्या ७५८५ हुई।

१२. सर्वोदय प्रदर्शिनी

स्वागत समिति ने २२ अगस्त, १९४८ की बैठक में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर एक प्रदर्शिनी आयोजित करने का भी निश्चय किया था। इस सिलसिले में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया वह नीचे लिखे अनुसार है।

"स्वागत समिति निश्चय करती है कि कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के साथ एक खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शिनी का आयोजन किया जाय। इस प्रदर्शिनी की व्यवस्था कांग्रेस के तत्सम्बन्धी प्रस्तावों के अनुसार अ० भा० चरखा संघ, अ० भा० ग्रामोद्योग संघ, हिन्दुस्तानी तालीम संघ तथा गो सेवा के सुपुर्द की जाय। यह संघ प्रदर्शिनी के कार्य संचालक के लिए जो प्रदर्शिनी समिति बनावे उसमें दो सदस्य स्वागत समिति की ओर से भेजे जांय।"

"प्रदर्शिनी का स्वरूप चरखा संघ के तत्सम्बन्धी प्रस्तावों तथा फरवरी १९४६ के खादी जगत् में प्रकाशित पू० गांधीजी के तत्सम्बन्धी लेखानुसार होगा।"

"जहां तक प्रदर्शिनी की आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध है उसका सब खर्च स्वागत समिति करेगी और टिकिट फीस तथा खेल तमाशों की आमदनी में से २५ प्रतिशत रकम उपरोक्त संघों को दी जायगी।"

प्रदर्शिनी समिति के अध्यक्ष श्री श्री कृष्णदास जाजू तथा मन्त्री श्री कृष्णदास भाई गांधी चुने गये। स्वागत समिति की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार श्री सिद्धराज ढड्ढा तथा श्री ओमदत्त शास्त्री प्रदर्शिनी समिति में नामजद किए गए। प्रदर्शिनी समिति ने प्रदर्शिनी का नाम 'सर्वोदय प्रदर्शिनी' रखने का सर्व सम्मति से निश्चय किया।

प्रदर्शिनी के नये रूप और मौजूदा महंगाई को देखते हुए प्रदर्शिनी में हानि रहने की सम्भावना के कारण, प्रदर्शिनी समिति ने अपनी ओर से ही स्वागत समिति से टिकिट और खेल तमाशे की आमदनी में से पहले स्वीकृत २५ प्रतिशत के बजाय १० प्रतिशत लेना तय किया। मुनाफा रहने की

श्री कृष्णदास जाजू (अध्यक्ष) प्रदर्शनी समिति उद्घाटन के समय स्वागत भाषण पढ़ते हुए।

हालत में १० प्रतिशत से अधिक और २५ प्रतिशत तक इच्छानुसार रकम प्रदर्शिनी फण्ड में देने का प्रश्न स्वागत समिति पर छोडा गया।

प्रदर्शिनी का प्रवेश शुल्क चार आना रक्खा गया। प्रदर्शिनी का निर्माण प्रदर्शिनी समिति की देखरेख में किया गया।

जयपुर अधिवेशन के वक्त हुई यह सर्वोदय प्रदर्शिनी अब तक कांग्रेस के अवसरों पर हुई सब प्रदर्शिनियों की अपेक्षा अनोखी तथा अभूतपूर्व थी। इस प्रदर्शिनी के द्वारा समाज रचना के विभिन्न अंगों पर सर्वोदय आदर्श की दृष्टि से लोगों के सामने एक प्रत्यक्ष नमूना पेश किया गया था। प्रदर्शिनी का पूरा और अधिकृत विवरण प्रदर्शिनी समिति द्वारा प्रकाशित एक अलग पत्रिका में दिया गया है। यह विवरण पत्रिका अ० भा० चर्खा संघ के कार्यालय से प्राप्त हो सकती है।

४ स्वयंसेवक शिविर तथा स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं की भरती

कार्यकारिणी की तारीख २९ अगस्त की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार स्वयंसेवक समिति के संयोजक व दलपति श्री जयनारायण व्यास ने स्वयंसेवक समिति की पहली बैठक में अपनी अनुपस्थिति में श्री शिवबिहारी तिवाडी को अधिकार दिया कि वे स्वयंसेवक संगठन का कार्य सम्हाले। वनस्थली विद्यापीठ की श्रीमती सज्जनदेवी स्वयंसेविका दल की संचालिका नियुक्त की गई। कुल मिलाकर ५००० स्वयंसेवक और १००० महिला स्वयंसेवकाओं की भरती की बात सोची गई। २० सितम्बर से चार सप्ताह के लिए एक शिक्षण कैम्प जयपुर में चलाया गया। स्वयंसेवकों की भरती के सम्बन्ध में स्वागत समिति की ओर से आवश्यक विज्ञप्तियां प्रकाशित की गई और जिला कांग्रेस कमेटियों के मार्फत यह काम कराया गया।

१३. गांधीनगर के पैमाने तथा व्यय का अनुमान

स्वतन्त्र भारत के इस पहिले अधिवेशन पर देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत बडी संख्या में लोगों के आने की कल्पना सभी को थी। दूसरी ओर अधिवेशन को अभूतपूर्व बनाने की इच्छा भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं

के दिलों में थी। अतः बड़े पैमाने पर अधिवेशन होने की आशा के कारण गांधीनगर का दायरा भी बड़ा रखा गया और खुले अधिवेशन तथा विषय निर्वाचिनी के पण्डाल व झण्डा चौक का निर्माण भी इसी आधार पर काफी बड़े पैमाने पर किया गया। अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के अलावा करीब १००० प्रतिनिधियों तथा ४००० दर्शकों के लिए निवास की व्यवस्था सोची गई। भोजन के सम्बन्ध में कार्यकर्ता, स्वयंसेवक आदि समेत कुल मिलाकर करीब चालीस लाख खुराकों (Diets) की व्यवस्था सोची गई।

स्वागत समिति के आय व्यय का अनुमान पत्र ता० १४-११-४८ की कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार स्वागत समिति में सामान समेत कुल करीब ५७ लाख रुपयों की लागत का अन्दाजा लगाया गया था जिसमें से ३१ लाख रुपया सामान की वापसी का मानकर वास्तविक खर्च का अन्दाज २६ लाख रुपये का था। टिकटों तथा निवास, भोजन व बाजार की दूकानों आदि से करीब २ इतनी ही आमदनी हो जाने का भी अनुमान था।

१५. सामग्री संग्रह तथा अन्य देनदारी

इतने बड़े पैमाने पर नगर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में समय लगना स्वाभाविक था। पिछले कांग्रेस अधिवेशनों के समय चीजों की न इतनी मंहगाई थी और न उनके क्रय विक्रय पर इस प्रकार का नियन्त्रण। यातायात के साधन भी सुलभ थे। जयपुर कांग्रेस के वक्त की बात भिन्न थी। बिना सरकारी सहायता के खाने पीने की सामग्री की बात तो दूर, पर टीन तथा टैन्टों आदि का मंगाना और मिलना भी असम्भव ही था। कांग्रेस स्वागत समिति के सामान चीजों को नियन्त्रित भावों पर जुटाने की भी समस्या थी। सामग्री संग्रह समिति ने अपनी नीति यह भी बनाई कि वह जयपुर शहर या अन्य स्थानों से उन चीजों को नहीं खरीदेगी। जहां से खरीदने पर वहां के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़े।

स्वागत समिति के सामने एक और सिद्धान्त का प्रश्न भी था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के समय से कांग्रेस अधि-

वेशनों को स्थानीय ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा क्रियात्मक रूप से उनका महत्व जन साधारण को समझाने के लिये थे।

साधन रूप में परिणित करने की योजना सामने रखी है। स्वागत समिति के सामने राष्ट्रपिता द्वारा प्रचलित इस परम्परा की रक्षा करने की भी समस्या थी। उसने निवास, पण्डाल आदि के निर्माण में आसपास होने वाली चीजों के उपयोग के प्रश्न पर विचार किया। पर जांच करने पर काफी मंहगे भावों पर भी आवश्यक घास और वांस का निश्चित समय में प्राप्त होना और उनके जरिए गांधीनगर का निर्माण असम्भव प्रतीत हुआ। अतः स्वागत समिति को सफेद टीन की चद्दरों के उपयोग का निश्चय करने के लिए वाध्य होना पडा। इस निश्चय के वाद भारत सरकार तथा रेल्वे की सहायता और सहयोग से टीन तथा अन्य सामान जैसे टैन्ट, वांस, वल्ली, चांवल, गेहूँ आदि आदि आवश्यक सामग्री दूर २ से प्राप्त की गई। आम तौर पर स्वागत समिति के लिए सभी आवश्यक सामान सामग्री संग्रह समिति द्वारा खरीद करने की व्यवस्था सोची गई।

१६. अन्य व्यवस्था

अधिवेशन की तैयारी तथा व्यवस्था के सिलसिले में कांग्रेस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वागत समिति ने समय २ पर नीचे लिखे अनुसार कुछ उल्लेखनीय निर्णय किए थे। उदाहरण के लिए शरावबन्दी की नीति को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर में मदिरा की विक्री व उसके उपयोग का निषेध किया गया था। यह भी तै किया गया था कि स्वागत समिति द्वारा संचालित भोजनशालाओं में निरामिष भोजन का ही प्रबन्ध किया जाय। गांधीनगर की सजावट राजस्थानी कला और स्थापत्य के आधार पर करने का निश्चय किया गया।

प्रचार प्रकाशन समिति ने कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर समय २ पर संवाद, वुलेटिन आदि प्रकाशित करने के अलावा एक 'राजपूताना गाइड' प्रकाशित करने का भी निश्चय किया। समिति ने अधिवेशन की एक वृतात्मक फिल्म लेने तथा अधिवेशन की कार्रवाई आल इण्डिया रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट कराने की व्यवस्था भी की।

गांधीनगर में दुकानें लगाने का समय १० दिसम्बर से २२ दिसम्बर

तक का निश्चित किया गया था । स्वागत समिति ने यह भी निश्चय किया कि गांधीनगर में अधिवेशन के समय आने वाले लोगों की आवश्यकता पूर्ति की दृष्टि से ही दुकानें की जाय, केवल प्रचारार्थ नहीं ।

गांधीनगर के निर्माण, सजावट, सुरक्षा, पानी, रोशनी, सफाई, डाक तार टेलीफोन, तथा अधिवेशन में आने वाले लोगों के लिए स्वागत सत्कार, भोजन, निवास, सवारी, रोगोपचार, बाजार, रेल्वे यातायात, कांग्रेस अध्यक्ष के जुलूस तथा अधिवेशन में प्रवेश के सम्बन्ध में आवश्यक नियम आदि बनाने के सिलसिले में सम्बन्धित उपसमितियों के अलावा स्वागत समिति की कार्यकारिणी तथा संचालन समिति की बैठकें समय २ पर होती रही । कुल मिलाकर स्वागत समिति कार्यकारिणी की १० तथा संचालन समिति की १८ बैठकें हुई ।

१७. अधिवेशन

अधिवेशन के कार्यक्रम की शुरूआत ता० १४ दिसम्बर को आचार्य श्री विनोबा भावे के जयपुर आगमन के साथ हुई । उन्होंने ता० १५ को सर्वोदय प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया । विषय निर्वाचिनी समिति की बैठकें ता० १६, १७ को तथा खुला अधिवेशन ता० १८, १९ दिसम्बर १९४८ को हुआ । ता० १६ की दोपहर को कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारमैया का दिल्ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा पदार्पण हुआ । जयपुर स्टेशन पर स्वागत समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधियों एवं जनता की अपार भीड ने उनका शानदार स्वागत किया । इसी अवसर पर उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के प्रयत्न से स्टेशन के बाहर निर्माण कराई गई पूज्य महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण समारोह भी किया । इसके बाद अध्यक्ष महोदय को एक अभूतपूर्व जलूस के साथ जयपुर के मुख्य बाजारों में होकर ले जाया गया । जलूस में मेरठ कांग्रेस से पैदल यात्रा द्वारा लाई गई 'ज्योति' भी थी । स्थानीय रामनिवास बाग म्युजियम के बाहर जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल द्वारा उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष महोदय को मानपत्र भेंट किया गया ।

विषय निर्वाचिनी समिति की बैठकें ता० १६, १७, १८ व १९ को विषय निर्वाचिनी पण्डाल में हुई । ता० १८ की सुबह राष्ट्रपति द्वारा झण्डा

चौक में झण्डारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। खुले अधिवेशन की कार्रवाई ता० १८ को दिन के २ बजे शुरू हुई। स्वागताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट के भाषण के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारमैया ने अध्यक्ष पद से भाषण दिया।

राजस्थान में यह अधिवेशन पहली ही बार हो रहा था। प्रान्त के कार्यकर्ताओं के दिलों में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अपने आदरणीय अतिथियों का सब सम्भव प्रकार से स्वागत व सत्कार करने की भावना प्रबल होना स्वाभाविक था। स्वागताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट के सुझाव पर प्रान्त के कार्यकर्ताओं ने यह तै किया था कि अधिवेशन के समय कांग्रेस अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रति अपने प्रेम और आदर की अभिव्यक्ति के रूप में तथा साथ ही आदर्श के अनुरूप उन्हें अपने हाथ से कते हुए सूत द्वारा बनी हुई पोशाक भेंट की जाय। प्रान्त के रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं ने इस अतिथियज्ञ में उत्साह से भाग लिया। चर्खा संघ का भी इस काम में पूरा सहयोग मिला। इसके लिए कुल १५२१॥ गुंडी सूत एकत्रित हुआ। प्रान्त की यह भावनापूर्ण भेंट खुले अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को दी गई। यहां एक उल्लेख करना भी जरूरी है कि अधिवेशन में लगने वाली मुख्य ध्वजा भी कार्यकर्ताओं के हाथ के सूत से बनी हुई थी। राजस्थान सूत्रकार (बुनकर) सभा ने न सिर्फ अपने सदस्यों द्वारा काता हुआ सूत दिया बल्कि उस सूत का झण्डा भी स्वयं ही बुना। झण्डे में चर्खे सहित तीन रंग बुनाई में ही तैयार किए गए थे। यह झण्डा राजस्थान की बुनाई कला का एक सुन्दर नमूना है और सदा के लिए सुरक्षित रहने की दृष्टि से प्रान्त के सरकारी संग्रहालय में रख दिया गया है। अधिवेशन के अवसर पर स्वागत समिति की प्रचार प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान दिग्दर्शन' पुस्तिका भी अध्यक्ष महोदय तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को भेंट की गई।

१८. जयपुर कांग्रेस का सन्देश

यह अधिवेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वर्गारोहण के बाद पहला अधिवेशन था। इसके अलावा पिछले अधिवेशन के बाद स्वाधीनता प्राप्ति के बावजूद एक भयंकर तूफान और नैतिक संकट का सामना देश को करना

पड़ा था। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से देश के नाम एक नया सन्देश प्रसारित किया गया जिसमें राष्ट्रपिता के बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की गई। इसके अलावा जयपुर कांग्रेस ने स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक मण्डल तथा एशियाई मुल्कों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए। कुल मिलाकर कांग्रेस में १६ प्रस्ताव स्वीकार किए गऐ।

अधिवेशन की कार्रवाई में देश के नेताओं तथा अ० भा० कांग्रेस कमेटी के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। काश्मीर के प्रधान मन्त्री तथा दक्षिणी अफ्रीका, मलाया, लंका आदि देशों से आए हुए प्रवासी भारतीय प्रतिनिधिगण व विभिन्न देशों के राजदूत आदि भी उपस्थित थे।

कांग्रेस अधिवेशन सम्बन्धी कार्यक्रम के अलावा इस अवसर पर कुदरती जीवन सम्मेलन, कम्पोस्ट कान्फरेंस, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन आदि कार्यक्रमों के लिए भी स्वागत समिति की ओर से सुविधायें दी गई थीं।

अधिवेशन की तैयारी तथा कार्यक्रम के सिलसिले में होने वाली घटनाओं की सूची मय तारीखों के परिशिष्ट (४) में दी गई है। स्वागताध्यक्ष व नव निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण तथा अधिवेशन की कार्रवाई भाग २ में दी गई है।

संयोजक निर्माण समिति

श्री दौलतमल भंडारी

१६ कार्य-विवरण (विस्तृत)

जैसा कि पिछले अध्यायों में उल्लेख किया जा चुका है, कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी के लिए स्वागत समिति की कार्यकारिणी ने मुख्य प्रश्नों पर सैद्धान्तिक निर्णय करके उसके रोज व रोज के काम के संचालन का भार विभिन्न उपसमितियों पर छोड दिया था। उपसमितियों के काम में आपसी सम्पर्क, सिहांवलोकन तथा मार्गदर्शन के लिए उसने उन्हीं समितियों के संयोजकों की एक संचालन समिति भी नियुक्त करदी थी। समितियों के अलावा अनेक प्रकार के ऐसे काम थे जिन्हें स्वागत समिति के मन्त्रियों के सीधे संचालन में प्रधान कार्यालय को ही करना पडा। इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी इन उप समितियों तथा मुख्य कार्यालय के कार्य विवरण से मिल सकती है, जो संक्षिप्त में नीचे लिखे अनुसार है:—

गांधीनगर निर्माण

गांधीनगर के निर्माण का काम मुख्य तौर पर निर्माण समिति के जिम्मे किया गया था। बाद में सुविधा की दृष्टि से खुले अधिवेशन का पण्डाल बनाने के लिए एक पण्डाल समिति अलग बना दी गई थी। प्रदर्शिनी के निर्माण का कार्य प्रदर्शिनी समिति की इच्छानुसार उन्हीं की देख-रेख में निर्माण समिति के इन्जीनियरों और कारीगरों द्वारा किया गया।

निर्माण समिति

गांधीनगर में अधिवेशन का जो स्थान चुना गया वह एक ओर तत्कालीन झालाना स्टेशन और दूसरी ओर जयपुर शहर के छोर पर स्थित मोतीडूंगरी के बीच ऊँचे नीचे टीबों के रूप में पडा हुआ था। उसके धरातल को समतल करना और उसका मुख्य सडकों से सम्बन्ध जोडना आवश्यक था। इस नगर में पचास हजार व्यक्तियों के सुविधापूर्ण निवास की व्यवस्था की कल्पना से काम को आगे बढाना था। इसके अलावा लाखों आदमियों की भोजन व्यवस्था, कांग्रेस नगर के मुख्य अंग झण्डा चौक, विषय निर्वाचिनी का पण्डाल तथा खुले अधिवेशन का पण्डाल आदि इसी बडे पैमाने से निर्माण करने आवश्यक हो गए। इन सबके लिए नये सिरे से सडक बनानी, पानी व

नल लगाने और बिजली की व्यवस्था करने का सवाल भी स्वाभाविक तौर पर सामने आया । इस सब भारी काम के लिए समय बहुत कम था और आवश्यक टीन, बल्ली, बांस आदि सामान सैंकडों मील दूर से आना था। निर्माण समिति के संयोजक श्री दौलतमल भण्डारी तत्कालीन जयपुर राज्य के विकास मन्त्री भी थे और उन्हें जयपुर सरकार की पूरी मदद थी और पी० डब्ल्यु० डी० पानी, बिजली आदि विभागों के अधिकारियों तथा उनके कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग भी । जयपुर राज्य के एक इन्जीनियर श्री त्रिलोकीनाथ सेठ की सेवाएं जयपुर राज्य से मांग ली गई थी । उन्होंने तथा समिति के सहायक संयोजक श्री बदरीनारायण सोढाणी ने बडे उत्साह और लगन से सारा काम सम्हाला और पूरा किया । राज्य के चीफ इन्जीनियर श्री पद्मनाभन, पानी विभाग के श्री प्रहलादराय तथा बिजली विभाग के श्री पांडे व श्रीटिक्कू से भी निर्माण काम में पूरी सहायता मिली।

कार्य कारिणी तथा संचालन समिति द्वारा किए गए निश्चयों के अनुसार इन्जीनियर श्री सेठ ने गांधीनगर का नक्शा तैयार किया । (नक्शे के लिए देखिए; परिशिष्ट स०   (गांधीनगर निर्माण) कार्य के पैमाने पर का अन्दाज नीचे लिखे आंकडों से जाना जा सकता है:—

१. खुले अधिवेशन पण्डाल में ३ से ४ लाख व्यक्तियों के बैठने योग्य स्था
२. विषय निर्वाचिनी समिति पण्डाल में करीब ३० हजार व्यक्तियों के लिए स्थान
३. नेता निवास में ५०० व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था
४. प्रतिनिधि निवास में ४००० प्रतिनिधियों की व्यवस्था
५. दर्शक निवास में १२००० दर्शकों के ठहरने की व्यवस्था
६. किसान निवास में २०००० व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था
७. ५०० परिवार कुटीर
८. ६००० स्वयंसेवकों व १००० स्वयंसेविकाओं के लिए कैम्प
९. छोटी बडी ३०० दुकानें
१०. पांच बडे गोदाम
११. करीब २१ भोजनशालायें

गांधीनगर के इंजीनियर
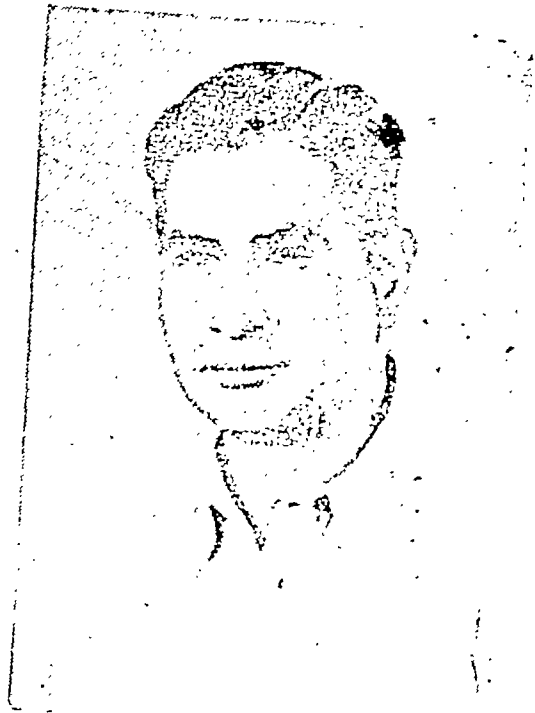
श्री त्रिलोकीनाथ सेठ

१२. कार्यकर्ता निवास तथा कार्यालय

१३. प्रदर्शिनी तथा ग्रामोद्योगी वाजार

निर्माण कार्य के लिए २७,००० कैनवास की छोलदारियां और २६५१ टन लोहे का सामान भारत सरकार की मार्फत तथा परिमाण में वांस, वल्लियां आदि सामान सीधा खरीदा गया । राजस्थान की विभिन्न रियासतों तथा जागीरदारी ठिकानों के अलावा भारत सरकार के रक्षा विभाग, सैन्ट्रल आर्डिनेंस डिपो, कानपुर, से ५०० तम्बू किराये पर मँगाये गये । अधिवेशन के ध्वजदण्ड की ऊँचाई यह कांग्रेस का ५५वां अधिवेशन होने से ५५ फीट रखी गई । गांधीनगर में नवनिर्मित सडकों की लम्वाई करीव ५ मील तथा झंण्डा सर्किल के व्यास की लम्वाई १५०० फीट रक्खी गई ।

तत्कालीन जयपुर सरकार ने गांधीनगर में सडकों के अलावा पानी तथा विजली की लाइनें डालने का काम अपनी ओर से किया । तीन चार महीनें के थोडे से समय में ही यह काम यहां के पी० डवल्यु० डी० विभाग ने पूरा किया । सहायता के रूप में अन्य राज्यों की तरह रकम देने तथा स्वागत समिति के लिए समय उस २ लाखों रुपया उधार देने के अलावा गाधी नगर निर्माण के काम में भी इस तरह तत्कालीन जयपुर राज्य की ओर से यह उल्लेखनीय सहायता स्वागत समिति को मिली । पानी, विजली तथा सडकों के काम में राज्य की ओर से करीव लाख रुपया खर्च हुआ। गांधीनगर में विजली फिटिंग का काम ठेके से कराया गया । गांधीनगर कैम्प और 'गांधीनगर' (झालाना) स्टेशन के वीच की सडक वनाने का काम वी० वी० एण्ड० सी० आई रेल्वे के मार्फत कराया गया।

इस सव कार्य को करने के लिए करीव ३००० श्रमिकों (जिनमें काफी शरणार्थी भी थे') तथा कार्यकर्ताओं ने कई महिनों तक रात दिन कार्य किया । समय की कमी तथा वांस वल्ली आदि जरूरी सामान निश्चित समय पर न आ सकने के कारण निर्माण का कार्य में एक सप्ताह तक स्थगित रखना पडा जिसके फलस्वरूप दर्शन निवास, किसान निवास, स्वयं-सेवक कैम्प तथा परिवार कुटीर का कुछ काम समय पर पूरा नहीं हो सका। पर दो ढाई महीने की छोटी सी अवधि में एक जंगल को विजली, नल तार, टेलीफोन आदि आजकल की सव सुविधाओं से परिपूर्ण एक नगरी में,

परिवर्तित कर देना सचमुच वडा सराहनीय काम था जो निर्माण समिति तथा उसके कार्यकर्ताओं ने किया

डाल समिति

खुले अधिवेशन का पण्डाल गांधीनगर के उत्तरी छोर पर पूर्व ओर रखा गया था। इसका मंच करीव ढाई हजार व्यक्तियों के वैठने योग्य लम्वा चौडा वनाया गया। पण्डाल में करीव दो लाख व्यक्तियों के वैठने की व्यवस्था की गई थी। पण्डाल में लाउड स्पीकर की व्यवस्था अन्य कांग्रेस अधिवेशनों में सुपरिचित फर्म शिकागो रेडियो द्वारा की गई थी। पण्डालमें विछायत के सम्बन्ध में किए गए निश्चय के अनुसार विछायत प्रतिनिधियों, स्वागत समिति के सदस्यों, प्रेस तथा विशिष्ठ व्यक्तियों के व्लाक तक सीमित रखी गई। मंच पर सव कपडा खादी का ही इस्तेमाल किया गया था। मण्डप के वाहर ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) द्वारा किसानों के लए अधिवेशन की कार्रवाई निःशुल्क सुनने की सुविधा भी की गई थी। इस समिति का कार्य सम्पादन सरदार हरलालसिंह के संयोजकत्व में हुआ।

सजावट समिति

सजावट समिति में राजस्थान के ख्याति प्राप्त कलाकार थे जिन्होंने जगह २ स्वागत द्वार वनाने के अलावा गांधीनगर, मंच तथा पण्डाल की पूरी सजावट की योजना वनाई। सजावट समिति का काम वास्तव में नगर निर्माण के वाद ही शुरु हो सकता था पर सजावट की रूपरेखा और योजना वनाने का काम पहले से कर लिया गया। सजावट की सारी योजना में राजस्थान की कला तथा राष्ट्रीय भावनाओं के चित्रण का विशेष ध्यान रखा गया था।

गांधीनगर में कुल मिलाकर ३३ द्वार वनाये गये थे। मुख्य प्रवेश द्वार लगभग ४० फीट चौडा और ३० फीट ऊँचा था। इन ३३ द्वारों में से सिरकियां, घाँस, पत्तों आदि के २१ दरवाजे और ७ कपडे के थे। शेष दरवाजों के निर्माण में कलश, टोकरियां, हल, अशोक चक्र, चर्खे तथा सूप का उपयोग किया गया था। यह द्वार राजस्थान के प्रमुख दस्तकारों और कलाकारों की भवन निर्माण कला के उत्कृष्ठ उदाहरण थे। इन सवके उपयोग का उद्देश्य द्वारों में कला के साथ साथ राजस्थान की ग्राम्य जीवन की

संयोजक सजावट समिति

श्री देवीलाल सांभर

संयोजक पंडाल असामान समेट समिति

सरदार हरलालसिंह
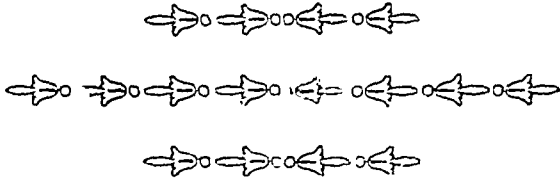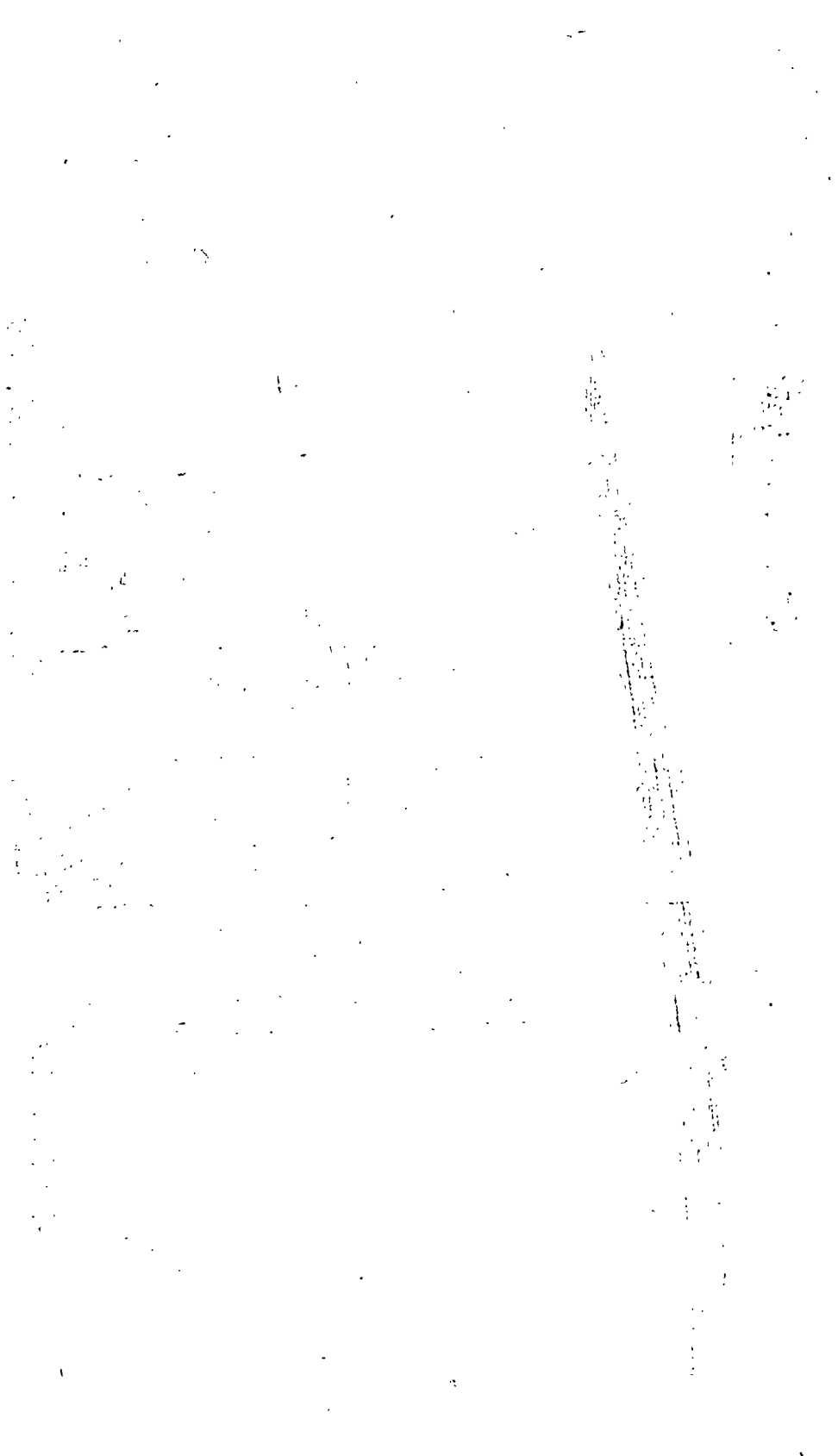
आचार्य श्री विनोबा भावे–

सर्वोदय प्रदर्शिनी, गांधी-नगर के उद्घाटन के पूर्व सामूहिक प्रार्थना में तल्लीन

झांकियां दिखाना था। सजावट के काम में अधिकांश स्थानीय वस्तुओं तथा कलाकारों का ही उपयोग किया गया था। विषय निर्वाचिनी पण्डाल और खुले अधिवेशन के मण्डलों में सजाये गये चित्रों में से अधिकांश चित्रकला के प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकार श्री इन्द्र दूगड तथा विद्या भवन, उदयपुर, के श्री गोरधन जोशी द्वारा चित्रित किये गये थे।

स्वागत समिति कार्यकारिणी के निश्चयानुसार कांग्रेस नगर के द्वारों के नाम राजस्थान के राजनैतिक शहीदों के नाम पर रखने का निश्चय किया गया जिसके लिए कार्यकारिणी ने एक कमेटी नियुक्त की थी और उसके निश्चय के अनुसार द्वारों तथा नगर के मुख्य मार्गों का नामकरण किया गया। नगर के मुख्य द्वार का नाम श्री जमनालाल बजाज द्वार रखा गया। (द्वारों के नाम के लिए देखिए परिशिष्ठ ५)

मुख्य द्वारों पर "नौबत" बजाने की भी व्यवस्था थी। 'राजस्थान दिग्दर्शन' का मुख्य पृष्ठ, विषय निर्वाचिनी के मंच के पिछवाडे में लगा हुवा भील चित्र, व पण्डाल के मंच पर लगे हुए ७ गांधीजी के चित्र भी सजावट समिति के इन्हीं कलाकारों द्वारा बनाये गये थे। विषय निर्वाचिनी समिति पण्डाल व अधिवेशन पण्डाल में पुष्पहार और झण्डियों की सजावट तथा गांधी स्मारक कोष के लिए ५५ चित्र भी इसी समिति द्वारा बनाये गये थे।

सजावट के काम की सभी लोगों ने प्रसंशा की इतने थोडे समय और कम लागत में तथा रोजमर्रा के काम की भी साधारण चीजों द्वारा एक नए पहलू से जन साधारण के जीवन की झांकियों को कलात्मक तथा आकर्षक ढंग से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है, यह इस सजावट से स्पष्ट जाहिर होता था। इस सबका पूरा श्रेय सजावट समिति के संयोजक, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार श्री देवीलाल सामर तथा उनके सहयोगी श्री इन्द्र दूगड, श्री गोरधन जोशी, श्री रामगोपाल विजयवर्गीय आदि को है। श्री देवीलाल सामर तथा श्री गोरधन जोशी दोनों को इस काम के लिए छुट्टी देने के लिए स्वागत समिति विद्याभवन उदयपुर की आभारी है।

सर्वोदय प्रदर्शिनी

सर्वोदय प्रदर्शिनी जयपुर कांग्रेस अधिवेशन का एक प्रमुख और स्मरणी

अंग थी । प्रदर्शिनी का निर्माण सर्वोदय विचार धारा के आधार पर किया गया था । इसके निर्माण में कमती ज्यादा लागत का अधिक खयाल न करते हुए देहात में पैदा होने वाली घास, वांस आदि चीजों का ही उपयोग किया गया था । प्रदर्शिनी के वांस के वने हुए प्रवेश द्वार अत्यन्त आकर्षक, सुन्दर ओर साथ ही सादे थे । वांस, सरकी, घास आदि से वनायी हुई मीनार तथा "वापू मण्डप" भी अपने ढंग की अनोखी चीजें थी ।

प्रदर्शिनी समिति के निश्चयानुसार प्रदर्शनी में नई तालीम, खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा, खेती, घरेलू उद्योग तथा ग्राम संस्कृति आदि वातों के समुचित प्रदर्शनि की व्यवस्था की गई । प्रदर्शनी में एक "राजस्थान भवन" का भी आयोजन किया गया था । प्रदर्शनी की व्यवस्था के लिए देश के विभिन्न प्रान्तों से आये हुए कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन सुवह सामुहिक प्रार्थना कार्यक्रम रखा जाता था जिसमें श्री श्रीकृष्णदास जाजू तथा आचार्य श्री विनोवा भावे के प्रवचन भी हुए । प्रदर्शनी में मनोरजन के लिए सगीत, नृत्य, आदि के कार्यक्रम में विद्याभवन उदयपुर तथा दक्षिणी भारत की पार्टियों ने भी भाग लिया ।

सर्वोदय प्रदर्शनी सचमुच भारतवर्ष में अपने ढंग की पहली ही प्रदर्शनी थी जिसमें भारतीय ग्राम्य जीवन का दर्शन इतने उत्कृष्ट ढंग से कराया गया हो । यदि यह कहा जाय कि जयपुर कांग्रेस का सवसे अधिक सफल और आकर्षक कार्यक्रम सर्वोदय प्रदर्शनी थी तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इतने वडे परिश्रम और कल्पना शक्ति से निर्मित सुन्दर प्रदर्शनी अधिवेशन के साथ विघटित करनी पडी यह सचमुच खेद की वात थी । काश ऐसी प्रदर्शनी किसी भी प्रकार से स्थायी वन सकती । इस प्रदर्शनी का पूरा विवरण अ० भा० चरखा सघ की ओर से अलग प्रकाशित किया गया है ।

भोजन व्यवस्था

पहले कहा जा चुका है कि स्वागत समिति कार्यकारिणी द्वारा निर्मित भोजन समिति ने गांधीनगर में आने वाले लोगों के लिए वीस लाख तथा जयपुर शहर में ठहरने वाले लोगों के लिए वीस लाख इस प्रकार कुल चालीस लाख खूराकों (Diets) की व्यवस्था का विचार किया था । इतने वडे काम की व्यवस्था के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा रसो-

स्थिति उन दिनों बहुत ठीक नहीं थी । जन साधारण की कांग्रेस अधिवेशन के कारण सभी चीजों पर और खासकर खाद्य पदार्थों के अधिक मंहगा हो जाने का भय भी था ।

अधिवेशन के लिए जो हजारों टन माल वाहर से रेल द्वारा लाये जाने को था। उसे स्टेशन पर उतारना और फिर गांधीनगर पहुँचाना अपने आप में एक वडी समस्या थी । जयपुर स्टेशन से गांधीनगर करीव ४ मील पडता था और गांधीनगर (झालाना) स्टेशन छोटा होने के कारण थोडे से समय में सैंकडों वैगन माल उतारना सम्भव नहीं था । अतः रेल्वे अधिकारियोंसे वातचीतकरके झालाना स्टेशन से गांधीनगर के नजदीक माल उतारने के लिए एक विशेष साइडिंग का प्रवन्ध किया गया । सामग्री संग्रह समिति ने अपना वडा गोदाम इसी साइडिंग पर रखा और अधिकांश माल यहीं से फिर आवश्यकतानुसार गांधीनगर में जगह २ पर पहुँचाया गया । स्वयं सेवकों की वर्दियां तया गांधीनगर के लिए आवश्यक फरनीचर भी सामग्री संग्रह समिति ने जुटाया । इस समिति के सफलता पूर्वक काम करने का श्रेय इसके संयोजक श्री विजयचन्द जैन तथा उनके सहयोगियों को है जिन्होंने थोडे से समय में इतने कठिन और भारी काम की व्यवस्था की ।

गांधीनगर में वाजार व आवश्यक दुकानों आदि के प्रवन्ध तथा विज्ञापनका चार्ज वाजार विज्ञापन समितिके पास था । इस समिति के संयोजक श्री सुभद्रकुमार पाटणी थे । गांधीनगर में दुकानें लगाने के सम्वन्ध निम्न लिखित आधार पर आवेदन पत्र मांगे गये थे ।

वाजार विज्ञापन समिति

१. क. सर्वोदय प्रदर्शिनी तथा उसके साथ संलग्न, ग्रामोद्योगी वस्तुओं के वाजार के अलावा गांधीनगर में विज्ञापन, प्रचार, विक्री की दृष्टि से अन्य कोई वाजार नहीं लगाया जायगा।

ख. गांधीनगर में ग्रामोद्योग वाजार के अलावा उन्हीं दुकानों को स्थान दिया जायगा जिनकी अधिवेशन के दिनों में गांधीनगर में आकर वसने वालों के लिए उपयोगिता हो।

२. गांधीनगर में दुकानें लगाने वालों के निवास के वारे में यह तै किया गया कि वे अपनी २ दुकानों में रहें या फिर अन्य दर्शकों की तरह दर्शक निवास में अपने ठहरने की व्यवस्था करलें।

संयोजक बाजार विज्ञापन समिति

श्री शुभभद्र कुमार पाटनी

संयोजक प्रचार प्रकाशन समिति

ो चन्द्र गुप्तवाष्णय

३. स्वागत समिति के जिन बैंकों में खाते थे उनको अधिवेशन में स्टालें निःशुल्क दी गई।

४ अधिवेशन में खोंमचे वालों को अनियन्त्रित रूप से न घूमने देने के बारे में हुए निश्चय के अनुसार आठ दिसम्बर के बाद खोमचे वालों को अधिवेशन में आने की इजाजत नहीं दी गई।

गांधीनगर की दुकानों में खाद्य पदार्थों के भावों को नियन्त्रित करने के लिए दुकानदारों को अपनी २ दुकानों पर भावों की सूचि लगाने तथा बाजार विज्ञापन समिति द्वारा अपनी देखरेख में भोजनालय चलाने की भी व्यवस्था की गई। चार साइकिल स्टैन्डों का ठेका बोली लगाकर दिया गया जिनमें प्रत्येक स्टैन्ड पर १५०० साइकिलें रखने की व्यवस्था थी।

कपडा मिल के विज्ञापनों को छोडकर अन्य उद्योगों के विज्ञापनों को भी आमदनी की दृष्टिसे गांधीनगर में स्थान दिया गया। गांधी नगर में मुख्य प्रवेश द्वार के नजदीक ही सड़क के दोनों ओर अनेक सुन्दर विज्ञापन बोर्ड लगाये गये थे। इसके अलावा दूसरे विभिन्न स्थानों पर भी विज्ञापन व्यवस्थित ढंग से लगाये गये थे। बाजार विज्ञापन समिति की ओर से बाजार में दुकान लगाने वालों तथा विज्ञापन देने वाले लोगों की जानकारी के लिए आवश्यक नियमावली तथा दुकानों आदि का नक्शा भी प्रकाशित किया गया।

—प्रचार प्रकाशन समिति—

जैसा कि पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है, अधिवेशन की तैयारी सम्बन्धी प्रचार तथा उस अवसर पर उपयोगी साहित्य के प्रकाशन का काम प्रचार प्रकाशन समिति के सुपुर्द किया गया था। इस समिति के संयोजक श्री चन्द्रगुप्तजी वार्ष्णेय ने काफी परिश्रम से प्रचार कार्य सम्पादित किया।

अधिवेशन सम्बन्धी सम्वाद भारतवर्ष के प्रायः सभी दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों तथा राजपूताना और जयपुर के सभी पत्रों को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में नियमित रूप से भेजे जाते रहे। समय समय पर अधिवेशन की दृष्टि से भिन्न २ विषयों की आवश्यकतानुसार पूरी जानकारी देने के लिए संक्षिप्त पत्रक तथा बुलेटिन भी प्रकाशित किए गए।

अधिवेशन के अवसर पर दूर २ से आने वाले व्यक्तियों को राज-

पूताना की कला तथा राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में आवश्यक परिचय कराने के उद्देश्य से १६८ पृष्ठ की एक सचित्र "राजस्थान दिग्दर्शन" नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई। पुस्तिका में प्रान्त के ऐतिहासिक स्थानोंके भव्य चित्रों के अलावा राजस्थान की जानकारी सम्बन्धी आवश्यक मोटी २ सभी बातों का समावेश किया गया था। पुस्तिका सभी को पसन्द आई और राजस्थान की भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से यह विद्यार्थियों, प्रवासी राजस्थानियों, तथा विदेशी यात्रियों के बडे उपयोग की वस्तु बन गई है। गांधीनगर तथा अधिवेशन की जानकारी कराने के लिए "गांधीनगर परिचय" नाम से एक अन्य छोटी पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।

अधिवेशन के अवसर पर पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार समितियों के प्रतिनिधियों एवं प्रमाणित फोटोग्राफरों को प्रेस पास देने सम्बन्धी नियम बनाकर उनके काम में सुविधा देने की व्यवस्था की गई। अधिवेशन की कार्रवाई की एक विवरणात्मक फिल्म लेने तथा इस कार्रवाई को रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट कराने सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था भी प्रचार प्रकाशन समिति द्वारा की गई। अधिवेशन की कार्रवाई की रिपोर्ट "वायर रेकार्डिंग मशीन" द्वारा लेने की व्यवस्था भी की गई तथा "आल इण्डिया शार्टहैंड इन्स्टीट्यूट" द्वारा भी रिपोर्ट तैयार करवाई गई।

—सवारी समिति—

अधिवेशन के सम्बन्ध में सवारियों की उचित व्यवस्था करने का भार श्री गुलाबचन्द कासलीवाल के संयोजकत्व तथा श्री भँवरलाल अजमेरा के मन्त्रित्व में सवारी समिति पर छोडा गया था। सवारी समिति का कार्य मुख्यतः नीचे लिखे अनुसार चार प्रकार का था :—

१. अधिवेशन के सिलसिले में जुटाये हुए सामान को स्टेशन या शहर से गांधीनगर तक तथा गांधीनगर में ही एक स्थल से दूसरे स्थल तक ढोने के लिए मोटर ट्रकों की व्यवस्था करना।

२. कांग्रेस अधिवेशन के लिए आए हुए कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों, प्रतिनिधियों तथा यात्रियों को स्टेशन से गांधीनगर या जयपुर

संयोजक सवारी समिति
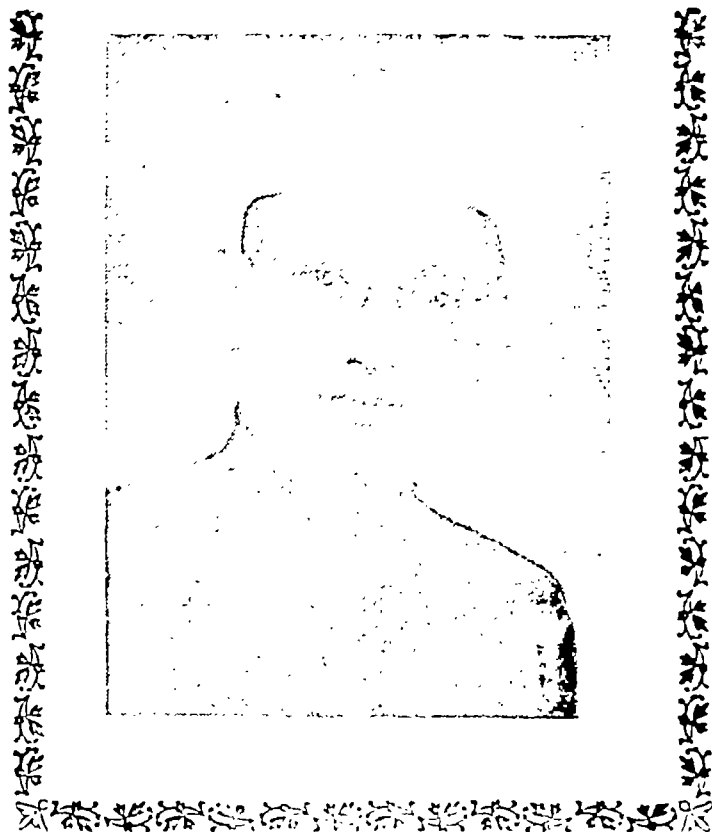
श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
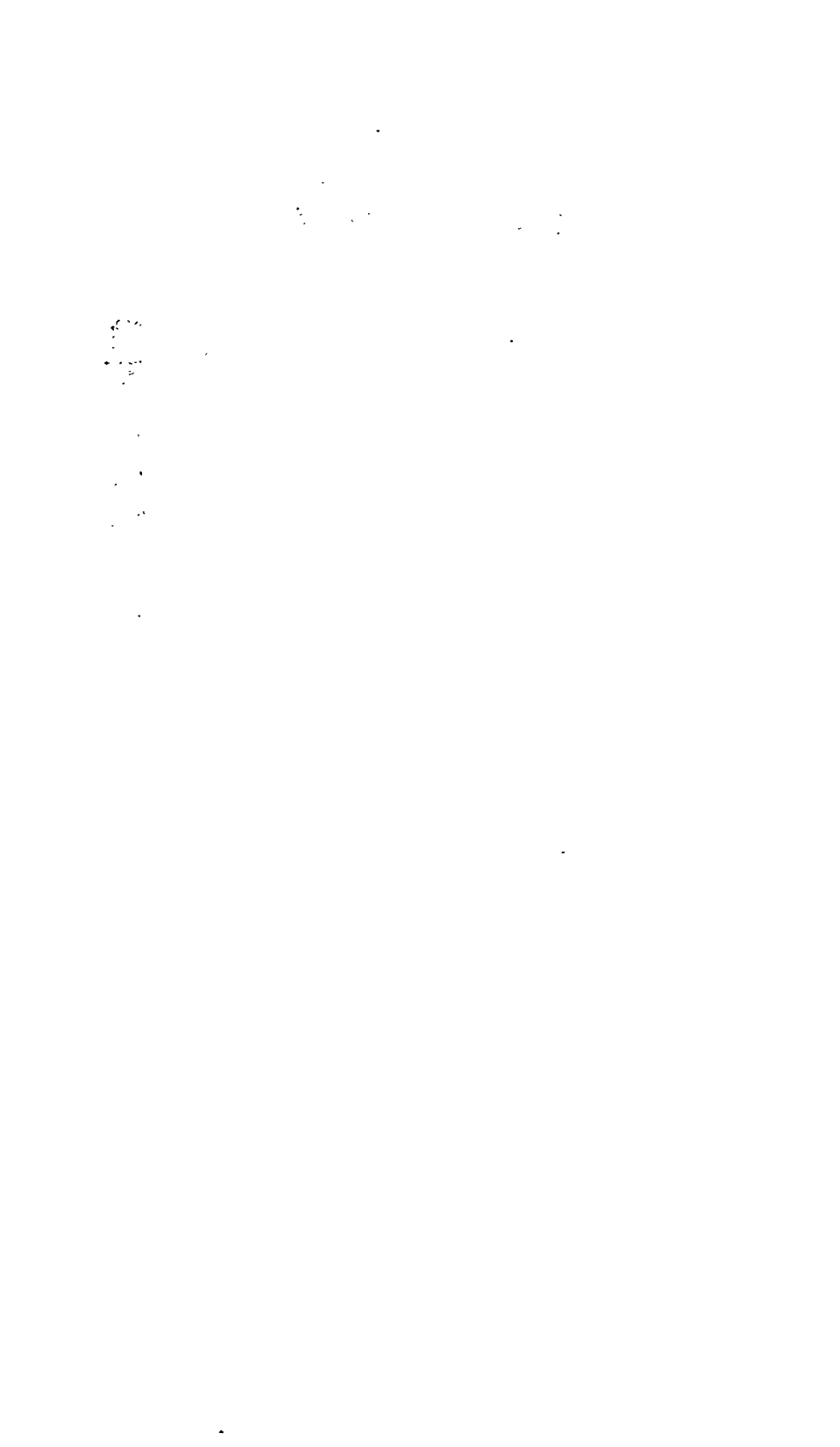
तथा गांधीनगर और जयपुर के बीच जाने आने के लिए बसों की व्यवस्था करना ।

३. अधिवेशन के काम के लिए तथा आगन्तुक नेताओं व विशिष्ट मेहमानों के लिए मोटरों की व्यवस्था करना ।

४. गांधीनगर में आने वाली अन्य लोगों की कारों तथा लारियों के प्रवेश आदि के नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक नियम बनाना ।

उपरोक्त काम की व्यवस्था के लिए सवारी समिति ने स्वागत समिति द्वारा खरीदे हुए मोटर ट्रक व गाडियों आदि के अलावा किराये के ट्रक मोटरों से भी काम लिया । मोटर बसों की व्यवस्था स्थानीय बसों केन्द्रीय सरकारी महकमों के मारफत रोहतक ट्रांसपोर्ट कम्पनियों से तथा कारों की दिल्ली के टैक्सी वालों से की गई । बस सर्विस में स्वागत की ओर से टिकिट काटने वाले कन्डेक्टरों तथा निरीक्षकों की व्यवस्था भी की गई थी । स्वागत समिति की गाडियों तथा बाहर से आई हुई कारों के लिए एक मोटर गेरेज की व्यवस्था की गई थी । स्वागत समिति के काम में आने वाली गाडियों के अलावा अधिवेशन के समय गांधीनगर में अन्य गाडियों के प्रवेश के लिए २५ रु० शुल्क रखा गया था । अधिवेशन के काम के सिलसिले में सवारी समिति के मारफत कुल ५५००० गैलन पैट्रोल के कूपन खर्च हुए ।

— सफाई समिति —

कांग्रेस अधिवेशन के लिए गांधीनगर में ठहरने वाले लाखों आदमियों के मलमूत्र की सफाई न केवल स्वच्छता की दृष्टि से बल्कि गांधीनगर और जयपुर शहर के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक थी । इस पवित्र काम के लिए किसी प्रकार के वैतनिक कर्मचारी रखना न केवल कठिन होता बल्कि कांग्रेस और सर्वोदय के आदर्श की दृष्टि से अवांछनीय और अनुचित भी स्वागत समिति ने पिछले अधिवेशनों के वक्त बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करके इस काम को उत्साह के साथ स्वेच्छा से करने वाले प्रान्त के रचनात्मक कार्यकर्ताओं को सौंपा, इस कठिन काम की जिम्मेदारी को उठाने वाली नियुक्त की गई सफाई समिति प्रान्त के, कर्तव्यनिष्ठ

पुराने कार्यकर्ता श्री लादूराम जोशी के संयोजकत्व में चलायी गयी। उन्हें बन्शीधर शर्मा जैसे उत्साही कार्यकर्ता का सहयोग भी मिला।

गांधीनगर के भिन्न २ कैम्पों में और स्थानों में प्रर्याप्त संख्या में खड्डे खोदकर पखाने और पेशावघर बनाये गये जिनके चारों ओर की स्थाई चार दीवारी लगाई गई। उनकी सफाई आदि के नियमों के चार्ट छपवाकर जगह २ टांके गए। सफाई समिति के अन्तर्गत काम कराने वाले कार्यकर्ताओं ने अपने काम के क्षेत्र बांट लिए और रोजमर्रा से सफाई शुरू करने का कार्यक्रम जारी रहा। मिट्टी से सफाई करने के लिए सफाई समिति की ओर से कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए विभिन्न कैम्पों में फावडे, खुरपे आदि आवश्यक सामान के अलावा डी० डी० टी० और फिनाइल के उपयोग की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा कुछ कैम्पों में आवश्यकतानुसार कमोड की व्यवस्था भी की गई थी। गांधीनगर की सडकों की सफाई व छिडकाव भी की व्यवस्था का भार जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल ने अपने जिम्मे लिया जिसके लिए स्वागत समिति उक्त कौंसिल की आभारी है। कुल मिलाकर गांधीनगर की सफाई की व्यवस्था सन्तोषजनक रही।

—रोगोपचार समिति—

डा० राजमल कासलीवाल के संयोजकत्व में रोगोपचार समिति ने चिकित्सा सम्बन्धी कार्य को संचालन करने की एक योजना बनाई जिसके अनुसार गांधीनगर में आउटडोर रोगियों के अलावा ८० रोगियों के ठहरने के लायक एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया। इस अस्पताल के पुरुष विभाग की देखरेख का काम डा० एस० सी० मेहता तथा महिला विभाग की देखरेख का काम डा० (मिस) एन० एक्विनो को सोंपा गया। डा० श्यामनाथ कन्सल की देखरेख में २० रोगियों के उपचार के लिए एक घूत रोगियों का अलग विभाग था। जोधपुर सरकार के चिकित्सा विभाग की ओर से एक्सरे व इलेक्ट्रोथिरेपी के अस्पताल की व्यवस्था भी की गई। साधारण चोट, जख्म, खांसी, बुखार आदि की तत्काल चिकित्सा के लिए गांधीनगर में भिन्न २ स्थानों पर दिन रात काम करने वाले ६ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गए। शफाखाने में गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसूती गृह का भी प्रबन्ध किया गया था। बंगाल केमिकल्स वर्क्स ने एक डिस्पेंसरी

संयोजक सफाई समिति
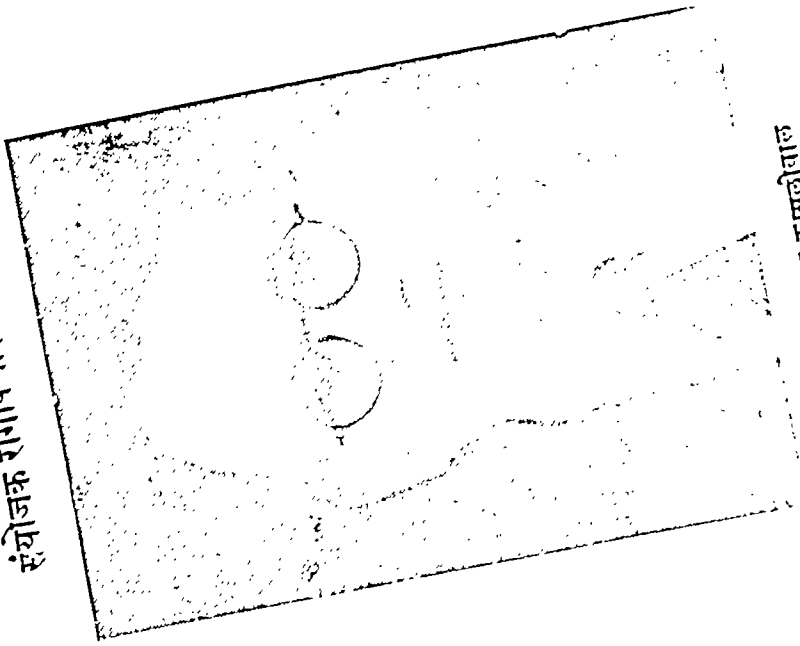
श्री लादूराम जोशी

संयोजक रोगोपचार समिति

श्री राजमल कासलीवाल
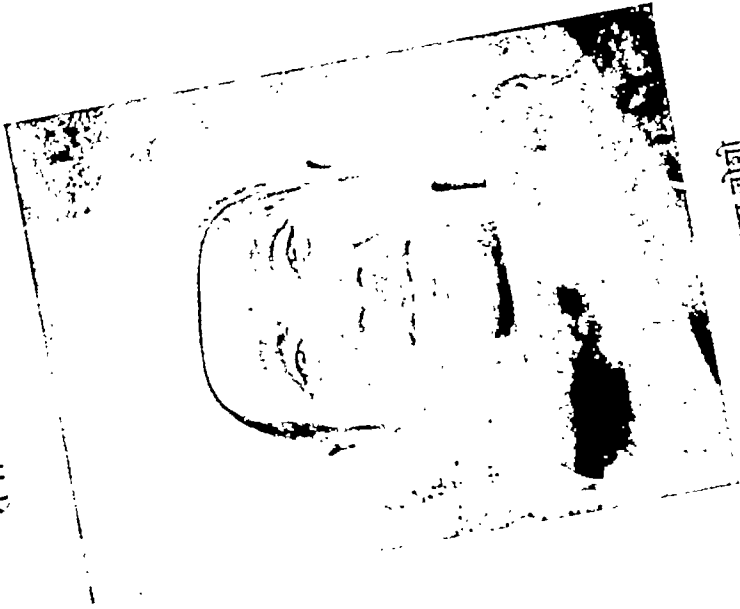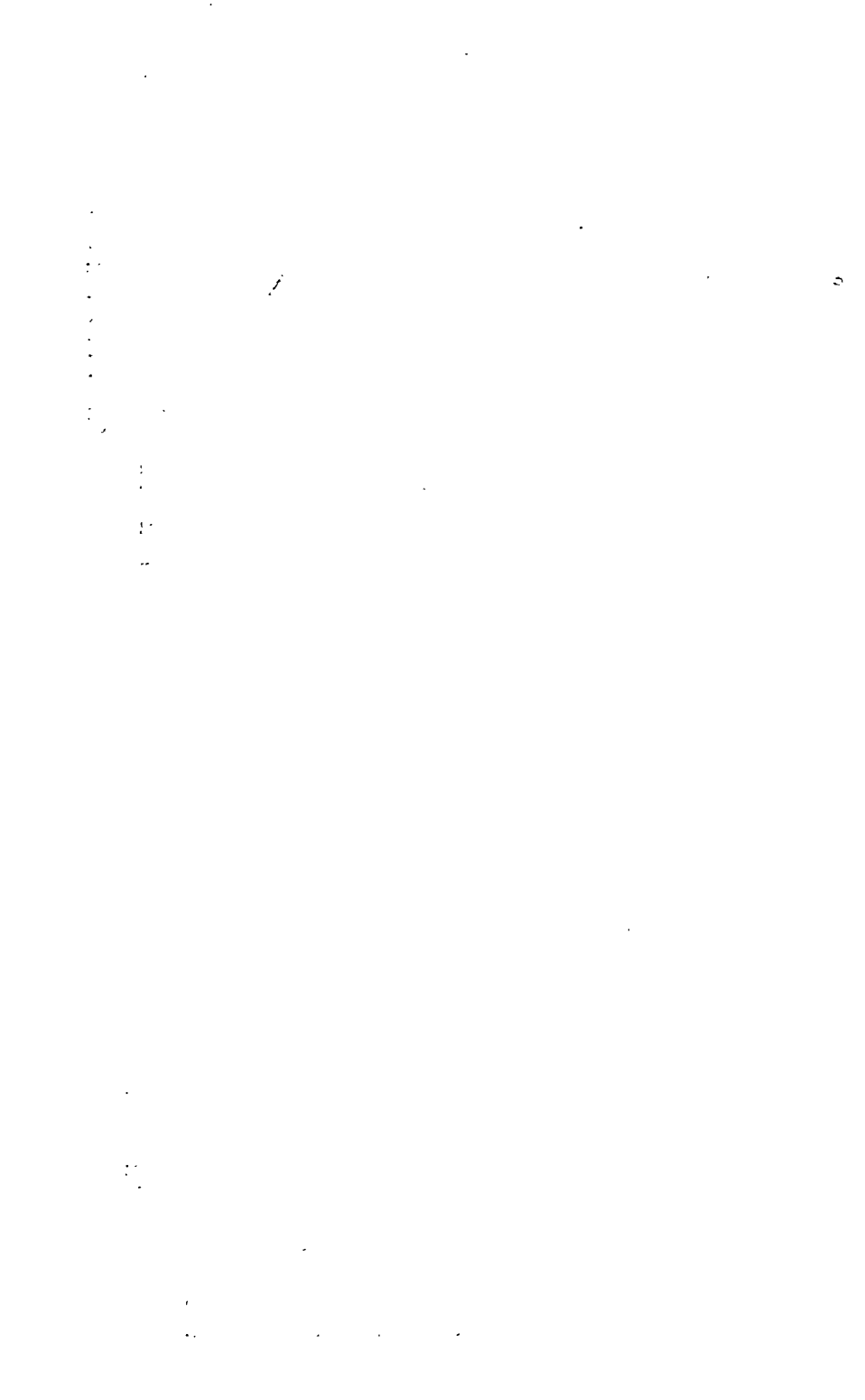
और प्राथमिक सहायता केन्द्र तथा मारवाडी रीलिफ सोसाइटी ने एक मेन डिस्पेंसरी तथा कई प्राथमिक सहायता केन्द्र भी खोले ।

ऐलोपेथिक पद्धति के साथ २ गांधीनगर में आयुर्वेदिक चिकित्सा का बाहर से प्रबन्ध भी था । इस विभाग की व्यवस्था का भार जयपुर के तथा आये हुए वैद्यों की सहायता से श्री स्वामी जयरामदास, श्री स्वामी मंगलदास एवं राजवैद्य श्री नन्दकिशोर शर्मा पर था । आंतरिक रोगियों के लिए ८ पलंगों की व्यवस्था थी, और छूत रोगियों की चिकित्सा का भी प्रबन्ध था ।

गांधीनगर में निर्माण का काम करने वाले कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों की चिकित्सा के लिए गांधीनगर में १ नम्बर से ही एक चिकित्सा केन्द्र खोल दिया गया था जिसमें १ डाक्टर, ३ कम्पाउन्डर, तथा १ नर्स के रहने की व्यवस्था थी । चिन्ताजनक रोगियों को गांधीनगर से सवाई मानसिह हास्पीटल तक ले जाने के लिए आवश्यक एम्बूलेंस की भी व्यवस्था की गई थी एम्बूलेंस का प्रबन्ध बीकानेर तथा सिरोही राज्य और अजमेर से, व जयपुर आइसोलेशन हास्पिटल तथा मारवाडी रिलीफ सोसायटी कलकत्ता की ओर से किया गया था ।

चिकित्सा सम्बन्धी सामान में अस्थायी औजारों के जो बाद में सरकारी हास्पिटल में काम आने लायक थे, खरीदने की व्यवस्था जयपुर सरकार द्वारा की गई तथा अधिकतर औषधियां डाक्टरों एवं औषध निर्माण करने वाली व्यापारिक फर्मो से मुफ्त में प्राप्त हुई ।

कांग्रेस कैम्प होसपिटल के ऐलोपेथिक विभाग ने कुल ९ चिकित्सा केन्द्र, आयुर्वेदिक विभाग ने ४ चिकित्सा केन्द्र चलाये, जिनमें क्रमश: २९२५५ तथा १०१६८ इस तरह कुल ३९४२३ रोगियों की सेवा की गई । रोगोपचार समिति के ऐलोपैथिक विभाग को १९८ डाक्टर तथा आयुर्वेदिक विभाग को ८० वैद्यों की अवैतनिक सेवायें मिली । बेंगाल केमिकल्स वर्क्स, कलकत्ता, चिकित्सा विभाग, जयपुर, स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग जयपुर तथा मारवाड रिलीफ सोसायटी, कलकत्ता का पूरा सहयोग भी समिति को प्राप्त हुआ । रोगोपचार समिति के लिए कुल २०,००० रु० की रकम खर्च के लिए स्वागत समिति ने स्वीकार की थी परन्तु उसमें से रोगोपचार सम्बन्धी व्यवस्था में केवल २५० रु० खर्च किया गया । बाकी सब काम निःशुल्क प्राप्त दवाओं

और सेवाओं से चलाया गया। मुफ्त दवाइयां देने वाली लगभग ८० व्यौपारिक कम्पनियां थी जिन में बंगाल केमिकल एन्ड फार्मेस्युटिकल वर्क्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने बडी उदारता पूर्वक हजारों रुपये की कीमती दवाइयां भेंट की।

स्वागत सत्कार समिति

अधिवेशन के सिलसिले में आने वाले महमानों, प्रतिनिधियों, तथा नेताओं आदि का यथाचित सत्कार करने तथा उन्हें हवाई अड्डे और रेल्वे स्टेशन से अपने २ कैम्पों में पहुँचाने सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था करने का भार तत्कालीन जयपुर सरकार के राजस्व मन्त्री श्री टीकाराम पालीवाल के संचालन में स्वागत सत्कार समिति पर डाला गया। स्वागत सत्कार समिति की ओर से इस काम के लिए स्टेशनों और हवाई अड्डों पर यात्रियों को आते ही कुछ देर सुस्ताने और उनके सामान आदि को ट्रकों में लादने की व्यवस्था की गई थी।

रेलवे यातायात समिति

कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी के लिए बाहर से रेल द्वारा माल मगाए जाने की व्यवस्था के अलावा अधिवेशन में लोगों के आने जाने की भी प्रबन्ध खास तौर से बिठाने की आवश्यकता थी और इस काम के लिए रेल्वे अधिकारियों से रोज करीब टिकट सम्पर्क बनाये रखकर उनका सहयोग प्राप्त करना जरूरी था। इस काम की जिम्मेदारी सम्भालने के लिए स्वागत समिति ने श्री राजबहादुर श्रीवास्तव के संयोजकत्व में रेल्वे यातायात समिति का निर्माण किया। श्री राजबहादुर ने जयपुर से बाहर का काम सम्भाला और यहां उनके सहायक के रूप में श्री रामचन्द्र कासलीवाल ने काम किया। उसके अनुसार अजमेर और दिल्ली के रेल्वे अधिकारियों से अधिक काम के लिए प्रथम श्रेणी की प्राथमिकता प्राप्त करके उनसे बराबर पत्र व्यवहार द्वारा तथा मिलजुल कर समय पर माल लदवाने की व्यवस्था की गई। समिति की एक सभा ता० २५-१०-४८ को भारत सरकार के रेल्वे मन्त्री माननीय श्री के० संतानम के सभापतित्व में की, जिसमें रेल्वे के कई अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में रेल्वे व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक बातें की गई तथा अधिवेशन के अवसर पर नेताओ, प्रतिनिधियों, दर्शकों आदि के लिए भी स्थान २ से विशेष रेल गाडियों (स्पेशलों) का प्रबन्ध करने पर विचार किया।

संयोजक स्वागत सत्कार समित

सीताराम पालीवाल

संयोजक जूलूस समिति

श्री रूपचन्द सोगानी
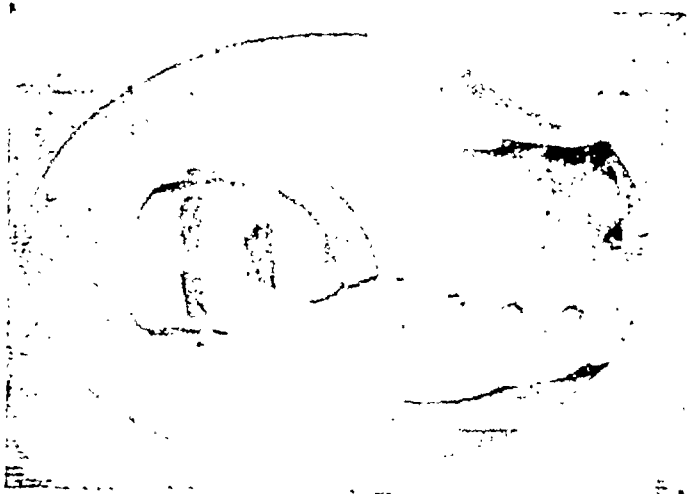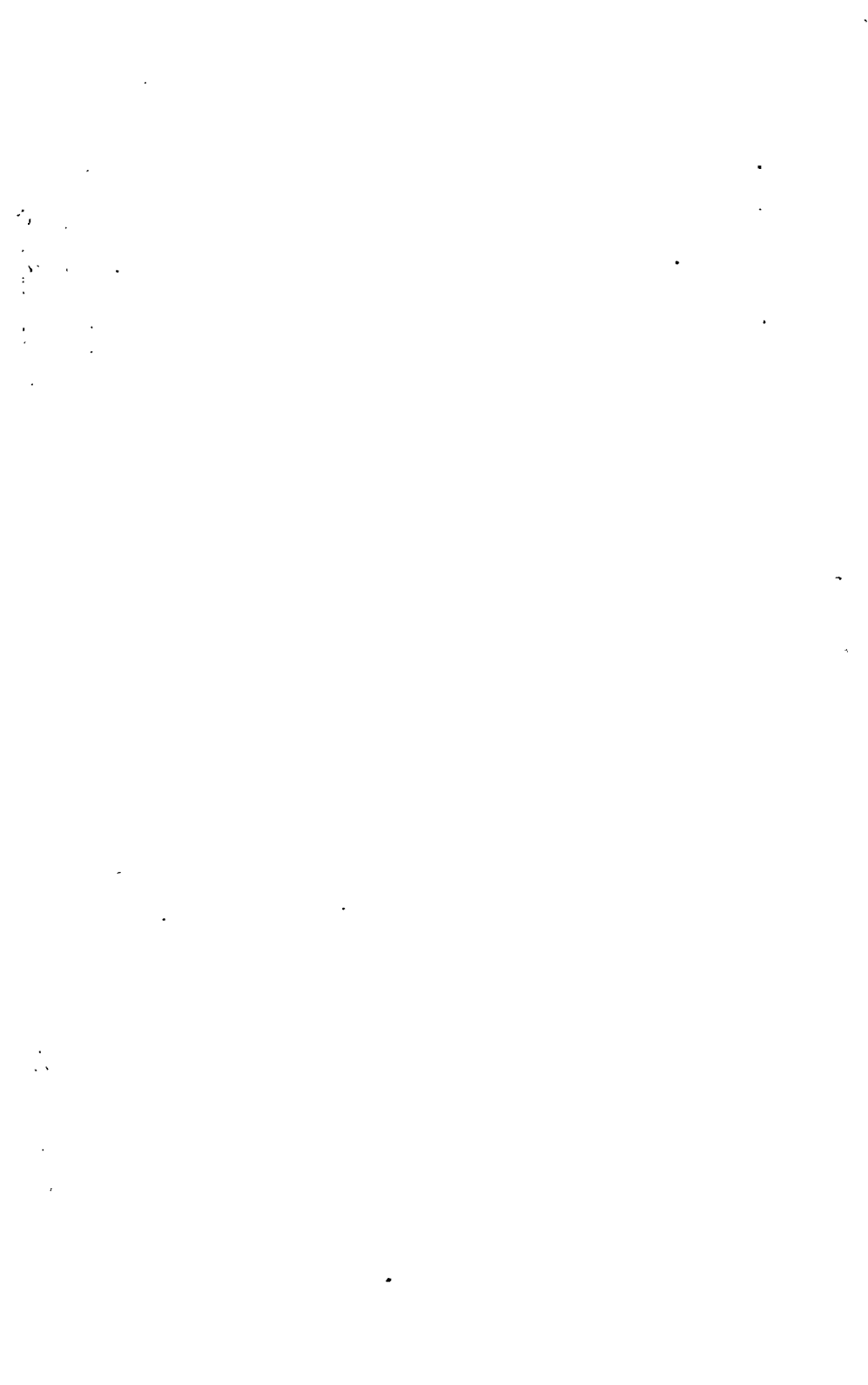
इस समिति के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारमैया को एक स्पेशल ट्रेन द्वारा दिल्ली से जयपुर लाने का भी प्रबन्ध किया गया। स्पेशल गाडियों के आने और जाने का टाइम टेबिल अच्छी तरह प्रकाशित कर दिया गया। इस प्रकार लाखों आदमियों को जयपुर और गांधीनगर स्टेशनों पर लाने और ले जाने की सुन्दर व्यवस्था की गई। यह सराहनीय बात थी कि अधिवेशन के पहले और बाद में थोडे ही समय में हजारों लाखों यात्रियों को लाने ले जाने का काम बडी सहूलियत से पार पडा।

जैसा कि उपर बतलाया जा चुका है, कांग्रेस अधिवेशन के लिए चुने गये स्थान के नजदीक के रेल्वे स्टेशन का नाम झालाना था। अधिवेशन की स्मृति सदा के लिए कायम रखने के लिए स्वागत समिति रेल्वे ने अधिकारियों को यह सुझाव भेजा कि झालाणा स्टेशन का नाम गांधीगर स्टेशन रख दिया जाय। स्वागत समिति को खुशी है कि रेल्वे ने इस बात को मंजूर कर लिया और झालाना का नाम अब गांधीनगर हो गया है। गांधीनगर स्टेशन के प्लेटफार्म को बडा तथा सुन्दर बनाया गया और स्टेशन स्टाफ आदि का भी विशेष प्रबन्ध किया गया।

अधिवेशन के सिलसिले में रेल्वे यातायात समिति के काम का अन्दाजा नीचे लिखे आंकडों से लग सकेगा:—

१, गांधीनगर तथा जयपुर रेलवे स्टेशनों पर अक्टूबर से दिसम्बर १९४८ तक अधिवेशन के लिए विविध सामान के कुल आये हुए मूल डिब्बों की संख्या १८०८ थी।

२. रेल्वे द्वारा ढोए हुए फुटकर सामान का अन्दाजा १८१०० टन का था।

३, अन्य रेलवे के अलावा बी० बी० सी० आई० द्वारा करीब २ दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाई गई।

इस बारे में रेल्वे विभाग तथा बी० बी० एण्ड० सी० आई० रेलवे के अधिकारियों का तथा खास तौर से श्री एम० डी० सेटना चीफ कन्ट्रोलर रेल्वे प्रायरिटीज का सराहनीय सहयोग स्वागत समिति को मिला।

स्वयं सेवक समिति

कांग्रेस अधिवेशन जैसे आयोजन को सफल बनाने के लिए कर्तव्य पालन करने वाले, अनुशासन मानने वाले तथा भली प्रकार ट्रेनिंग पाए हुए स्वयंसेवकों की व्यवस्था करना अनिवार्य रहा है। विशाल पैमाने पर आयोजित जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन की सफलता भी बहुत कुछ स्वयंसेवक संगठन पर निर्भर थी। कांग्रेस अधिवेशन के पहले कांग्रेस विरोधी तत्वों की कार्रवाइयों के कारण कुछ वर्गों में फैली हुई राजनैतिक द्वेष भावना को ध्यान में रखते हुए गांधी-नगर की सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था के लिए इस प्रकार के संगठन का महत्व और भी अधिक हो गया था। प्रान्त की कांग्रेस नई बनने के कारण यहां कोई कांग्रेस सेवा दल पहले से संगठित नहीं था। स्वयंसेवक दल के संगठन के महत्वपूर्ण कार्य का भार श्री जयनारायण व्यास पर छोड़ा गया। उनकी अनुप-स्थिति में संगठन सम्बन्धी कार्य श्री शिव बिहारी तिवारी तथा कार्यालय संबंधी कार्य श्री ज्ञानचन्द चोरड़िया ने किया।

अधिवेशन के लिए करीब पांच हजार स्वयं सेवकों तथा १००० सेवि-काओं का अन्दाज लगाया गया था। अनुमानित संख्या से काफी अधिक तादाद में स्वयं सेवक अधिवेशन में आये थे। इसके अलावा अ० भा० कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में चल रहे देश के विभिन्न प्रान्तीय सेवा दलों के प्रतिनिधि स्वयंसेवक भी आमंत्रित किये गये थे।

स्वयं सेवको की भर्ती का काम जिला कांग्रेस कमेटियों की मारफत कराया गया। स्वयंसेवक दल के समुचित शिक्षण के लिये जयपुर में चार सप्ताह के लिये ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। ट्रेनिंग में नायक व उपनायक की श्रेणी के स्वयंसेवकों व स्वयंसेविकाओं ने शिक्षण प्राप्त किया। ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने अपने २ स्थान पर जाकर स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी। ता० २० सितम्बर १९४८ को पुराने घाट में स्थित शिशोदीणीजी के बाग में इस केन्द्रीय शिक्षण कैम्प का उद्घाटन तत्कालीन जयपुर सरकार के शिक्षामन्त्री श्री देवीशंकर तिवाडी द्वारा किया गया। इसके साथ ही सांगानेर के पास वुडलैंड में अधिवेशन के काम में हाथ बंटाने के लिए स्काउटों का एक शिक्षण-शिविर श्री रामस्वरूप धीमन की देखरेख में चलाया गया।

स्वयं सेविकाओं के काम को तेजी से आगे बढाने के लिए एक स्वयंसेविका समिति का भी संगठन किया गया जिसकी अध्यक्ष वनस्थली विद्यापीठ की श्रीमती सज्जनदेवी एवं मन्त्राणी सु० श्री शांति गुप्ता थी।

स्वयं सेवकों की परेड का एक दृश्य

अधिवेशन के कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री शंकरराव देव ने जयपूर में शिक्षण पाने वाले स्वयं सेवक दल का निरीक्षण किया और उन्हें अधिवेशन के समय अपनी जिम्मेदारी को निभाने के आदेश दिए। स्वयं सेवकों के शिक्षण में अ० भा० कांग्रेस सेवा दल के मुख्य शिक्षक श्री एस० वी० इनामदार का भी मुख्य हाथ रहा।

कांग्रेस स्वयं सेवकों तथा छोटी लडकियों की पोशाक सफेद खादी की कमीज, नीले रंग का हाफ पेंट, सफेद टोपी तथा स्वयं सेविकाओं के लिए सफेद खादी की साडी, हरा ब्लाउज, व केशरिया पट्टी निर्धारित की गई। स्वयं सेवकों को स्वागत समिति की ओर से आधी कीमत पर पोशाक देने की व्यवस्था की गई थी।

कांग्रेस स्वागत समिति कार्यकारिणी के निश्चयानुसार गांधीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी विना पुलिस की सहायता के ता० १ दिसम्बर १९४८ से स्वयं सेवक दल पर छोडी गई। प्रांत के सभी भागों के स्वयं सेवकों व स्वयं सेविकाओं की गांधीनगर में पहुंचने की तारीख १० दिसम्बर निश्चित की गई। आम तौर पर स्वयं सेवकों ने मार्ग व्यय स्वयं उठाया।

स्वयं सेवकों व स्वयं सेविकाओं के ठहरने की व्यवस्था अलग २ कैम्पों में की गई थी। गांधीनगर के दूर २ फैले हुए विभिन्न स्थानों तथा अधिवेशन के कार्यक्रम की स्वयं सेवकों को आवश्यक जानकारी प्राप्त कराने के लिए सिर्फ दो तीन दिन का समय मिला। स्वयं सेवकों ने रेल्वे स्टेशनों विभिन्न निवास कैम्पों तथा भोजनालयों में यथा सम्भव सेवा करने के अलावा विषय निर्धारिनी तथा खुले अधिवेशन के पंडालों व यातायात नियंत्रण की व्यवस्था का कार्य भी किया। राष्ट्रपति के जुलूस में भी स्वयं सेवक व स्वयं सेविका दल ने प्रमुख भाग लिया। यदि प्रांत में कांग्रेस सेवा दल की व्यवस्था पहले से होती और कांग्रेस अधिवेशन के सेवा दल को गांधीनगर के विभिन्न स्थानों और अधिवेशन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिलता तो निःसंदेह स्वयं सेवक दल उससे कहीं अधिक अधिवेशन के समय सेवा कर सकता था, जितनी की उक्त मर्यादाओं के भीतर वह कर सका।

प्रवेश नियंत्रण समिति

गांधीनगर के विभिन्न कैम्पों, अधिवेशन पंडाल, विषय निर्वाचिनी पंडाल, प्रदर्शनी आदि में विभिन्न श्रेणी के टिकिटों द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में नियम बनाकर व्यवस्था करने का काम श्री पूर्णचन्द जैन के संयोजकत्व में प्रवेश नियंत्रण समिति द्वारा सम्पन्न किया गया। समिति ने अपनी अनेक बैठकों में विस्तृत चर्चा के बाद प्रवेश सम्बन्धी नियमों की रूपरेखा निर्धारित की। इनके अनुसार मंडलों में प्रवेश आम तौर पर विभिन्न श्रेणी के टिकिटों, बैजों एवं निःशुल्क प्रवेश पत्रों द्वारा व्यवस्था की गई। इनका विवरण नीचे लिखे अनुसार है।

१. प्रतिष्ठित मेहमानों के अलावा, कांग्रेस प्रतिनिधियों, पत्र प्रतिनिधियों फोटोग्राफरों, कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के बैज व प्रवेश पत्र दिए गए। राष्ट्रपति के लिए एक कलापूर्ण एवं सुन्दर बैज बनाया गया जिसके मध्य में राष्ट्रपति शब्द देवनागरी लिपी में अंकित था और जिसके चारों ओर अ० भा० कांग्रेस ५५ वां अधिवेशन, दिसम्बर १९४८, जयपुर लिखा गया था। स्वागत समिति के पदाधिकारियों के लिए भी विशेष प्रकार के बैज बनाये गये थे। उक्त प्रकार के बैजों में सीमित तथा सर्वदेशिय दो प्रकार के प्रवेशाधिकार रखे गये थे।

२. खुले अधिवेशन के पूरे समय के लिए दर्शक टिकिट १० रु०, २५ रु, ५० रु० १०० रु०, २५० रु०, ५०० रु०, और १००० रु० की क़ीमत के रखेगये। विषय निर्वाचिनी के प्रवेश टिकिट की दर रु० २५, ५०, १००और ५०० रखी गई और उसके लिए एक दिन के लिए कम से कम दर का टिकिट १५ रु० का रखा गया। इन टिकिटों पर प्रधान स्वागत मंत्री, कोषाध्यक्ष, तथा संयोजक प्रवेश नियंत्रण समिति के हस्ताक्षरों की मोहरों के अलावा गुप्त चिन्ह विशेष भी लगाया गया था टिकिटों की पृष्ठभूमि पर राजस्थान के दर्शनीय स्थान तथा ग्राम्य जीवन सम्बन्धी रेखा चित्र छापे गये थे।

भोजन के टिकिट छापने का काम भी प्रवेश नियन्त्रण समिति द्वारा ही किया गया था। अ० भा० कांग्रेस के सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के प्रवेश पत्रों का वितरण अ० भा० कांग्रेस के कार्यालय द्वारा तथा दर्शक टिकिट की बिक्री की व्यवस्था अर्थ समिति द्वारा की गई

संयोजक प्रवेश नियन्त्रण समिति

श्री पूर्ण चन्द्र जैन

संयोजक निवास समिति
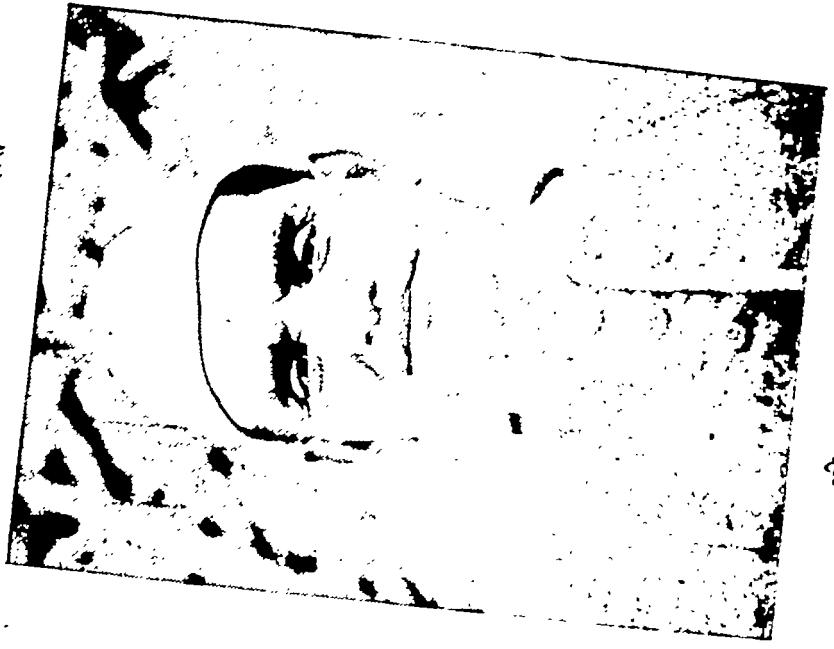
श्री रघुवर दयाल गोयल
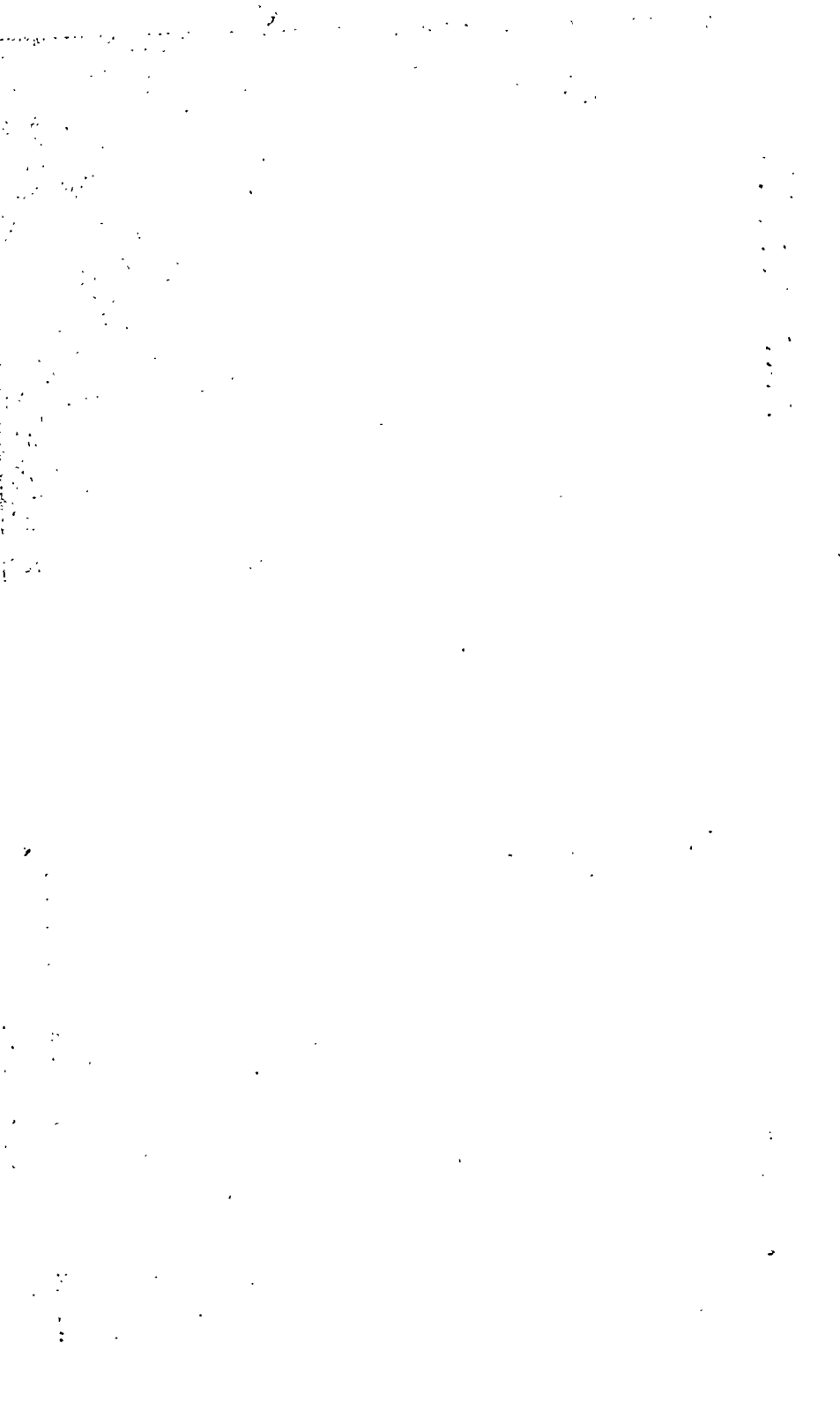
तीन से बारह वर्ष तक के बच्चों के लिए आधे दाम में टिकट देने की व्यवस्था थी। निःशुल्क प्रवेश पत्र पाने वाले कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में कार्यकारिणी के निश्चय के अनुसार स्वागत समिति के १००० कार्यकर्ता राजपूताना के विभिन्न जिलों के १००० तथा सिंध सहित अन्य प्रान्तों के प्रति लाख के पीछे दो व्यक्तियों के आधार पर करीब ६००० कार्यकर्ताओं को मिला कर कुल ८००० कार्यकर्ताओं को निःशुल्क प्रवेश पत्र दिये गये ।

दिल्ली, मध्य भारत तथा गुजरात के पडोसी प्रान्तों को उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार निश्चित संख्या के अतिरिक्त ५०, ५० अधिक कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर निःशुल्क प्रवेश पत्र देने की सुविधा दी गई। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस हालांकि कांग्रेस संगठन का बाकायदा अंग नहीं थी पर उनकी ओर से भी ३०० कार्यकर्ताओं को निःशुल्क प्रवेश पत्र देने का निश्चय किया गया ।

स्वागत समिति के कार्यकर्ताओं के अलावा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने आधे कांग्रेस एवं रचनात्मक काम में लगी हुई राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को तथा आधे में राष्ट्रीय मजदूर, हरिजन, किसान तथा विद्यार्थी-वर्ग के लोगों को स्थान देने का ध्यान रखा गया। कार्यकर्ताओं को राजपूताना में जिला कांग्रेस कमेटियों से तथा अन्य प्रान्त के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश पत्र दिए गए।

स्वागत समिति की विभिन्न समितियों के सदस्यों तथा विभागों के कार्यकर्ताओं को प्रवेश पत्र समितियों के सदस्यों के मार्फत वितरित किये गये। विभिन्न समितियों के अंतर्गत काम करने वाले श्रमजीवी वर्ग को भी काम की सुविधानुसार बारी बारी से अधिवेशन देखने का मौका दिया गया। इसके अलावा पंडाल के बाहर निःशुल्क अधिवेशन की कार्यवाही सुनने के लिए लाउड स्पीकरों आदि की विशेष व्यवस्था की गई थी।

निवास समिति

अधिवेशन के बहुत पहले से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से निवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछ ताछ होने लग गई थी जिनको स्वागत समिति कार्यकारिणी तथा संचालन समिति के निर्णयों के आधार पर सूचित किया जाता

रहा। निवास समिति ने भी नगर निर्माण होने से पहले ही अपना प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया था। स्वागत समिति कार्यकारिणी और संचालन समिति के निर्णय के आधार पर गांधीनगर में विभिन्न श्रेणी के लोगों को ठहराने की नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी :

१. नेता निवास में नीचें लिखे व्यक्ति ठहराये गये :

१. कांग्रेस के अध्यक्ष तथा उनके साथी।

२. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा उनके परिवार।

३. अ. भा. कांग्रेस के सदस्य तथा उनके परिवार

४. विदेशों से आये हुए प्रतिनिधि।

५. प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष तथा उनके परिवार।

६. केन्द्रीय सरकार के मंत्रीगण।

७. प्रांतीय सरकारों, रियासतों एवं रियासती संघों के प्रधानमंत्री व मंत्री गण।

८. अन्य विशिष्ट व्यक्ति।

कांग्रेस अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के अलावा नेता निवास में ठहरने वाले सदस्यों से प्रति व्यक्ति ५ रुपया तथा उनके परिवार वालों से १० रुपया प्रति व्यक्ति निवास शुल्क लिया गया।

२. प्रतिनिधियों को अलग कैम्प में ठहराने की व्यवस्था की गई और उनसे पांच रुपया प्रति व्यक्ति मय चारपाई के खर्च के निवास शुल्क लिया गया।

३. दर्शक निवास में ठहरने वालों से निवास शुल्क बिना चारपाई के पांच रुपया प्रति व्यक्ति लिया गया। दर्शक निवास में स्वागत समिति के सदस्यों के लिए अलग ब्लाक सुरक्षित रखा गया।

४. परिवार कुटीर में २०० रुपये तथा १२५ रुपये की दो श्रेणियां रखी गई।

कांग्रेस– अध्यक्ष महोदय का जलूस जौहरी बाजार (जयपुर) में गुजर रहा है ।
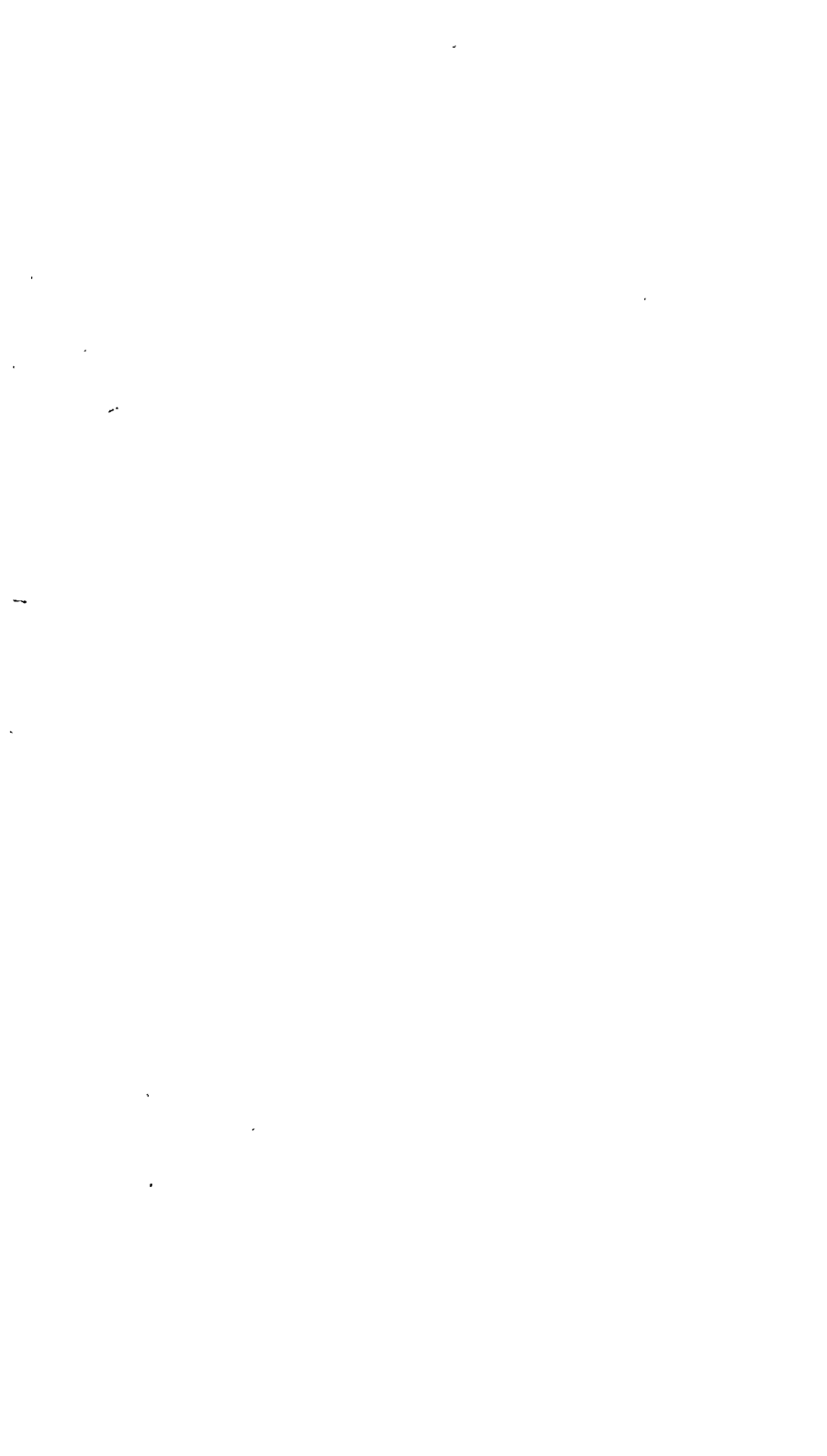
५. आस पास से कुछ समय के लिए आने वाले किसान, श्रमजीवी आदि लोगों के लिए किसान निवास में निःशुल्क सार्वजनिक विश्राम गृह की व्यवस्था की गई।

६. कार्यकर्ताओं के निवास, प्रदर्शनी, निर्माण, भोजन तथा रोगोपचार विभाग के कार्यकर्ताओं के निवास की व्यवस्था अपने अपने कार्य स्थल के नजदीक की गई।

अन्य क्षेत्रों से आये हुए कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता निवास में ठहराया गया।

७. डाक, तार, रेल, आदि विभाग के कार्यकर्ताओं को निश्चित शुल्क लेकर रहने के स्थान देने की व्यवस्था की गई, तथा उनके कर्मचारियों के लिए निशुल्क निवास की व्यवस्था की गई।

८. गांधीनगर के अलावा महाराजा कालेज, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स कालेज, कालेज के होस्टल, मैडिकल कालेज आदि में भी ठहराने की व्यवस्था की गई। निवास समिति के संयोजक श्री रघुवीर दयाल गोयल थे। उन्होंने तथा उनके सहयोगियों ने कई हफ्तों तक लगातार मेहनत से काम किया।

जलूस समिति

कांग्रेस अध्यक्ष के जलूस की परम्परा के अनुसार शानदार बनाने की दृष्टि से जलूस समिति ने अपनी योजना बनाकर तैयारी शुरू की। जलूस में शामिल होने वाले लोगों व उनकी तरतीब के बारे में निश्चय किया गया तथा जयपुर शहर को झंडों, फरियों आदि से सजाने और यातायात को नियंत्रित करने की भी व्यवस्था की गई। काफी चर्चा के बाद राष्ट्रपति की बैलों के रथों पर सवारी निकालने का निश्चय किया गया। रथ में राष्ट्रपति के साथ स्वागता-ध्यक्ष, स्वागत समिति के प्रधान मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा स्वागत समिति के उपाध्यक्ष श्री माणिक्यलाल वर्मा थे। जलूस में स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं की बहुत लम्बी कतार थी। जलूस को देखने के लिए शहर के मुख्य बाजारों में दोनों ओर लाखों व्यक्तियों की अपार भीड़ उपस्थित थी। जूलूस स्टेशन रोड से शुरू होकर राम निवास बाग में म्युजियम के पास समाप्त हुआ जहां राष्ट्रपति को जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल द्वारा मान पत्र भेंट किया गया। इस समिति के संयोजक श्री रूपचन्द सोगानी थे।

सामान समेट समिति

अधिवेशन के तुरंत बाद ही गांधीनगर में बिखरे हुए सामान को एकत्रित करने के लिए निर्मित की गई सामान समेट समिति ने विभिन्न समितियों के सामान को विषय निर्वाचिनी पंडाल तथा अन्य स्थानों पर एकत्रित किया। छोटा सामान शुरू में ही बिक्री समिति को सम्भला दिया गया। सामान समेट समिति का सम्पूर्ण कार्य सरदार हरलालसिंह के सँयोजकत्व में हुआ।

ब. प्रधान कार्यालय

अधिवेशन का निमन्त्रण स्वीकार होने के साथ ही कांग्रेस स्वागत समिति का कार्य एक प्रकार से शुरु होगया था। स्वागत समिति के प्रारंभिक संगठन तथा स्वागत सदस्यों की भर्ती आदि कार्य की शुरुआत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा करदी गई थी। १ अगस्त १९४८ की प्रातःकाल सूर्योदय के समय हिन्द होटल त्रिपोलिया में कांग्रेस स्वागत समिति के कार्यालय का तत्कालीन जयपुर राज्य के मुख्य सचिव और स्वा० स० के प्रधान मन्त्री श्री हीरालालजी शास्त्री द्वारा उद्घाटन हुआ।

जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है, अधिवेशन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई उपसमितियों का निर्माण किया गया था पर ये सभी समितियां एक साथ न बनकर समयान्तर से बनी थीं। कई समितियों के निर्माण से पहले और समाप्त होने के बाद उनका काम निपटाने के लिए जिम्मेदारी स्वभावतया प्रधान कार्यालय पर आई। समितियों के होते हुए भी एक ओर इन समितियों और कार्यकारिणी व संचालन समिति के बीच तथा दूसरी ओर आपस में इन समितियों के बीच परस्पर संपर्क रखने की जिम्मेदारी प्रधान कार्यालय पर ही थी। प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के अलावा इन विभिन्न समितियों में से अधिकांश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ स्टेशनरी, फरनीचर, टाइपराइटर आदि आवश्यक सामान को जुटाने तथा उनके आपस के सम्पर्क का काम भी कार्यालय को करना पड़ा।

हिसाब

कार्यालय के हिसाब विभाग के संगठन की शुरुआत स्वागत समिति के मुख्य खजांची की नियुक्ति के साथ हुई। श्री मोहनलाल चोकडायत ने यह

काम अन्त तक काफी मेहनत से निभाया । थोड़े समय बाद ही इस विभाग में एक अकाउण्टेंट, दो तीन रोकड़िया तथा ५,६ कार्यकर्ता रख लिये गये। इस विभाग को स्वतन्त्र रूप में संचालन करने के लिए जिस प्रकार के अनुभवी हिसाबनवीस की आवश्यकता मालूम हो रही थी।

बहुत कोशीश करने पर भी वैसे व्यक्ति की सेवायें प्राप्त नहीं हो सकी। बावजूद इस कमी के हिसाब विभाग के समय समय पर लाखों रुपयों के लेन देन का काम बिना किसी उल्लेखनीय गडबड या हानि के निभा लिया। यह सब हिसाब विभाग के कार्यकर्ता के परिश्रम और सच्चाई का द्योतक है। हिसाब विभाग को अपने काम में समिति के हिसाब परीक्षक श्री गुटगुटिया कम्पनी के श्री मदनलाल शर्मा व आन्तरिक हिसाब परीक्षक श्री महावीर प्रसाद भगेरिया तथा श्री भगवानदासजी भार्गव से भी काफी सहायता मिली। काम की सुविधा की दृष्टि से थोड़े बहुत समय के लिए निवास, निर्माण, भोजन, सामग्री संग्रह स्वयं सेवक, प्रदर्शिनी बाजार विज्ञापन आदि समितियों द्वारा भी अपने २ स्वतन्त्र हिसाब रखे गए, जो बाद में ज्यों २ काम समाप्त होता गया प्रधान कार्यालय के हिसाब के साथ सम्मिलत कर लिए गये ।

हिसाब के अलावा प्रधान कार्यालय में पत्र व्यवहार, सामान स्टोर खरीद तथा विवरण, कार्यालय तथा डाक, तार, सवारी आदि अन्य सामान्य व्यवस्था तथा पछताछ विभाग भी थे। अन्त में स्वागत समिति द्वारा खरीदे हुए सामान की बिक्री के लिए बिक्री विभाग भी प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत ही काम करता रहा।

प्रधान कार्यालय के पत्र व्यवहार विभाग का काम करीब चार महीनें १२ घंटे से १५ घंटे रोज चलता रहा। जिसमें बारी २ से अनेक कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ टाइप, डिस्पेच, फाइलिंग आदि का काम किया। स्वागत समिति को शुरु में टाइपराइटर तथा पर्याप्त संख्या में हिन्दी व अंग्रेजी के शीघ्र लिपि लेखकों की काफी कमी महसूस हुई। पर आखिर में अधिकतर कालेज के विद्यार्थियों द्वारा उनके बचत के समय में बारी २ से इस काम में मदद मिली। प्रधान कार्यालय के काम में शुरु से ही श्री छीतरमल गोयल की अत्यन्त उपयोगी सेवाएं स्वागत समिति को मिली। उन्होंने बड़ी लगन, निष्ठा और सच्चाई से सारे काम को संभाला।

पूछताछ

स्वागत समिति के कार्यालय में अधिवेशन सम्बन्धी सब प्रकार की जानकारी के अलावा अनेक प्रकार के व्यापारियों, ठेकेदारों, कार्यकर्ताओं आदि विभिन्न श्रेणी के लोगों का आकर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछना स्वाभाविक था। उन सबको आवश्यक जानकारी देने और उनमें से स्वागत समिति के कार्य के लिए सेवायें ग्रहण करने वालों की दृष्टि से स्वागत समिति के दफ्तर में एक पूछताछ विभाग संगठित किया गया, जहां लोग विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपने सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी, अपना नाम, पता आदि भी नोट करा दिया करते थे जिससे ज्यों २ काम बढता गया त्यों २ कार्यकर्ता जुटाने में काफी मदद मिली।

स्वागत समिति का कार्यालय १५ नवम्बर को गांधीनगर चला गया। गांधीनगर में जानें के साथ ही अधिवेशन के समय के लिए पूछताछ, रोशनी डाक, तार, टेलीफोन, की वयवस्था गांधीनगर के साइन बोर्ड तैयार कराने और लगाने की कार्यवाही प्रधान कार्यालय द्वारा की गई। गांधी नगर के द्वार पर जयपुर और गांधीनगर के स्टेशनों आदि सबको मिलाकर पूछ तांछ विभाग के ९ शाखा कार्यालय खोले गये।

अधिवेशन के लिए आने जाने वाले लोगों की सूचना के संवन्ध में आवश्यक जानकारी प्रसारित करने विभिन्न समितियों के सदस्यों, प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत काम करने माले कार्यकर्ताओं का प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों से आयें हुऐ कार्यकर्ताओं की सूची वनवा कर उनके भोजन, निवास तथा प्रवेश पत्र आदि की व्यवस्था करने का प्रवन्ध प्रधान कार्यालय द्वारा किया गया। अ० भ० कांग्रेस कमेटी कार्यालय के आवश्यक सामान को जुटाने की व उसके कार्यकर्ताओं के निवास आदि की व्यवस्था भी प्रधान कार्यालय द्वारा की गई।

विविध

स्वागत समिति कार्यकारिणी के निश्चयानुसार प्रान्त के रियासती सँघों व रियासतों के राजा महाराजाओं, न्यायधीश, तथा अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शेख अब्दुल्ला को अधिवेशन के लिए स्वागत समिति की ओर से निमँत्रण भेजे गये।

अधिवेशन के समय होने वाले अन्य कार्यक्रमों में स्वागत समिति की कार्यकारिणी की आज्ञा से कुदरती जीवन सम्मेलन, जी० ओ० सी० कांफ्रेंस, किसान सम्मेलन आदि के लिए गांधीनगर में पंडाल आदि का उपयोग करने की इजाजत दी गई। किसी अन्य राजनैतिक दल के या सर्वोदय की दृष्टि से सैद्धांतिक तौर पर विरुद्ध पड़ने वाले किसी भी कार्य के लिए कांग्रेस नगर का कोई भाग उपयोग में नहीं लिया गया।

पिछले कांग्रेस अधिवेशन के स्थान मेरठ से जयपुर तक पैदल यात्रा द्वारा 'ज्योति' लाने के काम में रास्ते में पड़ने वाली सभी कांग्रेस कमेटियों ने सहायता और सहयोग दिया जिसके लिये स्वागत समिति उनकी आभारी है। ता० १४-१२-४८ को यह 'ज्योति' जयपुर में पहुंची और जनता द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया।

गांधी नगर में आग बुझाने आदि की व्यवस्था का प्रबन्ध जयपुर म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने अपने जिम्मे लिया।

अधिवेशन के बाद तुरंत ही अधिकांश समितियों ने अपना काम समाप्त कर दिया और उनके कार्यों में मुख्यतः लेने देने आदि के प्रश्नों को प्रधान कार्यालय द्वारा निपटाना पड़ा। इस कार्य में कार्यालय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

बिक्री

स्वागत समिति ने कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो करीब ३७॥ लाख रुपयों का माल खरीदा था उसमें से बचे हुए विविध प्रकार के सामान को बेचने का काम कठिनाई से भरा हुआ था। यह काम, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कार्यकारिणी के निश्चयानुसार प्रधान कार्यालय के एक नये बिक्री विभाग के जिम्मे आया। कंट्रोल भावों से खरीदे हुए सामान को कंट्रोल भावों से ही बेचना था, 'सरकार से वापस लौटाने की शर्त पर खरीदे हुए सामान सरकार को या जिन्हें सरकार दिलाना चाहती थी उसे लौटाना था। टेंट, बल्ली आदि सामान को लागत कीमत पर पहले शरणार्थी विभाग को देना था और बाकी बचे हुए सामान को नीलाम, टेंडर या प्राइवेट बिक्री द्वारा इस प्रकार बेचना था कि स्वागत समिति का माल अनुचित प्रकार से कम दामों में न बिक जाय।

इस काम के लिए कार्यकारिणी द्वारा किये गये निर्णयों के अनुसार सामान की सूची तैयार कराके कार्यकारिणी के सदस्यों को भेजी गई और उनसे विक्री के सम्बन्ध में सुझाव भी मांगे गये। लोहे का सामान, टैंट, गेहूं, कई मोटरें, पत्थर आदि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ने खरीदे। बाकी सामान संस्थाओं नागरिकों एवं व्यापारियों को बेचा गया। माल की बिक्री में यथा साध्य संस्थाओं को प्राथमिकता देने का ध्यान रखा गया। बिक्री सम्बन्धी इन कठिनाइयों से भरे हुए काम को भीलवाडा के सेवा भावी कार्यकर्ता श्री भंवरलाल भदादा ने में अपने अनुभव और परिश्रम से यथा योग्य सहयोगी जुटाकर सराहनीय रूप से पूरा किया और सामान की बिक्री से जितनी रकम वापिस आने की आशा थी उससे काफी ज्यादा रकम बिक्री से मिली।

डाक तार

गांधीनगर में डाक तार की व्यवस्था सराहनीय रही। भारतीय डाक विभाग तथा तत्कालीन जयपुर सरकार के डाक व टेलीफोन विभाग का इस कार्य में पूरा सहयोग रहा। ता० २५ अक्टुबर १९४८ से एक अस्थायी डिलिवरी डाक तार घर तथा ता० ३१ अक्टूबर से टेलीफोन गांधीनगर में चालू किया गया। ता० १३ दिसम्बर से २१ दिसम्बर १९४८ तक यू० पी० आई० तथा ए. पी. आई. के प्रेस तारों के अलावा कुल ३४०७११ शब्दों के प्रेस तथा प्राइवेट तार भेजे गए। भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शिनी भी काफी सफल रही। डाक तार टेलीफोन की व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों से सम्पर्क रखने का काम श्री कोमलचन्द पाटणी को सोंपा गया जो उन्होंने योग्यता पूर्वक किया।

सामान बेचने के बाद भी उसकी कीमत वसूल करने, खरीदे हुए या किराये पर लाये हुये विभिन्न सरकारों की मारफत मंगाये गये सामान सम्बन्धी बिलों का हिसाब निपटाने में अनिवार्य तौर पर साल भर से अधिक लग गया जब कि शुरु में यह काम चन्द महीनों का समझा जाता था। भारत सरकार रेल्वे तथा राजस्थान सरकार के कई हिसाबों को निपटाने में असाधारण विलम्ब हुआ।

हिसाब की जांच का कार्य स्वागत समिति के आडिटरों श्री के० एन० गुटगुटिया एन्ड कम्पनी के श्री मदनलाल शर्मा तथा उनके सहयोगियों ने

बड़े परिश्रम से और निशुल्क सम्पन्न किया जिसके लिए स्वागत समिति उनकी बड़ी कृतज्ञ है।

अधिवेशन सम्बन्धी सब खरीद फरोक्त और लेन देन के बाद आय व्यय का जो कुछ नतीजा रहा वह इस रिपोर्ट में प्रकाशित तलपट से स्पष्ट होगा।

इस तलपट के अनुसार कुल ३७४९३७५ रु० २ आ० का माल खरीदा गया, जिसमें से ३३४५४३५ रु० ५ आ० का सामान वापिस बिका। इसके अलावा २०४९६८४ रु० २ आ० ९ पा० व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न मदों में खर्च हुये। इस प्रकार अधिवेशन में हुए कुल २४४९६२४ रु० १५ आ० ९ पा० व्यय हुए

प्रवेश टिकिट निवास शुल्क सवारी, बाजार विज्ञापन, तथा सर्वोदय प्रदर्शिनी के टिकट आदि से ९७३५८९ रू० ५ आ० ९ पा० रुपये की आमद हुई। शेष जो कमी रही वह विशेश सहायता से पूरी की गई जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। (हिसाब-परीक्षकों की रिपोर्ट, उसके संबध में संयुक्त मन्त्री जी का निवेदन तथा कार्यकारिणी और स्वागत समिति द्वारा रिपोर्ट पर स्वीकृति-प्रस्ताव परिशिष्ट सं० ६ के १-२-३ में दिये गये हैं।)

२०. उपसंहार

राजस्थान में ही नहीं भारत के रियासती हिस्से में कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। जयपुर का अधिवेशन स्वतन्त्र भारत के लिए भी पहिला ही अधिवेशन था। इसी वर्ष महात्मा गांधी का भी, जिनके मार्ग दर्शन में पिछले लगभग ३० वर्ष तक कांग्रेस की समस्त गतिविधि का संचालन होता रहा, आसाधारण परिस्थितियों में निधन होचुका था। इन सब कारणों से यह कल्पना तो थी कि जयपुर कांग्रेस अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण और अपने ढंग की होगी। पर उसके काम का विस्तार वास्तव में अन्दाज से बड़ा साबित हुआ। इस अधिवेशन की परिस्थितियां पहिले के अधिवेशनों से भिन्न होने के कारण उस समय के आंकड़ों तथा योजनाओं से भी विशेष मदद नहीं ली जा सकी। परिणाम स्वरूप जयपुर कांग्रेस की अधिकांश तैयारी हमें अपनी ही सूझ-बूझ और विचार विमर्श के आधार पर करनी पड़ी। जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है इस तैयारी के लिए समय भी बहुत कम मिला था। एक ओर जहां हमारे सामने यह सब कठिनाइयां थीं वहां दूसरी ओर परिवर्तित परिस्थितियों के कारण हमें केन्द्रीय सरकार

के विभिन्न महकमों के अलावा राजस्थान की रियासतों से भी पूरी मदद मिली जिससे हमारी कठिनाइयां कुछ अंशों में कम जरूर होगई। भारत सरकार के रेलवे, डाक, तार, टेलीफोन विभाग के अलावा उद्योग, रक्षा और खाद्यविभाग तथा यू० पी और सी० पी० सरकारों के जंगलात और सप्लाई विभाग से अधिवेशन सम्बन्धी सामग्री को देश के विभिन्न क्षेत्रों से खरीदने और गांधीनगर तक पहुंचाने आदि के कार्यों में हमें काफी सहायता मिली। इसके लिए स्वागतसमिति भारतसरकार, अन्य प्रान्तीय तथा सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ है।

इस कार्य में राजस्थान के कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति कार्यकर्ता, विद्यार्थी, मजदूर हरिजन, किसान महिलायें तथा राजागण, व्यापारी आदि सभी वर्गों के लोगों ने तथा राजस्थान एवं भारत के पत्रकारों ने कांग्रेस को सफल बनाने के लिए अपना २ सहयोग दिया। कांग्रेस अधिवेशन के लिए स्वागत समिति में हजारों स्वागत समिति के सदस्य, स्वयंसेवक और स्वयं सेविकायें, अवैतनिक कार्यकर्ता, एवं श्रमजीवियों ने अधिवेशन सम्बन्धी कार्यों में अपना हाथ बंटाया।

राजस्थान से बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों ने भी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अपना हिस्सा अदा किया। कलकत्ता तथा बम्बई में स्थानीय समितियों का निर्माण हुआ जिनसे अधिवेशन के काम में मदद मिली। व्यक्तिगतरूप से कई कार्यकर्ताओं के अलावा कलकत्ते की मारवाडी रिलीफ् सोसायटी ने भी हमारे काम में उल्लेखनीय मदद पहुंचाई। अधिवेशन की तैयारी सम्बन्धी कामों के लिए लाखों रुपए की व्यवस्था आवश्यक थी जो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान, मत्स्य और सिरोही की तत्कालीन सरकारों की विशेष सहायता के अलावा समय २ पर जयपुर राज्य बैंक आफ जयपुर, युनाइटेड कार्मशियल बैंक, बैंक आफ बीकानेर, तथा बच्छराज एण्ड कंपनी व पुरोहित स्वरूपनारायण आदि द्वारा दी गई उधार रकम की सुविधाओं के कारण सम्भव होसकी। सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में स्वागत-समिति को तत्कालीन जयपुर राज्य के दीवान श्री वी० टी० कृष्णामाचारी तथा विभिन्न रियासतों के मन्त्रीगण से उल्लेखनीय सहयोग मिला। स्वागत समिति उन सब की कृतज्ञ है। तत्कालीन जयपुर सरकार की ओर से स्वागत समिति को आर्थिक सहायता के अलावा नगर निर्माण, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था में भी बडी सामयिक और उल्लेखनीय सहायता मिली। स्वागत समिति उन सबके लिए हृदय से आभारी है।

अधिवेशन सम्बन्धी तैयारी में समय समय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय की ओर से भी हमें मार्ग दर्शन और मदद मिलती रही जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

कांग्रेस अधिवेशन के बारे में स्वागत समिति के लिए अपनी ओर से कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। इस बारे में अधिवेशन के समय में ही हुए भाषणों से कांग्रेस के नेताओं तथा समाचार पत्रों द्वारा राय जाहिर की जा चुकी है। कांग्रेस स्वागत समिति के लिए तो अधिवेशन की तैयारी और व्यवस्था में रही हुई कमियों और अनुभव की कमी के कारण हुई भूलों को महसूस करना ही अधिक स्वाभाविक है। कांग्रेस स्वागत समिति को यह स्वीकार कर लेने में कोई संकोच नहीं है कि निस्सन्देह जयपुर कांग्रेस की व्यवस्था में कई कमियों और कठिनाइयों को शायद कम किया जासकता था पर हम इतना ही कह कर संतोष मानते हैं कि हमने अधिवेशन को सफल बनाने में अपने प्रयत्नों में कमी नहीं रखी।

कांग्रेस के पिछले अधिवेशनों के समय देश परतन्त्र था और कांग्रेस देश की आजादी की लडाई में अग्रणी थी इस लिए उसके अधिवेशनों को जनता एक यात्रा के रूप में मान कर सभी कठिनाइयों और व्यवस्था सम्बन्धी कमियों को दरगुजर भी कर लेती थी। इस बार केन्द्रीय सरकार और राजस्थान की राजनैतिक सत्ता कांग्रेस के हाथमें होने के कारण स्वभाविक तौर पर जनता को अधिक सुविधाओं की अपेक्षा थी। इस आशा को जितने अंश तक पूरा करने में हम असफल रहे उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है।

कांग्रेस की कार्यवाही के अन्त में आदरणीय पण्डित जवाहरलाल नेहरु ने इस प्रकार बडे पैमाने पर लाखों रुपये के खर्च से शान शौकत के साथ किए जाने वाले अधिवेशनों को देश की नई परिस्थिति में अनावश्यक बतलाते हुए आगामी अधिवेशन मर्यादित रूप में करने की सलाह दी थी। सम्भवतः अब कांग्रेस के इतिहास में इतने बडे पैमाने पर अधिवेशन होने का मौका नहीं आ पायगा। हर सूरत में कांग्रेस के इतिहास में जयपुर के इस अधिवेशन का अपना विशेष स्थान रहेगा।

गोकुल भाई भट्ट
अध्यक्ष।

हीरालाल शास्त्री
प्रधान मंत्री।
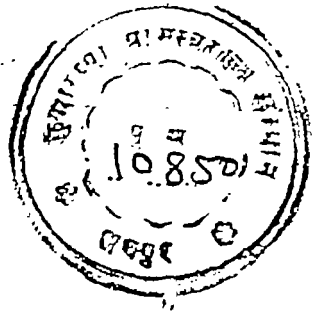
गांधीनगर के प्रवेशद्वार
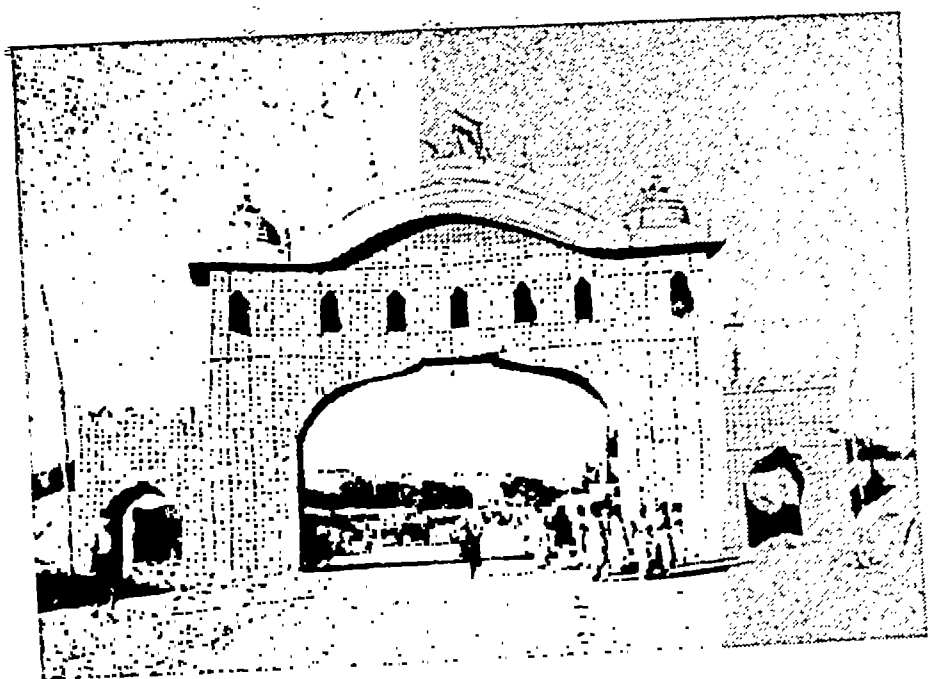
गांधीनगर के जो राज-स्थान की निर्माण कथा के प्रतीक थे और जिनमें घास 'घडे'
चांक फूस आदि ग्राम्य वस्तुओ का उपयोग किया गया था इनके नाम
राजस्थान के शहीदों के प छे रक्खे गये थे ।

दूसरा भाग

स्वागताध्यक्ष

श्री गोकुल भाई भट्ट

का
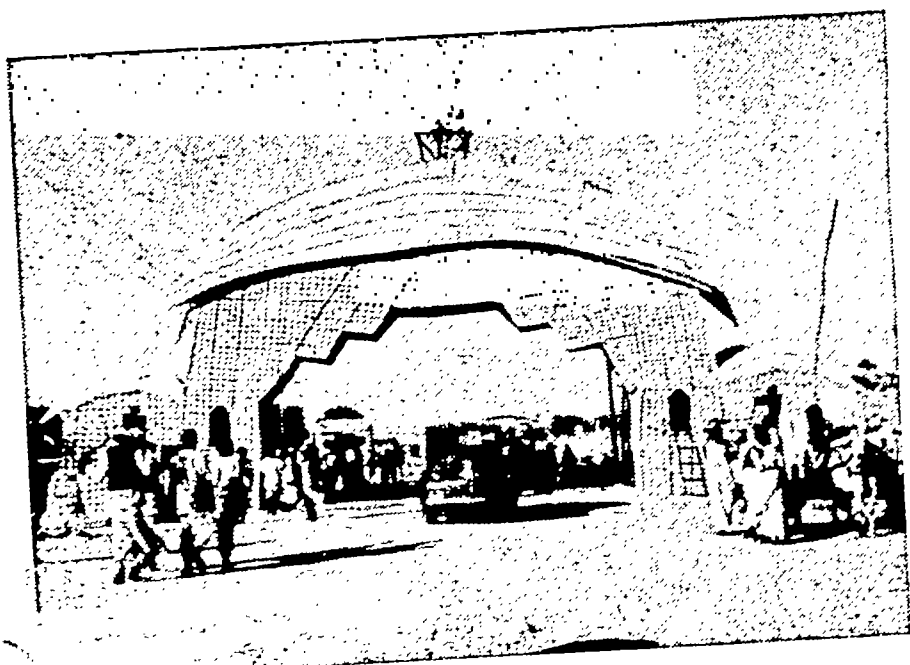
अभि—भाषण

१९४८

पूज्य नेतागण, प्रतिनिधि भाई बहनों तथा अतिथियों,

आज का यह शुभवसर राजपूताना प्रान्त का धन्य दिन है। आपके दर्शनों से हम पावन हुए हैं। हमारी राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस ने भरतपुर की अपनी जून मास की बैठक में आपको न्योता देन का प्रस्ताव किया, तब हमें पूरा विश्वास नहीं था कि राजपूताना का निमन्त्रण मान लिया जायगा। जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने हमें जुलाई मास में इजाजत दी। तब से हम आनन्द के साथ बढ़ी हुई जिम्मेवरी का अनुभव करते रहे हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह पहला अधिवेशन कांग्रेस रियासती प्रान्त में हो रहा है यह रियासती जनता का सौभाग्य है। देशी राज्यों में रहने वाले भारतवासियों का एक निराला समाज है, उसके सामने रोज बरोज अनेक उलझनें आती रहती है, उसका जीवन विपदाओं से घिरा हुआ था। वह कई तरह की गुलामियों से दवा हुआ था। इस समाज ने क्या २ कष्ट भोगा है और कहीं कहीं अभी भी भोग रहा है इसका बयान करना नहीं चाहता। राजा महाराजाओं ने अपने ऊपर का दबाव दूर होते ही समय को पहचानना शुरू किया और वे इस पुण्य भारत भूमि के केन्द्रीय प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने का अपना धर्म समझने लगे। यह हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है लेकिन अभी भी हमारे कई जागीरदार साहिबान व उनके कर्मचारीगण अपनी मन मानियां चला रहे हैं और वे पुराने रवैये को नहीं बदल रहे हैं, यह खेद का विषय है। उम्मीद है कि वे नये जमाने के अनुसार जनहितकारी श्रेयस्कर मार्ग ग्रहण करेंगे।

हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के विषय में जो ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर हुआ था उसका मर्म जितना आज प्रतीत होता है उतना उस समय हमारे कई मित्रों के खयाल में नहीं आया। लेकिन रियासती प्रजा को उठाने में अगर किसी ने ज्यादा मदद पहुँचाई तो वह हरिपुरा प्रस्ताव ने उसने हमें प्रेरणा दी, हमारी सुस्ती हटाई, हमारी कार्यक्षमता बढ़ाई और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दी। हम स्वावलम्बी बने। राष्ट्रपिता महात्मा जी के आशीर्वाद से हमारी प्रगति बढ़ने लगी। और मुझे यह कहते अत्यन्त हर्ष होता है कि न सिर्फ हम हमारी लड़ाई लड़ते रहे लेकिन भारतवर्ष के आखरी मुक्ति संग्राम में भी हम कन्धे से कन्धा मिलाकर चले हैं। त्याग, तपश्चर्या और कुरबानी में रियासती प्रजा भारतीय प्रान्तों से

पीछे नहीं रही है। पिछडी हुई प्रजा को और आगे लाने के लिये ही यह अधिवेशन करने का पहला मौका रियासती प्रान्त को मिला मालूम होता है। रियासती प्रान्त दूसरों के स्तर पर जल्दी से पहुँच जायेंगे इसमें किसी को सन्देह नहीं रखना चाहिए।

जिस प्रान्त में आपका आगमन हुआ है वह राजपूताना के नाम से प्रसिद्ध है। इसका इतिहास चित्र विचित्र रहा है। प्रान्त के कई प्रदेश पुराणप्रसिद्ध भी हैं। प्रान्त इसकी आधुनिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। ब्रह्मतेज, क्षात्र तेज, या सेवातेज देशकाल के बन्धनों से परे हैं। राजपूताने ने इसी न्याय से निम्न दोहे को चरितार्थ किया है:—

पाछा फिर मत झांकज्यो, पग मत दीज्यो टार।
कट भळ जाज्यों खेत में, पर मत आज्यो हार॥

समरांगण के लिए विदा होने वाले अपने भरतार को ऐसा ओजस्वी सन्देश देने वाली वीरांगनाओं की इस वीरभूमि में कई घटनायें घटी हैं। किन किन का उल्लेख करूँ और किन किन को टाल दूँ। महाराणा प्रताप का पुण्य स्मरण किसको नहीं होता होगा। उनके भील साथी और देश के लिए सम्पत्ति समर्पण करने वाले भामाशाह को भी कौन भूल सकता है। वीरता के चेतक और संचारक कवि, गायक, देवी-भक्त चारणों का स्मरण भी करना चाहिए। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को संधिपत्र भेजा था तब कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को जिस वाणी में स्वधर्म सिखलाया था उसका थोडा सा आस्वादन कीजिए।

घर वांकी दिन पाधरा मरद न मुकै माण।
घणा नरिन्दा घेरियो, रहे गिरदां राण॥
माई एहदा पूत जण, जेहडा राणा प्रताप।
अकबर सूतो ओ झकै, जाण सिराणै सांप॥
अकबर एकण वार दागल की सारी दुनी।
अण दागल असवार, रहियो राण प्रतापसी॥
पातळ जो पतशाह, बोले मुख हूँता वयण।
सिहर पछमदिश मांह, उगै का सपराव सुत॥

पटकूं मच्छां पाण कै पटकूं निज तन करां।
दीजै लिख दीवाण, इण दो महली वात इक ॥

इस चेतावनी का प्रभाव अनुपम पडा। महाराणा ने भी पत्र देखते ही अपनी भूल सुधारी और उत्तर भेजा :—

तुरक कहासी मुख पतो, इण तनसूं इकलिंग।
ऊगै जांहीं ऊगसी प्राची बीच पतंग ॥
खुशी हूंत पीथल कमध, पटको मूंछां पाण।
पछटण है जैसे पतो, कमला सिर के वाण ॥

इसी महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा फतेहसिंहजी जब दिल्ली दरवार में कुल की परम्परा को छोडकर जाने लगे तव वारहट केशरीसिंह ने जो पत्र लिखा वह भी एक ऐतिहासिक घटना है। वारहट्टजी की चुंगटी असरकारक रही, महाराणा फतेहसिंहजी दिल्ली स्टेशन से ही वापिस दरवार में न जाते उदयपुर लौट गए।

सकल चढावे शीश दान धरम जिणरो दियो।
सो खिताव वखशीश, लेवण किम ललचावसो ॥
देखे लो हिन्दवाण, निज सूरज दिस नेहसूं।
पण तारा परमाण, निरख निशाशा नाखसी ॥
मान मोद शीशोद, राजनीति वल राखणो।
गवरमिन्ट की गोद, फल मीठा दीठा फता ?

इस भूमि में सिर्फ वीरता ही नहीं दिखाई देती है, लेकिन कविता और ललित कलाओं का भी विकास यहां हुआ है। चित्र, स्थापत्य, और नृत्य में राजपूताना की विशेपता रही है। साहित्य को यहां प्रोत्साहन मिला। इतना ही नहीं परन्तु अपूर्व साहित्य का निर्माण हुआ है। नैसर्गिक ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक और आर्थिक प्रसंग और प्रश्नों की छानवीन यहां हुई है। भक्ति और भावुकता में यह किसी से पीछे नहीं रहा है। लक्ष्मी, सरस्वती और भवानी तीनों का यह संगम स्थान है।

"गढ तो चित्तौडगढ और सब गढैया" जैसे गढ यहां है, रमणीय झील है, कोट किलों का शुमार नहीं है। पहाडियों की गोद में, चोटी पे या हृदय पर स्थित राजमहलों की ललित रचनायें भी देखने में आती हैं। अर्बुदगिरि और उस पर बने हुए देलवाडा के जैन मन्दिर की तुलना किससे करें ? वनौषधियों से हरेभरे आबु पहाड से अरवली की पर्वत श्रेणी शुरू होती है, वैराठ और मत्स्य प्रदेश आज के अलवर तक अरवली के दर्शन होते हैं। मारवाडियों का यह प्रान्त कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ के हृदय से लगा हुआ था, यहां की मीराबाई ने जिसकी प्रतिष्ठा बढाई ऐसे इस हमारे प्रान्त के एक सुन्दरतम नगर जयपुर में आपका स्वागत करते हुए हमें अत्यन्त आनन्द होता है। लेकिन

किस विध करूँ सम्मान तिहारो ?
अधुरो मधुरो स्वागत म्हारो
दया प्रेम से आप स्वीकारो। किस०।

जहां आप विराजे हैं, उसका नाम रक्खा है गांधीनगर। यह तो एक अस्थायी आबादी है इसको नगर कहने के बजाय गांधीग्राम कह सकते हैं। ऐसे खूबसूरत जयपुर के समीप अपना गांधीनगर बना है। यह जंगल था, उबड-खाबड जमीन थी यन्त्रबल से और पुरुषार्थी मजदूरों के हाथों से इसका निर्माण हुआ है। स्थान का निर्णय करने में दो दृष्टि रक्खी थी। सम्पत्ति का व्यय हो वह अविकसित को विकसित करने में हो, और पुरुषार्थियों के निवासों के नजदीक अधिवेशन हो ताकि उन्हें काम मिले और जो साधन सामग्री यहां लगे वह उनके काम में आ सके। ता० २ अक्टूबर को पूज्य महात्माजी की जन्मतिथि के दिन पूज्य विनोबाजी के वरद हस्तों से नगर स्वर्ण निर्माण की नींव डाली गई थी। यह रचना आप जो देख रहे हो वह चन्द दिनों में खडी की गई है। इसका निर्माण कार्य मुश्किल रहा है परन्तु अनेकों ने सहयोग दिया। जयपुर राज्य की मदद विशेष उल्लेखनीय है। सिर्फ जयपुर सरकार ने ही नहीं परन्तु जयपुर महाराज साहेब ने भी इस काम में खुद दिलचस्पी ली और मदद की। राजपूताने के जोधपुर, राजस्थान, मत्स्य, बीकानेर, सिरोही इन सब रियासती व रियासती संघों ने अलग अलग प्रकार से गांधीनगर के निर्माण कार्य में शुश्रुषा कार्य में, प्रदर्शनी में, स्वागत कार्य में, मदद पहुँचाई है। हमारी केन्द्रीय सबसरकार के

महकमों न बन सके है पूरी सहायता दी है। स्थायी और प्रवासी राजपूताना वासी भी इस काम में जुट गए हैं, वरना जो कुछ पूर्ण अपूर्ण काम २, २॥ मास में हुआ है वह नहीं होता।

इस अधिवेशन की जिम्मेवरी उठाने वाले राजपूताना के सब कार्य-कर्ताओं को रचनात्मक तथा राजनैतिक कार्यक्रम द्वारा प्रेरणा व प्रोत्साहन देने वाले सरलमना सेवक प्रेमी जमनालालजी बजाज हमारे बीच में नहीं है इसका हमें बड़ा अफसोस है। राजपूताना की आज की जागृति को लाने वाले कई एक शहीदों की, साथियों की याद आती है, उनके त्याग तपश्चर्या बलिदान से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मनोकामना को पूरा करने जा रहे हैं। राजपूताना की एक प्रान्त की कल्पना और भावना १९२२ के बीजोलिया सत्याग्रह के काल में जन्मी, राजस्थान सेवा संघ, अजमेर मेरवाड़ा राजपूताना मध्यभारत कांग्रेस संघठन से कुछ अंश में उसको पोषण मिला, परन्तु राजपूताना कार्यकर्ता संघ द्वारा ही सन् १९४१ से प्रान्त के सब कार्यकर्ता विशेष रूप से एकसूत्रित हुए। अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद का विधान उदयपुर अधिवेशन से मुकम्मिल बनने लगा और हमारे वहां का कार्यकर्ता संघ परिषद की प्रादेसिक सभा में परिणित हुआ तब से राजपूताना प्रान्त निर्माण का विचार गति पकड़ता गया और आज वह संकल्प सा बन गया है। मुझे आशा है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के महाराजाओं के साथ जो विचारविनिमय हो रहा है वह सफल होगा और उसकी प्राथमिक विचारणा मन्त्रणा हमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार का एक प्रान्त का रूप धारण करेगी। इस ओर ऐसे कार्य में भारत सरकार के रियासती विभाग के अधिष्ठाता ने जो अद्भुत काम किया है उनकी भूरि २ प्रशंसा करने में हम असमर्थ हैं। मैं हमारे पूज्य नेता सरदार वल्लभ भाई की क्या तारीफ करूँ? वे हमारे दक्ष और निपुण सरदार हैं। कृतनिश्चयी वीर हैं। उनके शिस्तपूर्ण कड़े प्रेममय निमन्त्रण में रह कर ही हम हमारे रियासती संघों का तन्त्र सन्चालन करते रहेंगे तभी हम भारतीय प्रान्तों की बराबरी कर सकेंगे। इस हमारे नेता ने करीबन ६०० रियासतों की काया बदल दी है, उनकी राजाओं ने, नवाबो ने महाराजाओं ने पूरी मदद की है इन राजा महाराजाओं का भी हम तहेदिल से कदर करते हैं।

जो-लोग आज तक प्रजाशक्ति को ठुकराते थे वे प्रजा के हाथों में राज्यों की वागडोर क्यों सोंप देते हैं ? यह एक जासुदू सा मालूम होता है, लेकिन हमें अब याद आता है कि महात्मा गांधीजी ने हमें क्या कहा था और उनकी भविष्यवाणी क्या थी। ऐसे दीर्घ दृष्टि वाले हमारे भाग्य विधाता राष्ट्रपिता का शरीर दर्शन हमें आज नहीं हो रहा है, हमारे दुर्भाग्य हैं कि वे आज मौजूद नहीं हैं। सत्ता प्राप्ति के बाद देश पर अनेक सकट आये। यादवस्थली जैसे दृश्य नजर आये, भाई भाई के खून का प्यासा बन गया, इन्सानियत भारत में से लुप्त हो गई हो ऐसा लगने लगा, अन्धकार छा गया था, अरण्यों में भूले भटके हम तितर वितर होने लगे थे, हमारे में से कई घरों से विछुडे हुए दुःखगर्ता में पड़े थे। लोगों को लगा कि यह भूकम्प सा क्या आया ? क्या प्रलय होने वाला है ? अंग्रेज गये लेकिन कैसा जाल विछा गये ? ऐसे जटिल कलेशमय भयावह वातावरण को साफ करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे पूज्य नेता पण्डित जवाहरलालजी और उनके साथियों पर थी, वे हिम्मत से काम करने लगे,-पूज्य वापू के मार्गदर्शन में उन्होंने बडी भारी आपत्तियों का सामना सफलतापूर्वक किया। दुनियां की तवारीख में कामयावी की ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेताओं से तालीम पा रहे हैं कि जिनका जीवन सेवा और तपोमय है, जिनका ध्येय विश्वकल्याण है और जिनका तरीका सच्चाई और प्रेम का है। पूज्य वापूजी ने ऐसी अपनी कर्णधार मध्यस्थ सरकार पर भरोसा रखने को वार वार कहा है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि पं० जवाहरलालजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथी असूलों के पक्के हैं और वे जनता की सुख शान्ति को सुरक्षित रखने वाले हैं। दिल्ली के प्रार्थना प्रवचनों में पूज्य वापूजी ने कई मरतवा नीचे के उद्‌गारों को दोहराये हैं।

"आप अपनी सरकार पर यह भरोसा रखिये कि वह अन्याय करने वालों से हर शहरी की रक्षा करेगी फिर उनके पास कितने ही ज्यादा और अच्छे हथियार क्यों न हो। आप अपनी सरकार पर यह भी भरोसा रखिए कि यह अन्याय से वेदखल किये गये अल्पमत के हर मेम्वर के लिए हरजाना मांगेगी और वसूल करेगी।"

अनाशक्ति योग के उपासक शक्ति संचारक वापू की हत्या यह विकृत मानस का द्योतक है। हत्या ने वापू को उच्चता की चोटी पर पहुँचा दिया,

हमारी आंखे खोली, और सुने हुए सीखे हुए सबक याद करने का, तथा उसे अमल में लाने का अमूल्य अवसर दिया। जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण का आयोजन करने जा रहे हैं, जबकि हम हमारी अनेक न्यूनतायें दूर करने की सोच रहे हैं तब बापू ने जो मार्ग हमें बतलाया है उसी पर ही चलना चाहिए। हमारी नैतिकता शून्यवत हो गई है ऐसे समय सन्मार्ग गामी बापू का अनुसरण ही हमें बचा सकता है। बापू ने हमारी सभ्यता का हमें दर्शन कराया, सच्चा अर्थशास्त्र हमें समझाया और सत्य अहिंसा जैसा जनकल्याण का अमोघ साधन सुझाया, मोह कर्दम के बाहर निकालने की जिसने चेष्टा की, शहरों की तडक भडक और कृत्रिम जीवन व्यवहार की निरुपयोगिता जिसने सिद्ध कर बताई, भारतदर्शन और देशोदय गांवों को सुधारने, सम्हालने और स्वावलम्बी बनाने से ही हो सकता है यह जिसने कोटिवार हमें कहा, शिक्षा का असली स्वरूप, धर्म की सच्ची ज्योति जिसने दिखलाई थी वे ही हमें प्रकाश की ओर ले जायेंगे, वे ही हमें रामराज्य का सुभग दर्शन करा सकेंगे। उन्हें हम याद करते रहेंगे लेकिन कोरी याद से क्या होगा ? अगर हम उनके बताये मार्ग पर न चलें तो मैं कहूँगा कि "कोडी को तो खूब सम्हाला लाल रतन को छोड दिया" उन्होंने अपनी हिन्द "स्वराज" किताब में जो लिखा है वह पुरानी विचार धारा है ऐसा कोई न समझे। प्रायः सब प्रश्नों की छानबीन उस किताब में है और वह हमारी सूत्रिका (Mannual) बन सकती है। नये सर्वोदय समाज की आधारशिला यही हो सकती है।

आज हमारे कई साथियों को सत्ता के आसन सम्हालने पडते हैं, वे जिस पद पर बैठे हैं, वह मायावी हैं और डर है कि हम पदलालसा की भूलभूलैया में फंस न जांय। सत्ता के स्थान ग्रहण करने से अगर हम जनहित नहीं कर सकते हैं, हम हमारा असली मार्ग छोड देते हैं या परवश पंगु बन जाते हैं तो हमें उन स्थानों को छोडने होंगे यही हमारी इस कांग्रेस संस्था का रवैया रहा है और रहेगा। इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता है। परन्तु हमारे में से कई एक साथियों का खयाल ऐसा बनता जाता है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद अब कोई काम बाकी नहीं रहा। जीतना था वह जीत लिया जीवन कृतार्थ हो गया। यह विचार एक गलत है। समय आ गया है कि हमें अब ज्यादा काम करने लग जाना चाहिए। हमारे में से जो सत्ता स्थानों पर है वे और दूसरे सबको मिलकर रचनात्मक कार्य

विशेष रूप से करना होगा । रचनात्मक कार्य यही हमारी पक्की नींव है जिसके सिवा हमारी स्वराज इमारत वन नहीं सकती । हमारे रचनात्मक कार्य का मध्य विन्दु है गांव और गांव की खुशहाली की चावी है चरखा जो सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाश और प्रसन्नता फैला सकता है । इस चरखे को अपनाने से ही रामराज्य की स्थापना हो सकेगी वरना कागजी घोडे हम भले दौडाते रहें । हमारी दृष्टि गांव की तरफ ही दौडनी चाहिए, हमारे हरेक कार्य से गांव समृद्ध, सुखी और संस्कारी वन जाना चाहिए । हमारे उत्थान का यही मापदण्ड होना चाहिए । गांव अपनी पंचायतों द्वारा सच्चे स्वराज की ओर हमें ले जा सकता है । वैसे तो हमने कई सुन्दर कार्यक्रम और योजनायें वनाई हैं और इस अधिवेशन में वनेंगी, लेकिन मुझे जो वात खटकती है, जिस बुराई का अन्देशा है वह है आलस्य, अतिविश्वास, सत्तामद और सत्ता लालसा । जनसम्पर्क हमारा कम होता जा रहा है, हमारी प्रवृत्तियों में दिखावा ज्यादा आता जाता है, गहराई लुप्त होती जाती है और कहीं कहीं आडम्वर आने लगा है । मुक्ति संग्राम लडे गये थे सुख और शान्ति के लिए । अगर आज हमारे दिल में उत्साह, प्रसन्नता विश्वास, चेतना और भ्रातृभाव न आने लगे तो आई हुई आजादी किस काम की ? हमारा असली काम है सेवा का । सेवा का आधार है प्रेम, और प्रेम प्रवाह का उद्‌गम होता है सत्यगिरि से, सत्य से सँलग्न है शिवम् सुन्दरम् ।

भारतव्यापी हमारी कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई अहिंसात्मक असहयोग शस्त्र से। उसने पशु वल का मुकावला किया और विजय प्राप्त किया। हम अव युद्ध पिपासु राजनीतिज्ञों को वतादें कि भारत में क्या विशेषता थी और है । कांग्रेस की अखण्ड ज्योति सवका पथप्रदर्शन कर सकती है । दुःखियों को सहारा, पीडितों को सांत्वना और दलितों को आराम दे सकती है। आज हम कंगाल से हैं, हमारे सुखी घर नष्ट प्राय हो गये हैं तो भी हम हमारापन नहीं छोडेंगे । सिंह भूखा हो तव भी घास कभी नहीं खायगा। हम हमारे स्वस्ति वचनों में तीन वार शान्ति मन्त्र का उच्चारण करते हैं इसका लक्षणार्थ यह है कि शान्ति मुझे, देश को और दुनियां को मिले। हम स्वार्थपरायण ही नहीं रह सकते । हमारे कार्य से एकमात्र हमें ही लाभ हो ऐसा नहीं हो सकता । अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना हममें कहां तक आने पाती थी उसका ज्वलन्त उदाहरण है हमारा शान्ति पाठ । कूपमण्डूक हम

नहीं रह सकते । हमारी दृष्टि सर्वत्र दौड़ेगी, जहां जहां अच्छापन होगा उस मधु का हम संचय करेंगे लेकिन कौनसी चीज इष्ट और अनिष्ट है उसका विवेक करना होगा । वाह्य आडम्बर में जकड़ने वाली, अन्तर का ह्रास करने वाली सत्य से विमुख करने वाली वेली भारत वृक्ष पर नहीं चढ़ने देंगे । हमारे जीवन में सादगी उच्चता और निर्मलता आवे ऐसा ही हमारा कार्यक्रम हो सकता है । समाज को ज्ञानवान, शक्तिवान और समृद्ध वना सके ऐसा क्रियाशील कार्यक्रम देश के सामने रखने और हमारी इस संस्था को विशेष कर्तव्यपरायण वनाने के लिए आप पधारे हैं । आपका यहां का चन्द दिनों का निवास सुविधा जनक हो यही हमारा-स्वागत समिति का कर्तव्य है ।

मेरा आज का कार्य राजनैतिक प्रश्नों की चर्चा करने का नहीं है मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि असुविधाओं से भरे पड़े रेतीले परन्तु प्रेमल इस गांधीनगर में बैठ कर जो भोजन व खाद्य पदार्थ मिलें उन्हें पाकर, हमारी त्रुटियों के लिए हमें क्षमा कर दें, निश्चित होकर जयपुर अधिवेशन को विशिष्ठ प्रकार से परिणामदायी वनाइये ।

माननीय अध्यक्षजी ! आपके हाथों में कांग्रेस की नाव आज से आ रही है, आप जैसे अनुभवी खेवट हमारी नाव को पार लगा दो यही आपसे प्रार्थना है । कांग्रेस का उज्ज्वल इतिहास विशेष ज्वलंत वने यही हम सब की अभिलाषा है, प्रभु इसे पूर्ण करें ।

जयहिन्द
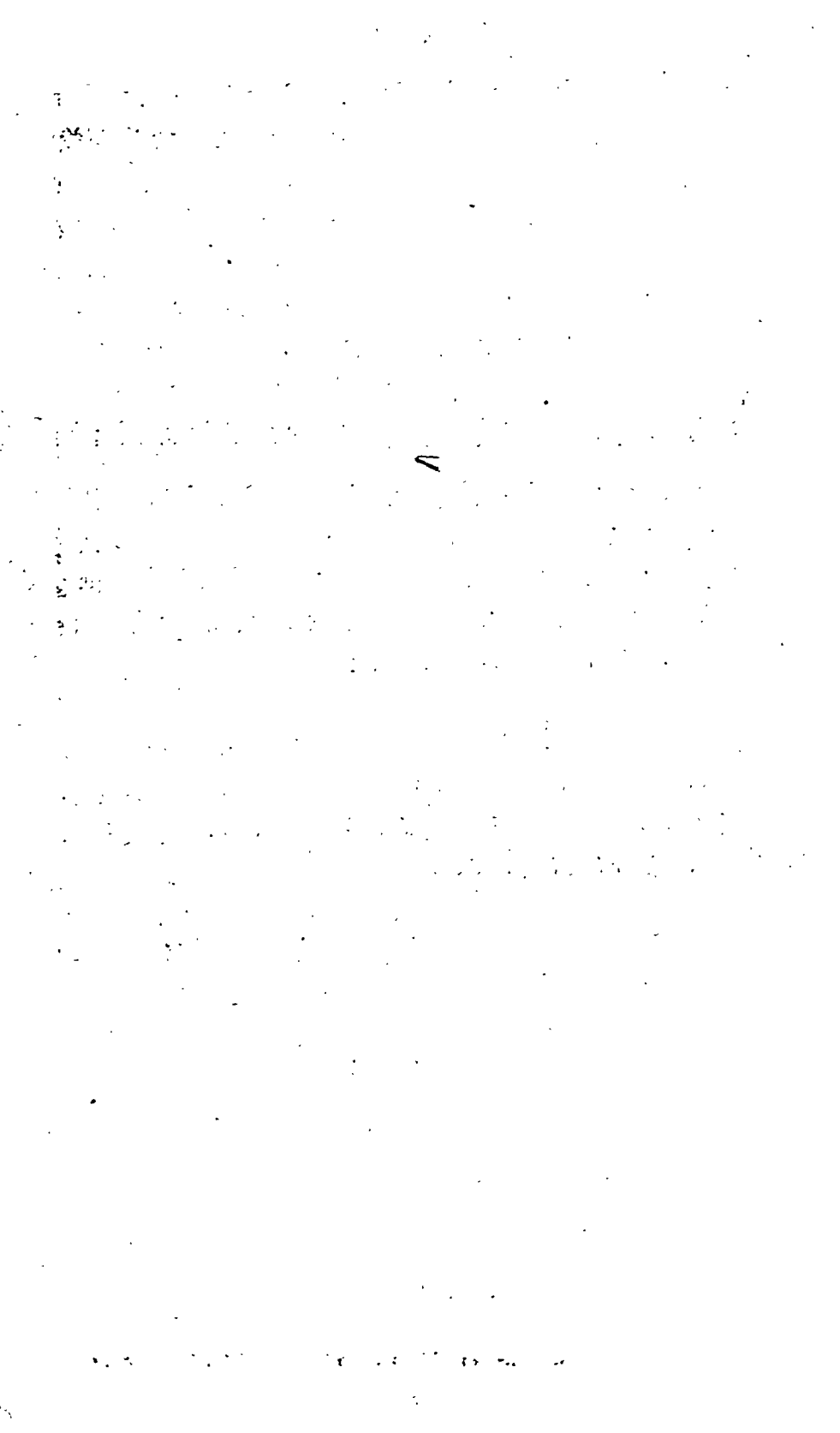
शहीद द्वार
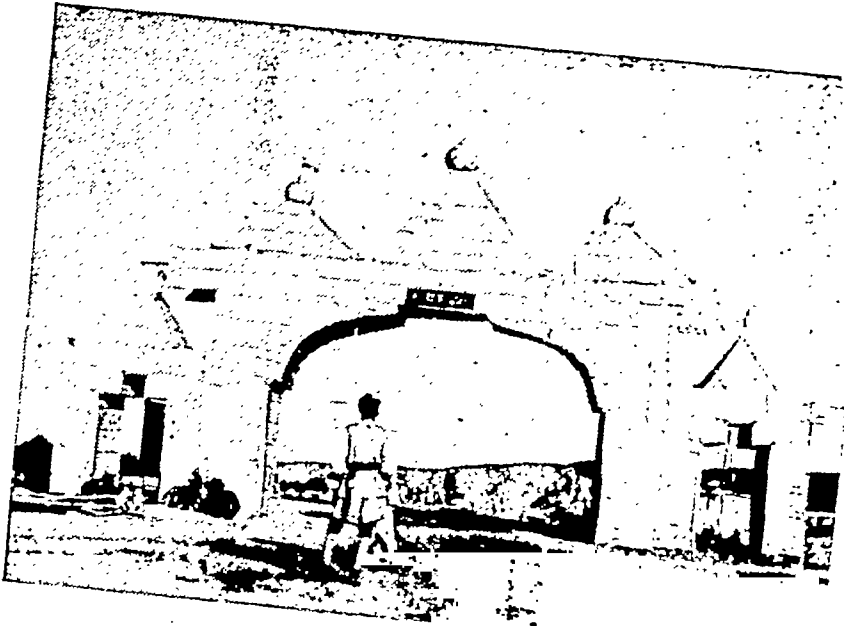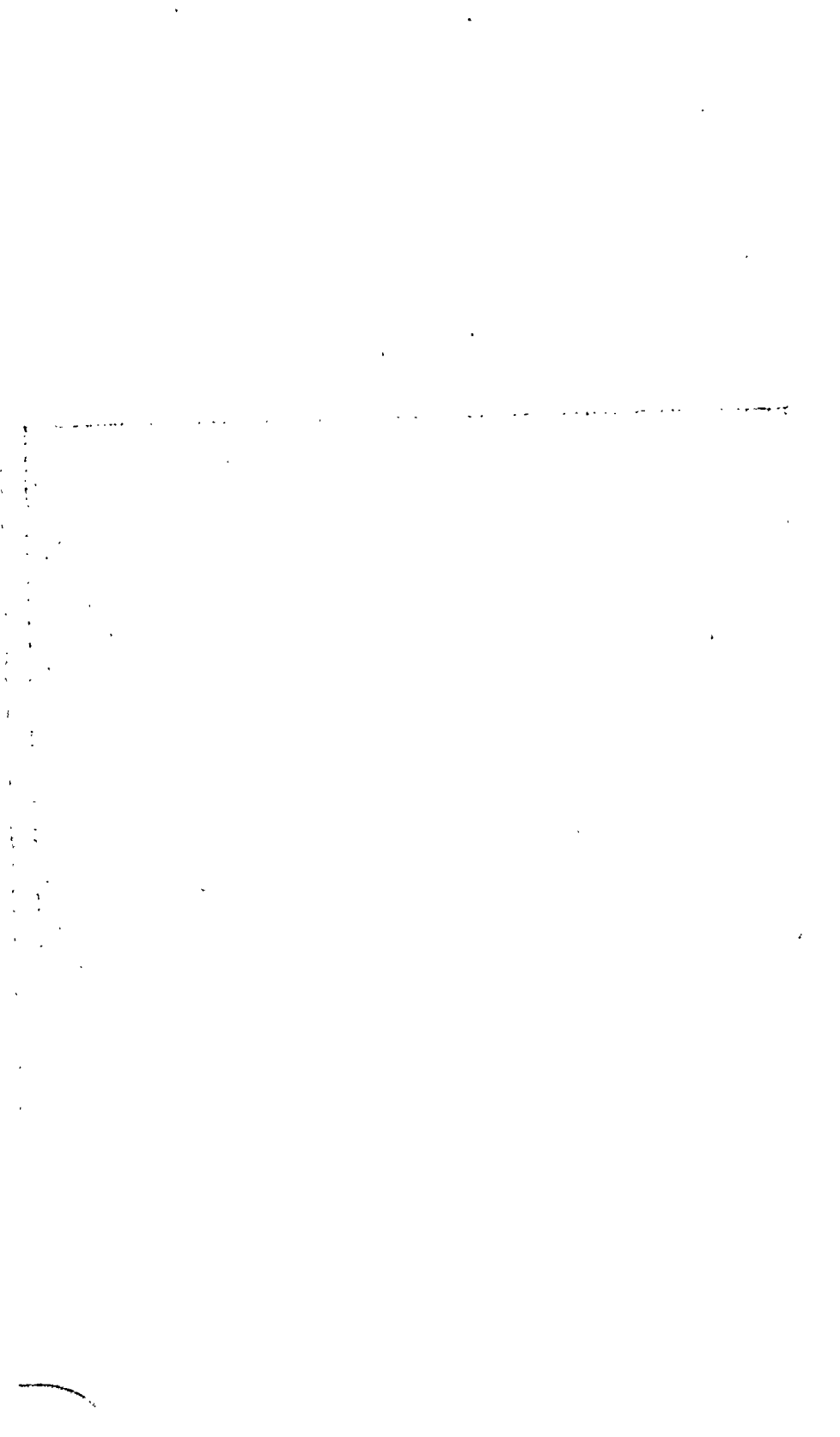
राष्ट्रपति का अभिभाषण

(५५ वां कांग्रेस अधिवेशन)

डा० पट्टाभि सीता रमय्या

जयपुर

१८ दिसम्बर १९४८

दोस्तो !

दो साल से ऊपर हुए जब हम सब, देश के दूर-दूर के हिस्सों से आ-आकर, मेरठ में जमा हुए थे। आज हम इस तारीखी नगर जयपुर में फिर से जमा हो रहे हैं। इन दोनों बार के जमाव में बहुत बड़ा फरक है। मेरठ में हम उस विदेशी ताकत को ललकारने के लिए जमा हुए थे जो उस समय हम पर राज करती थी। आज हम जमा हुए हैं अपनी आजादी का संगठन करने को। यह आज़ादी हमने उन साधनों से पाई है जिनका इससे पहले कोई नाम भी नहीं जानता था। अगर जानते थे तो शायद पुराने जमाने के कुछ महात्मा या ऋषि-मुनि। इसी तरह के एक महात्मा ने जो शायद इस युग का आखरी और सबसे बडा महात्मा था, हमें इस विजय तक पहुँचाया है। यह विजय हमारी और हमारे पूरे राष्ट्र की है। इतिहास में यह अपने ढंग की एक अनोखी विजय है। इससे राज्य काज के मैदान में भी हमारी जीत हुई है और सदाचार या धर्म के मैदान में भी। दुर्भाग्य से उस महात्मा का शरीर अब हमारे बीच में नहीं है, उसकी आत्मा हमारे इस इतने बड़े जमाव के चारों तरफ मण्डला रही है। वह महान् आत्मा आज भी हमारे सारे देश के ऊपर निगाह रख रही है। [हमें अपने समाज और देश की नए सिरे से रचना करने के लिए हिम्मत और बढावा दे रही है, और गिरते-पडते हम सबको धीरे-धीरे सत्य और अहिंसा के असली रास्ते की तरफ ले जा रही है।

इस थोडे समय के अन्दर हम अपने बहुत से देशभक्तों और देश सेवकों को खो चुके हैं। उनमें से बहुतों ने देश आजाद कराने के लिए बडी बडी कठनाइयां झेली थीं और अपनी जिन्दगियां दे रखी थीं। उन सब की याद में अपनी श्रद्धांजलि चढाना इस समय हमारा सबसे पहला फर्ज है। इनमें बहुतों के नाम भी हमें मालूम नहीं, जिनके याद हैं उनमें सबसे पहला नाम देश के सबसे बडे अगुआ राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का है। इसके साथ ही हमारा कर्तव्य उस महान् व्यक्ति की पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धांजली भेंट करने का है कि जिसने अपने सारे जीवन को स्वराज्य महायुद्ध के अर्पण किया है। हमारे प्यारे भाई बाबू सुभाषचन्द्र बोस, जिन्हें लोग प्यार के साथ उनके सार्थक नाम "नेताजी" से याद करते हैं, एक कर्मठ सेनानी और सच्चे बलिदानी थे। वह एक अलौकिक पथ के पथिक और मार्गदर्शी थे, क्योंकि
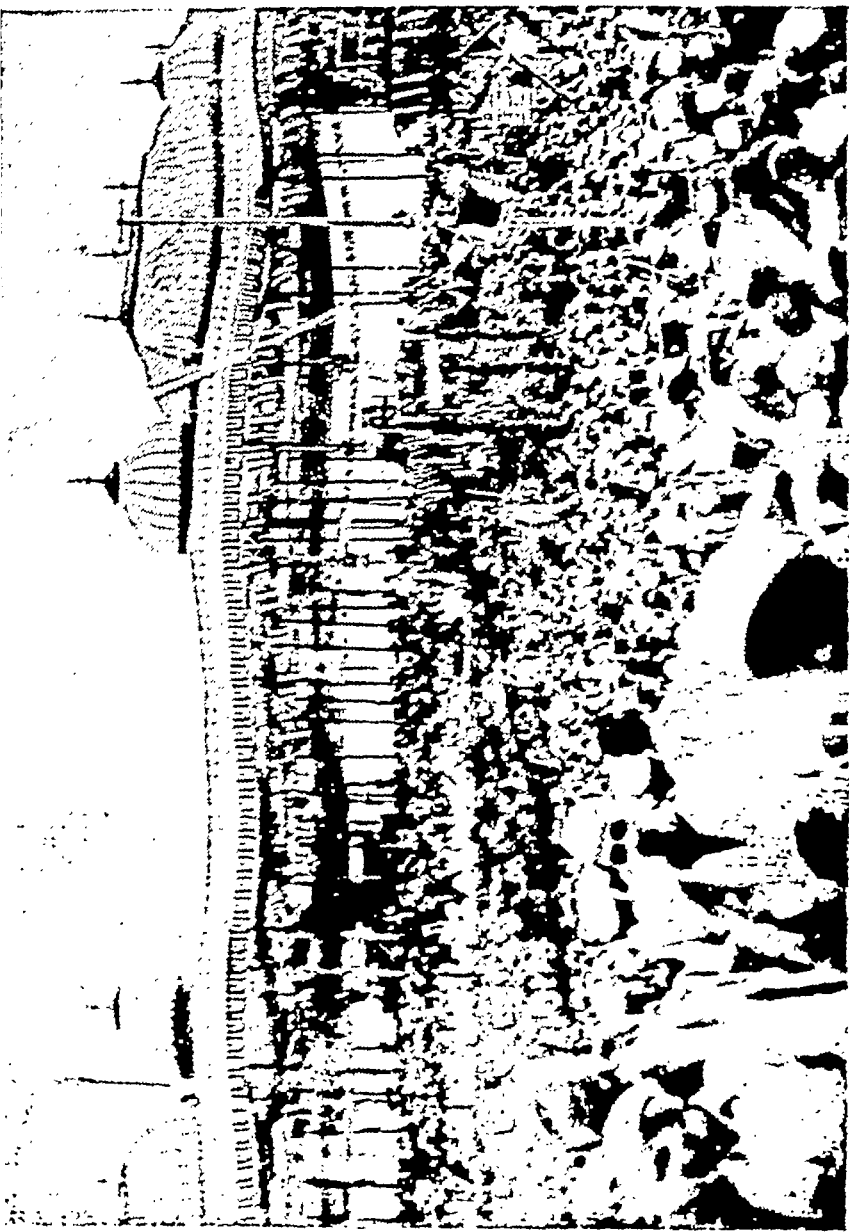
मंच— खुला अधिवेशन Dais—open Session

वह देशभक्ति के नशे और स्वतन्त्रता की अटूट श्रद्धा में बेचैन थे। और सफलता की उस सीमा तक पहुँच चुके थे कि जो केवल उन्ही को प्राप्त प्राप्त होती है जिनमें साहस और कार्यक्षमता की पराकाष्ठा हो। उनके असीम त्याग और तपस्या का फल हम सब भोग रहे हैं। महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय ने सन् १९०९ में लाहौर की कांग्रेस में और सन् १९१८ में दिल्ली की कांग्रेस में सभापति का आसन लिया था, श्री विजय राघवाचार सन् १९२० की नागपुर कांग्रेस के सदर थे। दोनों राष्ट्र के बहुत बडे नेता थे। दोनों ने हमारी इसकौमी इमारत को खडा करने में उस समय से काम करना शुरू किया था जब कि अभी इस इमारत की बुनियादें भी नहीं पडी थीं। उनके और उस समय के साथियों के अनगिनत कारनामे इस इमारत की बुनियादों में कंकडों की तरह दबे पडे हैं। पर उन कंकडों के बिना इस इमारत का खडा हो सकना नामुमकिन था। महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग और काशी जैसे पवित्र स्थानों में रहना पसन्द किया और बनारस में अपनी अमिट यादगार छोडी। ऊँचे चरित्र, पाक जिन्दगी, संस्कृत साहित्य से प्रेम और सनातन धर्म को फिर से चमकाने की कोशिशों से मालवीय जी ने पुरानी हिन्दू संस्कृति को बहुत कुछ उजागर किया। हिन्दू धर्म और हिन्दू दर्शन शास्त्र के वह बहुत बडे पण्डित थे। उन्ही पुरानी बुनियादों पर उन्होंने नए देश की रचना करनी चाही। श्री विजय राघवाचार दक्खिन के रहने वाले थे। वह 'विद्यासागर' कहलाते थे और सचमुच विद्या के सागर थे, कानून के वह बहुत बडे जानकार थे। दुनियां-भर के विधानों, कानूनों, नजीरों और देश-भर के रीति-रिवाजो की उन्हें इतनी बडी जानकारी थी कि आज अगर वह होते तो अपने विधान की रचना जैसे कामों में हमें उनसे बडी मदद मिलती। उनमें त्याग, बहादुरी और साहस भी हद दरजे के थे। कांग्रेस के बिलकुल शुरू के दिनों में देश की आजादी के लिए जेल जाने का रास्ता उन्होंने ही हमें दिखाया।

इन दो गुरुजनों के अलावा और जो देशभक्त हाल में हमसे बिछुडे हैं उनमें दो नाम सबसे आगे आते हैं। एक श्री० के० एफ० नरीमान और दूसरे श्री बी० जी० हौरनीमैन। एक पारसी और दूसरा अंगरेज, पर दोनों के दिल और दिमाग पक्के हिन्दुस्तानी। श्री नरीमान के पुरखे एक हजार बरस पहले इस देश में आकर बसे थे। श्री० नरीमान ने इस देश के लिए बडे-बडे कष्ट झेले और उसकी सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया।

सन् २५ और सन् २६ में वम्बई के वैकवे के मामले में जो धान्धली हुई थी उसे उन्होंने मुल्क के सामने लाकर हमारे इतिहास का एक खासा अध्याय लिख डाला । हमारी सन् ३० की लडाई में उन्होंने वम्बई के मोर्चे को वडी सुन्दरता से सम्हाला । अव समय आया था कि देश तरह-तरह से उनके साथ अपने प्रेम और मान का सवूत देता । पर वह चल वसे । श्री हारनीमैन ने अंगरेज होते हुए भी हिन्दुस्तान को अपना घर वना लिया था। जिस देश को उनके अपने देशवासियों ने गुलाम वना रखा था उसे अंग्रेजों ही के पंजों से आजाद कराने के लिए श्री हारनीमैन ने पूरे पचास वरस तक लगातार और अथक कोशिश की। इस अन्याय के खिलाफ वह वरावर अपने देशवासी अंगरेजों के शरमाते रहे । किसी देश के रहने वालों के लिए जो उसी देश में पैदा हुए हों अपनी मातृभूमि को आजाद करने में जिन्दगी खर्च कर देना आसान और कुदरती वात है, पर जव किसी दूसरे देश में पैदा हुआ आदमी किसी देश की भलाई, आजादी और वढौती के लिए अपना जीवन अर्पण करता है तो हमारे दिलों में यह विश्वास पक्का होने लगता है कि एक-न-एक दिन सारा मानव समाज अपनी एकता को अनुभव करेगा, आदमी के अन्दर की नेकी चमकेगी, गैरियत के परदे टूटेंगे, मेरी कौम और तेरी कौम के भ्रम जाल कटेंगे, सव इनसानों को सवकी भलाई में अपनी भलाई दिखाई देगी, सवके अन्दर के भगवान जागेंगे, वेइन्साफी और जुल्म का अन्त होगा, और सारी दुनियां के लोग एक कुनवे की तरह प्यार और मुहव्वत के साथ रहना-सहना शुरू करेंगे। यही वह मंजिल है जिसकी तरफ हमारी दुनियां इस समय धीरे-धीरे वढ रही है।

इसी अरसे में हमने देश के और भी वहुत-से नौनिहालों और सच्चे सेवकों को खोया । इस तरह के लोगों की मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना उनके नेक कामों और उनके असर को नहीं मिटा सकता । उनकी मिसाल ही के सहारे दुनियां आगे वढती और तरक्की करती रहती है । इन्हीं ईंटों पर यह आलीशान इमारत धीरे-धीरे ऊपर को उठती रहती है ।

इस मौके पर हमारा फर्ज है कि हम अपने प्रसिद्ध देशवासी कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना की याद में भी अपने प्रेम और श्रद्धा के फल चढाएँ । सन् १९१८ तक जिन्ना साहव का इस इन्डियन नेशनल कांग्रेस के साथ वहुत गहरा नाता रहा । कांग्रेस की वुनियादों को मजवूत करने में

उन्होंने बहुत बडा हिस्सा लिया । बाद में अगर वह कांग्रेस से अलग हो गए तो इससे उनके इस महान काम और उनकी उन सेवाओं की कदर कम नहीं हो जाती जो कांग्रेस के शुरू के दिनों में वह पूरे जोश, हिम्मत और लगन के साथ करते रहे । हुकूमतें बदल जाने या अलग-अलग राज कायम हो जाने से खून नहीं बदल जाता । हमारी निगाहों में जिन्ना साहब हमारी ही तरह हिन्दुस्तानी थे, हमारे देश के चमकते हुए सितारों में से थे और इस रिश्ते से देश हमेशा मुहब्बत और इज्जत के साथ उनकी याद को कायम रखेगा ।

महात्मा गांधी

अब मैं फिर उस सबसे बडी मुसीबत की तरफ आता हूँ जो हाल में हम पर टूटी है ।

महात्मा गांधी का उठ जाना हमारा इस समय का सबसे बडा नुकसान था और है । यों तो महात्मा गांधी के चले जाने से सारी दुनियां को एक बहुत बडा धक्का पहुंचा है । दुनियां के इतिहास में आज तक किसी भी आदमी के उठ जाने पर दुनियां-भर में इतना शोक और मातम नहीं मनाया गया जितना महात्मा गांधी के उठ जाने पर । पर अभी तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं। देश के उस सबसे बडे और सबसे प्यारे, सबसे ऊँचे और सबसे नेक नेता के उठ जाने से हमारा देश सच्चे अर्थों में अनाथ हो गया । और बातों को अभी जाने दीजिए, सबको मिलाकर ले चलने और दूर तक देख सकने की उनमें जो शक्ति थी वह और किसी में नहीं है। वह हमारे लिए प्रेम की गँगा थे । उनकी आंखें हमारे रास्ते की मशालें थीं। कोई दूसरा आदमी उनकी जगह नहीं भर सकता । प्रेम और अहिंसा की वह मूर्ति थे । वह नूर-ही-नूर थे । अपने प्रेम की जोत से उन्होंने हम सब के अन्दर आजादी की जोत जगाई । उन्होंने एक जगह कहा है—"प्रेम दूसरों को जलाने की जगह खुद अपने को जला डालना पसन्द करता है।" इसी उसूल पर उन्होंने पहले अपने अन्दर के छै बडे दुश्मनों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, मत्सर पर विजय पाई, और फिर बाहर के पशुबल का अपने आत्मबल से सामना करके बाहर के सबसे बडे शत्रु को जीता। उन्होंने झूठ को सच से, अन्धेरे को अपने अन्दर की रोशनी से और मौत को अपनी जिंदगी से जीता । वकालत और डाक्टरी जैसे पेशों, उद्योग-धन्धों, समाज,

सदाचार, धर्म, रीतिरिवाज, जिस-जिस चीज की उन्होंने टीका की या उसे हाथ लगाया, उस उसके पुराने ठेकेदार उनके दुश्मन हो गए । पर उन्होंने जिसे भी छुआ, उसके मैल को जलाकर उसे निखार कर सोना बना दिया। सच्चाई उनकी तलवार थी । अहिंसा उनकी ढाल थी। दीनता उनका बल था । प्रेम उनका आदर्श और उनकी सबसे बडी साधना थी । करोडों बल्कि अरबों मनुष्यों में वह एक मनुष्य थे; वह राजनीतिज्ञ थे, वह योद्धा थे; ऊंचे दरजे के कलाकार थे । अर्थ-शास्त्र के भी वह अपने ढंग से और खास कर दुनियां की आम जनता के भले-बुरे की निगाह से इतने बडे जानकार थे कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। उन्होंने राजनीति को ऊंचा उठाकर दीन धर्म के रुतबे तक पहुँचा दिया । उनके जीवन का यह सबक हमेशा के लिए अपना काम करता रहेगा । इन सबसे बढकर गीता के शब्दों में वह स्थितप्रज्ञ थे । सूफियों की भाषा में उनकी बुद्धि अकलें सलीम थी । उनमें न किसी से लगाव था न किसी से डर गुस्सा था वैर उनके स्वभाव ही में न रह गया था । एक अवतार की तरह वह धरती पर आए और उन्होंने अपने समय की दुनियां को अपने बराबर तक उठाने की कोशिश की । वह गुलाम हिन्दुस्तान को अपने अनोखे ढंग से आजाद करने आए थे । उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया । इस मिट्टी में गिरे हुए राष्ट्र को उन्होंने ऊपर उठा दिया । दूसरे अवतारों की तरह अपना काम पूरा करके वह चल बसे । श्रीराम की तरह उन्होंने अपने वचन को निबाहा। बुद्ध भगवान की तरह उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। हजरत ईसा की तरह उन्होंने सबको प्रेम और सेवा का उपदेश दिया और अपने प्रेम और सेवा से दूसरों की आत्माओं को जगाया। इस्लाम के पैगम्बर की तरह उन्होंने नस्ल और जात-पात के घमण्ड और छुआछूत को तोड कर इनसानी बराबरी का उपदेश दिया और खुद उस पर अमल करके दिखलाया ।

हिन्दू धर्म के वह सबसे बडे और सबसे ऊंचे नमूने थे । गीता और उपनिषदों की तालीम को जिस तरह उन्होंने अपने जीवन में ढाला था इस युग में शायद ही किसी दूसरे ने ढाला हो। दुनिया-भर में उन्होंने हिन्दू धर्म का नाम रोशन किया और दुनियां की निगाह में उसका मान बढाया। इससे भी बढ कर हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी वगैरह के भेदों से ऊपर उठकर वह सच्चे मानव-धर्म के मानने वाले थे । वह खुद कहा करते थे—

"मैं हिन्दू हूँ इसीलिए मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं पारसी भी हूँ मैं सब धर्मों का मानने वाला हूँ।" वह सर्व धर्म समभावी थे, अलग-अलग धर्मों के बाहरी कर्मकाण्डों और रीति-रिवाज के फरकों से ऊपर उठकर उन्होंने उस 'दीन' और उस "धर्म" को अपना लिया था जो सब धर्मों और मजहबों की जान है। वह उस प्रेम धर्म, उस मजहबे इश्क, उस मानव धर्म, उस मजहबे इनसानियत के मानने वाले थे जिसका वैदिक ऋषियों, मुसलमान सूफियों और ईसाई सन्तों ने एक समान राग अलापा है। मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि जबकि हर समय देश में पूरी मजहबी आजादी होना जरूरी है और जबकि अलग-अलग तरह के रीति-रिवाज भी हमारे जीवन की सुन्दरता को उसी तरह बढा सकते हैं जिस तरह एक बाग में तरह-तरह के फूल, फिर भी आजकल की भटकी हुई दुनियां में दीन धर्म को जिंदा रहना है तो यह प्रेम धर्म, यह आलमगीर मानव-धर्म ही आगे के संसार का मुख्य धर्म होगा। इस निगाह से महात्मा गांधी के जीवन का सबसे बडा सबक उनकी प्रार्थना में गीता के श्लोकों और कुरान की आयतों का साथ-साथ पढा जाना था। इस बारे में उनके विचारों का निचोड इन शब्दों में है:—

"ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
सबको सन्मति दे भगवान"।

धर्म, मजहब के मामले में यह उदारता और रवादारी ही में हमें उनकी आखिरी और सबसे बडी नसीहत है। दूसरे सब तंग रास्ते अन्धेरे और बरबादी के रास्ते हैं।

इंगलैण्ड के मशहूर विद्वान ग्लेडस्टन ने कहा है:—
"मामूली सदाचार के दायरे को बढा देने का नाम ही राजनीति है।"
महात्मा गांधी भी यही मानते थे। लार्ड एक्टन ने कहा है—

"सारा (योरुपी) इतिहास आजादी की लगातार कोशिशों से भरा हुआ है; और आजादी की कोशिशें ही सदाचार को बढाने वाली कोशिशें हैं।"

राज का असली काम दुनिया की ताकतों का इस तरह संगठन करना है, जिससे नेकी और न्याय बढ़े। आजादी किसी राजकाजी मकसद को पूरा

अनहोनी बात है। इस तरह के संघ में राष्ट्रों-राष्ट्रों के लडाई-झगडे बराबर बने रहेंगे। उस संघ में अपने नाश के बीज छिपे होंगे। सारी दुनिया में एक संघ या एक राज कायम करने का अगर कोई रास्ता है तो वह केवल अहिंसा ही का रास्ता है। हम कह चुके हैं कि अहिंसा जिन्दगी बिताने के एक ढंग का नाम है। दुनिया को एक करने के लिए जरूरी है कि दुनिया के सब राष्ट्र इस ढंग को अपनावें। सबका ध्यान अपने ऊपर काबू पाने, अपनी खुदगरजी को छोडने और अपनी आत्मा को पहचानने की तरफ हो, यही अहिंसा है। इसी का नाम विश्वसंघ है। यही रामराज या हुकूमते इलाही है।

कांग्रेस और उसका प्रेजीडेंट

कांग्रेस का यह ५५वां इजलास है। आजाद हिन्दुस्तान में कांग्रेस का यह पहला इजलास है। हमारे मुल्क के जो हिस्से पहले देशी रियासतें कहलाते थे उनमें से किसी रियासत में भी यह पहला इजलास है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस इजलास का मुझे प्रेजीडेंट चुना है। आपने मुझे आजाद राष्ट्र का 'पहला सेवक' चुना है। दो साल पहले तक 'राष्ट्र का पहला सेवक' कहलाने में कांग्रेस के प्रेजीडेण्ट का कोई रकीब नहीं था। पर अब देश आजाद हो जाने के साथ-साथ मुझे डर है कि एक रकीब पैदा हो गया है। मेरा मतलब प्रधान मन्त्री से है। वह हाकिम हैं। इसलिए मैं खुशी से इस नाम के लिए उनके अधिकार को अपने अधिकार से ज्यादह मानता हूँ। 'राष्ट्रपति' नाम मुझे कुछ दिखावटी और बोझल मालूम होता है। पर आप आगे के लिए कांग्रेस के प्रेजीडेण्ट को चाहे राष्ट्र का पहला सेवक कहें और चाहे राष्ट्रपति कहें। इस समय इस पदवी के साथ गहरी जिम्मेदारी भी है, वह इसलिए क्योंकि हमारा देश आजाद तो हो गया पर अभी आज़ादी को बनाए रखने के लिए पक्के और ठीक रास्ते पर नहीं पड़ा है। यही हमारे आगे का बडा जबरदस्त और नाजुक काम है। मैं मानता हूँ कि देश पूरी तरह आजाद भी १७ सितम्बर सन् ४८ को उस समय हुआ जब शख्सी या एक तन्त्री राज के आखरी किले को हमने सर किया। हमारी इण्डियन यूनियन की सरकार फूंक-फूंक कर लेकिन साथ ही बडी मजबूती के साथ कदम आगे को बढाती रही है। १७ सितम्बर को हमारी सरकार यह कह सकी कि अब सचमुच इस युनियन की एक-एक इंच जमीन

आजाद है, मानो जनता की है। इसके लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार तो शुक्रिए की हकदार है ही, साथ ही कुछ-न-कुछ हकदार वह इण्डियन नेशनल कांग्रेस भी है जिसने आधी सदी से ऊपर तक हर तरह के विदेशी, खानदानी या शख्सी राज की जगह देश में आम जनता का राज कायम करने के लिए लगातार कुरबानियां की।

कांग्रेस को पैदा हुए ६३ वरस हो चुके। इन ६३ वरस के अन्दर बड़े-बड़े देश भक्तों, देश सेवकों, जां-निसारों और राजनीति के पण्डितों ने कांग्रेस को धीरे धीरे रूप दिया। इनमें से कुछ के नाम अभी तक हमें याद हैं, कुछ के इतिहास में अमर रहेंगे और बहुतों के दुनिया भूल चुकी और भूलती जा रही है। आज उन सब मुबारिक हाथों की बनाई और पाली-पोसी हुई कांग्रेस एक नए जीवन में कदम रख रही है। आज तक हमारा काम आजादी के लिए अहिंसा की लडाई लडना था। अब से हमारा काम आजाद देश को पक्का, बलवान और खुशहाल बनाना है। हमारा काम अब देश में अमन-आमान कायम करना और देश का संगठन करना है।

कांग्रेस के सामने बडी-बडी कठिनाइयां आई। उसे बार-बार मुसीबतों के जंगलों और निराशा की जिन अन्धेरी रातों में से निकलना पड़ा, उन सबको यहां गिनाने की जरूरत नहीं है। यह कह देना काफी है कि कांग्रेस धीरे-धीरे उन सब आजमायशों में से तपकर निकलती रही, और हर बार अन्त में कसौटी पर खरी उतरती रही। इस तरह की संस्थाए बदल सकती हैं। उनकी काया-पलट हो सकती है पर वह मर नहीं सकती। देश के जीवन के हर कोने में उनका असर बढता ही जायगा। इसमें देश का भला है। देश के बहुत से हिस्सों में लोगों की साठवीं सालगिरह बडे-ठाट बाट के साथ मनाई जाती है। कहीं कहीं इस मौके पर बूढे पति और पत्नि का फिर से ब्याह रचा जाता है और समझा जाता है कि यह नया गठबन्धन परलोक में भी कायम रहेगा। हमारे देश और हमारी कांग्रेस का अब यह नया गठबन्धन हो रहा है। दोनों को एक दूसरे की सेवा का नए सिरे से वचन करना होगा और एक दूसरे की सलामती में अपनी सलामती समझनी होगी। आज का यह अवसर बडा पवित्र और जिम्मेदारी का अवसर है। एक नया यज्ञ रचा जा रहा है, जिसके लिए आपने मुझे नया पुरोहित चुना है। मैं अपनी पूरी शक्ति-भर यत्न करूंगा कि इसके योग्य साबित हूं, और

मुझसे पहले के बड़े-बड़े पुरोहित देश के सामने जो आदर्श और जो मर्यादा रखते आए हैं, उसे पहले से ज्यादह साफ और उज्वल रखूं, और हिन्दुस्तानी राष्ट्र के असली और प्राचीन रूप को कायम और बनाए रखूं ।"

हमारी नई जिम्मेदारियां

१५ अगस्त सन् १९४७ को अंग्रेजों को चले जाने के समय से हमारा काम बहुत बढ़ गया है । तब तक हम अपनी ही गुलामी और अपने ही दुखों में डूबे हुए थे । हमारी आंखें दुनियां की तरफ कम जाती थीं । आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का एक एक विदेशी महकमा तो था, पर उसका काम सब इतना ही था कि अपने देश की गुलामी का रोना दूसरे देशों के सामने भी रोए । आज हम एक आजाद देश हैं । हमारे मन्त्रिमण्डल का एक अपना विदेशी विभाग है । आजाद हिंद के आजाद राजदूत दूसरे देशों में जा-जाकर रह रहे हैं । दूसरे देशों में हम अपने ट्रेड कमिश्नर और अपने गुमाश्ते भेजते हैं । यू० एन० ओ० में और यूनैस्को में हमारे प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं और हिस्सा लेते हैं । मजदूर कान्फ्रैन्सों और अन्तर्राष्ट्रीय पार्लमेण्टरी सभाओं में हमारे आदमी भाग लेते हैं । फिर भी हमारी निगाहें अभी दूर तक नहीं जा रही है । अभी तक हमें कुछ छोटी चीजें बडी और कुछ बडी चीजें छोटी मालूम होती हैं । हमें अपनी निगाहों को बढाना और फैलाना होगा, हमें अहतियात रखनी होगी कि कुंए के मेंढक की तरह अपने कुंएही को दुनिया न समझ बैठें । खुद अपने देश हिन्दुस्तान को भी हमें नई, बडी और उदार निगाह से देखना होगा । हमारे प्रधानमन्त्री के हाल के लन्दन और पैरिस के दौरे से हमें इस बारे में बडी मदद मिली है । उनके इस दौरे से नये हिन्द की पूरी तसवीर हमारे सामने आ गई है । अब हमें दिखाई देने लगा है कि दुनिया के छः बड़े-से-बड़े मुल्कों और छः बड़े से राष्ट्रों में हमारे देश और हमारे राष्ट्र की जगह है । कुछ की राय में हमारी जगह अब इससे भी ऊपर है । अपनी इस नई जगह को समझते हुए हमें पुरानी तंग-नजरी और पुराने छुटवहम को सदा के लिए फेंक देना होगा । हमें अपने ऊपर भरोसा पैदा करना होगा बिना किसी तरह का घमण्ड मन में लाए हमें इस महान राष्ट्र की आन और उसकी शान का ख्याल रखना होगा। अपने ऊपर भरोसे का जागना ही हमारे बल का बढना है।

इसके लिए जरूरी है कि हमारे नेताओं के नेता, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने नए हिन्द की जो सुनहरी अहिंसात्मक तसवीर हमारे सामने रख

दी है उसी के अनुसार हम अपने को और अपने देश को ढालें और उसी रूप में दुनिया के सामने खड़े हों। अपने अब तक के बिगड़े हुए रूप से और दुनियां के बनावटी चमक-दमक के रूपों से दोनों से हमें बचना होगा तब दुनिया इस बात को देख सकेगी कि महात्मा गांधी के उसूलों के अन्दर ही दुनिया की सुख शान्ति और खुशहाली का असली सर चश्मा है। हमारे अपने उस रास्ते पर चलने से ही दुनिया उसकी कदर करना सीखेगी और समझेगी कि आए दिन की जंगों और चारों ओर की निराशाओं के जिस भँवर के अन्दर दुनिया इस समय पड़ी हुई है उससे निकलने का यही एक रास्ता है। दुनिया की पिसी हुई जनता राजनीतिक नेताओं के इन झगड़ों-टंटों को बहुत पसन्द नहीं कर रही है। वह युद्धों से ऊब गई है और ऊबती जा रही है। राजनीतिक नेताओं में से भी बहुत से दुनियां के दुखों के असली इलाज की तरफ ध्यान देने लगे हैं। नए महायुद्ध से सब बचना चाह रहे हैं। हमें इस समय अन्तर्राष्ट्रीय हालत की बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। दो सबसे बड़े राष्ट्र दलों में तिजारती लाग, डाट और अपने अपने असर के दायरों को बढ़ाने की होड़ अभी कम नहीं हो रही है। ऐसे अवसर पर हमें पहले अपने अन्दर पूरी तरह निगाह डालनी चाहिए। देश के बच्चों की ठीक-ठीक तालीम, उद्योग-धन्धों की उन्नति, गांवों की जिन्दगी का नए ढंग पर संगठन, राष्ट्र के आदर्शों को पक्का और साफ रखना, अपनी कायदादारी को मजबूत करना, अपने अन्दर से हर तरह की फिरकापरस्ती और फूट के अंकुरों को बीन-बीन कर अलग करना, इन सब बातों की तरफ पूरा ध्यान देते हुए बाकी दुनियां की दलबन्दियों से हमें जहां तक हो सके अलग रहना चाहिए। जहां तक बन पड़े दुनिया के सब राष्ट्रों के साथ मित्रता निबाहना वह तरीका है जिससे हम दुनियां की गुत्थियों को सुलझाने में मदद दे सकते हैं।

दूसरे देशों से सम्बन्ध

यह एक अलग सवाल है कि दुनिया के किसी दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र दल के साथ हमारे क्या सम्बन्ध हों, हमारा देश एक पूरी तरह खुदमुख्तार और आजाद लोकराज (Sovereign Independent Republic) होने का फैसला कर चुका है, यह फैसला नहीं बदल सकता अन्दर के शासन में और बाहर की

दूसरी ताकतों से अपने सम्बन्ध को तय करने में, दोनों में हम पूरी तरह आजाद और खुद मुख्तार हैं और रहेंगे । पर आजादी का यह मतलब नहीं होता कि हम दुनिया से अलग रहें या दूसरे देशों से हमारा कोई समझौता या नाता-रिश्ता ही न हो । दुनिया के सब देश तरह-तरह एक दूसरे के साथ बन्धे हुए हैं । इस आपसी सम्बन्ध को ठीक रखने में ही सारी दुनिया का भला है । हिन्दुस्तान चाहे आजकल के दो बडे बडे राष्ट्र दलों में से किसी एक में मिले या किसी दूसरे गिरोह में शामिल हो, हर सूरत में कुछ समझौता या शर्तें कुछ लेना-देना ऐसा करना होगा जिसमें दोनों का, बल्कि सबका, भला हो । इन समझौतों और शर्तों को देख-भाल कर तय करना होगा । यह काम तजरबेकार नेताओं का है । इसका आखरी फैसला हमारी विधान सभा के हाथों में होगा । पर आखरी फैसले से पहले दूसरे राष्ट्रों के साथ बातचीत और एक दूसरे को समझना जरूरी है। हमारे प्रधान मन्त्री इसी तरह की बातचीत के लिए हाल में योरुप गए हुए थे । इस काम में उनकी कुशलता और उनकी अपनी आन के बदौलत सब देशों की निगाहें हिन्दुस्तान पर लगी हुई हैं । एक तरफ प्रशान्त महासागर और दूसरी तरफ ऐटलांटिक महासागर दोनों के बीच की महराब का हिन्दुस्तान ही महवर है । इसी तरह दुनिया के बहुत से राजकीय नेता हमारे प्रधान मन्त्री को एशिया और योरुप को जोडने वाली कडी मानते हैं । वह उस एशियाई शक्ति के विदेशी विभाग के मन्त्री हैं जो अगर सम्भल कर चले तो दुनिया के राजकाजी समतोल की तराजू के पलडों को अपने अकेले बोझ से इधर या उधर झुका सकती है। पच्छिम के बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि दुनिया की बेजबान करोडों जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रधान मन्त्री समय पडने पर युद्ध के खिलाफ और शान्ति के हक में अपना पूरा असर डाल सकते हैं । हमारे देश के लिए वह दिन बडे गौरव का दिन होगा। हमें भरोसा है कि इस मामले में भी यानी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे कदम जिस तरह पडेंगे उससे हमारे देश का मान बेहद बढेगा।

देश की नई रचना

अब मैं फिर देश के अन्दर के काम पर आता हूं । शिकायतें करने और दूसरों के दोष निकालने का समय बीत चुका । अब हमें नए देश और नई आजादी की रचना करनी है । हमारी जिम्मेदारियां बेहद बढ

गई है। हमारे देश की हालत इस समय उस घर की सी है जिस पर कई बरस तक फौजी कब्जा रहा हो और जिसे फौज एक दम खाली छोड कर चली गई हो, या उस उपजाऊ जमीन की-सी जिसे किसी महायुद्ध के दौरान में लगातार कई बरस तक फौजों ने रौंदा हो। हमें अपने घर को फिर से ठीक करना है। इस समय हम जो रचना या तामीर करेंगे उसी पर हमारी सच्ची और असली आजादी का महल खडा होगा। देश में योरुप वालों के आने और विदेशी हुकूमत के कायम होने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन, हमारे मुल्क के रहन-सहन, हमारी कल्चर और रंग-बिरंगी हरी-भरी और सुन्दर हिन्दुस्तानी जिंदगी के सब तार टूट-टूट कर इधर-उधर बिखर गये थे और अभी तक बिखरे हुए हैं। सबसे बडा दुःख यह है कि जिस तरह देर के गुलाम को अपनी गुलामी में आनन्द आने लगता है उसी तरह हममें से बहुत-सों को इस बिखरने में ही अपना भला दिखाई देने लगता है। हमें उन सब तारों को फिर से जमा करना और मिलाना है, और उन्हें इस तरह से गूंथना है कि नए जमाने और नई साइन्स की सारी तरक्की हमारी उदारता और एकता के सहारे हमारे देश में आगे बढ सके और फल-फूल सके। इन्सानी समाज की बढौती के लिए इस ज़माने की जडें पिछले जमाने में मजबूत गडी होनी चाहिए, और आने वाले ज़माने की जडें इस जमाने में होनी चाहिए। नए पौदे नई हवा में पनपेंगे, पर उनकी जडें पुरानी मिट्टी में ही रहेंगी। पिछले ज़माने, हाल के ज़माने और आने वाले जमाने तीनों को मिलाकर ही मानव-उन्नति का चक्करदार जीना तय्यार होता है।

काम सचमुच आसान नहीं है। पर देश का बड़ा भाग्य है कि इसके लिए महात्मा गांधी की तीस बरस की तालीम, उनके असूल, उनकी अपनी मिसाल हमारे सामने है। हम अभी सौ बरस तक उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने राष्ट्रीय जीवन को पक्का कर सकते हैं। आगे की मंजिलें अपने आप हमारे सामने खुलती जायंगी। इस तरह दुनियां के देशों के लिए हम एक मिसाल बन सकते हैं। विचारों और आदर्शों की दुनिया आज एक गहरे इनकलाब में से निकल रही है। अभी तक भी धन दौलत दुनियां में सबसे बडी ताकत मानी जाती है। पर यह ताकत अब धीरे-धीरे घट रही है। मानव सेवा या इनसानी ख़िदमत की ताकत उसकी जगह धीरे-धीरे बढ़ रही है। हिन्दू धर्म-शास्त्र में विद्या और परोपकार को सबसे ऊंचा दर्जा

और धन दौलत को तीसरा दर्जा दिया गया था । विद्वान के लिए गरीबी उसकी शान को बढ़ाने वाली समझी जाती थी । अब ज़माना और भी बदला है । गांधीजी ने वर्णाश्रम धर्म का नया रूप हमारे सामने रख दिया है। जिसमें हर आदमी अपना पुरोहित, खुद अपना योद्धा, खुद ही अपने और देश के लिए कमाई करने वाला और खुद ही अपना सेवक बन सके। इसीका नाम गांधीवाद है । गांधीवाद ही को हिन्दुस्तान का समाजवाद (इण्डियन सोशलिज्म) कहा जा सकता है । पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने, जो चार बार इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेण्ट चुने जा चुके हैं, फैजपुर की सोशलिस्ट कांफ्रेन्स को यह सन्देश भेजा था—"इण्डियानाईज युअर सोशलिज्म" यानी 'अपने समाजवाद को हिन्दुस्तानी समाजवाद बना लो ।" गांधीजी से बढकर समाजवादी और गांधीवाद से बढ कर समाजवाद हमारे लिए नहीं हो सकता । हमारा फर्ज है कि उन्हीं के बताए हुए ढंग पर अपने सारे समाज का फिर से संगठन करें और जितनी जल्दी हो सके देश को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनावें । हमारी आबादी ३० करोड है। हमारे साठ करोड़ हाथ हैं । हाथ की कारीगरी की यहां कमी नहीं! हमें देश को समझना है कि मेहनत करना ही भगवान की पूजा करना है । एक मेहनती और होशियार कारीगर की जानकारी और कल्चर के सामने हमारी यूनिवर्सिटियों की दी हुई सारी विद्यायें और सारी कल्चर फीकी है । बडी बडी मिलों में लोगों को जोत देना और फिर उनके लिए फुरसत और तालीम की चीख-पुकार करना अमली बात नहीं है । इसके मुकाबले में हमारे घरेलू धन्धे और हमारे गांव की दस्तकारियां एक ऊँची सभ्यता की अमिट बुनियादें हैं । किसी भी देश की सभ्यता का असली अन्दाजा उसकी दस्तकारियों और उसके आम लोगों के कामों ही से लगता है ।

अब सवाल यह उठता है कि पिछले दो साल में हमने इस बारे में क्या किया । अव्वल तो हमारी सूबाई सरकारों और केन्द्रीय सरकारों के सामने काम बहुत रहा है । दूसरे ऐसी नई-नई कठिनाइयां जिनका पहले कभी गुमान भी न हो सकता था, रोज आती रही हैं । नतीजा यह हुआ कि वह सब वायदे जो उन्होंने जनता से किए थे वह अभी पूरे नहीं कर सके । देश के अन्दर नए ढंग से या पुराने ढंग से कारखानों और उद्योगों को बढ़ाना एक बहुत बड़ा काम है । बडे-बडे चालू कारखानों को भी सरकार के लिए अपने हाथों में ले लेना साल-दो साल के अन्दर नामुमकिन था।

वाहर से तरह-तरह के सामान और मशीनों का मिलना कठिन हो गया। अमरीकन डालर का राज हमारे लिए अंग्रेजी स्टरलिंग के राज्य से भी ज्यादह कड़ा और डरावना साबित हुआ। दुनियां में उद्योग धन्धों की शकलें इतनी जल्दी-जल्दी वदलती रहती हैं कि उन का साथ दे सकना मुश्किल हो जाता है। फिर पूरव और पच्छिम के बीच की दौड़ भी घुटने तोड़ने के लिए काफी हैं। इन और दूसरी बातों की वजह से हम इन दो वरस में जितना करना चाहते थे नहीं कर सके। हमने यह भी देख लिया कि प्रान्तों को वहुत ज्यादह उनके ऊपर छोड़ देने से केन्द्रीय सरकार कमजोर हो जायगी और प्रान्तों को भी नुकसान पहुँचेगा। इस तरह टुकड़े-टुकड़े हो जाने से हमारे मिट जाने का साफ डर है। हमें इस मामले में भी फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहिए। देश के दोनों तरफ के दो वड़े-वड़े टुकड़ों के कट जाने से हमारी गुत्थियां और वढ़ गई हैं। मुस्लिम लीग और उसकी मांगों के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आए दिन के झगड़े और आए दिनके मसले इतना ज्यादह वक्त ले लेते हैं कि हमारी सरकार के लिए दूर की योजनाओं की तरफ ध्यान देने में अभी कुछ और देर लगेगी, जमींदारियों को अभी मिटाने के लिए जितने धन की जरूरत होगी उससे हमारे करेन्सी नोटों का फैलाव और चीजों की कीमतें दोनों बेहद वढ़ जायेंगी। यही कठिनाई देश भर के अन्दर एकदम शराव वन्दी कर देने में दिखाई देती है। नहरों और पानी से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी वड़ी-वड़ी योजनाओं में भी अभी यही देर है। घरेलू धन्धों और हाथ की कारीगरियों के वढ़ने से वेशक हमें हर समय फायदा है। इनकी तरफ जितना ध्यान दिया गया उससे ज्यादह दिया जा सकता था। पूंजीपति और साहूकार तरह-तरह के वहाने लेकर अपनी पूंजी को रोक रहे हैं। समझौतों से काम करना पड़ता है। पर वड़े-वड़े व्यापारी इजारों और मोटे मोटे मुनाफों को देर तक चलने दिया नहीं जा सकता। इन्हें वन्द करना ही होगा। सरकार अपनी वाग न पूंजीपतियों के हाथ में दे सकती है न मजदूरों के। इस समय हमारी सवसे वड़ी जरूरत यह है कि केन्द्रीय सरकार को ज्यादह-से ज्यादह मजबूत किया जाय। मैं सव देशवासियों से अपील करूंगा कि देश के भले के लिए वह इसमें ज्यादह-से-ज्यादह मदद दें।

हमें अपने जीवन और अपनी हकूमत दोनों में सच्चाई, ईमानदारी और नेकी को वहुत ज्यादह ऊँचा स्थान देना होगा। इसके विना न हम

अपने समाज को ठीक रख सकते हैं और न हकूमत को पाक कर सकते हैं। कपडे और खाने की दिक्कत को कम करने के लिए हमें दूसरों का मुंह ताकने और बाहर से माल मंगाने की जगह ज्यादह खेती करनी चाहिए, ज्यादह दरख्त लगाने चाहिए और हर एक को सूत कातना चाहिए। रिश्वत और चोर बाजारी को मिटाने के लिए लोगों को सजा दिलाने पर भरोसा करना काफी नहीं है। इसके लिए भी हमें देश में सदाचार इनसाफ और ईमानदारी को जगाना होगा।

रिश्वत काफी बढ गई है और उसकी वजह से सरकार के खिलाफ भी लोगों में असन्तोष बढा है। पर जब तक रिश्वत देने वाले अपनी खुदगरजी के लिए रिश्वत देते रहेंगे, रिश्वत बन्द हो सकना कठिन है। यही बात चोर बाजारी के बारे में कही जा सकती है। कण्ट्रोलों के बारे में भी सरकार एक भूल-भुलैयां में पड गई है। जाहिलों की जहालत और बदमाशों की बदमाशी के सामने कायदे-कानून अकसर धरे रह जाते हैं। सच पूछिए तो शख्सी हुकूमत में जुर्मों का रोक सकना ज्यादह आसान होता है। लोकराज और अधिकारों के युग में कम-से-कम एक बार जुर्मों का बढ़ना कुदरती है। कभी कभी तो जिसे रिश्वत पकडने के लिए रखा जाता है वही खुद रिश्वत लेता दिखाई देने लगता है। फिर भी हमारी सरकारों ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रही है। कारखानों और मजदूरों के मामलों में, लाखों शरणार्थियों को फिर से बसाने में और हजारों भगाई हुई बहनों को वापिस लाने में, तालीम और तन्दुरुस्ती के महकमों में आने-जाने के साधनों को ठीक करने और ठीक रखने में और इन सबसे बढ कर पुरानी देशी रियासतों की कायापलट करने में और फौज का नए सिरे से संगठन करने में हमारे यूनियन की सरकार ने जो कुछ किया है और जिन मुश्किलों के होते किया है उसका पूरा अन्दाजा अभी तक सब लोगों को आसानी से नहीं हो सकता। 'हिन्दू ला कोड' भी हमारी कानून सभा के सामने है। वह एक बहुत बडी चीज है। अपने को सनातनी समझने वाले भाइयों की तरफ से उसका विरोध हुआ है। जो धर्म या समाज जमाने के साथ नहीं बदलता वह जिन्दा नहीं रह सकता। इस बारे में मैं केवल इतना ही और कहूँगा कि हमारे सनातन धर्मी भाई अगर अपने कदम थोडे-बहुत आगे को बढाते रहें तो वह हमारे काफले के पैर पीछे खिंचने की जगह उसे आगे बढने में मदद दे सकते हैं।

राष्ट्र की तरक्की के बुनियादी असूलों का हमारे नए विधान के मसौदे में बुनियादी अधिकारों और यूनियन की नीति के रूप में पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है। विधान में यह दो हिस्से ही हमारे विधान की बुनियाद और उसकी जान हैं। बाकी सब हिन्दुस्तानी राष्ट्र के महल की सजावट है। हमारा यह राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीयता बेदाग है। उसमें न कोई धार्मिक पक्षपात होगा, न कोई मजहबी तअस्सुब, न उसमें साम्प्रदायिकता का दोष होगा और न फिरकापरस्ती की बुराई। हमारा देश हिन्दुस्तान दुनियां-भर के धर्मों और मजहबों का संगम है—वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, और यहूदी धर्म, सबको उसमें एक बराबर जगह है। दुनियां का यह अकेला देश है जिसमें ठीक तरह की सच्ची राष्ट्रीयता पनप सकती है और फल-फूल सकती है। सच यह है कि हमारा यह गुण और हमारी विशेषता ही दीन और धर्म की जान है। हमारी जिन्दगी की ऊँचाई, बड़ाई और भरपूरता इसी एक बात में है। जब धर्म इस उदारता और रवादारी को छोडकर कट्टर तंग फिरकापरस्त या साम्प्रदायिक बन जाता है तो जिन्दगी के सारे गुण सुकड़कर और मुरझाकर रह जाते हैं और कौमें अपने जहर से खुद अपने को मार लेती हैं। हमारी नैशनेलिज्म, हमारी राष्ट्रीयता सबको अपने अन्दर लिए हुए और सबका एक बराबर मान रखने वाली रहेगी। धर्म, मजहब फिरके, साम्प्रदाय, कल्चर, भाषा, नसल, जात-पात या इनमें से किसी की बिना पर हमारे राष्ट्र और हमारे देश में किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जायगा।

हमारी रियासतें

पहली बार हमें स्वराज जैसी बरकत मिली है। यह आजादी कहीं आसमान से उतर कर नहीं आई। दिल्ली की सैक्रेटेरियट के उत्तरी ब्लाक की ऊँची महराब पर यह शब्द खुदे हुए हैं:—

"आजादी किसी कौम पर ऊपर से नहीं उतरती।

"आजादी के लिए कौम को खुद अपने तईं ऊपर उठना पड़ता है।

"आजादी एक बरकत है जिसे अपनी मेहनत से लेना होता है।

"अपने को आजादी के योग्य बनाकर ही कोई कौम आजादी पा सकती है।"

स्वराज्य हासिल करने और स्वराज्य को बनाए रखने की यही कुंजी है। हमारे पिछले हाकिम जो जबरदस्ती हमारी इस जायदाद पर कबजा कर बैठे थे छोड़ कर चले गए। इस जायदाद के साथ वह हमारे लिए काफ़ी लेनदारियां छोड गए हैं और काफी देनदारियां भी। देनदारियों को हम धीरे-धीरे चुकाते जा रहे हैं। अंग्रेज़ अगर चाहते तो काश्मीर और हैदराबाद दोनों को हमारी लेनदारियां बनाकर छोड सकते थे। पर शहंशाहियत दिलों से इतनी जल्दी नहीं मिटती। अंग्रेजों की पुरानी फूट डालने की आदत न गई। वह हमारे लिए इस देश में ५६२ (पांच सौ बासठ) अल्स्टर, या कहिए हमारे शरीर पर ५६२ दाग छोड गए। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने पूरी होशियारी और पूरे बल के साथ इतनी बडी गुत्थी को सुलझाया इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी स्टेट्स मिनिस्टरी को जितना भी सराया जाय, थोड़ा है। उनके पक्के इरादे और उनकी दूरदर्शिता के सामने सारी कठिनाइयां बालू की भीत की तरह गिरती चली गई। हैदराबाद आजकल के लोकराज की तरफ़ तेजी से बढ रहा है। काश्मीर की गुत्थी कुछ दूसरी तरह की थी, पर काश्मीर भी हैदराबाद ही की तरह रास्ते पर आए बिना नहीं रह सकता। दोनों में फ़रक यह था कि हैदराबाद में लोग आजादी चाहते थे और निजाम का राज एकतन्त्री राज था, काश्मीर में वहां की बहुत बडी आबादी हमेशा लोकराज चाहती रही, महाराजा भी किसी-न-किसी तरह राजी हो गए, लेकिन बाहर से दुश्मनों ने हमला कर दिया। दोनों के पीछे समझदार लोगों को तीसरे का हाथ और उस तीसरे के पीछे एक चौथे का हाथ दिखाई दे रहा है। हमारी आजादी अभी चार दिन का बच्चा है। छोटी उमर के बच्चों को इस तरह के रोग हुआ ही करते हैं। हम आज अपने उन सिपाहियों और अफ़सरों को आदर के साथ याद करते हैं जिनकी जीतों ने हिन्द की इज्ज़त और उसकी शान को बढ़ाया है।

कई-कई रियासतों को मिलाकर एक करने का काम बहुत कुछ हो चुका, पर अभी बहुत बाकी है। महाराजा ग्वालियर ने जिस तरह ख़ुशी से मालवा की रियासतों से मिलना स्वीकार किया, उसकी हम तारीफ करते हैं। दूसरे राजाओं के लिए ख़ासकर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के महाराजाओं को यह बडी अच्छी मिसाल है। इन चार रियासतों, आजकल राजस्थान की रियासतों और मत्स्य-यूनियन को मिलाकर एक बड़ा राज-

स्थान बन जाने से इस सारे प्रदेश का बल बढ़ेगा। रामपुर और भोपाल का मिलना भी अभी बाकी है। कूच, बिहार, त्रिपुरा, और मनीपुर की सरहदी रियासतों में शहरी और फौजी दोनों तरह की कई गुत्थियां हैं। ट्रावनकोर और कोचीन का केरला के साथ और मैसूर का करनाटक के साथ उचित शर्तों पर मिलना होनहार दिखाई देता है। इसी तरह सौराष्ट्र, गुजरात और बड़ौदा को मिलाकर एक बड़ा गुजरात राज बनने की आशा है। पुराने ढंग की रियासतों के दिन हो चुके। आजकल के लोकराज के साथ इस ढंग की हकूमतें बेमेल हैं और चल नहीं सकतीं। रियासतों के मामले में अभी और भी कठिनाइयां हैं। राजाओं, महाराजाओं और नव्वाबों से उतरकर, खासकर हैदराबाद, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर में सैंकड़ों छोटे-छोटे ठाकुर, जागीरदार, बिसवेदार और इलाकेदार हैं जिनके हाथों में बड़े-बड़े अधिकार, माल के, दीवानी के और फौजदारी के, चले आ रहे हैं। रियासतों के अन्दर जिन जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां हम सुना करते थे वह बहुत करके इन्हीं लोगों की होती थीं। कई जगह इन लोगों की बुराइयों के लिए महाराजा को बदनाम होना पड़ता था। इन इलाकों, जागीरों, और ठकुराइयों को भी खत्म करना जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह जमींदारियों को खत्म करना जरूरी है। यह बता देना भी आवश्यक है कि हम जमीदारियों के खिलाफ हैं, जमीदारों के नहीं। जागीरों और इलाकों के खिलाफ हैं, जागीरदारों और इलाकेदारों के नहीं। हमारी यह इच्छा है और हमें इसकी पूरी आशा है कि हमारे बहुत से नेक और तजुर्बेकार जमीदार, जागीरदार और इलाकेदार नए उद्योग-धन्धों के मैदान में और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में देशके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकेंगे।

यह सच है कि जिन रियासतों के नए संघ बने हैं उनमें अभी तक टिकाऊ और काम की सरकारें नहीं बन सकीं। पुरानें खपरैल के घर को गिराकर दूसरा छतदार घर बनानें में देर तो लगती ही है। कुछ दिनों तो मलबा ही इधर-उधर फैला हुआ ही दिखाई देता है और उन मलबे में नए सांप-बिच्छू भी पैदा हो जाते हैं। यही हमारी बहुत-सी रियासतों की आजकल हालत है। पुराने महाराजा अपनी प्रजा के पास रहते थे। लोग जब चाहें उन तक पहुंच सकते थे, पर आज रेवेन्यु इंसपेक्टर दस मील पर रहता है,

मामलतदार तीस मील पर, कलक्टर उससे भी दूर और दिल्ली तक आ सकना तो लोगों के खयाल से भी वाहर की वात है। और फिर जो कुछ किसी को कहना हो उचित अधिकारी की मार्फत कहे। इस तरह की वातों में लोगों की कठिनाइयां वढ़ गई है। हमें भरोसा है कि यह सब कठिनाइयां थोड़े दिनों की है। हम धीरज के साथ अपनी हालत सुधारते रहें तो यह सब कठिनाइयां दूर होंगी और सच्ची आजादी और लोकराज की वरकत इन सब पुराने और पिछड़े हुए इलाकों में लोगों के लिए सच्ची वरकत सावित होगी।

भाषाई सूबे

एक और सवाल है जिसे हमें हिम्मत और दूर अन्देशी के साथ हल करना होगा। दोनों तरफ़ के पाकिस्तानी हिस्सों को छोड़कर बाकी हिन्दुस्तान आज वहुत-सी रियासती या सूबाई इकाइयों का एक फैडरेशन या संघ है। इस संघ का नाम ही 'हिन्द यूनियन' है। इस तरह के संघ की कल्पना कोई नई कल्पना नहीं है। सन् १९१७ के होमरूल आन्दोलन के दिनों में भी इसी तरह का संघ वनाने की चर्चा हुई थी। उस समय भी सूवों की स्वाधीनता पर जोर दिया गया था, और वही अधिकार संघ के अधिकार माने गए थे जो सारे राष्ट्र के भले को देखते हुए सूबे खुद अपनी इच्छा से संघ को दे दें। ऐसे संघ में विना दूसरों की मदद के, अपने सूबे के साधनों से ही अपने गुजारे और रक्षा का खुद इन्तजाम करना हर संघ का अपना काम होगा। हमारे सूबों के पास साधन भी तरह-तरह के और काफी मौजूद हैं। सूबों को इस वात के लिए मौके और इस काम में मदद जरूर मिलनी चाहिए कि वह इन साधनों को अपने ढंग पर वढ़ा सकें और उनसे काम ले सकें। इस काम का ढंग हर सूबे की सीधी-सादी आम जनता अच्छी तरह जानती है। अनपढ़ होने हुए भी जनता इस काम में मंजी हुई होती है, अपनी वात कह सकती है, और अपनी हकूमत चला सकती है। यह सब काम लोग अपनी मातृभाषा या अपने सूबे की जवान में ही कर सकते हैं। इसी लिए इस वातकी जरूरत है कि हर सूबे की तालीमी, राजकाजी और कानून वनाने वाली संस्थाएं अपना सब काम उस सूबे की जवान में ही करें। भाषा के हिसाव से हिन्द के अलग-अलग सूबों की नए सिरे से हदवन्दी करने की यही गरज है।

अंगरेज सरकार को इस से कोई मतलब न था कि वह रचनात्मक ढंग से हमारे राष्ट्र के प्रश्नों पर विचार करती और इस तरह के एकरंगी भाषाई सूबे बनाती। उत्तर में अब भी लगभग इसी तरह के सूबे हैं। मुसीबत बेचारे दक्खिन वालों की है। विन्ध्याचल से उत्तर के हिस्से और दक्खिन के हिस्से, दोनों की की अपनी-अपनी अलग-अलग गुत्थियां हैं। दक्खिन के लोग उत्तर वालों के साम्प्रदायिक झगडों के सब पहलुओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते। यही हाल दक्खिन की गुत्थियों के बारे मे उत्तर वालों का है। दिसम्बर सन् १९१६ में लखनऊ के अन्दर साम्प्रदायिक मसले पर एक समझौता हो गया तो अंगरेजों ने इसके बाद फरवरी सन् १९१७ में दक्खिन में नई साम्प्रदायिक गुत्थी खड़ी कर दी। मैं कह रहा था कि दक्खिन में एकरंगी यानी भाषाई सूबे नहीं हैं। मिसाल के लिए, मद्रास में थोडे दिनों पहले तक पांच भाषाएं बोली जाती थीं, अब चार बोली जाती है। बम्बई में दस साल पहले तक चार और अब तीन बोली जाती हैं। सी० पी० में दो बोली जाती हैं। कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग चार सूबों में बंटे हैं। मराठी बोलने वाले तीन हकूमतों में बंटे हुए हैं। कालिजों में प्रोफेसर या विद्यार्थी, कचहरियों में वकील मवक्किल और जज और धारा-सभाओं में उनके मेम्बर एक दूसरें की बात नही समझ पाते। अंगरेजी बहुत कम लोग जानते हैं। और करोडों जनता अंगरेजी से इतनी दूर है कि अंगरेजी से भी एक दूसरे को समझने का काम नहीं चल सकता। धारा सभाओं में जिस पार्टी के ह्विप ने जिधर कह दिया उधर हाथ उठ गए। पार्टी का फैसला मानना जरूरी होता है, लेकिन पार्टी के मेम्बर अक्सर एक दूसरे की बात नहीं समझते। मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक फ्रांसीसी रईस ने किसी रूसी स्त्री से शादी की। वह विवाह आदर्श विवाह समझा गया, क्योंकि दोनों में से कोई दूसरे की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझता था। वह न एक दूसरे से बहस कर सकते थे न झगड़ सकते थे। क्या हमारे देश के दक्खिन की सब संस्थाएं इसी तरह की आदर्श संस्थाएं होनी चाहिए। विधान सभा ने इसके लिए एक कमीशन बनाया था। कमीशन की रिपोर्ट हमें बहुत मदद दे सकती है। मैं मानता हूं कि इस मामले में विधान सभा और सरकार दोनों के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं। भगवान ने हमें सूझ-बूझ कठिनाइयों को दूर करने और गुत्थियों को हल करने के लिए ही दी है उठाकर रखने के लिए नहीं। इसमें जरा भी शक नहीं कि अगर थोड़ी सी हिम्मत, हमदर्दी और सूझ-बूझ से काम लिया जावे तो ऐसे हल

निकाले जासकते हैं जिनसे भाषाई सुवे चाहने वालों की उचित इच्छा पूरी हो सके। यह आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, बल्कि तीस बरस के ऊपर का है। न यह साम्प्रदायिक या किसी खास जाति के लोगों का है यह आन्दोलन राष्ट्रीय है, रचनात्मक है और लोकतन्त्री है। हमारी सरकार को एक-न-एक दिन और वह भी जल्दी ही ऐसे इलाकों की कठिनाइयां हल करने के लिए जिनमें दो भाषायें बोली जाती हैं, सूवों की नए सिरे से हदवन्दियां करनी पड़ेंगी। सीधी या गोल लकीरें खींच देने से ही कोई देश नहीं बन जाता और न नदियों और पहाड़ों से कोई राष्ट्र बन जाता है। हर देश और हर राष्ट्र में तरह-तरह के लोग होते हैं जिनकी उन्नति तारीखी रिवायतों, वहां की धरती, पहाड़ और नदियों, आब-हवा और राजनीति सब पर निर्भर होती है। भाषा ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जो उन्हें बांधे रखती है। कल्चर भाषा से पैदा होती है और उसके बाद आती है रीति-रिवाज, आदतें। रहन-सहन उसके भी बाद आते हैं। इस तरह हर राष्ट्र में बहुत से उपराष्ट्र होते हैं जिनकी अलग २ कल्चरें मिलकर वह संगम बनाती है जिसे राष्ट्र की कल्चर कहा जाता है। इन्द्र धनुष के रंग सात अलग-अलग दिखाई देते हैं। साइन्स वाले कहते हैं कि उसमें चार हजार रंग अलग देखे जा सकते हैं। पर वह सब रंग एक दूसरे में रल-मिल जाते हैं और अलग रहते हुए भी मिलकर एक सुन्दर धनुष बना देते हैं। लगभग यही हाल भाषाओं का है।

सूबों की हदबन्दी हो जाने के बाद भी जिन इलाकों में दो भाषायें मिलती हैं वहां हमें कम तादाद वालों का ध्यान रखना होगा। हमें उनके साथ इस तरह का बरताव करना होगा कि वह सारे देश को अपना देश कह सकें। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी होनी चाहिए जैसा अनगिनत रुखों वाला हीरा जिसमें हर सूबे और हर कल्चर का रुख अपनी अलग दमक दिखाता रहता है। एकता का मतलब एक रंगीपन नहीं है, बल्कि रंग-रंग के फूलों को मिलाकर उनमें सुन्दरता पैदा करना असली एकता है। बंगाल की भावुकता, उड़ीसा वालों का कला-प्रेम, आंध्र के लोगों के खुले दिल, तामिल नाड के लोगों की सीधी-सच्ची बातें, केराला की सफाई और करनाटक का संगीत, महाराष्ट्र का मनतक, गुजरातियों की व्यापार बुद्धि, बिहारियों की सादगी और पंजाबियों की मरदानगी, ऐसे यू० पी० की कुछ मिली-जुली चीजें सब मिला कर ही हिन्दुस्तानी सभ्यता की तसवीर बनती है और तब

हमें पता चलता है कि एकता का मतलब बेजान एकरंगीपन नहीं है बल्कि अनेक रंगों का सुन्दर ताना-बाना तय्यार करना है।

इसीसे मिलता-जुलता सवाल चीफ कमिश्नरों के सूबों का है। इन सूबों के लोग यह चाहते हैं कि स्वराज और लोकराज का पूरा फायदा हमें भी पहुँचे। विधान सभा की कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। मसलन् अजमेर के लोग अगर चाहे तो आगे चलकर राजस्थान में मिल सकते हैं। कुर्ग को वहां के लोग जिधर चाहें इधर-या-उधर मिलना पड़ेगा, पर अभी तो दिल्ली को पक्के तौर पर लैंफिट-नैन्ट गवरनरी सूबा बना देना चाहिए और अजमेर और कुर्ग के साथ भी जब तक कोई आखरी फैसला न हो यही करना चाहिए। कुछ दोस्तों की राय है कि इन सवालों को हल तो करना है पर अभी इसमें बहुत पेचीद-गियां हैं, इसलिए उन्हें अभी नहीं छेड़ना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि हमारे जैसे राष्ट्र का जो आजाद होने पर अपना नए सिरे से संगठन करना चाहता है क्या कोई सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें पेचीदगियां न हों? यह दलीलें दिमागी काहिली की निशानी है। राष्ट्र की गुत्थियोंको इस तरह एक दूसरे के बाद लाईन में खड़ा नहीं किया जा सकता कि एक-एक की बारी आती जाय और उसे सुलझाते जायं। फ्रांस और गोआ के इलाकों को हिन्द युनि-यन में शामिल करना है। सैंकड़ों रियासतों को मिलाना है। क्या जब एक काम हो जाय तभी दूसरा शुरू किया जा सकता है? इस तरह के बहुत से काम हमने साथ-साथ किए हैं और कर रहे हैं। मुझे मिसालें देने की जरूरत नहीं है। जब तक टले टला देने से बुरा काम अच्छा नहीं हो जायगा और जो काम अच्छा है उसे टलाया ही क्यों जाय? इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि हिम्मत के साथ इन कामों को हाथ में ले और देश-भर में सच्चे लोकराज के रास्ते से सब रुकावटें दूर करने की तरफ लग जाय।

हमारी सरकार ने इन सोलह महीने में बहुत कुछ किया है। जो कुछ उसने किया है उस पर किसी भी सरकार को अभिमान हो सकता है। उसने पहाड़ जैसी कठिनाइयों को अपने सामने से हटा दिया है। बड़ी-बड़ी गुत्थियों को हल कर डाला है। मुल्क से गरीबी दूर करने और खुशहाली कायम करने के लिए उसने कदम बढ़ाये हैं। मंहगाई को दूर करनेके लिये उसने जो तजवीजें की हैं उनसे बहुत बड़े नतीजे निकलें या न निकलें पर

की राय है कि इस मामले में सूबों की सरकारें जो कुछ अपने-अपने दायरों में कर सकती हैं उन्हें फौरन करना चाहिए ।"

दिल्ली की केन्द्रीय धारा सभा ने हाल के महीनों में इस बारे में जो कुछ किया है वह हम सबको मालम है । इससे पहले की सरकारें इस मामले में आम तौर पर जिस बेपरवाही से काम लेती थीं वह अब नहीं रही । कांग्रेस गवर्मेन्ट मानती है कि मजदूर या उसकी मेहनत कोई सौदा करने की चीज नहीं है । मजदूर के बिना दुनियां का कोई व्यापार, कोई धन्धा नहीं चल सकता । मजदूर की अपनी अहमियत और उसकी अपनी शान है जिसे मानना और बनाए रखना दुनियां का फर्ज है । इसी बात को सामने रखकर मजदूर विभाग के मन्त्री ने सन् १९४६ में पांच बरस की एक योजना बनाई थी । इस योजना का मतलब यह था कि दुनियां के सबसे उन्नत देशों में जो नए-नए कानन मजदूरों के बारे में जारी हैं उन्हीं के ढंग पर इस देश के मजदूरी कानूनों को बदला और ढाला जाय, उसी तरह के नए कानून बनाए जांय, मजदूरों की शिकायतों को दूर करने और उनके झगडों को तय करने के लिए सब जगह एक-से ढंग बरते जाय, उनके काम करने और रहने-सहने के तरीकों को ऊपर उठाया जाय और आम मजदूरों और खासकर कोयले की खानों में काम करने वालों की हालत में बडे-बडे पैमा पर सुधार किए जायें, इत्यादि ।

१९४७ का इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४८ का मिनियम वेजज ऐक्ट, १९४८ का फैक्टरीज ऐक्ट, सन् ४८ ही का कोलमाइन्स प्रौविडेण्ट फण्ड एण्ड बोनस स्कीम्स एक्ट, इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट इत्यादि बडी जल्दी-जल्दी एक दूसरे के बाद पास किए गए हैं । इनमें से कुछ कानूनों को देश ने मजदूरों के अधिकारों का चार्टर कह कर उनका स्वागत किया इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को अमल में लाने के लिए जो-जो कार्रवाइयां की गई हैं उनमें से मजदूरों और मालिकों के झगडे शान्ति से और हंसी खुशी से तय होने की आशा है ताकि हडतालों और तालाबन्दियों से देश का जो नुकसान होता है वह न हो और पैदावार न रुके ।

इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेन्स एक्ट पर भी सरकार अमल कर रही है। इससे मजदूरों को बडी मदद मिलेगी । अनुभव के बाद इसी तरह के और

भी कानून बनाए जायंगे। नये फैक्टरीज एक्ट से भी बहुत सी पीढ़ियों की मुसीबतें कट जायंगी। २५ लाख मजदूरों के उससे बहुत से दुःख दूर हो जायंगे।

बिहार, सी. पी. और पश्चिमी बंगाल की कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ५०००० मकान बनवाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा कारखानों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के लिए दस लाख मकान और बनाने की योजना है, हमारा मजदूर विभाग एक और बहुत बड़ी योजना चला रहा है। नेशनल इम्पलाईमेन्ट सर्विस के नाम से इसकी जगह-जगह शाखायें होंगी जिसमें मजदूरों को तरह-तरह के काम सिखाने, तकनीक सिखाने और बेरोजगारों को रोजी दिलवाने के केन्द्र खोले जायंगे। उद्देश्य यह है कि इतने बड़े देश का कोई आदमी और कोई हाथ बेकार न रहे और सबका ठीक-ठीक उपयोग हो सके।

हमारा देश खेतीहर देश है इसलिए यहां किसान की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी तुरन्त ध्यान देना है। दिल्ली सरकार और सूबाई सरकारों ने मिलकर इस बारे में खोज और तैयारी शुरू कर दी है। सन् १९४८ के मिनिमम वेजिज़ एक्ट के अधीन यह भी देखा जा रहा है कि खेतीबाड़ी के काम करने वाले मजदूरों को भी पेट-भर से कम मजदूरी कहीं न मिले। किसानों और किसानी काम करने वाले मजदूरों की दशा को हर तरह सुधारना और उन्हें ऊँचा ले जाना राज का और हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। यह बहुत बड़ा है और पेचीदा और कठिन भी है। पर हमारी मजदूरों के लिए इससे बड़ा और ज्यादा जरूरी कोई काम भी नहीं।

हमारे मन्त्रिमण्डल के मजदूर विभाग ने थोड़े-से दिनों में इन सब बातों में जो कुछ कर दिखाया है वह कम नहीं है। पर अभी बहुत करना है। पिछले साल दिल्ली में जो एशियन रीजनल कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें पता चला कि मजदूरों के मामले में हिन्दुस्तान एशिया के देशों में सबसे बढ़ा हुआ है। हमारे देश में इस बारे में चुपचाप एक इतनी बड़ी क्रान्ति हो रही है और एक ऐसा नया युग आ रहा है जिसमें किसी आदमी का किसी भी दूसरे की मेहनत से बेजा फायदा उठाना असम्भव होगा।

गांव की नई रचना

फिर भी हमें यह मानना पडेगा कि खेतीवाडी और गांवों के किसान की तरफ जितना ध्यान हमें देना चाहिए उसका पासंग भी अभी हम नहीं दे पाये। शहरों और कारखानों के मजदूर ज्यादा बोल लेते हैं। उनकी तरह से दूसरे भी बोलते रहते हैं। पर गांवों के मजदूरों, किसानों और कारीगरों की आवाज अव्वल तो उठती कम है और उठती भी है तो बेढंगेपन से। कारखानों के २०-३० लाख मजदूरों की तरफ, अंग्रेजी राज के दिनों में भी सबका ध्यान गया पर गांव के गरीबों की तरफ जिनकी गिनती कहीं अधिक है जितना ध्यान जाना चाहिए नहीं गया। अंग्रेजों को तो उधर ध्यान देने में अपना कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। उलटी अपनी हानि ही दिखाई दी।

सच यह है कि पिछले सौ बरस के अन्दर अंग्रेज हाकिमों का सारा ध्यान उन महकमों की तरफ रहा जिनकी मार्फत उन्हें लगान और टैक्स वसूल होते थे। वही उनका फौलादी ढांचा था। पुलिस और मजिस्ट्रेट पुश्तपनाह थे। जिन कामों से राष्ट्र की रचना हो सकती थी यानी हमारे लाखों गांव, जनता का स्वास्थ्य, खेती, डंगरों का इलाज तालीम, उद्योग-धन्धे, और सहकारी संस्थाये इनकी तरफ न केन्द्रीय सूबाई सरकारों का का काफी ध्यान लगा था न हमारी उन राजनीतिक संस्थाओं का ध्यान था जो उस समय इन सारी बातों को छोटी समझती थीं और जिनकी सारी शक्ति राजनीतिक आजादी हसिल करने में लगी हुई थी। १५ अगस्त सन् १९४७ को नए हिन्द का जन्म हुआ। राजनीतिक आजादी के साथ २ देश की नई समाजी और आर्थिक रचना की तरफ हमारा ध्यान गया। हमारे गांव का रंगरूप जो ३० बरस पहले था वह अब नहीं रह गया है। दोनों महायुद्धों ने हमारे सारे जीवन को जडों से हिला दिया है। आज हमारा सबसे बडा सवाल खाने की कमी है। आबादी के बढ़ने और बरमा के हिन्दुस्तान से अलग हो जाने के कारण ये कठिनाई और बढ गई है।

पिछले तीस बरस के अन्दर हिन्दुस्तान भर में कई सरकारों ने और कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने गांव की नए सिरे से रचना के लिए कई तजवीजें बनाई और नमूने के नये गांव भी कायम किये। प्राइवेट संस्थायें अधिकतर एक-एक आदमियों की संस्थायें थीं। वह एक आदमी हट गया या

मर गया तो संस्था भी खतम हो गई। सरकारी योजनायें, जैसे पंजाब में ब्रेन साहब की योजना इसलिए नाकाम रही क्योंकि उन्होंने हमारे गांव वालों के ऊपर नये पच्छिमी ढंग को थोपना चाहा और गांव वालों ने कभी उन योजनाओं को खुशी से नहीं अपनाया न उनमें गांव वालों को अपना फायदा दिखाई दिया। कुछ सरकारी अफसरों ने डंडे हाथ में लिए, नमूने के गांव बनाये। वह अफसर कहीं दूसरी जगह बदल गया और गांव फिर ढेर हो गए। दूसरे गांव वाले भी उस नमूने की नकल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि बिना डंडे और सरकारी शान के उस तरह का काम चल ही नहीं सकता था, न कहीं से मसाला मिल सकता था। यह सब तो होता रहा फिर भी आज देश के सब लोग गांव की हालत सुधारने की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। नई समाजी कारबारी और आर्थिक-खोज और सर्वे भी जगह-जगह हुई हैं, योजनायें बनी हैं, रिपोर्टें तय्यार हुई हैं। गांव की जिंदगी के सब पहलुओं की खासी अच्छी चर्चा की गई है, कांग्रेस की नेशनल प्लॅनिंग कमेटी ने छब्बीस जिल्दें तैयार की हैं जिनमें गांव की जिंदगी की अच्छी तसवीर मौजूद है। जनता की तन्दुरुस्ती के बारे में भी कमेटी की चार जिल्दें और तालीम पर सार्जेंट रिपोर्ट भी मौजूद है। और भी बहुत-सी कीमती रिपोर्टें खेतीबाड़ी पर, उद्योग-धन्धों पर, बाजारों पर और इसी तरह की चीजों पर मौजूद हैं। इनमें से किसी-किसी पर कहीं-कहीं थोड़े-बहुत तजरबे भी हो रहे हैं। अभी इन पर और बहुत अधिक तजरबों की जरूरत है।

अनाज और खाने की चीजें ज्यादा पैदा करने की, उद्योग-धन्धे की और पानी से सस्ती बिजली बनाने की ओर भी योजनायें हैं। दामोदर नदी की योजना, रामचन्द्र सागर की योजना, कोसी और हीरा कुण्ड की योजना, केन्द्रीय और सूबाई सरकारों की तरफ से चल रही हैं। खासकर नदियों के पानी से शक्ति पैदा करने की अनेक योजनायें देश-भर में चल रही हैं। बहुत-सी जमीन ऐसी थी और है कि जो बहुत उपजाऊ है, और मामूली बारिश से, या नई योजनाओं के जरिए अधिक उपजाऊ हो सकती है, जो मलेरिया के कारण निकम्मी पड़ी है। इस तरह की जमीनों को ठीक करके काम में लाया जा सकता है। यू० पी० की तराई में यहां काम चल रहा है। इस तरह की जमीनों और पानी से शक्ति पैदा करके अगले १०-१५

वरस के अन्दर बडी-बडी आशायें की जा रही हैं। कहा जाता है कि इनसे हमारी अन्न की पैदावार बहुत बढ़ जायगी, उद्योग-धन्धों के लिए आसानियां हो जायगी, लोगों के रहने-वसने के अच्छे इन्तजाम हो जायंगे और सारे देश को लाभ होगा।

यह सब बडी-बडी योजनायें हैं। देश देखना चाहता है कि १०-१५ वरस में इनके जरिए क्या कुछ करके दिखाया जा सकता है। पर हम २० वरस तक इन्तजार में नहीं बैठ सकते। हमारे पास जो कुछ आदमी, धन और साधन हैं उनकी मदद से हमें अपने लाखों गांवों के लिए अभी भी कुछ न कुछ करना है। हिन्दुस्तान के गांव वालों से यह नहीं कहा जा सकता कि देश को आजादी तो मिल गई पर गांव वालों की आर्थिक आजादी के लिए अभी दस बीस वरस और इन्तजार करना पडेगा। गांव वालों को तो अभी इस समय खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपडे और रहन-सहन के लिए भले लोगों के-से साधनों की जरूरत है। यह कैसे हो?

अब जरा जिस तरह पिछले सौ वरस के अन्दर गवर्नमेंट ने अपने महक्मों का संगठन किया उस पर निगाह डालिए। सबसे पहले लगान वसूल करने का महकमा लीजिए। सारे देश को कई सूबों में बांटा गया, सूबों को जिलों में और जिलों को तहसीलों में। हर तहसील में एक तहसीलदार। तहसील की लगान वसूली की इकाई थी। हर तहसील या तालुके में एक लाख से दो लाख तक आबादी थी और एक सौ से दो सौ तक गांव। फैलाव सौ मुरब्बा मील से लेकर दो सौ मुरब्बा मील तक। हर जिले में १० से २० तक तालुके और हर जिले की औसत आबादी बीस लाख। तहसील भी एक तहसीलदार के लिए बहुत बडी चीज समझी गई तब एक एक तहसील में ५-५, १०-१० फिरके बनाये गए और हर फिरके में एक-एक रेविन्यू इन्सपेक्टर रखा गया। हर गांव में एक-एक मुखिया या चौकीदार इस तरह गांव से लेकर ऊपर तक लगान वसूली का पूरा संगठन कर लिया गया। उस सारे संगठन से गांव वालों को कोई फायदा नहीं पहुँचा। उनके थोडे बहुत फायदे के अंग्रेजी राज में ६ ही महकमे थे—तन्दुरुस्ती का महकमा खेतीबाडी, जानवरों का इलाज, तालीम, उद्योग-धन्धे और सहकारी विभाग। इन सब महकमों का पूरा संगठन १९१९ में जाकर पूरा हो गया जबकि इन सबमें सूबों के लिए डायरेक्टर और जिलों और तहसीलों के लिए

अलग-अलग अफसर बनाये गये। लेकिन तहसील से नीचे इन महकमों का कोई फैलाव नहीं था। इनके सब अफसर अहलकार या नौकर तहसील तक ही रह जाते थे। डायरेक्टर लोग अपनी गश्ती चिट्ठियां जिला अफसरों को भेजते थे और जिला अफसर तहसील अफसरों को। उसके नीचे उनका कोई काम न था। इन सब महकमों की सबसे नीचे की कडी यानी तहसील और गांव के बीच की कडी सबसे मजबूत कडी होनी चाहिए थी पर यह वह कडी ही नदारत थी। एक-एक तहसील के दो-दो सौ गांव इतनी दूर तक फैले होते थे और आने जाने के साधन इतने कम थे कि तहसील अफसर एक-एक गांव को एक दिन देकर पूरी तहसील का दौरा भी न कर पाता था कि उसको बदल दिया जाता था और उसकी जगह पर आये अफसर को नये सिरे से काम करना पडता था। ये अफसर लोग गांव में जाकर गांव वालों को जमा करके केवल उनसे बातें करते थे। बातें करने के बाद गांव वालों से पूछा जाता था कि कोई शिकायत तो नहीं है, तो वे हमेशा जवाब देते थे कि हमारे गांव में पीने के पानी के कुएं की कमी है। अफसर निराश होकर उनसे यह कहकर चला आता था कि मैं आपकी जरूरत ऊपर के अफसर तक पहुंचा दूंगा। दूसरा अफसर आता–फिर यही बात होती और यही जवाब मिलता था। सच यह कि इस काम के लिए तहसील की इकाई बहुत बडी इकाई थी। दूसरी कमी यह थी कि इन छः महकमों में आपस में कोई सम्बन्व नहीं था। तन्दुरुस्ती का अफसर आता था तो गांव वालों को समझाता था कि खाद के ढेर तुम्हारी तन्दुरुस्ती के लिए बहुत बुरे हैं इनसे मक्खियां पैदा होती हैं और मक्खियों से बीमारी बढ़ती है। उसके बाद खेती के महकमों का अफसर आता था। वह गांव वालों से कहता था कि खाद तुम्हारी खेती के लिए बहुत उपयोगी चीज है और उसे अच्छी तरह जमा करो एक करो। एक ही गवर्नमेंट दोनों अफसरों को तनख्वाह देती थी पर बेचारा गांव वाला समझ नहीं पाता था कि किसका कहना माने। अगर यह दोनों मकहमे मिलकर काम करते तो वे गांव वालों से कहते कि खाद का कम्पोस्ट तैयार करो जिससे मक्खियां भी न हो और खाद का खाद बना रहे।

अमरीकी पादरी स्पेन्सर हेंच ने कई साल तक ट्रावनकोर के गांवों में काम करने के बाद एक किताब लिखी है "Up From poverty" उस

किताब में उन्होंने लिखा है कि सरकार के छः अलग-अलग महकमे साल में छः वार अलग-अलग आकर गांव वालों की ६० गज जमीन की झोंपडी की देखरेख करते हैं। एक आता है गांव के बच्चों के चेचक का टीका लगा जाता है, दूसरा आता है गांव के डंगरों को सुई चुभो जाता है, तीसरा आता है और गांव वालों को लोहे के हल और वीज वगैरा देने का वायदा करता है। पर गांव वालों की जो सबसे पहली जरूरत है, पानी पीने का कुआं सडक और स्कूल उसे कोई पूरा नहीं करता।

इन छओं महकमों में ऊपर तो हैं बड़े-बड़े दफ्तर और बड़ी-बड़ी तनख्वाहों वाले नौकर और विभाग और उप विभाग, पर नीचे इनके पैर दिखाई नहीं देते, लगान के महकमे की तरह इन्हें नीचे फैलाना और ठीक करना जरूरी है।

भोर कमेटी ने देश-भर में तन्दुरुस्ती की हालत को अच्छी तरह देखने-भालने के वाद अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि—इस तन्दुरुस्ती महकमे के नीचे बहुत से छोटे-छोटे दफ्तर या छोटी इकाइयां होनी चाहियें, और हर दफ्तर का सम्बन्ध दस हजार से लेकर बीस हजार आदमियों तक होना चाहिए। इस तरह की पन्द्रह या पच्चीस इकाइयों को मिलाकर उनके ऊपर एक और दफ्तर होना चाहिए और हर जिला तन्दुरुस्ती विभाग के अधीन इस तरह के तीन से पांच तंक दफ्तर होने हर छोटे-बड़े दफ्तर में एक तन्दुरुस्ती केन्द्र होना चाहिए जिससे तन्दुरुस्ती के बारे में सारी चीजें जनता में फैलाई जायं। भोर कमेटी ने एक बड़ा प्रोग्राम ३० से ४० वर्ष तक का रक्खा है और एक छोडा प्रोग्राम पांच-पांच साल के दो टुकडों में दस वरस का। भोर कमेटी ने यह भी कहा है कि इन छओं महकमों में एक महकमे के काम से दूसरे महकमे के काम में मदद मिलती है। इसलिए छओं काम साथ-साथ चलने चाहिए।

कमेटी ने अपनी पूरी योजना दी है जिसके अनुसार हर गांव में छओं महकमों का कार्य एक साथ एक ही जगह से चल सके और किसी भी गांव का कोई भी रहने वाला वहुत-सेवहुत ५-६ मील चलकर किसी केन्द्र तक पहुँच सके। हर केन्द्र में गांव का एक अस्पताल होगा जिसमें रोगियों के रहने की जगह होगी, टीके का प्रवन्ध होगा, क्विनीन जैसे खास-खास दवायें मिल सकेंगी, फर्स्ट एड का सामान मिल सकेगा, डाक्टर और

दाइयां रहेंगी, खाद और बढ़िया बीज मिलेंगे, आदमी और पौधों की बीमारियों के लिए कीड़ेमार दवाओं का प्रबन्ध रहेगा, मलेरिया का, प्लेग, का जानवरों के इलाज का इन्तजाम रहेगा, सहकारी बैंक रहेगा, सहकारी स्टोर रहेंगे, जिनमें गांव वालों की जरूरतों की सब चीजें मिल सकेंगे गांव के धन्धे और दस्तकारियां सिखाने का इन्तजाम होगा, बालकों की शिक्षा का इन्तजाम रहेगा, नमूने का स्कूल रहेगा, गांव के लिए रेडियो रहेगा, डाकघर रहेगा, पुलिस की चौकी रहेगी और पंचायत का दफ्तर रहेगा। इसमें काम करने के लिए कुछ सरकारी नौकरों में से आदमी लिए जा सकते हैं और यह कानून बनाया जा सकता है कि डाक्टरी, इन्जीनियरी, पशु चिकित्सा, खेतीबाड़ी और टीचर्स कालिजों से निकलने वाला हर लड़का क्रम से एक साल से लेकर तीन साल तक इस तरह के गांव केन्द्रों में काम करके राष्ट्र की सेवा में हिस्सा ले। इन केन्द्रों के खर्च के लिए वहीं के लोगों से चन्दा या सामान वसूल किया जा सकता है। लोकल बोर्डों, सूबाई सरकारों और गांधी मेमोरियल फण्ड या कस्तूरबा मेमोरियल फण्ड जैसी प्राइवेट संस्थाओं से भी मदद ली जा सकती है। केन्द्र के इन्तजाम के लिए गांवों ही के चुने हुए आदमियों और जिला या तहसील के उन-उन कामों के विशेष जानकारों की इन्तजामी कमेटी बनाई जा सकती है।

इस तरह के केन्द्र हमारे गांवों को शहरों के साथ जोड़ देंगे और फिर उन बीच वालों लोगों की जरूरत नहीं रहेगी जिनके कारण आजकल गांव वालों के ऊपर कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं और गांव वालों का रहन-सहन और गिरता चला जा रहा है। इन्हीं केन्द्रों के जरिए ऊपर की योजनायें हर गांव तक पहुंच जायंगी और देश की पैदावार बढ़ सकेगी। हमारे तिजारत के केन्द्र और एक दर्जे तक कल-कारखानों के केन्द्र शहर हो सकते हैं पर हमारी खाने कपड़े वगैरह की अधिकतर जरूरतें गांव के धन्धों से और गांव की खेती और कच्चे माल की पैदावार से ही पूरी होनी चाहिए और पूरी होगी। अब हमें जितनी जल्दी हो सके गांवों का संगठन करना चाहिए और देश के ७ लाख गांवों तक आजादी का असली फायदा पहुंचाना चाहिए। शहरों की आबादी कुल आबादी का २० फीसदी है। पर ८० फीसदी डाक्टर इन्हीं २० फीसदी आबादी में रहते हैं और बाकी २० फीसदी ८० फीसदी आबादी में रहते हैं। ऐसे ही हमारे गांव में तीस हजार औरतों

पीछे या दस हजार माताओं पीछे एक दाई होती है और डाक्टर भी मुश्किल से एक । हमें जल्दी से जल्दी इधर ध्यान देना चाहिए। इस कमी को पूरा किए विना गांव के फिर से संगठन का काम नहीं चल सकता । न्याय के लिए पंचायतों की जरूरत है, जंगलों की हिफाजत की जरूरत है । हर गांव में पीने के लिए अच्छा पानी मिलना चाहिए आसानी से और ठीक शर्तों पर उधार मिलना चाहिए, गांव के उद्योग-धन्धों को खूब जगाना औरवढाना चाहिए, खेती के काम को खूब तरक्की देनी चाहिए, साल में कई-कई फसलें हो सकें इसके लिए मिट्टी का इम्तहान होना चाहिए, नहरों और रजवाहों को वढाना चाहिए, ऐसी छोटी २ मशीनें-जो हर घर में चल सके और जिनकी गांव में मरम्मत हो सके वननी चाहिए, और हर झोंपडे में विजली पहुँचनी चाहिए ।

गांव वालों को ऊँची-से-ऊँची तालीम देने का सवाल भी वडा जरूरी सवाल है । जिस तरह हमें छोटी मशीनों और पंचायतों को गांव में पहुंचाना है उसी तरह तालीम, प्रयोगशालायें और उडानविद्या सिखाने के केन्द्र भी होने चाहिए । रसायन-विद्या यानी केमिस्ट्री और अमली साइन्स वच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाने के लिए भी थोडी-थोडी दूरी पर गांव में इन्तजाम होना चाहिए ।

मेरठ के पास दौराला गांव में "विज्ञान-कला-भवन" नाम की एक ऐसी संस्था है कि जहां मिडिल पास लडकों को रसायन-विद्या, पदार्थ-विज्ञान और उच्च गणित शास्त्र की शिक्षा हिन्दुस्तानी में ही दी जाती है।

महात्मा गांधी ने जो असली विरासत छोडी है उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कई ऐसे कार्यकर्त्ता कर रहे हैं जिन्होंने अपना सारा समय कार्य-कौशल्य महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और शिक्षाओं के आगे वढाने और प्रचारित करने में लगाया है। कई संस्थायें और आश्रम ऐसे हैं जो महात्मा गांधीजी के जीवन-काल में ही स्थापित हुए थे और जो सत्याग्रह की विद्युत शक्ति के उत्पादक केन्द्र वने रहे हैं । इन आश्रमों को चलाने वाले अपने मालिक के महा प्रयाण के कुछ ही दिन वाद श्री विनोवा भावे और श्री राजेन्द्र वावू के नेतृत्व में वर्धा में जमा हुए थे, और उन्होंने गांधीवाद की पताका को देश भर में फहराते रहने का संकल्प किया। फलस्वरूप सर्वोदय समाज की स्थापना हुई जो "ग्राम सेवा" द्वारा गांधीवाद को जीवित रखेगा । इसका भी संगठन काफी लचीला और विस्तृत है ।

राजनीति के शोरशार में हमें अपने गांव की दस्तकारियों की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था उसका पासंग भी नहीं दे सके। कल-कारखानों में बहुत ही कम आदमी खप सकते हैं, खेती में उससे बहुत ही ज्यादा खपने चाहिए, पर खेती से आमदनी कम होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने पुराने तरीकों पर अपनी दस्तकारियों को जगाना और बढ़ाना चाहिए।

जापान में हर घर एक कारखाना है। तोकियो शहर के अन्दर ५०००० ऐसे कारखानें हैं जो एक-एक या दो-दो कमरों में चलते हैं। अकेले बांस से जापानी १२० अलग-अलग तरह की सुन्दर-सुन्दर चीजें बनाते हैं जिनमें बड़ी होशियारी और कला की जरूरत पड़ती है। सन् १९३७ में वहां २५ फी सैकडा किसान खेती के अलावा कोई-न-कोई अलग दस्तकारी करते थे। सन् १९४३ में ६५ फीसदी से ऊपर किसान कोई-ना-कोई दस्तकारी भी जरूर करते थे। ५०००० से ऊपर छोटे २ कारखानें वहां खेतों के अन्दर हैं जो खेती के साथ २ चलते हैं। यह गिनती बराबर बढ़ती जा रही है। देहाती दस्तकारियां सिखाने का काम सरकार खूब करती है। खेती से सम्बन्ध रखने वाली दस्तकारियां किसानों को मुफ्त सिखाई जाती हैं। ये दस्तकारियां सात साल की तालीम पाये हुए किसान लडकों और लडकियों को मुफ्त सिखाई जाती हैं। गांव में किसी मजदूर की जरा-सी भी शक्ति निकम्मी नहीं जाती और शहरों में मजदूरों और कारीगरों की भीड नहीं होने पाती। खेतों में पैदा हुआ कच्चा माल वहीं-का-वहीं चीजें बनाने में काम में आ जाता है। जिससे किसानों की आमदनी खूब बढ़ जाती है। जापान के गांव बड़े खुशहाल गांव हैं।

जापान की सरकार ने पिछले महायुद्ध के बाद जून सन् ४८ में अपने यहां के गांवों का फिर से संगठन बनाने के लिए योजना निकाली है। उनका कहना है कि इसके बिना राष्ट्र का फिर से संगठन नहीं हो सकता। इसके लिए वहां की सरकार ने नीचे लिखे नियम बनाये हैं:—

(१) जो दस्तकारियां योजनायें दी गई हैं उनके कारखाने गांव में, समुद्र के किनारे, पहाडी इलाकों में और हरी-भरी घाटियों में ही होने चाहिए जहां कच्चा माल वहीं-का-वहीं मिल सके।

(२) जितनी पूंजी की जरूरत हो वह सहकार (cooperation) से गांव वालों से ही लेनी चाहिए ।
(३) मजदूर जहां तक हो सके आसपास से लेने चाहिएं ।
(४) जितनी किसी चीज की मांग वढाई जाय उतने कारखाने वढाये जा सकते हैं ।
(५) चीजें अच्छी वननी चाहिए और लोगों के शौक के अनुसार तरह २ की वननी चाहिए ।
(६) सरकार के दूसरे विभागों से इन दस्तकारियों को पूरी मदद मिलेगी ।
(७) सेंट्रल अग्रेरियन वंक से इन दस्तकारियों को पूंजी की मदद मिलेगी ।

इस तरह की दस्तकारियों से छोटे-छोटे घरों और कुटुम्बों का सुख, उनकी खुशी और उनकी पवित्रता वनी रहती है । लोग रोजी भी कमा लेते हैं, अपने हाथों और अपने आंखों को कला भी सिखा लेते हैं और अपने दिल के अच्छे और ऊंचे भावों को भी अपनी वनाई हुई चीज में प्रगट कर पाते हैं । इस तरह की दस्तकारियां आदमी की आन और उसकी आत्मा को ऊंचा करती हैं । आजकल के योरप की हवा में लोग काम चलाने को ज्यादा देखते हैं, पर काम चलाने के साथ-साथ कला और सुन्दरता मिलकर चलनी चाहिए । ऐसी हालत में कोई चीज निकम्मी नहीं जाती । रोजगार वेहद वढ जाते हैं । कचरा दौलत वन जाता है । दर्जी के यहां कतरनें और वढ़ई के यहां की छिपटियां नये रूपों और नये रंगों में नई शानदार चीजों के लिए कच्चा माल बन जाती हैं । हर घर कारखाना हो जाता है । समुद्र के किनारे की सीपियों और भोगों से लेकर नारियल तक और फेंकी या टूटी हुई चीजों के टुकडों तक सवके दिन फिर जाते हैं । गांव की सारी पूंजी काम में लगी रहती है । सबको रोजी मिल जाती है और राष्ट्र का जीवन मालामाल हो जाता है ।

इस तरह की सब दस्तकारियां चर्खे और खद्दर ही का फैलाव है । चर्खा गांव की दस्तकारियों का राजा है । हमारे देश में चर्खा ही सत्याग्रह आन्दोलन की धुरी था । आगे भी हमारे देश के सच्चे आर्थिक इन्कलाव और सुधार की वुनियाद चर्खा ही होगा । जिस चर्खे के सहारे हमने अपनी

आजादी हासिल की है उसे भूलना या उससे बेपर्वाही करना हमारे लिए हर तरह खतरनाक होगा। जापान लड़ाई में हार गया पर अपनी घरेलू दस्तकारियों के सहारे वह अपने यहां की जनता को खुशहाल और जानदार रख रहा है। इन्हीं के सहारे पर वह फिर उभरने की हिम्मत रखता है। इस बारे में हम जापान से काफी सबक सीख सकते हैं।

इसलिए हमें अपने यहां की घरेलू धन्धों की तरफ पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए। अलग-अलग सूबों की सरकारों को इस बारे में मिलकर काम करना चाहिए ताकि सबकी अच्छी-अच्छी चीजें सब जगह बिकें और फैलें। इस तरह खद्दर को बढ़ाने और फैलाने के लिए हमें खास कोशिशें करनी चाहिए। दूसरे घरेलू धन्धों के लिए भी इसी तरह की कोशिशों की जरूरत है। हमारे भण्डार और नमूनाघर सब जगह होने चाहिए। देश-भर की दस्तकारियों की सूचियां बननी चाहिए। कारीगरों की गिनती होनी चाहिए। हर तरह के काम में सिखाने की संस्थायें होनी चाहिए। कच्चे माल का ठीक २ फैलाव होना चाहिए, सरकारी संस्थाओं के जरिए लोगों को आसानी से पूंजी उधार मिलनी चाहिए। नई-नई खोजें होनी चाहिए। चलती-फिरती नुमाइशें होनी चाहिए। विद्यार्थियों के डेप्युटेशन जाने चाहिए। विशेष जानकारों को और उस्तादों को एक जगह से दूसरी जगह बुलाना चाहिए। सब जगह छोटे-बड़े अजायबघर होने चाहिए। नमूनों पर और तरह २ के डिजाइनों पर किताबें और साहित्य होना चाहिए। किताबघर होने चाहिए वगैरह।

अनाज

अन्न ही जीवन है। राज्य का सबसे बड़ा फर्ज यही है कि सबको खाना-कपड़ा और रहने को मकान मिल सके। डेढ़ सौ बरस के अंग्रेजी राज के बाद यकायक हमें बताया जाता है कि हमारा मुल्क अपनी जरूरत के लिए काफी अनाज पैदा नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जितनी आबादी बढ़ती जाती है उतना अधिक अनाज हमारे यहां नहीं पैदा होता है। यह बात दिमाग को कुछ चकरा देती है।

(१) हिन्दुस्तान की कुल जमीन जिसमें अनाज पैदा होता है १९ करोड़ एकड़ बताई जाती है। इसमें से पांच करोड़ एकड़ ऐसी है जिसमें

नहरों से पानी पहुँचता है और दस करोड ऐसी है जिसमें केवल बारिश के पानी से काम लिया जाता है ।

जो नई योजनायें वन रही है उनसे पन्द्रह साल के वाद दो करोड़ सत्तर लाख एकड़ जमीन खेती के लिए और बढ़ जायगी । इन १३ साल में जितनी आवादी बढेगी इससे उसका काम चल जावेगा ।

(२) इसी सवाल को दूसरी तरह से देखें । खेती की जमीन हर आदमी पीछे आज पौन एकड़ है । हर आदमी को खाने में १७५० कैलरी मिलनी चाहिए । इस हिसाब से हर आदमी पीछे एक एकड़ जमीन से कुछ कम होनी चाहिए ।

(३) हमारे यहां बहुत सी उपजाऊ जमीन मलेरिया की वजह से निकम्मी पडी है । ऐसी जमीन दो लाख मुरव्वा मील यानी १२ करोड़ एकड़ वताई जाती है ।

इस तरह जव कि ३० करोड़ की आवादी के लिए हमें लगभग २५ करोड़ एकड़ जमीन चाहिए, हमारे पास इस समय है सिर्फ १६ करोड़ एकड़ । दो करोड सात लाख एकड १५ वर्ष में तैयार होने की आशा है, और १२ करोड एकड मलेरिया का इलाका है ।

तो फिर करना क्या चाहिए ? एक ही तरीका है । वह यह कि खाद के जरिए हम अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढावें । एक दूसरा इलाज यह है कि हम साल में अदल-बदल कर कई फसलें पैदा करें, या उस तरह की प्रोटीन फूड तैयार करें जिसे 'फूडयीस्ट' कहते हैं जैसी कि हाल में लकडी के वुरादे से और भूसे से तैयार की जा चुकी है । एक और इलाज यह भी है कि हम मिलों में धान का कूटा जाना और छिलका उतारा जाना कानून से वन्द कर दें । इस तरह का कानून तो लोगों की तन्दुरुस्ती को ठीक रखने के लिए भी जरूरी है । इससे हमें चावल भी ज्यादा मिलेंगे और चावलों के विटामिन भी नष्ट नहीं होंगे । आवपाशी का प्रवन्ध भी ज्यादह अच्छा होना चाहिए । इस वारे में हमारी सरकार के अलग २ विभाग ठीक मिलकर काम नहीं कर रहे हैं । इस तरफ हमें और सरकार को पूरा २ ध्यान देना चाहिए । मलेरिया वाली जमीन को भी हमें जल्दी-से-जल्दी ठीक कर लेना चाहिए ।

हमारी अनाज की समस्या खेती की समस्या भी है और उसी में राष्ट्र की तन्दुरुस्ती की समस्या भी मिली हुई है। हमारी कुल जमीन का दस फी सैंकडा खेती के काम में आता है। थोडी सी मेहनत के साथ हम इसे दुगुना और चौगना कर सकते हैं और फिर आसानी से केवल अपनी ही नहीं और मुल्कों की अन्न की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी कुल नदियों के पानी का केवल पांच फी सैंकडा खेती के काम में आता है। एक कावेरी नदी ऐसी है जिसका ९५ फी सैंकड़ा इस काम में आता है। अगर हम अपनी नदियों का और खुलकर खेती के लिए और बिजली की शक्ति पैदा करने के लिए उपयोग करें तो राष्ट्र की धन-दौलत सैंकडों गुना बढ सकती है। हमारी जो जमीनें केवल मलेरिया के कारण निकम्मी पडी हैं उनके बारे में सररोनाल्ड रॉस ने लिखा है—कि इस देश के जंगलों के खजानों पर दो परोंवाला पहरेदार मलेरिया का मच्छर इस तरह जम कर बैठ गया है कि राष्ट्र को उससे लाभ नहीं होने देता। इन मलेरिया वाले इलाकों की जमीन बहुत उपजाऊ है। वहां साल में ५० इंच से लेकर १०० इंच तक बारिश होती है। मट्टी अच्छी है। आबादी बहुत कम है। एक मुरब्बा मील पीछे केवल ५० से १०० तक और वह भी पुरानी नीम जंगली जातियों के लोग बडी गरीबी के साथ रहते हैं। देश में इस तरह के तीन बडे २ टुकडे हैं। एक साठ हजार मुरब्बा मील का पूर्वी घाट के बराबर-बराबर दूसरा पश्चिमी घाट के पास और तीसरा उत्तर में हिमालय की तराई में। इनमें से पहले में नदियों और झरनों का पानी बहुत है। पानी के निकास की कमी के कारण ही वहां मलेरिया बढ़ा हुआ है। पर अब हम मलेरिया को जीतने जा रहे हैं। वायनड में एक रुपया फी आदमी फी साल के कम खर्च पर मलेरिया रोका जा रहा है। इस तरह की योजनायें और जगह भी चल रही हैं। मलेरिया को खतम करके हम अपने खाने की समस्या को भी हल कर सकते हैं और राष्ट्र की तन्दुरुस्ती भी बेहद बढ़ा सकते हैं। इस तरफ पूरा पूरा ध्यान देना और जल्दी-से-जल्दी ध्यान देना हमारी सरकारों का काम है।

तन्दुरुस्ती

हमारी तन्दुरुस्ती का असर राष्ट्र के जीवन के सब पहलुओं पर समाजी, माली, राजकाजी विभागों और हमारे चलन पर बहुत गहरा पड़ता है। पर अब तक हमारी सरकारों का ध्यान उधर बहुत नहीं।

है। कितने लोगों को यह पता है कि दुनिया के सारे कीडों का वजन और सब जानवरों के वजन से नौ गुना है। दो मक्खियां, एक नर और एक मादा मिलकर अगर उन्हें जगह मिल जाय तो दो साल के अन्दर २० लाख मक्खियां पैदा करती हैं। मक्खी रात में मलेरिया फैलाती है और दिन में फैलेरिया (फ़ीलया) फैलाती है। कई जगह पीने के पानी के इन्तजाम से हैजा पेचिस और मियादी बुखार (Cholera Dysentry & Typhoid) बन्द हो गए हैं लेकिन उसी पानी की निकासी ठीक न होने की वजह से मलेरिया बढ़ गया है, जिससे बहुत ज्यादा आदमी मरते हैं। फैलेरिया भी हमारे देश में बढता जा रहा है, जिससे लाखों के बदन निकम्मे होते जा रहे हैं। हमारे घरों में चूहे हमारा हजारों मन अनाज खा जाते हैं और प्लेग फैलाते हैं। बिल्ली और कुत्ते रैबीज फैलाते हैं। मक्खियां पेचिश, हैजा, मियादी बुखार और उसके साथ २ मलेरिया और फैलेरिया पैदा करती है। इसी तरह मच्छर पिस्सू, जूं और तरह २ के जानवर और कीडे जिनमें कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं तरह २ की बीमारियां फैलाते हैं। मिल के सफेद चांवलों से बेरी-बेरी खूब फैलती है। उसे फौरन बन्द करना आवश्यक है।

एक मील पीछे न्यूजीलैंड में १० आदमी, अमरीका में १०॥ आस्ट्रेलिया में ११ और इंगलैण्ड में १२ मरते हैं। हमारे यहां एक मील पीछे २४ मरते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से हर हजार बच्चों पीछे न्यूजीलैण्ड में ३० गोद में ही मर जाते हैं, अमरीका में ४०, आस्ट्रेलिया में ३६, इंगलैण्ड में ४६ और हमारे देश में १६९। हर साल दो लाख मातायें हमारे यहां जापे में मरती हैं यानी हर हजार पीछे बीस इंगलैण्ड में हजार पीछे ४ और अमरीका में २ मरती हैं। कुल साल में हमारे यहां एक करोड मातायें बच्चे जनती हैं जिनमें से ४० लाख मातायें हमेशा के लिए अपनी तन्दुरुस्ती खो बैठती हैं। हमारे यहां ६३०० आदमियों के पीछे १ डाक्टर हैं। ४३००० आदमियों के पीछे एक नर्स है, जब कि होने चाहिए २३०० आदमियों के पीछे एक डाक्टर और ५०० आदमियों के पीछे एक नर्स। दाइयां तो बहुत ही कम हैं। डाक्टर ७५ फीसदी शहरों में काम करते हैं जबकि जरूरत गांव में ज्यादह हैं जहां की आबादी भी शहरों से ८-१० गुना है।

मलेरिया से हमारे यहां हर साल दस लाख आदमी मरते हैं और दस लाख ही कमजोर होकर दूसरे रोगों के शिकार हो जाते हैं, इस तरह असल में हमारे यहां हर चार मौतों में से एक मौत मलेरिया से होती है। फैलेरिया से मरते कम हैं पर लाखों हमेशा के लिए कुरूप, कमजोर और निकम्मे हो जाते हैं। इस पर भी सन् १९४४-४५ में तन्दुरुस्ती के सारे महकमों पर हमारी सूबाई सरकारों ने २॥ आने फी आदमी से लेकर १०॥ आने फी आदमी खर्च किया, जबकि यह खर्च होना चाहिए था कम से कम ३ रु० २ आ० फी आदमी।

शरणार्थियों की फिर बसाव

हमारी नई सरकार की बडी-से-बडी कठिनाई में से एक बडी कठिनाई शरणार्थियों के सवाल की है। यह सवाल अभी पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। मैं उन्हें शरणार्थी कहने की जगह परवासी या निर्वासित कहना ज्यादह ठीक समझता हूँ। यह लोग अपनी इच्छा से हमारी शरण में नहीं आये, देश के बटवारे से मजबूर होकर उन्हें अपने घर-बार छोड़ देने पडे। दुनियां के इतिहास में योरुप में भी और एशिया में भी, और भी बडे-बडे आबादियों के तबादले एक जगह से दूसरी जगह हो चुके हैं। पर हमारे देश के हाल के इस तबादले के सामने गिनती के हिसाब से भी और मुसीबतों की निगाह से भी, वे सब पिछले तबादले बिल्कुल छोटे और फीके दिखाई देते हैं। केवल पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में ही ४० लाख आदमी पश्चिम से पूरब को आये और ५० लाख पूरब से पश्चिम गये। लगभग ये सब लोग देश के दर्दनाक साम्प्रदायिक दंगों, मार-काट, बदलों और बदलों के बदलों से मजबूर होकर ही अपने घरों से निकले। मामूली दिनों में अगर शान्ति के साथ भी इस तरह का तबादला होता तो भी लाखों को दुख उठाना और मरना पड़ता, यहां तो हालत ही दूसरी थी।

हमारी पूर्वी पंजाब की सरकार को जन्म लिये अभी ८ दिन भी नहीं हुए थे कि उस मुसीबत का सामना करना पडा। लाखों बेगुनाह मर्द, औरत और बच्चे पूरे बढे हुए दरख्तों की तरह जडों से उखाड कर दूर फेंक दिए गए। हम यह कह सकते हैं कि हमने अंग्रेजों से अहिंसा की लडाई लडी उसी का यह नतीजा है, पर इससे दुखियों का दुख दूर नहीं हो सकता,

और मुल्क को भी उसके नतीजे भुगतने ही पडते हैं । इन सब लोगों के लिए कैम्प खोलना और उन कैम्पों में डेरों, खाने, कपडे रसोई, भण्डार बाजार, अस्पताल, पेशाब-पाखाने, जापे वगैरह-वगैरह का इन्तजाम करना बहुत बड़ा काम था और अभी तक है । इसके लिए बेहद आदमियों, रुपये और सब तरह के साधनों की जरूरत है । फिर उनको नये सिरे से बसाने और उनकी सब तरह की जरूरतों को पूरा करने का सवाल आता है।

अभी पंजाब की तरफ का यह सवाल हल नहीं हुआ कि पूरब बंगाल से पश्चिम बंगाल में लाखों के आने की खबरें आने लगीं । पश्चिम बंगाल से हर मील पीछे ७५० आदमी बसते हैं । अगर लगभग इतने ही वहां बढ जाये तो भयंकर अकाल तो पड ही गया समझो, दूसरी दर्दनाक मुसीबतें अलग रही जिनका हमें पंजाब में अनुभव हो चुका है । पर बंगाल में यह आबादी का तबादला क्यों हो ? पश्चिम की इस भयंकर गलती को हम पूरब में क्यों दोहरावें ? दोनों तरफ की सरकारों का और देश के नेताओं और काम करने वालों का फर्ज है, हम सबका धर्म है, कि इस बात की पूरी खोज करें और जिस तरह भी हो सके बंगाल में इस आबादी के तबादले को रोकें, और लाखों बल्कि करोडों को मुसीबतों से बचायें।

एक दर्जे तक हमारी आर्थिक नीति ने भी बंगाल की इस गुत्थी को और ज्यादह उलझा दिया है, उधर से इधर सरहद पार करके आने वाले माल पर हमने चुंगियां लगाई । उसके जवाब में इधर से जाने वाले माल पर उन्होंने चुंगियां लगाई । नतीजा यह हुआ कि कडवापन तो जो बढा सो बढा ही, साथ ही पूरब बंगाल में चीजें पश्चिम बंगाल से चौगुनी और पचगुनी महंगी हो गई । नतीजा जो होना था वह हुआ । लोग पूरब बंगाल से भाग-भाग कर पच्छिम बंगाल आने लगे ।

कुछ लोग इसका यह इलाज सुझाते हैं कि जितने आदमी उधर से इधर आवें उतने ही इधर से उधर भेज दिये जावें, या वहां से आने वालों के लिए उनसे जमीन ली जाय । पर ऐसे इलाजों से जाहिर है कुल भगदड बेहद बढेगी ही । यह इलाज रोग से भी ज्यादह बुरे साबित होंगे । अनुमान यह है कि आने वालों का औसत एक दिन में एक हजार से अधिक नहीं है ।

यह भी कहा जाता है, कि ढाका शहर में वहां की सरकार ने एक हजार मकान अपने काम के लिए खाली करा लिए हैं, जिससे १५०००

आदमी बेघर के हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार की यह नीति बन्द होनी चाहिए क्योंकि इससे भगदड़ बढ़े बिना नहीं रह सकती। इससे तो शक होता है कि वह लोगों को निकालना चाहते हैं हम चाहते हैं और आशा करते हैं कि हमारी यूनियन सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ बातें करके जिस तरह हो इस भगदड को रोके और लाखों करोडों बेगुनाहों को तरह-तरह की मुसीबतों से बचाए।

हमारी सूबाई सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने शरणार्थियों को फिर से बसाने और उनके दुखों को दूर करने में कोई कोशिश उठा नहीं रखी। दिल्ली सरकार ने दस करोड़ रुपया इसमें लगाया है। लेकिन यह काम थोडी देर का ही काम नहीं है। जब तक यह निर्वासी भाई यह नहीं समझेंगे कि इस राज में उनका अपना भी कोई घर है, कोई माल-मता है, उनके अपने गाय, बैल, भैंस, खेत और हल हैं, और जबतक वह यह नहीं देखेंगे कि इस फिर बसाने के काम में उनका अपना भी हिस्सा है, तब तक उन्हें सच्चा सुख और शान्ति नहीं मिल सकती। मेरी राय में इसके लिए नया शहर आबाद करना जरूरी है। शहर में हम एक दूसरे की सेवाओं के सहारे ही रहते हैं, गांव में खेत की पैदावार और दस्तकारियों से भी बडी मदद मिलती है। हिंद सरकार और सूबाई सरकारें जो कुछ कर सकती थीं, उन्होंने किया है। पर हमारे सरकारी महकमों का पुराना ढर्रा अभी बदला नहीं है। उससे काम में देरी भी लगती है और कठिनाइयां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सरकार को यह सुझाना चाहूँगा कि टी० बी० ए० की तरह की एक ऐसी संस्था कायम की जाय जो बहुत दर्जे तक खुद मुख्तार हो और जिन अनोखी और असाधारण हालतों से हम निकल रहे हैं उनमें बिना अलग २ महकमों के अडंगों के तेजी से काम कर सके

यह सब कहने के बाद मैं इस सारी कहानी के सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक पहलू पर आता हूँ। मेरा मतलब औरतों के भगाये जाने से है। इस मामले में जरा-सी भी ढील या कमजोरी गवारा नहीं की जा सकती। मैं उन त्यागी और निःस्वार्थ बहनों का बहुत बड़ा मान करता हूँ जो अथक परिश्रम करके और अपने को जोखम में डालकर इन तरह की बहनों को निकाल-निकाल कर ला रही हैं। मुझे कहते दुःख होता है कि इस बारे में हमारी आत्मा अभी तक पूरी तरह नहीं जागी। जिन घरों में

अभी तक इस तरह की वहीनें मौजूद हैं और उनके साथ यह अन्याय जारी है उन घरों को मैं क्या कहूँ ! हिंद यूनियन के अन्दर किसी आदमी के लिए एक भी इस तरह की वहन को अपने घर में रखे रहना, इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने २,४ या १० वहनों को रोक रक्खा है, किसी तरह क्षमा नहीं किया जा सकता। सदाचार कोई वेचने खरीदने की चीज नहीं है। हर आदमी की आत्मा को उसके अपने अच्छे या बुरे काम ही ऊपर या नीचे ले जाते हैं। अपने सदाचार, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को वचाना और पाक रखना हमारा काम है—दूसरे का नहीं। अपनी मर्यादा को ठीक कायम रखने से ही हम अपने-अपने अन्दर के भगवान को साक्षात कर सकते हैं।

भाषा

नई आजादी के साथ कई नई समस्यायें ऐसी हमारे देश में खड़ी हो गई हैं जिन पर विदेशी सरकार के रहते इतना जोर जोर नहीं दिया जाता था। हमारी राज-भाषा क्या होगी और हमारी राष्ट्र-भाषा क्या होगी ? शायद दोनों एक ही हों। एक ही हों या अलग-अलग हों इन सवालों का जवाब तो देना ही है। किसी राष्ट्र की राष्ट्र-भाषा चारों तरफ की हालतों और राष्ट्र के इतिहास दोनों के असर से अपने आप कुदरती ढंग से रूप लेती और वनती है। कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी भाषा को जिसे आम लोग वोलते हैं इस देश की राष्ट्र-भाषा स्वीकार किया है। लेकिन कहा जाता है कि आम लोग अलग-अलग वोलियां वोलते हैं और वोलियां वहुत सी हैं। फिर भी उत्तर हिन्दुस्तान के शहरों और वाजारों की भाषा हम सब लोग जानते हैं। आम जलसों में सब लोग जो भाषा वोलते हैं वह भी हम जानते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह भाषा ही हमारी राष्ट्र-भाषा होगी। आम लोग इसे 'हिन्दुस्तानी' कहते भी हैं। हमें एक ऐसी भाषा को राष्ट्र-भाषा वनाना है और बढाना है जो संस्कृत-भरी हिन्दी और अरवी-फारसी-भरी उर्दू दोनों के वीच की हो। ऐसी ही भाषा हम सचमुच वोलते भी हैं। रहा नाम का झगडा। नाम कुछ भी हो, राष्ट्र-भाषा तो अपने ढंग से रूप लेगी और ले रही है।

अब रह जाता है राज-भाषा का सवाल—राज-भाषा के लिए कुछ लोग संस्कृत-भरी पुरानी भाषा को फिर से लाना चाहते हैं। इस तरह

की कोई भाषा कभी रही हो या न रही हो, भाषा के मामले में हजार दो हजार बरस पीछे हटना, और उन-सब तरह तरह के असरों, नई-नई जातियों और नई-नई संस्कृतियों के असरों को जिन्होंने आजकल की मिली-जुली हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता को गढ़ने और रूप देने में बहुत बड़ा और शानदार हिस्सा लिया है, मिटाने की कोशिश करना घड़ी की सुइयों को पीछे की तरफ उलटा फिराना है।

अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले गए, लेकिन डेढ़ सौ बरस में जो कुछ उन्होंने हमें दिया है उसमें से बहुत कुछ छान फटक कर हमेशा हमारे काम आयेगा। अंग्रेजों से पहले मुस्लिम राज सदियों रहा। मुस्लिम संस्कृति के मिलने से हमारी सभ्यता और अधिक मालामाल हुई और हमारे देश की कला, दस्तकारियों और तरह-तरह की विद्याओं ने खूब तरक्की की, हमारे देश का बल बढ़ा और दूर-दूर के सूबों में आना-जाना और मेल-मिलाप भी खूब बढ़ा। हमारी समाजी जिन्दगी और हमारे साहित्य पर उसका गहरा असर पड़ा। इन बातों के होते हुए हमें बोल-चाल की भाषा या संस्कृत-भरी भाषा की बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। यह सच है कि आखिर में हमारे कानून राज भाषा में ही होने चाहिए और वही सनद माने जाने चाहिए पर अभी तो जो कानून अंग्रेजी में लिखे जायं और अंग्रेजी में पास हों उनका राज-भाषा में एक ठीक और बामुहावरा अनुवाद निकल जाना चाहिए। धीरे-धीरे अपने आप ही नई परिभाषाओं को सब समझने लगेंगे और वह सबके लिए आसान हो जायंगी और उसमें वह सब बातें आ जायंगी जो कानून और विधान की भाषा में होनी चाहिए। अभी इस मामले में जल्दी करना ऐसा ही है जैसा कच्चे फल को जल्दी से जबरदस्ती पकाने की कोशिश करना।

हिन्दुस्तानी समाज

आजकल की दुनियां में राजनीति और अर्थशास्त्र को इतनी बड़ी चीजें माना जाता है कि उनके सामने समाजी मसले की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हमारी कानून सभाओं, हमारे नेताओं और हमारे अखबारों, सबकी लगभग यही हालत है। बहुत दिनों के विदेशी राज ने हमारे इस रोग को और भी बढ़ा दिया है। समाजी निगाह से हमारा सारा देश बिलकुल एक बहुत दिनों के रोगी की तरह है। देश की जनता को

कोई ठीक राय किसी बात में अव्वल तो बन ही नहीं पाती और अगर कुछ दर्जे तक बन पाती है तो उसमें बल और असर दिखाई नहीं देता। विदेशी राज न आया होता तो हो सकता है कि धीरे-धीरे कुदरती ढंग से हमारा समाज अपने रूप को बदलता, बुरे रीति-रिवाजों को को छोड़ता और दुनियां के दूसरे देशों की तरह लेकिन अपने खास ढंग से, आगे बढ़ता और फलता-फूलता। लेकिन अब हमारे भद्दे से भद्दे रीति-रिवाज पत्थर की लकीर होकर रह गए। उनमें से लचक जाती रही। लोगों की सोचने-समझने की आदत ठस होकर रह गई। आत्माएं मालम होता है सो गई। समाज की तरफ जिम्मेदारी का खयाल बहुत ढीला पड़ गया। कहीं कुछ आदमी किश्ती समेत डूब जांय तो किसी का उधर ध्यान भी नहीं जाता। जापे में माताओं और गोद के बच्चों का धड़ाधड़ मरना किसी के दिल में दुख नहीं पैदा करता। प्रेम, दया और हमदर्दी मिटती जा रही है। अपने-अपने हक की सब बातें करते हैं। फर्जों को लोग भूल बैठे हैं। बड़े-बड़े कुटुम्ब जिनमें सब दूसरों के हित को देखते थे मिट गए। अब हर एक अपने ही हित को देखता है, और वह भी इस जड़ शरीर के हितों को। नतीजा यह है कि किसी का भी हित पूरा नहीं होने पाता। न घर का कोई सिरधरा न समाज का कोई सिरधरा। सब आजाद और सब बेलगाम। राज की तो कोई जरूरत ही नहीं रही। ब्राम्हण और पुरोहित भी केवल तीर्थ के पण्डे बनकर रह गए, पेट भरना और छोटे-छोटे रीति-रिवाज तोड़ने पर एक दूसरे को विधर्मी कहना। प्रेम जो समाज का सीमेंट था सूखकर बेकाम हो गया। समाज की इमारत क्या है? मलबे का एक ढेर है। इस तरह का समाज और इस तरह का देश देर तक नहीं चल सकता।

अगर हम अपने समाज और अपने देश को जिन्दा रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि पहले आम जनता की राय और उसके विचारों को ठीक करें और मजबूत बनायें। हमारी कानून सभायें सब तरह के विचारों के लोगों से सलाह करके समाज को पाक और मजबूत करने के लिए कानून बनावें। राजनीति और अर्थ-शास्त्र के साथ-साथ हमें धर्म और समाज को भी ठीक रखना है। हमारा आदर्श है सेकुलर नेशनल्जिम यानी वह राष्ट्रीयता जिसका किसी के धर्म-मजहब से कोई वास्ता नहीं। पर ऐसा न हो कि हम सेकुलर शब्द पर इतना जोर दे बैठें कि उसमें से राष्ट्रीयता

ही उठ जाये। हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता के फूल में से हिन्दुस्तान की महक नहीं मिटनी चाहिए। यह महक हमारी समाजी संस्थाओं से ही मिल सकती है। फूल सूख जाने पर भी महक दे सकता है और उससे इत्र निकल सकता है। यही बात हम इस तरह कहते हैं कि हमारी अलग-अलग संस्कृतियां मिटनी नहीं चाहिए। हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता की माला में सब वर्णों और सब संस्कृतियों के फूल अपना-अपना रंग और अपनी-अपनी महक लिए हुए चमकने चाहिए। इन्साफ यह है कि सबकी रक्षा की जावे, जिस-जिस में जो-जो सुगन्ध या अपना जो-जो मिठास है वह बना रहना चाहिए। हरेक के भले में ही सबका भला है।

हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता के सब अंगों की तरफ हमें बराबर का ध्यान देना होगा। इतिहास के जानकारों की राय है कि हमारे देश के मुसलमानों में दस हजार पीछे एक भी बाहर से आया हुआ नहीं है। आज-कल के मुसलमान कुछ पीढियां पहले के हिन्दू हैं, उनके कुछ रीति-रिवाज बदल गए, पर खून वही है, हाड-मांस वही है, दिल और दिमाग वही हैं। राजकाजी और माली नफा नुकसान तो एक है ही। थोडे दिनों के लिए हम भले ही बहक जाएं, पर अन्त में अपने देश, और अपने वतन और अपने राज के साथ प्रेम और लगाव जोश में आए बिना नहीं रह सकता। हम दोनों को यहीं रहना और यहीं मरना है। इन हाल के झगडों और मुसीबतों से भी और ज्यादा मालामाल राष्ट्रीयता जन्म लिये बिना नहीं रह सकती। नारियल का कोई बाग अगर जोर की आंधी से बुरी तरह हिल जाये तो दो साल तक उसमें फल नहीं लगते, पर तीसरे साल नीचे की जमीन और मिट्टी के नए हो जाने के कारण तिगुने से भी ज्यादा और पहले से कहीं ज्यादा मीठे फल आते हैं।

पिछले तीस बरस से हमारी गुत्थियों में एक और नई गुत्थी बढ गई है। यह गुत्थी सिक्खों के अलग सम्प्रदाय की है। यह सिक्ख आंदोलन शुरू में गुरुद्वारों के महन्तों के खिलाफ एक सुधार का आन्दोलन था, फिर हर साम्प्रदायिक आन्दोलन की तरह उसमें राजकाजी पहलू भी पैदा हो गया। आशा यह थी कि राष्ट्र के जीवन में सिक्ख अपना खास हिस्सा राष्ट्र की फौज को पूरा करना समझेंगे। पर सिपाही से बढ कर वह राजनेता होगये, और इस बिना पर अपने अलग हक मांगने लगे कि देश की शांति है। हमसे ही कायम है। सिक्खों के पांच ककारों में से कृपान पर इतना ज्यादा

जोर हाल-हाल में इसी वजह से दिया गया । बढते-बढते सिक्खों की अलग संस्कृति हो गई । पंजाब में जब हम अभी तक यह देखते हैं कि एक ही घर में एक भाई हिन्दू और दूसरा सिक्ख, बाप हिन्दू और बेटा सिक्ख, मियां हिन्दू और बीबी सिक्ख, तो यह समझना कठिन हो जाता है कि सिक्ख और हिन्दू दो अलग-अलग फिरके कैसे हो गए जिनमें एक बहुगिनत फिरका और दूसरा कमगिनत फिरका । मैंने एक घर का हाल सुना है जिसमें एक १७ बरस का लडका सिक्ख था, उसका बाप कट्टर हिन्दू था और बाबा कट्टर सिक्ख । इससे नतीजा यह निकलता है कि हमें अपने बच्चों को नए सिरे से ठीक तालीम देनी चाहिए । मां के दूध के साथ हमें बच्चों में यह बात बैठानी चाहिए कि हिन्दू और सिख एक हैं और दोनों की एक ही कल्चर है । हमारे मुल्क के ईसाई हमेशा से इसी मिली-जुली राष्ट्रीयता को मानने वाले रहे हैं । मुसलमानों में भी मिली-जुली राष्ट्रीयता का विचार मौजूद है । जब हिन्दू, सिख, ईसाई और मुसलमान उसी तरह पारसी, जैन और बौद्ध सबको मिला लिया जावे तो हिन्दुस्तान पत्थर की चट्टान की तरह ठोस और मजबूत दिखाई देने लगेगा और एक मिली-जुली हिन्दुस्तानी कल्चर चमकेगी ।

साम्प्रदायिकता

हर राष्ट्र, हर सभ्य देश और हर समाज में कुछ-न-कुछ अलग-अलग गिरोह होते हैं जिनसे मिलकर वह राष्ट्र या समाज बनता है। यह सब अलग-अलग गिरोह अलग-अलग कारणों से बनते हैं। कहीं एक धर्म मानने वालों का गिरोह, कहीं एक भाषा बोलने वालों का गिरोह कहीं खास तरह के विचार रखने या एक खास काम करने वालों का गिरोह वगैरह इस तरह के गिरहों को ही सम्प्रदाय या फिरके कहते हैं । इस तरह के किसी अपने फिरके की भलाई-बुराई का खयाल रखना फिरकापरस्ती नहीं जैसे यह सोचना फिरकापरस्ती नहीं है कि एक भाषा बोलने वालों या एक तरह के रहन-सहन वालों का एक सूबा हो । अपने फिरके के खास हितों का खयाल रखना या अपने फिरके वालों से खास लगाव होना भी एक कुदरती बात है, और बुरी बात भी नहीं कही जा सकती। पर जब अपने फिरके से लगाव का मतलब दूसरे फिरके से पक्षपात या तयस्सुब हो जाता है तब वह फिरकापरस्ती हो जाती है । तभी समाज में एक नई समस्या खड़ी हो जाती है । यह फिरकापरस्ती की

समस्या एक रोग है। यह एक राक्षस है जिसके बहुत-से सिर हैं। एक काट दिया जाता है तो दूसरा उग आता है। फूट और नफरतें पैदा हो जाती हैं। सिक्खों और मुसलमानों में, सिक्खों और हिन्दुओं में, हिन्दुओं और मुसलमानों में, ब्राह्मणों और अब्राह्मणों में, भूमिहारों और और कायस्थों में, कायस्थों और क्षत्रियों में, सवर्णों और अवर्णों में फूट और आपसी झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसी तरह जिन सूबों में कई-कई भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक भाषा बोलने वाले और दूसरी भाषा बोलने वालों में लाग-डाट चल पड़ती है। केवल मद्रास ही के अन्दर हरिजनों-हरिजनों में चौरासी बिरादरियां हैं। हमारे अंग्रेज हाकिमों ने इस तरह की सब बिरादरियों को और इस तरह के सब फिरकों को उनकी अलग-अलग फेहरिस्तें रखकर खूब पाला-पोसा और बढ़ाया। इस तरह पाल पोसकर वह यह रोग हमें विरसे में छोड़ गए। अब हमारा काम है कि इन अलग-अलग टुकड़ों में बुनियादी एकता को सामने लावें और चमकावें। देश-भर के सब फिरके और सम्प्रदायों के लोगों में एक दूसरे से प्रेम, इन्सानी हमदर्दी, इन्साफ और मेल-जोल बढ़ावें देश के सामने यही इस समय सबसे बड़ा काम है।

अलग सीटें

फिरकेवाराना सवाल से मिला हुआ सवाल कमगिनती यानी कमगिनत जमातों या फिरकों का है। ऊपरी निगाह से देखने में यह मालूम होता है कि कमगिनतों के लिए धारा-सभाओं या नौकरियों में अलग जगह रखना उनके हित में शुरू में अच्छा है और उसके बाद धीरे-धीरे हम पूरे मिले-जुले चुनाव पर जा सकते हैं। पर इससे एक तो बहुगिनत लोगों की जिम्मेदारी बहुत घट जाती है। होना यह चाहिए था कि बहुगिनत वाले अपने दिल से कमगिनत वालों की भलाई का खयाल रखते। इससे दोनों की आत्मायें ऊंची होतीं। पर कानून बन जाने से दोनों की आत्मायें गिरती हैं। कमगिनत वालों को झूठी तसल्ली हो जाती है। राष्ट्र के काम में कुशलता और काबलियत का माप गिर जाता है। कमगिनत वालों में एक छुटवहम हमेशा बना रहता है। उनकी हालत सदा के लिए वह हो जाती है जो किसी अमीर आदमी की दावत में गरीबी रिश्तेदारों की होती है। उनमें से किसी में असली बड़प्पन पैदा ही नहीं हो पाता। छोटे-छोटे लोगों को बिना अपने में काबलियत पैदा किए सीटें और नौकरियां मिलती रहती

है। इस तरह की चीजें सबके लिए बुरी हैं। इन्हें जहां तक हो जल्दी ही बन्द करना चाहिए।

जब वह दिन आयगा जिस दिन फिरकापरस्ती या साम्प्रदायिकता केवल एक पुराने इतिहास की चीज रह जायगी और हम एक-से-राजकाजी और आर्थिक हितों में बंधे हुए सबको अपना समझते हुए प्रेम, मेल-मिलाप और सच्चे भाई-चारे से रहने लगेंगे तबहमारा राष्ट्र सचमुच एक राष्ट्र होगा। उस दिन हमारी मातृभूमि सचमुच हम सबकी मां होगी और उसकी खिदमत करना हम सब ईश्वर अलाह की खिदमत करना समझेंगे तयस्सुब और हठधर्मियों का खात्मा हो चुकेगा, एक सच्चा मानवधर्म, मजहबे इन्सानियत सबकी आत्माओं को पाक और ऊंचा करेगा। तब ही हम सब अपने देश और अपने धर्म, मजसब के नाम को दुनियां में उजागर करेंगे।

हरिजन

हिन्दू समाज के अन्दर हरिजनों की गिनती कुल हिन्दुओं का पांचवां हिस्सा है। हरिजनों की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। जो समाज अपनी रूढ़ियों को बदल नहीं सकता वह देर तक जी भी नहीं सकता। इस सवाल पर इतना कहा जा चुका है कि मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं एक अलग हरिजन जाति होने के इस महान कलंक को और उससे पैदा होने वाली छुआछूत को हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने समाज से मिटा देने की पूरीं-पूरी कोशिश करनी चाहिए।

पशुधन

हमारा देश एक बहुत बड़े पैमाने पर खेतिहरों का देश है। गाय, बैल, भैंस, बकरी हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारे धर्मों में भी पशुओं से प्रेम करने की खास जगह है। इसीलिए देश भर में जानवरों का मारा जाना रोकने पर इतनी आवाजें उठती हैं। हिन्दू लोग तीन माताएं मानते हैं—गो माता, गंगा माता और भू माता। भू, यानी जमीन, से खाने को अनाज मिलता है। नदियों के जल से खेत सींचे जाते हैं और पैदावार बढ़ती है। गाय दूध देती है और उसके बच्चे खेती के काम में आते हैं। इसी लिए गाय-बैलों का मारा जाना देश के लिए अच्छा नहीं है। पिछली जंग के दिनों में इस देश में फौज के अन्दर हररोज तीस हजार बछडे मारे जाते थे, केवल इसलिए, क्यों कि उन्हें दूध पिलानें से गाय का दूध कम मिलता था और अंग्रेज सरकार उस घाटे

को सहने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देश-भक्तों और रहम दिल लोगों ने चीख-पुकार की तो यह हुक्म होगया कि हर बछड़े को १४ दिन जिंदा रखा जाय, पंद्रहवें दिन जो चाहें उसे मुफ्त ले जाय। और उस दिन कोई न लेजाय तो वछडे को मार डाला जाय। इस मामलें में देसके सब भाइयों से हम प्रेम की प्रार्थना करते हैं। गौ रक्षा कानून के जरिये नहीं की जा सकती। देश में सबको पूरी आजादी है। हर एक की पूरी आजादी वहां खतम होती है। जहां दूसरे की शुरु होती है। गौ-रक्षा एक इखलाकी और इन्सानी चीज है। लोगों के वुनियादी हकों, राज की आज्ञाओं या कानूनों से इसका कोई वास्ता नहीं। मेरे दिल में गाय की अधिक-से-अधिक भक्ति है और उसी निगाह से मैं कहता हूँ कि इस चीज को लोगों के दिलों पर ही छोड़ना होगा।

इसीसे मिलता-जुलता और राष्ट्र के जीवन के लिए वहुत ही जरूरी सवाल घी और वनस्पति का सवाल है। पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती जबतक उनकी देखरेख और सेवा न हो और सेवा नहीं हो सकती जब तक वाजार में उनका दूध और घी न विके। लेकिन डालदा मिला घी सस्ता पडता है तो फिर शुद्ध घी पर अधिक दाम कौन खर्च करेगा? शुद्ध घी का व्यापार घाटे का व्यापार हो जाता है। जिस तरह तिजारती फसलों की वजह से अन्न की फसलें कम उगाई जाती है और खोटे सिक्के चल जाने से खरे सिक्के दिखाई देने वन्द हो जाते हैं उसी तरह वनस्पति मिले घी की वजह से शुद्ध घी वाजार में टिक नहीं पाता इस तरह गांव के ढंगर मिटते जाते हैं, किसान की वरवादी वढती जाती है, क्योंकि शहरों में भैंस गाय दूध के लिए रक्खी जाती है और गांवों में अधिक तर घी वेचने के लिए। घी में यह मेल तव तक वन्द नहीं हो सकता जव तक वनस्पति को तेल की तरह पतला न रक्खा जाय और उसे घी की तरह जमाने की काननी मनाही न करदी जाय क्योंकि तरल वनस्पति को घी में नहीं मिलाया जा सकेगा। इसलिए वनस्पति का जमाना यानी उसका हड्रोजनेशन काननन वन्द होना चाहिए।

कांग्रेस, विधान सभा और सरकार

नये देश और नये समाज की रचना इस समय तीन वडी संस्थाओं के हाथ में है—कांग्रेस, विधान सभा और यूनियन सरकार। सवाल यह है कि इन तीनों का आपस में क्या सम्बन्ध हो। कांग्रेस ने मुल्क को आजादी दिलाई, विधान सभा उस आजादी को विधान के जरिये तरह २ से और अलग २ रास्तों पर डाल रही है। यह काम सिर्फ थोडी देर का काम है

जो विधान एक बार बन जायगा उसे जिस वक्त गो सरकार होगी वह अमल में लायगी। जिस तरह आदमी का शरीर होता है उसी तरह राष्ट्र का शरीर होता है। आदमी के शरीर में दिल सारे शरीर को अच्छा खून पहुँचाता है और बुरे खून को वापिस लेकर साफ करके फिर शरीर में चारों तरफ भेज देता है। हमारे राष्ट्र के शरीर में यह कम कांग्रेस का है, कांग्रेस कुछ सीधे प्रचार के जरिये और सरकार रूपी नाड़ियों के जरिये राष्ट्र की बढोती के अच्छे २ सिद्धान्त देश भर में फैलाती है, और फिर देश भर की टीका टिप्पणी और नुक्ताचीनी को अपने अन्दर लेकर उनकी मदद से फिर अच्छ नये सि न्त बनाकर देश में फैलाती है। इस तरह कांग्रेस आग जनता की राय और सरकार की शक्ति दोनों से फायदा उठाकर दोनों के जरिए देश की सेवा करती है।

अब जरा सरकार को लीजिए। सरकार का काम राज चलाना है। आए दिन जो सवाल उसके सामने आते रहते हैं उन्हें उसी समय हल करना पडता है। उसका काम ठोस काम है और रुक नहीं सकता।

कांग्रेस का काम ज्यादा फैला हुआ और ज्यादा बढता हुआ है। उसे पिछले जमाने के कारनामों, इस जमाने की कोशिशों और आगे की आशाओं इन तीनों को एक लडी में गूंथना पडता है। कांग्रेस ऋषि या शास्त्रकार है। सरकार राजा यानी हाकिम है। सरकार के हाथ में शक्ति है, कांग्रेस का अपना प्रभाव है। यह प्रभाव दिलों की चीज है, शक्ति ऊपर की चीज है। इसलिए प्रभाव शक्ति से अक्सर जीत जाता है। दूसरे शब्दों में हम जो देश में 'रामराज' कायम करना चाहते हैं सरकार उसमें का 'राज' है और कांग्रेस उसमें का 'राम' है।

इसी तरह का रिश्ता केन्द्रीय और सूबाई मन्त्रिमण्डलों और कांग्रेस के केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोर्ड में है। मन्त्रिमण्डलों के साथ उनकी पार्टियां भी हैं। यह रिश्ता एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एक दूसरे को समझने की कोशिश और साहस और रवादारी से ही ठीक २ चल सकता है। हमें इसमें आदमियों पर कम और असूलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। असूल भी ऊँचे और पक्के राष्ट्रीय होने चाहिए।

अब रह गया सेक्रेटेरियट का दफ्तर। सेक्रेटेरियट मन्त्रिमण्डल को चलाता है और वह मोटर का इंजन नहीं है। वह केवल मोटर के ड्राइवर के हाथ का वह पहिया है जो मोटर को सडक के ठीक हिस्से में रखता है।

या वह सरकार रूपी किश्ती की वह पतवार है जो किश्ती को ठीक धार में रखती है। यह याद रखना चाहिए कि सरकार कोई रेल की गाडी नहीं है जो लोहे की पटरियों पर चलती हो, वल्कि मोटर कार है जो मामूली सडक पर चलती है और जिसे दायें बायें ठीक रखना होता है। यह छोटा-सा काम सेक्रेटेरियट का है। मोटर का आक्सिलरेटर जिसकी शक्ति से मोटर चलती है कांग्रेस है।

देश की सबसे बडी राजकाजी संस्था कांग्रेस ने ६३ वर्ष तक जो मेहनत की है उसीका फल आज की सरकार है। देश में और भी बडी अच्छी २ संस्थायें रह चुकी हैं जिन्होंने अपने २ ढंग से देश की सेवा की है। पर देश की सबसे वडी शक्तियों से मोर्चा लेकर सारे देश को हिम्मत के साथ आजाद राष्ट्रों की पंगत में ला खडा करना और आगे वढने का अवसर देना कांग्रेस ही का काम था। शुरू के दिनों में कांग्रेस में भी नरम दल के लोग रहे हैं। उन पुराने नेताओं और बुजुर्गों के काम की हमें बेकदरी नहीं करनी चाहिए। छोटे, कमजोर वालक को मौसम की खराबियों के होते हुए भी पालना-पोसना एक काम है और जवान मजबूत आदमी से काम लेना दूसरी बात है। समय २ की अपनी २ जरूरतें होती हैं। उन गुरुजनों की सम्भाल कर रक्खी हुई नीवों पर ही आज हम इस महल को ऊँचा कर सके।

अब हमारा काम समय की हालत और जरूरतों को देखते हुए समझदारी के साथ आगे का रास्ता तय करना है। आम जनता अपनी वक्ती जरूरतों और अपनी भावनाओं के असर में सरकार पर दवाव डालती है। जनता की इन जरूरतों औरभावनाओं को समझते रहना कांग्रेस का फर्ज है। एक तरह से कांग्रेस सरकार का दिमाग है। मन्त्री लोग अपने दौरों में काम के दौरान में जो जो देखें सुनें उसकी कमी को पूरा करना कांग्रेस का काम है। मन्त्रियों को वडी तेजी से और भिड कर काम करना पडता है। उन्हें अवसर शान्ति से सोचने समझने की छुट्टी भी नहीं मिल सकती। उनकी इस कमी को पूरा करना और उन्हें मदद देना कांग्रेस का काम है।

कांग्रेस एक तरह से आम जनता और सरकार दोनों को जोडने वाली और दोनों में समतोल रखने वाली वीच की कडी है। जनता जल्दवाज होती है। सरकारें अपने पिछले वायदों से वन्धी होती है। हाल की मुश्किल उन्हे चकराती रहती है और आगे की भूल-भुलैया उन्हें और भी उलझनों में डालती रहती है। सरकारों को दायें-वायेंआगे-पीछे देखना पडता है। जनता को

सम्भाल से समझाते रहना और सरकार की चाल को जरा तेज करते रहना कांग्रेस का काम है।

यह सच है कि राज कांज में हर नौसिखिया राज के वारीक कल पुरजों को हाथ नहीं लगा सकता न उसे ऐसा करने दिया जा सकता है। साथ ही हकूमत के पुराने पथराये हुए और निकम्मे ढर्रों को भी ज्यूं का त्यूं नहीं चलने दिया जा सकता। आजकल की सरकारें एक तरफ तो जनता की प्रतिनिधि होती हैं और दूसरी तरफ राजकीय मशीन के चलते रहने के लिए जिम्मेंदार भी होती हैं। दुनिया भर में यही आजकल की सरकारों की सबसे बड़ी कठिनाई है। इसलिए वह अक्सर फूंक २ कर कदम रखते हैं, संभल कर बोलते हैं और अक्सर बहुत धीरे कदम उठाते हैं। दूसरी तरफ यह भी डर लगा रहता है कि जनता का राज कहीं फिर एक आदमी का या एक गुट्ट का मनमाना राज बनकर न रह जाय। पार्टी सरकारों को और भी दिक्कत पड़ती है। उन्हें एक२ बात में सारी पार्टी को साथ लेकर चलना पड़ता है। पार्टी में कभी-कभी जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। जल्दबाजी तो होनी ही है। कानून के मसौदों और योजनाओं पर ठंडे और बेलाग दिलसे बैठकर विचार बहुत विरले करते हैं। असल में तो पार्टी का काम सिर्फ असूल तय करना या पालिसी तय करना होना चाहिए। बाकी काम काजकारी शक्ति का है। काजकारी भी बहुत सा काम कमेटियों और सब कमेटियों के सपुर्द कर देते हैं। यह उन्हें करना पड़ता है। इन सब पेचों से निकलने के रास्ते भी हैं। पार्टी को हमेशा यह अधिकार है कि अपने काजकारी को आगे बढ़ने से रोक दें, आगे के रास्तों को देखें-भालें और ठीक समझें तो काफले को लौटा लें। कांग्रेस एक समय अपने इस अधिकार से काम ले चुकी है और इस तरह अपनी सचाई और सफाई का सबूत दे चुकी है। जनराज या लोकराज एक बड़ी नाजुक चीज है। लोकराज को इसमें एक तरफ वजीरों की झिझक और उनका सोच-विचार और दूसरी तरफ लोगों की जल्दबाजी, एक तरफ सरकारों के रंगविरंगे फीतों के ढर्रे और दूसरी तरफ जनता की इन्कलाब पसन्दी, दोनों को सम्भालते हुए बीच में से चलना पडता है।

कांग्रेस का नया विधान

कांग्रेस को इस बड़े और कठिन काम के काबिल बनाने के लिए ही कांग्रेस के नए विधान का मसविदा तय्यार किया गया है क्योंकि

कांग्रेस का पुराना विधान इसके लिए काम नहीं दे सकता। पुराने तजरबों से ही नया विधान बनाया गया है। जनता की राय इस पर ली जा चुकी है, कांग्रेस के इजलास में इस का मांजा जाना, रूप दिया जाना और पास होना अभी बाकी है। आगे के सालों में इस विधान पर अमल करना हमारा काम होगा। कांग्रेस भी एक पार्टी कही जाती है। पर कांग्रेस ने नए मसौदे में हिम्मत के साथ यह तय किया है कि देश का २१ बरस से ऊपर का हर मर्द और हर औरत कांग्रेस का प्रायमरी यानी बुनियादी मेंबर हो सकेगा। उसे केवल कांग्रेस के नीचे लिखे मकसद को मानना होगा जिसे पहले हम कांग्रेस की 'क्रीड' कहा करते थे। वह मकसद यह है:—

"इन्डियन नेशनल कांग्रेस का मकसद हिन्दुस्तान के लोगों की भलाई और तरक्की है और जायज और शान्ति के तरीकों से हिन्दुस्तान में एक ऐसा सहकारी संघराज या सबका राज कायम करना है जिसकी बुनियाद सबको बराबर के अवसर देने और सबको एक बराबर राजकाजी, आर्थिक और समाजी अधिकार मिलने पर हो और जिसका ध्येय दुनिया भर में शान्ति और भाईचारा कायम करना हो।"

इस मकसद को मंजूर करने से पहले उस पर लम्बी बहसें हुई और गम्भीरता के साथ विचार किया गया। इसमें पुराने और नये को बडी सुन्दरता के साथ मिलाया गया है और अलग-अलग तरह के विचारों में मेल और सामन्जस्य पैदा करके रखा गया है। दुनियां में अलग-अलग विचारता है और रहेंगे ही उन सबको जहां तक हो सके मिल कर चलाना समझदारी का काम है। इसीका नाम समझौता है। जहां इस तरह मिलकर नहीं चला जा सकता वहीं टक्करें और झगडे होते हैं। समझौते में सबको कुछ-न-कुछ झुकना पडता है। हमारा संघ राज (फेडरल यूनियन) एक तरफ पूरी सूबाई खुदमुख्तारी और दूसरी तरफ पक्की एकाकी (युनिटरी) सरकार दोनों के बीच का समझौता है। समाजवाद (सोशलिज्म) और पूंजीवाद (कैपिटलिज्म) दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। उन दोनों की निगाहों को एक करना जरूरी है, क्योंकि समाजवाद पूंजीवाद के खिलाफ उस पर एतराज के रूप में ही पैदा हुआ था। माल पैदा करने वाले किसान मजदूर और माल को काम में लाने वाली जनता दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, और यह

दोनों मिलकर माल को इधर-से-उधर पहुंचाने वाले बीच के दलालों से लडते हैं। कांग्रेस के इस नए मकसद में इसीलिए सहकार की वात कही गई है। सहकारी संस्थाओं में इन सव अलग—अलग विचारों का मेल होता है। सहकारी संस्थाओं के जरिए जमी हुई पूंजी निकल आती है, वीच के दलाल की जरूरत नहीं रहती। और अगर सहकारी संस्था माल का वंटवारा करने वाली है तो जो कुछ नफा होता है वह माल का उपयोग करने वालों में वट जाता है। अगर संस्था पैदा करने वाली संस्था है तो उसका नफा भी माल पैदा करने वालों में वंट जाता है। सहकार के इस सिद्धान्त से सवको वरावर के अवसर मिल जाते हैं और वरावर के ही राजकाजी आर्थिक और समाजी अधिकार मिल जाते हैं अधिकार एक जगह रहता है और संस्था का सारा इन्तजाम जहां तक हो सकता है ऐसे गिरोहों के जो एक दूसरे के साथ में होता है। जो एक दूसरे के साथ सहकार के वन्धन में वन्धे होते हैं।

कांग्रेस के नये मकसद में दूसरी नई वात दुनिया भर में शान्ति और भाईचारा कायम करनें को अपना ध्येय वनाना है इस ऊंचे ध्येय के साथ ही कांग्रेस का मकसद पूरा होता है। इस मकसद के आखरी हिस्से में उन सव आदर्शो का निचोड आगया जिसके लिए महात्मा गांधी जियें और जिसके लिए उन्होंने जान दी। कांग्रेस के काम का तल आज एकदम केवल अदनी आजादी से ऊपर उठकर दुनियाभर में शांति कायम रखनें तक पहुंच जाता है। यह वडी खुशी और संतोष की वात है कि हमारे प्रधान मन्त्री जव हाल में लन्दन गये तो लोगों नें यह विचार प्रकट किया था कि वही एक आदमी हैं जो कि सवसे आगे वढी हुई कौम के मुखिया की हैसियत से दुनिया में शान्ति कायम करनें की कोशिश कर सकते हैं।

कांग्रेस को अगर अन्तर्राष्ट्रीय राजकाज में हिस्सा लेना है तो अपने को मजवूत और पक्का वनाना होगा। हमें यह याद रखाना चाहिए कि कुछ ऐसी शक्तियां जो पहले कांग्रेस के साथ थी हाल में कांग्रेस से अलग हो गईं। हमारा काम यहां यह तय करना नहीं है कि इसमें किसका कितना कसूर था। यह वात जाहर है कि किसी विचार के लोग चाहें वे कितनें भी देशभक्त क्यों न हों और उनके असूल कितनें भी ऊंचे और अच्छे क्यों न हो किसी संस्था में रहकर उस संस्था के असूलों और उसकी पालिसी के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकते। हमें यह याद करके दुःख होता है कि किस तरह हमारे सोशलिस्ट दोस्तों नें कांग्रेस के साथ-साथ संवंध रखते हुए, अहिंसा

को बुरा कहा और केबिनेट मिशन के जरिये देश का हल ढूढ़ने को और अंत-रिम गवर्नमेंट बनाने को भी बुरा कहा। इससे उन राजनैतिक मामलों में कांग्रेस का सारा रुख ही बेबुनियाद हो गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे हमारे सोशलिस्ट दोस्त कांग्रेस से अलग हो गए।

एक और संस्था किसानों की है। उसके अपने अलग मेंबर हैं। कम या ज्यादा वह कांग्रेस से अलग रहते हुए एक बराबर की राजनैतिक संस्था की तरह काम करती हैं। किसानों का एक अपना बन्वा है। किसान अगर अपने हितों की खुद देखरेख करें तो इसमें किसी को कोई एतराज हो नहीं सकता। लेकिन जब वह कांग्रेस से अलग-अलग चलते हुए एक अलग संस्था की तरह राजनीति में दखल देने लगते हैं और अपने तौर पर कांग्रेस के अन्दर रहते हुए इस तरह काम करने लगते हैं जिस तरह एक संस्था के अन्दर दूसरी संस्था, तो उनके काम पर ध्यान देना पड़ता है। हम दिल से चाहते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह की सब संस्थायें कांग्रेस के साथ-साथ चलेंगी और कांग्रेस में रहते हुए उस कायदेदारी को पूरी तरह निबाहेंगी जिसका पालना और मानना कांग्रेस के सब मेंबरों के लिए जरूरी है।

कुछ लोग पुराने जमाने से चिपटे रहना चाहते हैं। कुछ लोग आने वाले जमाने को पहले समझकर पकड़ लेना चाहते हैं। समझदार आदमी इन दोनों से हमदर्दी रखता हुआ दोनों के बीच में खड़ा होता है। वह जानता है कि हम एक हालत से निकल कर दूसरी हालत में दाखिल हो रहे हैं। हाल का जमाना केवल पिछले जमाने और अगले जमाने के बीच का पुल है। हमें न पिछले से लड़ना है न अगले से। हमें केवल मजबूत क़दम के साथ आगे बढ़े चलना है। दुनिया अगर पिछले सारे जमाने को छांट कर फेंक दे तो खड़ी नहीं रह सकती। साथ ही कोई इन्सान नदी के एक पानी में दूसरी बार नहीं नहा सकता। इस धरती पर हर वक्त सुबह होती रहती है और हर वक्त सूरज डूबता रहता है। हमें निकम्मी घबराहट के साथ आने वाली सुबह की तरफ लपकने की जरूरत नहीं। न हमें उस डूबते हुए सूरज की बेक़दरी करनी चाहिए जो किसी वक्त निकला भी था और जिसने अपने समय में दुनियां को रोशनी दी थी।

दुनिया में हम सब नेकी की मशाल हाथ में लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे हमारे पीछे आ रहे हैं। हमारा फर्ज है जब हम सामने से

हटें तो रोशनी और जलती हुई मशाल होशियारी के साथ पीछे आने वालों के हाथों में सौंप दें ताकि आज के हमारे जवान कल कौम के बुजुर्ग बन सकें। जवानों का जमाना आगे आ रहा है, बूढ़ों का पीछे जा रहा है। दोनों में से कोई दूसरे की बेकदरी नहीं कर सकता। आदमी जवान से बूढा होता है और बूढे जवानों को पैदा करते हैं। जिंदगी दोनों के प्रेम मिलन का नाम है।

जब हम यह देखते हैं कि कांग्रेस के सामने कितना जरूरी और शानदार काम पड़ा हुआ है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए कांग्रेस को पहले अपने को पाक और अपने संगठन को मजबूत करना होगा। जो संस्था इतने ऊंचे मकसद को लेकर काम कर रही है उसके मेंबरों के लिए क्या यह बहुत ज्यादा है कि उन्हें खद्दर पहनने की आदत हो, वह छुआछूत मिटाने पर जोर देते हों और हर तरह के नशे से परहेज करते हों ? इससे सबकों दिखाई दे जायगा कि यह देश की आर्थिक जरूरतों को समझते हैं और उसकी सदाचार की मर्यादा का पालन करते हैं। कांग्रेस आपसे जब खद्दर पहनने को कहती है तो वह एक नए आर्थिक संगठन की बुनियादें रखती है। जब वह आपसे नशे की चीजों से परहेज करने को कहती है तो वह इस देश की राष्ट्रीयता को नेकी और नेकचलनी की गई नींव पर खड़ा करती है। जब कांग्रेस आपसे हर तरह की छुआछूत मिटाने को कहती है वह समाज के सारे तलकों को बराबर और ऊंचा करती है। जब कांग्रेस आपसे साम्प्रदायिक एकता के लिए अपील करती है और चाहती है आप दुनिया के मजहबों की इज्जत करें तो वह राष्ट्र के मन्दिर की उन दीवारों को ऊंचा करती है जिनसे उस मन्दिर की रक्षा होगी। सबकी आर्थिक और समाजी बराबरी, सबको बराबर के मौके और सबको बराबर का मान, चाहें कोई किसी भी नसल, मजहब, या जात का क्यों न हो और चाहे नर हो या नारी, यही हमारे राष्ट्र रूपी मन्दिर को बचाने वाली दीवार और उसकी छतें हैं। कांग्रेस की मेंबरी की शर्तें और कांग्रेस का मकसद दोनों मिलाकर ही सच्चे स्वराज्य का पूरा मन्दिर बनता है, जिसकी बुनियादें अपने ऊपर भरोसे पर, समाजी एकता पर, और सदाचार पर होंगी। इस तरह के कांग्रेस मेंबर की दुनिया की शान्ति और दुनिया भर के भाईचारे के लिए कोशिश कर सकते हैं।

हर प्राइमरी मेंबर के लिए यह भी जरूरी रखा गया है कि बाअसर मेंबर बनने के लिए वह रोजाना अपना कुछ-न-कुछ समय किसी-न-किसी

तरह के राष्ट्रीय या रचनात्मक काम में खर्च करें। इस तरह के काम कांग्रेस समय-समय पर बताती रहेगी। मेंबर को इस तरह के प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत भी करने होंगे। काम बहुत से होंगे जिनमें से कोई सा चुना जा सकेगा। समय जितना कोई खुशी से दे सके, जरूरत सिर्फ दिल और इरादे की है। जहां दिल होगा वहां रास्ते निकल ही आते हैं। और जब रास्ता निकल आता है तो दिल अपने आप नाम को थोडा सा काम करने से तसल्ली नहीं मानता। नेक काम में भी लगभग वैसा ही नशा होता है जैसा बुरे काम में। आदमी अक्सर जो चाहता है और कहता है वही हो जाता है। उसके दस्तखत उसे हमेशा अपने इरादे की याद दिलाते रहेंगे। इस तरह का काम थोडा-थोडा रोज करते-करते कुछ ही दिनों में बहुत दिखाई देने लगता है। तब उसकी क़दर भी खूब होती है। सच्चे स्वराज का यही रास्ता है। कांग्रेस के नए विधान की यही कीमत है। उसी तरह यह विधान नये हिन्दुस्तान की रचना में मदद दे सकता है। इसमें आगे के लिए बडी २ आशायें छिपी हुई हैं। जब इस तरह नई कांग्रेस का नया ढांचा पूरी तरह तैयार हो जायगा तो न केवल अब तक के ३॥ करोड की जगह १७ करोड वोटरों का ही संगठन खडा हो जायगा, बल्कि पूरे ३० करोड दिमाग इस देश को राष्ट्रों की पंगत में सबसे आगे बिठाने की तदबीरें सोचने लगेंगे और ६० करोड हाथ उन तदबीरों को सफल बनाने में लग जायेंगे।

एशियाई देश

इन्डियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य केवल हिन्दुस्तान को आजाद कराना ही नहीं था। हिन्दुस्तान की आजादी एक अधिक बडे उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल एक साधन है। हमें ९ अगस्त १९४२ का अपना बम्बई का वह दृश्य याद रखना चाहिए जिसमें हमने केवल आजाद और खुद-मुख्तार हिन्दुस्तान ही की मांग नहीं की, बल्कि यह साफ २ मांग भी की थी कि हिन्दुस्तान की आजादी और खुदमुख्तारी हमसे पूरब, उत्तर और पच्छिम के उन पड़ोसी देशों की आजादी और खुदमुख्तारी का पेश खेमा और सबूत होनी चाहि, जो अभी तक योरुप की ताकतों के चुंगल में फंसे हुए हैं और अपने-अपने यहां लोकराज कायम करने के लिए शहनशाहियत से मोर्चा ले रहे हैं। हमारे चारों तरफ एशिया के दूसरे देश अपनी आजादी के लिए अभी तक लड रहे हैं। पिछली जंग के बाद तीन नए देश सामने

आये हैं —बर्मा, हिन्दुस्तान और लंका, । ये तीनों आजाद हो चुके । फिलिपाइन टापू भी आजाद हो चुके । दूर पूरब में इन्डो नेशिया और वायटनाम, मलायें और स्याम, अपने को अभी तक आजाद नहीं कर पाए । कोरिया रूस और अमरीका के बीच में बंटा हुआ है । बीच पूरब में अरबों और यहूदियों की दुश्मनी अभी तक शान्त नहीं हुई । सच यह है कि १५ अगस्त सन् १९४७ को हिन्दुस्तान का जो बंटवारा हुआ वह एक दरजे तक बाहर से बीमारी लगी थी । सन् १९३८–३९ में पील कमेटी ने अरबों और यहूदियों के बीच फिलस्तीन के बटवारे पर जोर दिया था । हिन्दुस्तान का बंटवारा भी उसी सिलसिले की एक चीज थी । एक हजार साल बीते जब अरबों ने ज्योतिष, हिसाब, वैद्यक, और दूसरी साइन्सों में दुनिया भर में नाम हासिल किया था । अरबों ही ने उस जमाने के योरुप में साइन्स की रोशनी पहुंचाई और फैलाई थी । लेकिन तुर्कों की गुलामी ने और सदियों की लगातार लडाइयों ने अरबों को गिराकर दुनिया की पिछडी हुई कौमों की पंगत में ला खडा किया । यहूदी भी एक बहुत पुरानी कौम है । दुनिया की तरक्की और तहजीब में उन्होंने किसी समय बडे मार्के का हिस्सा लिया है । इस लिए बडी लगन से उस दिन की बाट जोह रहे हैं जिस दिन अरब और यहूदी प्रेम के साथ मिलकर रह सकें ।

चीन की हालत दूसरी है । मकादन की हार और चीनी सिक्कों की टेढी समस्या से महान चीनी राष्ट्र की चिन्तायें बहुत बढ गई हैं । चीन के पडौसियों पर भी इसका बहुत बडा असर पड सकता है । चीन और हिन्दुस्तान में मिलाकर दुनिया की कुल आबादी के एक तिहाई से ज्यादह आदमी रहते हैं । चीन और हिन्दुस्तान मिलकर बाकी सारी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं । उनकी पुरानी सम्भावनायें, कला और दस्तकारियों में उनकी कुशलता सारी दुनियां का रंग बदल सकती है । हम बडे शौक के साथ उस दिन के इन्तजार में हैं जिस दिन चीन अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाकर शान्ति और शान के साथ दुनिया के बडे-से-बडे राष्ट्रों में अपनी जगह बना लेने में लग जायगा । हमें विश्वास है कि वह दिन जल्दी आने वाला है । उसके बाद दुनिया के राष्ट्र सच्चे सुख और सच्ची शान्ति का अनुभव कर सकेंगे ।

उस दिन को लाने के लिए जाहिर है कि पहला काम यह था कि एशियाई कौमों को उस तरह की एशियाई कान्फ्रेन्स में जमा किया जाय

जैसी १९४७ के शुरु में नई दिल्ली में हुई थी। अगर बीसवीं सदी ईसवी का इतिहास-लेखक कभी इस सदी की बडी-से-बडी घटनाओं को गिनाएगा तो शायद वह दोनों महायुद्धों से या जर्मनी, इटली या जापान में फासिज्म के खतम किये जाने से कहीं बढकर अहमियत एशियाई कौमों के उस जबरदस्त उभार को देगा जिसके नतीजे की शक्ल में २३ मार्च सन् १९४७ को एशियाई कौमों के प्रतिनिधि दिल्ली में जमा हुए थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू उस कान्फ्रेन्स के कार्यकर्ता और नेता थे। श्रीमती सरोजनी देवी ने बड़ी योग्यता के साथ उस बडे काम में पण्डित जवाहरलाल जी को मदद दी थी। एशिया की २२ कौमों के प्रतिनिधि कान्फ्रेन्स में जमा हुए थे। कान्फ्रेन्स इन्डियन नेशनल कांग्रेस का बहुत दिनों का और प्यारा सपना थी। २१ बरस पहले सन् १९२६ में ब्रसेल्स में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स हुई थी। एशियाई देशों के प्रतिनिधि भी वहां गये थे। उन्होंने वहां यह तय किया था कि इस तरह की एक एशियाई कान्फ्रेन्स की जाय। आगे जाने की कठिनाइयों और राजकाजी अड़चनों की वजह से उस समय वह चीज न हो सकी। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया की राजनीति का रंग बदला। उस महायुद्ध ने हिन्दुस्तान को भी अछूता न छोडा। एशिया के २२ देश अब केवल देश ही नहीं रह गए बल्कि २२ राष्ट्र दिखाई देने लगे। हिन्दुस्तान की जगह उनमें खास तौर पर चमकने लगी।

सन् ४७ की एशियाई कान्फ्रेन्स पांडुओं के 'पुराने किले' में हुई। जापान से लेकर ईरान तक और सोवियट रूस से लेकर काबुल और कंधार तक के प्रतिनिधि उस कान्फ्रेन्स में आये थे। उनकी तरह तरह की शकलें और रंगबिरंगी पोशाकें देखने के काबिल थीं। साफ दिखाई देता था कि एशिया की कौमें बहुत दिनों की नींद के बाद जाग उठी है।

महात्मा गांधी ने कान्फ्रेन्स के सामने भाषण दिया। विंडल विल्की हाल ही में दुनियां को एक करने का खयाल फैला चुके थे। महात्मा गांधी का लोगों के सामने इस 'एक दुनिया" के खयाल पर ही जोर देना उस अवसर के लिए बहुत ही ठीक चीज मालूम होता था। पूर्व से पच्छिम को यकायक मिला देने से दुनिया एक नहीं हो सकती और न पुरानी और नई दुनियाओं या अमरीका और योरुप को मिला देने से दुनिया एक हो सकती है। एक दुनिया बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे बडी जरूरत यह है कि काले रंग के राष्ट्रों और सफेद रंग के राष्ट्रों में सच्चा भाईचारा पैदा हो जाय।

उस पुराने किले में जो हिन्दुस्तान के अन्दर सात सल्तनतों का उभरना और गिरना देख चुका है, हिन्दुस्तान की रहनुमाई में एशियाई राष्ट्रों का जमा होना एक नये एशिया का पैदा होना है। उसके बाद दो और कान्फ्रेन्से हो चुकी हैं। एक सितारों की विद्या के बारे में और दूसरी मजदूरों के बारे में। हमें आशा है कि थोड़े ही दिनों में हमारा देश एशिया का रहनुमा और दुनियां का केन्द्र बना हुआ दिखाई देगा। सारा एशिया आजाद होगा और एशिया की सच्ची आजादी ही 'एक दुनिया' के जन्म लेने का सच्चा कारण बनेगा।

दूसरे देशों में हिन्दुस्तानी

दूसरे देशों में हिन्दुस्तानियों का सवाल उन देशों के बारे में जो हमारी ही तरह हाल में ही आजाद हुए हैं, अभी सुलझ नहीं पाया। कारण यह है कि आज हिन्दुस्तान और बर्मा या हिन्दुस्तान और लंका या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो आजाद राष्ट्रों को बराबर की हैसियत से एक दूसरे से मामला निपटाना है। पहले हम इस तरह की बातों में इंगलिस्तान का मूंह ताका करते थे। पर अब हमें एक दूसरे से बातचीत करने और एक दूसरे पर असर डालने के लिए अपनी ही काबलियत का सहारा लेना पड़ता है। बर्मा के साथ, लंका के साथ और पाकिस्तान के साथ तीनों के साथ हमारी अलग-अलग गुत्थियां हैं। बर्मा में जिन हिन्दुस्तानियों की जायदादें ले ली गई हैं उनका मुआवजा तय करना है और उस पर बर्मा को राजी करना है। लंका में नागरिक अधिकारों और मजदूरों की गुत्थियां पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में भीं शहरी और आथिक अधिकारों का सवाल है।

अब रहा दक्षिण अफ्रीका का सवाल। दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा संबंध कई बरस से ठीक नहीं है। सन् १९४६ में न्यूयार्क में युनाइटेड नेशन्स असेम्बली ने दो तिहाई के बहुमत से एक ठहराव पास किया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका के काले गोरे के भेद-भाव को बुरा कहा गया था और यह सिफारिश की गई थी कि ये दोनों मुल्क यानी दक्षिण अफ्रीका और हिन्दुस्तान नये सिरे से एक दूसरे के साथ लिखा पढ़ी या बातचीत करें। सन् १९४७ में यू० एन० ओ० की असेम्बली ने भी वही ठहराव पास किया, पर इस बार $\frac{2}{3}$ बहुमत नहीं था। बदकिस्मती

से इस मामले को हल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हमसे अभी तक लिखा पढ़ी शुरू नहीं की। इसके खिलाफ पिछले साल से मलान गवर्नमेंट आने के सयय दक्षिण अफ्रीका की चाल इस वारे में और विगड़ गई। उन्होंने हाल में एक कानून अपने यहां पेश किया है जिसमें और भी वुरी तरह काले गोरे का भेद वढ़ता गया। इस तरह यह खींचातानी अव पहले से वहुत ज्यादह कड़वी हो गई है। यूनो की असेम्वली के सामने यह सवाल इसी साल फिर आने वाला है। उम्मीद है कि असेम्वली फिर ⅔ के वहुमत से उस ठहराव को पास करेगी और दोनों देशों में लिखा-पढी करके या किसी तीसरे दोस्त राष्ट्र को पंच वनाकर इस सवाल का उचित हल निकाला जायगा। काले-गोरे के भेद-भाव या इस तरह का कोई भी भेद-भाव वडी गहरी वात है। इससे दो देशों में जडवा और जंग तक हो सकती है। दुनियां में शांति वनाए रखने के लिए, इन्साफ और इमान दारी के लिए कोई ऐंसा हल निकालना चाहिए जिससे दोनों की तसल्ली हो। हमारी प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित इतनी होशियार और काविल हैं कि हमें यकीन है वह यू० एन० ओ० पर असर डाल सकेंगी और दक्षिण अफ्रिका की गवर्नमेंट को भी यह समझा सकेगी कि हमारी वात कितनी इंसाफ की है और इस मामले का फैसला शांति के साथ ही हो जाना चाहिए।

इनके अलावा हमारे उत्तर में कई छोटे २ देश हैं जिनके साथ हमें अपने मामले साफ करने हैं। सवाल यह है कि नेपाल, भूटान और एक दर्जे तक सिक्किम के साथ हिन्द यूनियन का संवंध किस तरह का होगा? नेमाल हिमालय पहाड़ के वीच के हिस्से में है। पूरव से पच्छिम तक नेपाल की लम्वाई ५०० मील है और कुल फैलाव ६५००० मुरव्वा मील है। हिमालप की वरफ से ढकी हुई चोटियों से लेकर यह मुल्क उस समतल जमीन तक फैला हुआ है जो करीव सोलह मील चौडी है और जो गंगा के मैदान से आकर मिल जाती है। नेपाल की आवादी साठ लाख है। नेपाल की नदियों में व्यापारी किश्तियां चल सकती है। वहां वडे २ जंगल हैं, घन है, खानें हैं, संतरे, गन्ने, पटसन, हेसियन, चावल, ज्वार, राई, मक्का, जौ और आलू होते हैं। हमें नेपाल की इनमें से किसी चीज का लोभ नहीं। नेपालियों की शुद्ध आर्य नसल और शानदार कल्चर नेपाल और हिंदुस्तान के वीच की ऐसी कड़ियां हैं कि जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

नेपाल का राज एक खानदान के लोगों के हाथ में है। राजा पूरी तरह खुदमुख्तार है। लोगों का धर्म है कि उसके वफादार रहें और जो वह कहे सो मानले। राजा का खानदान हिन्दुस्तान के और राज-कुलों की तरह अहने को ईश्वर का अंश बताता है। देश की सारी दौलत राजा की निजी जायदाद है। वही उसका मालिक है। राजा गद्दी पर बैठता है। लेंकिन उसका प्रधान मंत्री राज का सब काम करता है। प्रधान मंत्री की गद्दी भी उसी के बेटे या उसी के खानदानमे से किसी न-किसी को मिलती है। राज हर तरह से एक अकेले आदमी का राज और लेगाम है। हिन्दुस्तान से बिल्कुल मिला हुआ इस तरह का बेलगामी राज हिन्दुस्तान के लोकराज के लिए चिन्ता की चीज हुए बगैर नहीं रह सकता। सन् १७९० में चीन की फौज ने सारे नेपाल को रौद डाला था। अब भी चीन और नेपाल में फासला उतना ही है। लेकिन अब नेपाल किसी तरह चीन के आधीन नही हैं। दूसरे देशों से नेपाल का संबंध बहुत मानी रखता है, क्यों कि सन १९२३तक नेपाल का वही रुतबा था जो किसी बडी देशी हिन्दुस्तानी रियासत का। सब सिडियरी संघ के आधीन अंग्रेज सरकार जब चाहे नेपाल में दखल देने लगी। सन१८४६ से नेपाल इंगलिस्तान के ज्यादह २ मातहत होता गया। सन् १८३५ से नेपाल हिन्दूस्तान के साथ केवल ईस्ट इंडिया कम्पनी की मार्फत ही सम्बन्ध रख सकता था। सन् १९२३ में एक संधिनामे के जरिए नेपाल को खुदमूख्तार बना दिया गया। दस साल बाद नेपाल को इंगलिस्तान के साथ राजनैतिक सम्बन्ध रखने की इजाजत मिली और इंगलिस्तान के दरबार में नेपाल का एक एलची रहने लगा। जंग में मदद देने के इनाम में नेपाल को हिन्दुस्तान के खजाने से बीस लाख रुपए सालाना मिलते हैं। पिछली जनवरी के महीने से नेपाल ने हिन्दुस्तान के साथ राजनैतिक सम्बन्ध शुरू कर दिया है। हिन्दुस्तान के राजदूत नेपाल में और नेपाल के राजदूत (अंबसेडर) यहां रहने लगे। पर इससे हिन्दुस्तान की तसल्ली नहीं हो सकती क्योंकि हिन्दूस्तान शुरू से यह मानता आया है कि पूरब के सब देशो में जिम्मेदार हुकूमत कायम होनी चाहिए। नेपाल में लोलराज के लिए आंदोलन नेपाली कांग्रेश की तरफ से शुरु होगया हैं। नेपाली कांगग्रेस ने पूरी जिम्मेदार हूकूमत की साफ-साफ मांग की है। वह थोडे दिनों में कलकत्ते में अपना इजलास कर रहें हैं। नेपाली कांग्रेस कहती है कि वह सत्य और अहिंसा के असूलों पर चल रही है। हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है और इसलाकी मदद भी।

हमारे मुल्क का एक हिस्सा है जो इस समय पाकिस्तान में है और जिसमें हिन्दुस्तान के दो बडे नेता बादशाह खान और डा० खान साहब कैद हैं। पाकिस्तान ने इन दोनों को अपनी तरफ करने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। हमें आशा है कि उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबे के सवाल का कोई ऐसा हल निकाला जायगा जिससे उस सूबे के लोग संतुष्ट हो जावें।

हिन्दुस्तान म और भी ऐसे इलाके हैं जो भूगोल की निगाह से, इतिहास की निगाह से और यों भी हिन्दुस्तान का हिस्सा है। पुर्तगालियों का इलाका है और फ्रांसीसी इलाका दोनों इस समय नया जन्म ले रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं। हमारी यूनियन गवर्नमेंट इन इलाकों के हिन्द यूनियन म शामिल होने के बारे में लिखा-पढी कर रही है। जाहिर है यह काम बहुत नाजुक और कठिन है। उन्हें हिन्द यूनियन में शामिल होना ही पडगा। हिन्दुस्तान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके छोटे-छोटे टुकडे अलग करके कोई बाहर की ताकतें उन टुकडों के साथ खेलें।

आगे की एक झलक

एक पल के लिए हम यह देखने की कोशिश करें कि आज से दस बरस बाद हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी। इस तरह की कोशिश के लिए दस बरस कुछ बहुत ज्यादह नहीं है। इसके लिए हमें जरा पीछे हटकर भी एक निगाह डालनी होगी। हमें यह याद करना होगा कि किसी समय अंग्रेज हमारे देश पर हकूमत करते थे, हमारा अपना दूसरे किसी से कोई राजकाजी सम्बन्ध न था, हमारे सामने अपने देश की रक्षा का कोई मसाला न था, कोई हिन्दुस्तानी फौज न थी, हमारे यहां की रेलें और जहाज सब विदेशियों के कब्जे में थे, तार और टेलीफोन बाहर से आते थे, देश से तरह-तरह का कच्चा माल और चीजें बाहर समुद्र पार भेज दिया जाता था, हमारे एक-एक विद्यार्थी को पहली जमात से लेकर युनिवर्सिटी तक अपने कपडों, खेल के सामान और पढाई के लिए हजारों रुपए का विदेशी माल खरीदना पडता था, हमारे सिक्के इंगलण्ड के स्टर्लिंग के साथ बन्धे हुए थे, हमारी रेलों के किराये इंगलिस्तान की पार्लमेंट के कानून के अनुसार एक बोर्ड तय करता था, बाहर से नमक, चीनी मिट्टी के बर्तन पुराने अखबारों की रद्दी, पत्थर, आलू, और सेब जहाजों के निचले हिस्सों में भर २ कर जबरदस्ती हमारे ऊपर मढ दिए गए थे, देश की सारी

तिजारत का मकसद यही रह गया था कि अंग्रेजों के रहन सहन को किस तरह ऊंचा किया जाय। कालिजों में, कचहरियों में और कौंसिलों में हम अंग्रेजी ही में सोचते थे और अंग्रेजी ही में बात करते थे, बल्कि यों कहना चाहिए कि हमारी तरफ से हमारे लिए विदेशी हाकिम ही सोचते थे, करते थे, राज करते थे, हकूमत करते थे, इन्तजाम करते थे, लडते थे, और देश की रक्षा करते थे। वह सब बातें अब जाती रही और सदा के लिए जाती रहीं।

इस एक साल के अन्दर हम जो कुछ कर पाए हैं वह कुछ काम नहीं है। जो लोग यह समझ रहे थे और सोच २ कर हंस रहे थे कि हमारी नैया किसी भी चट्टान से टकराकर खतम हो जायगी उन्हें भरपूर निराशा हुई है। नए आजाद देश की उभरती हुई राष्ट्रीयता बहुत तरह के अच्छे बीजों के लिए बडी उपजाऊ भूमि होती है। जरा सोचिए इंगलिस्तान की औरतों को वोट का अधिकार पाने से पहले खासकर आखिरी दस बरस से ऊपर तक कितनी तकलीफें और कितने कष्ट भोगने पडे थे! हिन्दुस्तान की हमारी बहनों को यह अधिकार एक रात-भर के अन्दर बिना मांगे ही मिल गया। मद्रास धारा-सभा के एक ठहराव ने सारे हिन्दुस्तान की बहनों के लिए इस बारे में मैदान साफ कर दिया। दुनियां में शायद ही कोई दूसरा देश आपको मिले जिसमें एक स्त्री विदेशों में राजदूत (अम्बैसडर) है, दूसरी केन्द्रीय सरकार की एक मेम्बर है, और तीसरी एक सूबे की गवर्नर है, और चौथी विदेश जाने वाले कई डेप्युटेशनों की मेंबर रह चुकी है। दुनिया की किसी सरकार ने इस तरह बात-बात में और हंसते-खेलते शान्ति के साथ अपनी हजारों बरस की पुरानी ठकुराइयों, जागीरों और खानदानी हकूमतों को नहीं मिटाया, किसी ने अपने जहाजी-धन्धे, अपने यहां की बिजली, हवाई रास्तों और तार-बेतार वगैरह को इतनी जल्दी राष्ट्र की सम्पत्ति बनाने की कोशिश नहीं की। किसी ने अपने मजदूर संगठन को भी इतनी तेजी के साथ नहीं सुधारा। जिस हिसाब से हम बढ रहे हैं, हम उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी सारी जमीन राष्ट्र की सम्पत्ति हो जायगी। हमारे खास-खास धन्धों (की इंडस्ट्रीज) पर भी राष्ट्र का कब्जा हो जायगा, सबके लिए रहने को मकान मिल जायेंगे। हर लडके-लडकी और इन्सान के लिए तालीम का इन्तजाम हो जायगा और सबके लिए दवा-दारू और इलाज का प्रबन्ध होगा, ताकि छोटे-बडे शहर के और

गांव के हर हिन्दुस्तानी मर्द और औरत को अपने राज का सुख मिले, सब उसे अपना राज समझें और सबको उसका अभिमान हो।

केवल उसी तरह आप कांग्रेस के असली मकसद को पूरा कर सकते हैं। कांग्रेस ने देश से रामराज का वायदा किया है। महात्मा गांधी ने राम-राज की परिभाषा इन शब्दों में की है:—

"धर्म की निगाह से रामराज का मतलब है इस धरती पर ईश्वर का राज। राजनीति की निगाह से रामराज का मतलब है वह पूरा-पूरा लोकराज जिससे अमीरी, गरीबी, रंग, नस्ल, या धर्म मजहब के आधार पर किसी तरह की ऊंच नीच नहीं रहेगी। राम-राज में भूमि और राज दोनों की मालिक जनता होगी। इन्साफ तुरन्त पूरा और सस्ता होगा।

"इसलिए पूजा वन्दगी की, बोलने की और लिखने-छापने की सबको आज़ादी होगी। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि सबके ऊपर आत्मसंयम (अपने पर काबू) का नियम राज करेगा, सब अपनी इच्छा से उस नियम के अधीन रहना मंजूर करेंगे।"

गांधी जी ने यह भी कहा है कि—

"मेरी स्वराज्य की कल्पना राजकाजी आजादी की कल्पना नहीं है। मैं जीवन के हर पहलू में धर्म का राज यानी सत्य और अहिंसा का राज देखना चाहता हूं........किसी का गुलाम रहना आदमी की शान के खिलाफ है।"

गांधी जी ने यह भी कहा है कि—

"मेरे लिए देश-भक्ति और भगवान-भक्ति दोनों एक ही हैं... शहंशाहियत के लिए मेरी जीवन-योजना में कोई जगह नहीं...दुनिया के राष्ट्रों का असली लक्ष्य अपनी २ अलग-अलग आजादी नहीं है। हमारा सभी का लक्ष्य है अपनी इच्छा से सबका एक दूसरे पर निर्भर होना। मैं अद्वैत का मानने वाला हूँ। मैं सब इन्सानों की बुनियादी एकता बल्कि सब जानदारों की एकता को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर एक आदमी रूहानी तौर पर ऊपर उठता है तो सारी दुनिया उसके साथ उठती है और अगर एक आदमी गिरता है तो उस दर्जे तक सारी दुनियां गिरती है।

उन्होंने फिर कहा है कि—

"मैं एक ऐसे हिन्दुस्तान को लाने के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से-गरीब आदमी यह महसूस करें कि यह देश उनका देश है, जिसके बनाने

में उनकी भी पूरी-पूरी राय और उनका हिस्सा है, उस हिन्दुस्तान में न कोई ऊंची जात होगी न कोई नीची जात, उसमें सब धर्मों के लोग पूरे मेल-मिलाप के साथ रहेंगे......इस तरह के हिन्दुस्तान में छूआछूत की लानत के लिए कोई जगह नहीं हो सकती और न किसी तरह की नशे की चीजों के लिए। स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को.·· यही हिन्दुस्तान है जिसका मैं सपना देखता रहा हूँ।"

हिन्दुस्तान का भविष्य और चेतावनी

मैं कह चुका हूँ कि हमारे प्रधान मन्त्री एक महीने से ऊपर तक इंगलिस्तान और फ्रांस में सफर करने के बाद लौटे। वहां उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बहसों में हिस्सा लिया और यू० ऐन० ओ० के इजलास में भाषण दिया। पर इन बातों से हमें फूल नहीं जाना चहिए। हम बहुत आगे बढे हैं। पर अभी हमें उससे कहीं अधिक रास्ता तय करना है। हमसे ज्यादह पुराने आजाद राष्ट्रों में जो पक्कापन, टिकाऊपन, धीरज, एका और समतोल है उससे अभी हम बहुत दूर हैं।

पर सवाल यह उठता है कि यह समतोल कैसे पैदा हो? समतोल की जड है कहां? इस पर दो अलग २ राय हैं। एक तरफ तो जोशीले सुधारक यह समझते हैं कि दुनियां बिना स्वार्थ के, बिना खुदगरजी के चल सकती है। दूसरी तरफ तजुरबा यह कहता है कि आदमी के अधिकतर काम स्वार्थ से ही चलते हैं। यह दूसरी बात है कि समझदार आदमी यह अच्छी तरह सोच-विचार ले कि उसका सच्चा स्वार्थ किसमें है। पर अपना स्वार्थ पूरा करने का खयाल तो रहता ही है। दुनिया के बडे २ फिलासफर और शास्त्रकार जिन गुत्थियों को नहीं सुलझा पाए उन्हें हम केवल एक बडा राज बना कर और उसमें सब आदमियों को उस राजरूपी मशीन के पुर्जे बनाकर नहीं सुलझा सकते। आदमी मशीन नहीं है, लोभ और स्वार्थ उससे यकायक नहीं मिट सकते।

तो फिर सच्ची शान्ति और सच्चा समतोल असल में लोभ और सन्तोष इन दोनों का ठीक २ मेल बिठाने में है। अलग २ आदमियों में हो चाहे राष्ट्रों में हो, लोभ ही सारी अशान्ति की जड है। यह सोचना कि अपने पडौसी की धन-धरती का हमें बिलकुल लोभ न हो तो बडी अच्छी बात है और जरूरी भी। पर जब हम इस तरह, इस देश के पुराने ब्राह्मणों की तरह, अपनी मामूली जरूरतों को पूरा करके अपने अन्दर यह समतोल

पैदा करलें तो फिर हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्र के सब दूसरे भाइयों और बहनों की जरूरतों को भी उसी तरह पूरा होने का इन्त-जाम करें। इंगलिस्तान ने धीरे २ अपने को काफी बढाया है और बनाए रक्खा है। फिर भी वहां गरीबों और अमीरों के बीच बहुत बडी खाई है। मजदूरों के लिए तरह २ का प्रबन्ध करके, बुढापे में पेंशनें और बीमारी या चोट लग जाने का बीमा, बेरोजगारी में खाना, रहने के लिए घर, यतीम खाने वगैरह बनाकर इंगलिस्तान ने इस खाई को पाटने की कोशिश की है। इन चीजों से लाभ भी हुआ है पर टिकाऊ शान्ति या सन्तोष नहीं मिल सकता। पश्चिमी सभ्यता जो लाग-डाट और जल्दबाजी पर कायम है और जो अपने २ देश की दौलत बढाते रहने पर और मशीनों पर जोर देती है एक इस तरह की चीज है जो खुद ही तो रोग पैदा करती है और फिर खुद ही उनका इलाज ढूंढने लगती है। हमने अपने देश में दूसरी तरह के हल निकालने की कोशिश की है। हमारी सभ्यता की बुनियादें सहकार और सन्तोष में हैं। इसी लिए हम बहुत दर्जे तक उन समाजी भूचालों और तेज तूफानों से बचे रहे हैं जो दूसरे देशों में आये-दिन आते रहते हैं। हमारी राय में दुनिया को एक करने के लिए या दुनिया-भर में एक राज कायम करने के लिए यही पक्का और सच्चा तरीका है।

आदमी के अन्दर की बीमारियों, उसके दिल और दिमाग के रोगों को हमें देखना और समझना होगा। माता के दूध के साथ हमें शान्ति और अहिंसा का पाठ बच्चों के दिलों में उतारना होगा। अहिंसा के प्रचार ने हमारे अन्दर जो कुछ किया है, और हमारे दिलों को जितना बदला है वह अभी बहुत ही कम है। फिर भी अगर हम इस बात का मुकाबला करें कि ३५ बरस के अन्दर दो इतने बडे २ महायुद्धों ने दुनियां में क्या किया और ३० बरस से कम में हमने क्या किया तो फर्क साफ दिखाई दे जाता है। पहले महायुद्ध ने योरुप का नक्शा बदला। रूस इन्सानी बराबरी का नया मजहब लेकर सामने आया और उस बराबरी को उसने खून की नदियों में से निकाल कर कायम करना चाहा। दूसरे महायुद्ध ने एशिया के नक्शे को बदल दिया। दुनिया की आधी आबादी एशिया में रहती है। जापान को छोड कर बाकी सारा एशिया इससे पहले पराधीन था। महायुद्ध नदी की बाढ की तरह इधर-से-उधर रेत और मिट्टी लेजाकर नये २ टापू बना देते हैं और पुराने टापू मिटा देते हैं। महायुद्धों से सच्ची व्यवस्था

और असली शान्ति कायम नहीं होती। यह काम जब भी हो केवल अहिंसा से ही हो सकता है। परमात्मा न करे यदि तीसरा महायुद्ध छिड़ा तो दुनिया की आधी आबादी केवल भूख और अकाल के कारण ही नष्ट हो जायगी। हमें युद्ध का स्वप्न भी न देखना चाहिए, इसकी आशंका भी भयंकरता से खाली नहीं है क्योंकि केवल आशायें ही फलीभूत नहीं होती हैं, कभी २ आशंकायें भी सच्ची हो जाती है।

महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने नई तरक्की और अच्छे २ नये विचारों के 'बाने' को पुरानी विचार-धारा के 'ताने' में बुन कर दिखा दिया। पुरानी रूढियों और रीति-रिवाज के मैल को उन्होंने अपनी सत्य की आग में जलाया और अपनी अहिंसा से नई गुत्थियों को सुलझाया और बेचैनी को शान्त किया। कमी केवल यही है कि उनके उपदेशों को अभी तक हिन्दुस्तान ने भी पूरी तरह अपने गले से नीचे नहीं उतारा। अगर हम जरा और हिम्मत के साथ उनके उपदेशों को समझने और उन पर अमल करने की कोशिश करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान दुनिया को उसकी सारी मुसीबतों के हल का रास्ता दिखा सकता है।

हर युग का एक राह दिखाने वाला होता है। यह दूसरी बात है कि लोग धीरे-धीरे ठोकरें खाकर और कड़वे तजरबों के बाद ही उसके बताए हुए रास्ते पर आते हैं। इस युग के इस तरह के राह दिखाने वाले महात्मा गांधी हैं।

जयहिन्द !

PRESIDENTIAL ADDRESS

INDIAN NATIONAL CONGRESS

Fifty Fifth Session

Dr. B. PATTABHI SITARAMAYYA

JAIPUR

18th December, 1948

Friends,

INTRODUCTORY

Once again we gather from all parts of India in this historic city of Jaipur after an interval of a little over two years and we gather too—not to challenge a foreign power ruling over us as we did at Meerut, but to organize ourselves for the independence that we have earned by means unknown hitherto to the world except perhaps individually to the Saints and Seers of India of old. It is our misfortune that the Father of the Nation who had led us to victory is no longer in our midst in flesh and blood, but his spirit hovers over this colossal gathering, aye, over the whole country, to inspire its reconstructive activities and guide them all along the paths of 'Satya and Ahinsa' by which he had overcome the forces of evil.

TRIBUTE TO THE DEPARTED

We bemoan indeed the loss during the short interval of many sons and daughters of India, and it is our first duty to perform 'Tharpan' in memory of their life and labours devoted to the emancipation of their motherland.

In the death of our dear departed Mahatmaji, we feel the Nation is orphaned as we cannot make up for the loss of that great soul which was self-luminous and which first kindled this flame of Independence by his own lamp of love. With "that love which would rather burn itself than burn others" to use his own epigrammatic language he conquered not only his internal foes—called the **Arishadvargas—Kam. Krodh, Lobh, Moh. Mad and Matsary**, but vanquished the external foe that pitted his mighty brute force against his impalpable soul force. By his Truth he conquered Untruth, by his Light, he conquered Darkness, by his Life, he conquered Death and by his Death he gave a new Life to his motherland.

There was nothing which he touched that did not antagonize vested interests whether in the learned professions or trades, whether in the learned professions or trades, whether in callings or industries, whether in society or morals. But there was nothing to which he touched that did not turn into gold. If truth was his sword and Non-violence was his shield, humility was his strength and love was his strategy. It was thus that he who was a Man amongst men, Statesman and Warrior, Artist in thought as well as achievement, also became in turn an Economist unmatched in the day, a Prophet whose elevation of politics to a religion will abide for ever, and above all a...**Sthitha Pragna** who had conquered attachment, fear and anger. Briefly speaking, he was an **Avatar,** who descended amongst us from on high and sought to raise the contemporary world to his level. He fulfilled his task of emancipating enslaved India and chastening the demoralised nation and departed the world like the rest of the Avatars, after he had accomplished his mission. He was a Sree Rama for maintaining the integrity of the spoken word, a Buddha for renunciation and a Jesus for service and sacrifice. He came weeping when we were all laughing and died laughing leaving us all weeping.

(a) "Yad dari-ko-wakt e-zadan-e-to Hama Khandan Buwando-tu-Giryan Hamchuna zi ke wakhte-murdane to-Hama giryan Buwando to Khandan."

(b) "Dost thou remember that when thou wert born
All were smiling and thou wert weeping
So live then that when the supreme
moment of life comes
Thou shouldst depart smiling and all others
should be weeping."

Our next sacred duty is to pay our homage to the memory of one who had fought with his life the battle for Swaraj. Our dear brother, Babu Subhash Chandra Bose who

is appropriately and affectionately known as Nethaji, was a real warrior, hero and martyr. He ventured upon untrodden paths, for his was the restlessness of patriotic fervour, and his was the high soaring faith in his country's freedom. And he was within an ace of success which always comes to those that dare and do. Subhash Babu dared and did, and gave himself up as a voluntary offering on the altar of the motherland leaving us as the beneficiaries of his immeasurable service and inestimable sacrifice.

OUR PATRIARCH

Pandit Madan Mohan Malaviya of revered memory had presided over the Lahore (1909) and Delhi (1918) sessions of the Congress and Sri Vijaya Raghavachariar over the Puri session in 1920. Both are the patriarchs of the nation justly styled the Grand Old Men of India and both belonged to that generation of labourers in the field of indian Nationalism whose work lies embedded deep and firm in the foundations of its edifice. Neverthaness, both had always been on a level with their age. Pandit Malaviya chose the sacred cities of Prayag and Kasi for abode and built unto himself a lasting memorial in the great 'Hindu University', while his contribution to the renaissance of Hindu Culture by his vast learning, devotion to Sanskrit language and literature and revival of the Sanathana Dharma, marked him out as the one ancient pillar of Hindu Faith and Philosophy with which we sought to erect our mansions in modern organization. Sri Acharya hailed from the south of india and was a Vidya Sagar in the fullest sense of the term. His knowledge of Constitutional Law and Commton Law, Case Law, and Customary Law would have been a tower of strength to us today. He was the very embodiment of courage and led the way to jails in a public cause in the earlier years of the career of the Congress.

Amongst those that have recently left us, beside our Patriarchs, are our brothers K. F. Nariman, a Parsi and

B. G. Horniman, an Englishman, but both Indians to the core. Nariman's ancestors had made India their home a thousand years ago. He himself suffered much for the country and served it long. His stupendous labours in the exposure of the Back Bay Frauds constitute a shining chapter of recent history (1925-26). He has left us at a time when the nation was hoping to do higher honours to him. Mr. Horniman made India his home and devoted fifty years of his life and energies to the liberation of this ancient land held in bondage by his own countrymen whom he chastised day in and day out, during five decades until at last they quit the country. Service and sacrifice are natural to a born son of the Motherland but that an adopted son should have shown both in equal measure revives the fading hope in the innate goodness of mankind and in the ultimate triumph of right and justice. All these and many more losses we have sustained. But the world never despairs and would not be progressive if their noble work came with their demise to a sudden standstill.

It is our duty in addition to recall the name of Quaid-e-Azam Mohammad Ali jinnah Marhum whose intimate association with the Congress till 1918 had helped to strengthen its foundations. That he chose gradually to be aloof from it, dees not detract from the great good work done by him in the early years of the Congress. He was a man of iron will and supreme self-confidence.

I am deeply grateful to you for the duties you have laid on me as the President of the 55th Session of the Congress and its first session held by a free and united India. It is also the first session held in a former Indian State. As you all know it is the place of nativity of our beloved patriot the late Sree Jammalal Bajaj who was the standing host of the Nation in general and of the Congress in particular. Yours is really a call to me to be the first servant of an

emancipated Nation. Such a claim on a President's part might not have been challenged in the years gone-by but this year I am seriously afraid of a challenge by the Prime Minister of the Nation and if sol I readily yield the place of honour to him, keeping to myself the simple and less onerous though the more ostentatious title of 'Rashtrapati' (president). But call your President Frist Servant of India or Rashtrapati of the Congress, the honour if at all and the burden in any case, lies really in the fact that India is free and is looking forward to real Independence. I cannot conceal from you my own unwillingness to call India free of the 17th of September last, because the last bastion of autocracy and personal rule had not fallen till then. It was that day that the strong, albeit, circumspect policy of the Government of the Indian Union, made India—every inch of her, wholly free and the credit for such an act of emancipation and achivement goes to the congress that has all along guided the Indian National Movement earlier through its President and later through its Prime Minister and Deputy Prime Minister as well.

FOREIGN AFFAIRS

During its long history of struggle for the attainment of India's freedom, the National Congress was naturally absorbed in this struggle and could not pay much attention to foreign affairs. Nevertheless as far as the early twenties we find the Congress passing resolutions about foreign policy. In spite of our absorption in our national struggle we always viewed it as a part of the struggle of all oppressed and colonial people. Because of this we symathised with all other peoples in the world who might be suffering from exploitation or the domination of a foreign power. We were anti-Imperialist not only in India but in the rest of the world also. Inevitably we became anti-Fascist. Whether it was in China or Spain or Abyssinia or Czechoslovakia, the

National Congress raised its voice against Imperialist and Fascist forces and governments.

2. Inevitably, as a non-official organisation, the Congress could only lay down general policy and was not concerned with any specific problem. It was concerned directly with Indians ovrseas. It was also concerned both directly and indirectly with the problem of racial equality.

3. Now that India is an independent country, the Government has to face world problems not only on the basis of principle but also on the far more difficult plane of application of a principle in a complicated situation. Normally India does not wish to interfere with other countries, just as India would resent the interference of any other country in its own affairs. But the world today, in spite of friction and conflict, is an inter-related organism and it is impossible for any country to remain in isolation.

4. Independence brings rights and privileges; also it brings responsibilities and duties which always accompany rights and privileges. It is an inevitable consequence of independence that we should develop foreign relations, have representatives in foreign countries, and take part in foreign affairs. In any event this would be so, but in view of the fact that large numbers of Indians live abroad, it becomes our duty to take interest in them. Also our trade requires foreign contacts and foreign relations. We have today unfortunately even to buy foodstuffs from abroad; we have to buy many other things such as capital goods and machinery for the development of our country. But above all we have to participate in this growing structure of a World Order. Not to do all this would mean that we relied on others to do it on our behalf which again means dependence on others and not independence.

5 India, therefore, as an independent country has naturally developed these foreign relations, sent her representatives abroad to many conutries, and taken a full part

in international connferences and more especially the United Nations Organisation which is gradually and painfully staggering along towards that conception of World Order and co-operation which is embodied in the fine language of its Charter. Some of these international conferences, more especially those dealing with Asia, are finding their way to Indian soil because inevitably India is. becoming the focal piont of many activities in Asia.

6. What should our foreign policy be ? Broadly speaking the old principles which we have laid down so many times should govern our present policy also. That is to work for the ending of all Imperialisms and the domination of one country by another, the ending of racial discrimination and the establishment of racial equality, and world peace and co-operation aimed at ultimately the development of a World Order or One World. These are general policies but in their application many difficulties arise specially in the world today which is suffering from an excess of fear and suspicion, and so soon after the last great war, is again thinking of yet another and a vaster and more terrible war. Groups of power face each other in their in embattled might and try hard to develop their warlike resources.

7. In this hard world of war and starife India cannot be a weak and helpless spectator. She has to guard her freedom, but she will guard it badly if she forgets the essential principles for which she has stood under the guidance of the Father of the Nation.

8. India's policy has been laid down as one of avoidance of attachment to any bloc of powers which is antagonistic to another bloc This is a difficult position to maintain and sometimes it brings odium from oil the contending parties. Yet, not only on the ground of high principle, but also from the point of view of practical necessity and the good of India as well as the world, it is the only policy that

India can adopt. India must therefore ceaselessly strive to develop friendly relations with not only her neighbour countries but also with the countries of the world and exercise such weight and influence as she possesses to lessen international rivalries and prevent the drift to war. In the recent sessions of the United Nations, held in Paris, India has played no mean part in following this policy and has shown to the world that she can be friendly and co-operative with other nations without becoming a hanger-on of this or that bloc. If India left this policy, then indeed there would be little hope, for only warring factions will remain.

9 India is more specially interested in what is happening in Asia. I should like specially to refer to the grave crisis in Indonesia where a brave and gallant people fighting for their freedom have been harassed and threatened continuously by an Imperialist power. I should like to send my greetings to the Government and people of the Repeblic of Indonesia and to assure them that our entire sympathy is with them. We are convinced that whatever the immediate future may hold there can be no doubt that ultimately the free Republic of Indonesia will triumph. Indeed I might say that the process of eliminating Imperialism from Asia cannot be stopped and must go on. Every foreign power that holds dominion in any part of Asia must depart.

10 Africa is in a somewhat difficult position, but the same principle holds good there although it may take somewhat longer to apply it. To the people of africa I should also like to extend our warm sympathy and I want to make it clear that we do not want any Indian vested interest to grow or to exploit the African people. We want Indians in Africa to co-operate with the people there for the advancement of those people. We stand for no domination over any other country and no exploitation of any other people by our people.

11 The question has arisen as to India's future relationship with the Commonwealth which used to be called the British Commonwealth of nations. It is clear that India is going to be free, sovereign, independent Republic in no way subservient to or dependent on foreign authority. That Republic will draw its power and authority from the people of this country. Those people will owe no allegiance to any foreign country or authority. That is clear enough. At present we are passing through a transitional stage of Dominionhood. Dominion Status has certainly meant in practice independence in domestic and external policy. Nevertheless the concept of the Dominion cannot be fitted in with that of the Republic. Therefore Dominion Status must go. The question then arises as to whether it is possible and desirable of the free Indian Republic to have some relationship with the United Kingdom and other countries nassociated with her. This relationship cannot be that of a Dominion. It can only be the association of free and independent countries agreeing to have certain reciprocal relations which do not limit in any way their freedom in regard to domestic or international policy.

12. It is within these limiting factors that the question has to be considered. I have said above that India cannot remain in isolation from the rest of the world. It is to the advantage of India, as it will be to the advantage of other countries, to have closer contacts and associations. This may help us in many ways and this may also help the cause of world peace. But whatever associations may be built up, they must in no way derogate from the complete independence of India and the freedom of the policy that she pursues. India is too big and important a country to be swept away any more by a gust of wind from foreign shores. We stand firmly on our soil, receptive to all the good that can come to us, cooperative with others but not allowing ourselves to be pushed about in any direction against our will.

13. The old world in which we have lived so long is rapidly changing before our eyes, India is changing. We cannot therefore, always think in terms of the past, even of the immediate past, for if we do so we shall forget the present and we shall not be prepared for the future. Therefore all questions have to be considered in the light of this new world that is growing up and the changing conditions that we are in. In these conditions we seek co-operation wherever we can have it, while maintaining our freedom and dignity. There are enough forces in the world today breaking up and destroying. We should stand on the side of the builders, not on the destroyers.'

HOME AFFAIRS

Now let us turn the torch inwards for a while, for the era of martyrs has passed. We enter upon an era of heroes and statesmen, of poets and philosophers, an era of re-construction of the Nation and the re-orientation of national outlook. We have really to get hold of the broken ends of the threads of national culture snapped a thousand years ago and piece in with them the fibres of our modern progress. The past cannot be ignored, it lives in the present; the present is ever receding and heralding the future. The Past, Present and Future from the eternal spiral of progress, each coil carrying us to a higher altitude, so that we perpetually scale new heights. It is evident then that today we are at a turning point in history when conceptions based upon wealth yield place to those that emphasize service. Hindu society has all along been balanced between the claims of learning and the rights of wealth. It is for us to reorganize society and work out a composite structure so as to incorporate in it the basic principles taught by Mahatmaji. We have a population of 30 crores and a power resource of 60 crores of hands with a vast reserve of deftness and dexterity, All work is worship and the culture embedded in skilled workmanship is the greatest proof

of learning before which standards set up by universities pale into insignificance. The cry for leisure and study is a call of Theory divorced from practice, while the craft life of India and her cottage industries are a proof in practice of India's ancient civilization and advanced culture.

Our Goverments, Central and Provincial, have had none too easy a task before them. They are challenged on the one hand to implement the Election Manifesto which embodies certain principles and policies. But when these have to be put through two years after they had been drawn up, we find conditions not altogether congenial. The taking over of key industries cannot be done overnight. The Industrialization of the country is a problem of vast magnitude and is beset with unknown impediments. Capital goods are not available for love of money, Conditions change so swiftly that it is difficult to keep pace with their ever recurring mutations. The time lag always makes the gap between yesterday and today almost unbridgeable. That is not all. The day-to-day issues absorb all attention, the long range planning,—of the country and of its units, its industries, its resources and its needs, is postponed for no fault of the several Governments which even now bite more than they can swallow. Here are the Zamindaris which we undertook to abolish, but their abolition requires over 300 crores of compensation which would forthwith add to inflation by adding a quarter to our currency. Here is prohibition which would lose to the Provinces a good bit of their revenues and therefore make for deficit budgets—another supporter of inflation. Here are multipurpose river-projects which are urgently needed for the grow-more-food campaign, but which are a fruitful aid to inflation and more inflation. Here are cottage crafts the promotion of which is apt to restrict the flow of consumer goods from abroad, and therefore neutralize an effective remedy to the distemper of inflation. Life then is seen to be a bundle of contradictions, and therefore must be a cluster of compromises. The Congress has a radical

programme of nationalization of key industries, but for starting new concerns it requires cavital and talent as it does for taking over the old ones. It is easy for the captains of commerce and industry to withhold capital and plead that capital is fighting shy because of our radical programmes. our exacting scales of taxation, our relentleess methods of prying into secrets of business. Shall we then allow business monopoiies, fat dividends and evasion of taxes ? Dictation of terms whether by capital or labour, whether by Governments or Industry would be detrimental to corporate action and concerted effort. These are all matters of high policy and administration and we trust ourselves to the trained talent of Government for evolving proper solutions of problems of a complicated nature.

Government has incurred the displeasure of the public and courted a certain measure of unpopularity because corruption has been so well established that it excites no regret anywhere except in the sufferer. But every one that bribes, prospers, and bribing in the eye of the Englishman who ruled during the war. did not appear a crime. Bilateral crimes must imply bilateral responsibility. In this view he who pays is even more guilty than he who takes-whether in bribery or blackmarketing. For every offender who takes a bribe or blackmarkets, a thousand people have to be arraigned as abettors or accessories or even as parties and partners in crime. Government themselves are tossed about from pillar to post in regard to controls. Human resourcefulness transcends all Law. Law itself is in its very nature ambiguous and therefore the very fundamental rights enjoyed by people give them protection in the perpetration of crime. Personal rule and crime are incompatible with each other. Paradoxical as it may look. the rule of Law and the perpetration of crime are friends. That is why the Congress Governments are not able to give a glowing account of their achievements. Yet the achievements of the congress are remarkable. In the domain of Labour and Industry, in the treatment of evacuees and

recovery of abducted women, in the departments of Health and Education, in the sphere of communications and River projects, in reorganising the Army and reconstructing the States, there is a good credit balance maintained in favour of the Union Government.

The Hindu Law Code is on the anvil. It is a momentous measure. Since its introduction and progress through the legislature chiefly at the instance of the progressive and reformist section of your sisters, orthodox opinion has become audible. But in India orthodoxy while having its legitimate claim has become effete and inoperative clinging as it does to a bygone faith which has become a formula. orthodoxy has as much a place as heterodoxy in the annals of a country, but it must be live, animated and fall in with the changing times If the Sanatanists moved forw rd a step or two, they would be helpful members of our caravan and not clogs that drag it down and back.

The indications of the nation's progress and the inalienable principles on which it is based are embodied in the chapters of Fundamental Rights and Directives of our Constitution. They form the floor and the roof of the Constitution. The rest of it is the rest of it—scaffolding, equipment and furniture of the edifice of Indian Nationalism. We aim at nationalism pure and undefiled, not corrioded by religious bias, nor corrupted by communal canker. India as the meeting place of the world's religions—Vedic, Buddhistic, Jain and Sikh, Islamic, and Christian is the one country that is competent to evolve the right kind of nationalism, —which is enriched, enlivened and ennobled by true religi n. When religion instead becomes credal, dogmatic and domineering, it exerts a cramping influence on the outlook of life and cribs its achievements.

STATES

For the first time, we are in the enjoyment of Swaraj. The Liberty that it represents has not descended upon us like Mannah from the Heavens. It has been rightly in-

scribed on the great big arch of the Northern block of our Central Secretariat in Delhi that:

> Liberty does not descend upon a people. A people must raise themselves to Liberty. Liberty is a blessing that must be earned in order to be enjoyed.

This noble text carved on the Secretariat supplies the key to the attainment as well as the maintenance of Swaraj. *This big estate of ours has been left to us by* those who had poached upon it, with adequate assets doubtless, but with numerous encumbrances as well. We have got clear of the latter, one by one, but we are not out of the wood yet. Kashmir was a calculated legacy along with its balancing weight, Hyderabad. It was quite up to the British to have converted both these liabilitiest into assets but Imperialism dies hard; and long accunstomed to devious ways and dividing tactics, the British by their last act, left in India 562 Ulsters. Our Natsonal Government, however, has tackled the problem with strength and skill and displayed such marvel and might in solving it that high encomiums were showered upon the States' Ministry presided over by the venerable Sardar. He brought to bear upon the settlement of the issues before him a measure of farsightedness, diplomacy and decision so that all obstacles gave way like a house of cards before the first breath of gentle breeze.

The problems of Hyderabad and Kashmir are in sight of solution. Our one aim and purpose is to replace mediaeval feudalism by modern nationalism. Let us hope we have reached the end of the infantile diseases and distempers that invariably affect nascent nationalism. We raise our hands in salutation to our troops and officers whose first exploit is an achievement worthy of India's reputation for prowess and valour.

Much has been achieved in regard to the integration of the States, but much more remains still to be achieved. We greatly appreciate the act of sacrifice on the part of the Maharaja of Gwalior who though himself the head of a viable State, has chosen to group himself with Malwa. Here is a noble example to emulaate for the Maharajas of Jaipur, Jodhpur, Bikaner, and Jaisalmere. May we not expect a larger Rajasthan compounded of the Matsya Union, and the present group of Rajasthan States together with the aforesaid four States? Rampur and Bhopal have yet to integrate themselves. The outlying States of Cooch Behar, Tripura and Manipur offer a mixed problem of both civil and military interest. A rational integration of Travancore and Cochin with Kerala, and of Mysore with Karnataka is in the offing. Likewise Sourashtra and Gujrat including Baroda have to mix and make a united Brihad Gujrat State. The so-called viable States may well disappear as such. They are out of date, and out of tune with the ideals of modern democracy. The problem of the States, has only crossed the major hurdle. Besides the Princes, there is a body of intermediaries, notably in Hyderabad, Gwalior, Jaipur, Jodhpur and Bikaner who hold real power in their hands. Indeed the Princes have been subjected to blame for the sins of the latter who are known as Jagirdars, Viswedars and Ilakadars. They possess Revenue, Civil and Criminal powers. The excesses complained of in the States are largely traceable to their initiative. Our next step should be the abolition of this class of estates, as we are seeking to end the zamindaris in our provinces. We hasten, however, to make it clear that just as we are against tenures and powers and not against the holders thereof, we are only against Jagirs and not Jagirdars. On the contrary, we must absorb them all into the virgin fields of Industry and Diplomacy where their administrative capacities and the rich traditions of their rulership may well be pressed into service—much to the advantage of the Nation.

Public attention may here be drawn appropriately to the fact that settled Government has not as yet come into being in the States under the new set-up. Imagine an old tiled house demolished, to be replaced by a terraced one. The tiled and the bricks, the scantlings and the stones are all scattered round about while the owner nestles in a corner, treading over the debris in which in addition scorpions and snakes make their abode. The States in transition are just in that state. Formerly the people had their Prince—living round about them, accessible at all times, and disposing of suitors with sweet words and sweeter manners. But today the Revenue officers are miles away and all communications are to be on paper and sent through the proper channel. In effect then under a feudal system with a prince at its head, there used to be a direct approach to the highest authority while under a democratic Government, the approach is through the whole gamut of a heirarchy from the Patel and the Patwari to the Prime Minister. Time and patience are the only remedies to the prevailing distemper which is an inevitable phase in the process of recovery.

(a) LINGUISTIC PROVINCES AND (b) CHIEF COMMISSIONERS' PROVINCES

There is yet another problem awaiting solution by one who can think in broad sweeps and wide curves. Leaving alone the dismembered fragments that have seceded, India today stands as a single, united Federation composed of States and Provinces which will be pieced in together to form the new Indian Union on a Federal basis. The Federal structure of our polity is not a new discovery for it was planned out so early as in the year 1917 as part of the 'Home Rule Movement' with the States as integral parts therein. Its basis is Provincial Autonomy and the Federation is formed by the grouping together of certain

powers voluntarily surrendered by the Provinces in recognition of the community of interests of the nation as a whole. Each cush Provincial unit then has to build up its internal strength by its own unaided resources and it is gratifying to contemplate how adequate and varied these resources are. Only the units must be provided with suitable opportunities of marshalling all available resources by their own genius. Such a genius is inborn and resides in the unsophisticated masses of the country who, though illiterate are cultured, though uneducated, can speak and administer Again such a genius can only express itself in the mother-tongue of the people, which is often the regional language of the provinces. Hence the need to carve out institutions —educational, administrative and Legislative which transact all their internahl affairs through the Regional Language. That is the rationale of redistribution of India into Linguistic Provinces.

The British were not concerned to think out the Indian problem on lines of rehabilitating Indian Nationnlism built out of homogeneous units. The North of India is fortunately being administerred, roughly speaking, even now, through such homogeneous provinces; but not the South. The problem of the two divisions, North and south of the Vindhyas is peculiar to each. In the south, you have no homogeneous provinces. Madras is now divided between four languages, till lately five; Bombay between three, till a decade ago four, C.P. between two. The Kanarese live under four administrations and the Maharashtras under three. Professors and students in colleges, lawyers clients and Judges in Courts and Legislators in Assemblies do not understand one another. English is known to so few and altogether so alien to the millions of the people of the provinces that it has not proved a common vehicle of expression. Voting in Legislatures is, therefore mechanical, being enforced by party whips who have to be obeyed unquestioningly by the party members,

though really they do not understand one another. This reminds one of a story: The Viscount de Boisville married a Russian Lady. It was an ideal match for, as neither understood a word of the other's language, they could not argue, dispute or wrangle and even if they had been inclined to quarrel they would not have known how. Shall we follow this ideal arrangement and vote by raising our hands like the wooden pointers of a motor car operated by the driver through a button to show the direction of the ca'rs movement ? This is why the sympathy of the North is bespoken by the South.

A Commission has been appointed in this behalf by the Constituent Assembly and it is time its considered report was published. The difficulties that confront the Constituent Assembly and the Government are perhaps many and varied but human intellect is given to solve problems and not shelve them, and we have no doubt that with understanding, sympathy and courage, with breadth of vision, a stern sense of the practical and a due balancing of the immediate with the remote, we can readily find out solutions that will satisfy the legitimate demands of the advocates of the movement,-which, by the way, is not a mushroom growth but over thirty-three years old in the country and which is not a depressed class mission, nor a backward community movement, but wholly is national in outlook constructive in character and democratic in demands. When the immediate issues affecting the South are settled, as they are bound to be so, as to include our new provinces in the schedule of units of the new Union, the Government of the day will have to face the problem of realigning the boundaries of all the provinces in India so as to minimise the difficuities of bilingual areas and recognise the stern fact that such areas are the 'hyphens' that unit—not the 'dashes' that divide. A country is neither a geometrical entity in shape nor is a nation a geographical entit in composition. They are a mixture of people whose development depends upon historical traditions, physiographicalenvironment, climatic condi-

tions and geo-political forces. Language is their binding fator. Culture follows as a corollary. Customs and manners and qualities of head and heart tend to vary. A nation thus comes to consist of subnationalities, whose distinctive cultures serve as so many tributaries which by their confluence with the parent stream enrich its waters both in volume and content. The colours of the rainbow are seven in number—even so they are not geometrically marked off from one another. They shade off, one into the other. Really there are 4, 000 shades in them as the scientists say. Where there is intermingling of languages, there they form bilingual areas and each may have to be treated as a minority in the other. When the provinces are divided, it must be our study to create such confidence in our monorities that are long they may begin to feel that our motherland presents a composite, homogeneous nationality which like a multifacleted jewel reflecting variegated colours, is composed of different cultures reflected through diverse provinces. Unity is not uniformity but harmony in diversity.

We have an allied problem to face when we deal wits the Chief commissioner's Provinces which demand that the benefits of democracy should be fully extended to them. This demand has been recommended by an AD Hoc Committee of the Constituent Assembly. They cannot be treated as the Cinderellas of the new home. Ajmer may be absorbed into Rajasthan ultimately if the people so desire and may even become its capital. Coorg must join one of its neighbours in accordance with the wishes of its inhabitants though there is a school that chooses to remain isolated. Delhi may well be made a Lieut-Governor's Province as a permanent measure as also the other two, pending a final settlement.

But the opinion has been expressed that while these problems require a solution and while the solution offered cannot be open to question, this is not the time for tackling the complicated issues involved therein. Is there one

problem before an emancipated nation entering upon a programme of national reconstruction which is free from complications, from the tyranny of long enjoyed inertia ? The problems of a State cannot be arranged in a queue each waiting to take its turn in the omnibus of national progress. The French and Goan territories have to be recovered. The States had to be absorbed. Shall one of them wait till the other is completed ? A bad thing cannot be made good by mere waiting. A really good thing need not be put off for any reason whatever, especially when it is fundamental. Let thefore Governmenr take up this problem broadly and boldly and make a people's rule possible by removing the obstacles in their way,

It is true that extremes of passionate agitation alone awaken the dormant consciousness of a moribund nation, but when that consciousness is roused, a wise counsel, a moderate expression, a cautious rendering of the pledged word into practical action--it is these that constitute title to success and ensure it in abundant measure. Our Govornment has displayed all these qualities in due proportion and well may we look forward to a continued period of harmony and good understanding, fellowship and co-operation between the personalities that represent the Government of the day and the forces that represent the progressive spirit of the nation.

LABOUR

Labour is life, labour is the ternal wealth of the world. rural and urban, labour is the inexhaustible capital that shapes and sustains the organised industry of towns and the as yet unorganised occupations of the village. Labour has thus come to play not merely a prominent but pre-eminent part in the socio-economic structure of the country. It may be remembered that the Congress election manifesto embodied certain pledges in respect of labour. The success of Gandhian principles in labour at Ahmedabad has encouraged a wider

application of those principles in the field. They uphold the eradication of all exploitation, the speedy improvement of their conditions of work and life, their status in industry and society and the advocacy of the principles of Truth and Non-violence in their application to problems of labour as to other problems.

To give effect to these objects the Indian National Trade Union Congress has been brought into being. The object of this Congress is:

'To establish an order of society which is free from hindrances in the way of an all-round development of its individual members, which encourages the growth of human personality in all its aspects and goes to the utmost limit in eliminating progressively social, political or economic exploitation and inequality, the profit motive in economic activities and organisation of society, and the anti-social concentration of power in any form.

The Working Committee has recommended to all Congressmen to get the unions which they are organising and of which they are members, affiliated to the newly formed Indian National Trade Union Congress. No one gainsay the fact that despite these steps, there prevails a certain unrest in the sphere of labour which calls for attention.

While the means suggested by the Congress for improving the relations between employees and employers and for promoting amicable settlement of disputes will help to relieve the situation, the fact remains that the inflated level of prices which still persist is retarding the restoration of normal economic conditions and is leading to a vicious race between prices and wages, accentuating the existing difficulties and that no lasting solution of these difficulties will be available so long as a definite policy regarding a future price structure does not take shape and an orderly

and just basis is not provided for the economic relations in the country. While these fundamental problems can be handledp only by a Central Government, the Congress fells that such integration of policy and action in this matter as is possible in the provincial sphere should be attempted immediately.

The Country is well aware of the rapid stride the Central Legislature has effected in reeent months in the way of realising the objectives set forth by the Congress both in its election manifesto and in the directives that followed the elections.

The Indian National Congress having pledged itself to ensure a fair deal to India's toiling millions the Congress Governments become wedded to the policy of ameliorating the condition of labour. The doctrine of 'laissez faire' generally pursued by the previous Governments in matters relating to labour has yielded place to a positive and clear cut policy based on the concept that labour was not a commoditg of commerce, but an honourable and indispensable partner in indus try To 'discharge its obligations to the working classes, the Ministay of Labour has initiated a comprehensive and radical, if not revolutionary, programme of labour legislation and administrative action on the pasis of the Five-Year Plan dra' wn up by with the Labour Minister in 1946. The Plan envisaged revision and rationalisation of the existing labour laws with a view to bringing them in line with progressive legislation in the more advanced countries of the world, fresh legislation, standardisation of procedure for the settlement of industrial disputes, regulation of conditions of work, and launching large-scale welfare schemes for workers in general and coal-miners in parti-cular.

The Industrial Disputes Act, 1947, the Minimum Wages Act, 1948, the Factories Act, 1948, the Coal-mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948, the Em-

ployees State Insurance Act, etc., have been placed on the Statute Book with remarkable speed. Some of these enactments have been hailed by the country as 'The Charter of Workers' Rights." The Industrial Disputes Act reinforced by the administrative action taken to set up a tripartite machinery at various levels, for the resolving of industrial disputes through the peaceful and lawful method of arbitration and conciliation, constitutes a sound and positive step towards preventing loss of production through industrial conflict reflected in strikes and lock outs.

The Employees' State Insurance Act, which is already being implemented by the Ministry of Labour, is the first step in the direction of social security to be followed by more comprehensive action in the light of experience. The Factories Act is another noteworthy piece of legislation. which will have the effect not only of substantially improving the conditions of work in factories, but would remedy many age-long iniquities. It will benefit 25 lakhs of industrial workers.

A plan for building 50,000 houses for coal-miners has already beeh launched in the coalfields of Bihar, C. P. and West Bengal. There is another plan to construct a million houses for industrial workers all over the country. The Ministry of Labour is operating a comprehensive scheme of National Employment Service with a net-work of Employment Exchanges and Technical and Vocational Training Centres, the scope of which has been considerably widened to ensure the proper utilisation of the vast manpower resources of the country.

The problem of agricultural labour is a colossal and complex one. In the context of conditions in India, with her predominantly agricultural economy, this problem has to be tackled urgently. As a first step, an enquiry for the

collection of data which is essential to the formulation of policy has been started with the co-operation of the Provincial Governments. Moreover, powers have been derived under the Minimum Wages Act, 1948, to regulate wages in agriculture, as in industry, should the prevailing wage level be found to be iniquitable or below the standard. The legitimate rights of this most depressed section of the Indian working class should be secured and neither the complexities of the problem nor the serious difficulties in finding suitable remedies should deflect us from fulfilling the most urgent task of raising the standard of living of the agricultural worker.

The Ministry of Labour has achieved substantial results in a short time and has a spectacular record of which we can legitimately be proud. The preparatory Asian Regional Conference of the I.L.O. held last year in New Delhi brought out the fact that in labour matters, India was certainly taking the initiative in Asia. In India, a silent revolution is taking place and a new order is being born—an order in which exploitation of labour will be a thing of the past.

RURAL RECONSTRUCTION

Our Constitution is being hammered out. Let us ardently hope that under it, the villages of India, which form the centre and starting point of Indian Nationalism, will be restored to their pristine position and once more play a dominant part in the reconstruction of national life. We had been piously hoping that our Constitution would strike a new path and we rejoice to think that it has conceded the village its high position in the economy of the Nation. That alone will enable us to see that the constitution should be not like the habilaments of a person which have to be changed with variations in his growth and bulk, but rather be like the bark of a tree which grows with the girth of the tree. This would be possible only when the

constitution works out the genius of the Nation through its several organs. Village reconstruction and ecraft life are the real keynote of such renovation.

While labour has been vocal and even vociferous. labour relating to agriculture and village industries has not so far received the measure of healthy attention it deserves. Such self-assertions as agricultural labour has of and on displayed, have been not merely spasmodic but even erratic and only indicate the orderly regulation which it demands at the hands of the Nation. Our misfortune in the past has been that while the three millions of industrial labourers had begun to secure adequate measure of study and attention even during the days of the British, rural labour involving many more millions was wholly neglected by them, for they did not stand to gain aught for their country through its organisation on up to-date principles of modern life and society. Even the so-called Kisan Sabhas are peopled by proprietors of land not the landless cultivators.

Revenue Earning—Nation Building

The fact is that during the past hundred years the organisation of the Government Departments under the British had paid all attention to the efficiency of Revenue earning Departments which acted as its steel frame, duly supported by the Police and the magistracy, resulting in considerable neglect of the Revenue spending or nationbuilding departments which cover the socio-economic services dealing with rural India—such as Public Health, Agriculture, Veterinary, Education, Industries and Co-operative departments. These six departments have received scant attention not merely at the hands of the Central and Provincial Governments, but also of the political organisations of the day which gave high priority to problems of political emancipation and of the attainment of full political freedom. With the birth of New India on the 15th of August, 1947, and the down of political freedom emphasis has shifted to the socio-economic development of the

country. It is not as if the rural economy today is much the same as it was thirty years ago, What little of change there is, is due rather to time force than spirit force. The two world wars have so rudely disturbed rural economy that the outstanding problem today is deficiency of food, which has naturally become worse with increase in population and the separation of Burma from India,

Several Governments, voluntary organisations and private institutions have organised during the past thirty years suitable model rural reconstruction schemes throughout India which consisted in making 'model villages'. Most of the private organisations were 'one man shows' and died with the enthusiast who started the scheme, and in the case of Government schemes like Brayne's in the Punjab, they failed because they superimposed modern ideas on the villager, and the villager never felt these are for his good or are of his making. 'Model villages' were made by Government officers who held the 'big stick, and these collapsed soon after the enthusiastic Officers' transfer; nor could they by copied elsewhere, as the men, money and material put into 'models' are not available for other villages. Albeit, the need for improving rural India has been recognised all over the country and socio-economic surveys and careful plans and reports based thereon are available which deal with all aspects of village life as well as its special needs. The twenty-six volumes of the National Planning Committee sponsored by the Congress vouch for the former while the four volumes of the Bhore Committee Report on Public Health and Sergent Report on Education deal with health and education respectively. Several other valuable reports on agriculture, industries, marketing and so on are available. These are all awaiting implementation, and some of them are being implemented piecemeal in various parts of the country.

Another set of plans are available for increasing the production of food, industries, and cheap hydro-electric

power, such as the Multipurpose Projects of Damodar, Rampada Sagar, Kosi and Hirakud sponsored by the Provincial and Central Governments and the Central Water Works Irrigation and Navigation Commission (CWINC) while the country is flooded with similar projects on several water ways. The Reclamation of agricultural land lying waste which although quite fertile under a fair rainfall, and more so under these new projects has not been possible so long owing chiefly to Malaria, a portion of it is now being reclaimed by tractors as U.P. Terai. A combination of these land and water reclamation schemes throughout India will in the next 10-15 years provide more food, more power for industries, and help in the settling of population more evenly, so stabilising rural agricultural economy in Indian village life.

It is all very well to plan at high level, and the country will look forward very eagerly for the results of these projects in the next 10-15 years. But we cannot afford to wait for another generation without doing something in the Indian Villages with the limited resources of men, money and materials we have at present. The Indian villager cannot be told for the next 10 years that political freedom has dawned, but for economic freedom to begin to have its effect on his daily life he has to bide his time for a decade to come. Further, Food must be produced in rural areas and some organisation is called for at once at the bottom —at the village level—so as to give immediate relief. How can we give it ?

A brief description of the evolution of Government Departments during the past 100 years will be helpful at this stage. The Revenue taking departments were the first to be organised aided by the police and the judiciary. The country was divided into provinces. districts and tahsils. Each tahsil formed the revenue unit under a Tehsildar. The average taluk has 100-200 villages with a population n,of 100 to 200,000 persons and an area of about 100 to 250

square miles, There were 10-20 taluks in a district with an average district population of 2 millions. Even for revenue purposes the Tahsil was founded to be too big for a Tahsildar and so it was divided into about 5-10 firkas each in charge of a Revenue Inspector. Each village had a village headman or Chowkidar, who collected the revenue, and so its collection was well organised from the village upwards. But the villager was not interested in the efficiency of the revenue collecting departments and soon began to realise that the Government were not interested in his needs which are connected with the six development departments. These Departments grew up as noted from 1919 with directors for the provinces district and taluk officers for districts and tahsils, They however ceased to exist below the taluk level, with the Health Inspector, Agricultural Demonstrator, Educational Inspector, Veterinary Officer, Co-operative Inspector and Industrial Supervisor. The Directors of these departments passed on their ideas in the shape of circulars to the District officers who in turn passed them on to the taluk officers and there the circulars stagnated. The strongest link in the chain should have been the last link from the taluk to the village, but this became the weakest link. The taluk officer had 200 villages spread over a large area with inadequate transport facilities and communications and took three years to finish his range devoting a day for each village, and at the end of his period he was transferred invariably, for administrative reasons, only for his successor to start his fresh contacts once again. He had no more powers than to give 'talks' to the villagers, and when at the end of any of these talks the villager was asked if he had any doubt he invariably asked for a 'drinking water well'. The officers realising that all was not well that ended in the want of a water well quit the village offering to communicate their request to the authorities concerned a cycle is completed and the same cycle duly recurs. Largeness of jurisdiction was the

chief evil of these six departments. The second is their inco-ordination. These six departments which represented the six needs of the villager affect to serve the villager without any idea of the departmental activities. Thus, the Health Inspector told the villager that manure heaps are deleterious, to their health, as the manures breed flies and flies convery disease germs from filth to food. When the Agricultural Demonstrator next visited the village he told them manure is valuable to their lands and must be carefully preserved, and the same Government paid both officers to give them these talks which the poor villager was unable to put together. If both were co-ordinated, they would have told the villager to do composing of manures which does away with flies, as well as preserves their nutrient qualities. Spencer Hatch an American Missionary who had done several years rural work in travancore wrote in his book 'Up from Poverty that the six square yards of the Indian villagers' hut are looked after by six different departments at six different times of the year, one vaccinated his children, the other inoculated his cattle, a third offered to supply iron ploughs, manures and seeds etc., without the villagers' primary needs o a drinking water-well, village road and village school being satisfied.

A solution is needed to reorganise all the development departments; whose two chief evils are the large jurisdiction and want of co-ordination of the taluk officers. These six departments are fairly well organised at the top, at the Central Government and Provincial Government levels, and have three sections, Administaration, Research and Teaching. These offcers at the Centre and at the Provinces passed on their ideas in the shape of circulars to their district oficers who in turn passed them on to taluk officers, where they stagnated. A firka system as in the case of the Revenue Department is needed for these departments, on the lines indicated herein below:

The Bhore Committee Report after a careful survey and detailed study of the health conditions throughout the country has recommended the District Health Organisation with its smallest unit of administration, the primary unit, which will normally serve an area with a population of about ten to twenty thousand people. A number of such primary units (about 15 25) will together constitute a secondary unit, and a varying number of the latter (about 3-5) will form the district health unit. At each of the head-quarters of the District, Secondary and Primary units, will be established a Health Centre as a focal point from which different types of health activity will radiate into the territory concerned by each type of unit. The Committee has divided its plans into a long term and a short term programme; the former requiring 30-40 years and the latter worked out in some detail for two successive stages of five years. The Bhore Committee has also stressed the need for the national programme of reconstruction on a broad front. It stated 'the advance that can be made in any one section of this front will largely depend on the progress made simultaneously in others; in the circumstances it is important that simultaneously with the inauguration of the Health Scheme, the reconstruction plans of other departments should be brought into operation in the same areas.'

The scheme proposed consists in putting a primary centre at the centre of a circular area of 6 miles radius, called the 'Primary Ruro-urban Centre or Rurban Centre as it links the 100 square miles of villages in their circle having 20-30.000 population to the nearest Secondary Centre at Taluk headquarters, and serves to give urban facilities in a rural area. This centre will have all the six departments which serve the villagers' needs all at one spot, and any villager can reach it by walking 5 to 6 miles distance. There will be accordingly in the Health Sectio

a rural dispensary and a hospital with beds, inoculation and Vaccination centre, sale of medicines and drugs. such as quinine, disinfectants and first aid appliances, health visitors and midwives; the Agricultural Section will contain manures, improved seeds, and appliances and sprayers which can tackle insect pests of both plant and human diseases like malaria and plague; the Veterinary Section will contain Vaccines and medicines for cattle pests, and there will be a co-operative bank, co-operative stores catering to all the essential needs of the villager, a polytechnic which teaches village industries and handicrafts notably spinning and weaving, adult education centre, a model school, rural radio centre, a post office, a police station and a panchayat office. Officers to man these various sections may be drawn from the existing Government officers and students who graduate from Medical, Engineering, Veterinary, Agriculture and Teachers' Colleges who will compulsorily do social service in such a centre for a period of 1-3 years after leaving their service as part of their courses of training. The budget may be met from the people themselves who can afford to pay for these services, the local boards and the provincial grants, and voluntary agencies like 'Gandhi and Kasturba Mamorial Funds'.

The administration may be left to a working committee elected from the local representatives from the villages of this circle, as well as the representatives of experts from the district and taluk officers.

It is hoped that this organisation at the village level would give immediate relief to the villagers in a measure in place of the existing development departments which do not extend beyond the taluk stage and therefore do not really operate. These primary centres will help to link the village rural life with the urban life and take the place of the 'middle men' who form the present economic links

keeping the high level of rural indebtedness in the country with the consequent low level of the rural standard of life. Lastly, these centres which take some time to be firmly established will be the distribution centres through which the high level plans to increase production can reach the remotest Indian village. High level planning will take time and even when it is in full swing it needs the villages organisation envisaged here. Urban areas may be industrialised but rural areas will remain for ever as the producing centres for food and raw materials to supply the industries. Now is the time to start organisation at the village level and bring together the 7 lakhs of villages into groups by affording them relief and giving them the benefits of freedom. When 80 per cent of the doctors live in urban areas to serve twenty per cent of the people and 80 per cent of the people live in rural areas with twenty per cent of the doctors, when there is but one midwife for 30,000 women or 10,000 women of child-bearing age and when there is but one doctor for 6 300 persons the disparity between demand and supply may easily be conceived.

The problem therefore is one of supplying the missing links in food, education. cottage industries and health. It is these links that must be forged forthwith so that what is popularly called Rural Reconstruction may be taken up in earnest.

Panchayats designed to administer forests and crafts, credit and justice, drinking water and drainage demand attention. Cottage industry cries for resuscitation and agriculture calls for long range as well as short range attention covering soil analysis, rotation of crops, better facilities for irrigation and supply of smaller machinery and above all of power through electricity to every home and craft. Labour (Agricultural) has been neglected and provides a problem of a delicate and complicated character. But the real pro-

blem of the village is how to impart higher education in the lower reaches of the country. Just as industry and justice should be taken to the village, even so education with its laboratories and pilot factories should be taken to rural areas. At Daurala near Meerut you have a fine institution, Vijnana Kalabhavan, in which boys who have passed the middle pass course are given training in practical Chemistry, Experimental physics and higher Mathematics through the medium of Hindi, which correspond to the B.A. standard. Thus should the village be renovated so as to manufacture not only theneeds of the country but also to manufacture manufacturers of the future,

The real legacy in flesh and blood left to us by Mahatmaji is represented by the many workers who have devoted their time and talent, to the promotion and propagation of his teachings. The constructive workers in the various Asrams which are the power stations established during Mahatmajis time for the generation of the Electro motive force of Satyagraha have met at Wardha after the Master's departure under the gulidance of Vinoba Bhave—the first Satyagrahi of Inndia chosen in 1940 and are striving to keep the banner of Gandhism flying. They are the real apostles for the spread of the new Gospel, and constitute a tower of strength to the cause of National and Rural Reconstruction. The Sarvodaya Samaj they have formed has as its object the promotion of rural service and has the advantage of working under a constitution which is at once elastic and catholic.

CRAFTS

In the midst of the din and dust of political disturbances following our independence, we have not been able to give sufficient thought to the best means of consolidating our nation through a revival of crafts and arts. The loud complaint of 'too many people and too little land' and the allied call to go back to the land are incompatible with each other. Machinery employs but a mnitue fraction of

our people. Land engages no doubt a bigger fraction, but even so provides only under employment and a low standard of life. The secret of wider and ampler employment lies only in relieving the burden on land by restoring the craft life of old. In Japan every home is a factory and there are 50,000 single room or double room factories in Tokyo. From bamboo alone over 120 varieties of artistic things are prepared involving skill and originality. In 1937 seventy five per cent of the farmers worked only on farms, 25 per cent engaging also in outside work—such as rural industries. In 1938, fifty four per cent famers held supplementary jobs. In 1941, 58.1 per cent, in 1942, 61.5 per cent and in 1943, 65.1 per cent farmers had supplementary jobs—Japan has fifty thousand factories employing more than five workers in the farm villages, and this number is increasing constantly according to a recent estimate. Government is training village technicians for rural industries in sixty-eight model factories. Short courses in agricultural industries have been instituted and farmers are given free training. Both boys and girls, who have finished their seven years' primary course are recruited for Industrial education. The main odject in encouraging industrial centres in the rural areas is the absorbing of surplus village labour, avoiding congestion of unnecessary industries in the cities, utilising raw materials on the spot and raising the standard of income of farmers by providng them side-jobs in their leisure months. Government is anxiously encouraging farmers to take up side-jobs in the rural industries in order to stabilise the rural economy of Japan. Soldiers returning home from war areas have been settled in the villages and provided jobs in rural industries since the large industries will take a few years to revive their pre-war glory.

Plan Of Reconstruction :

The Government of Japan has recently (June, '48) evolved a plan of rural reconstruction afther the war. The

preamble states that in order to reconstruct the national economy of Japan co-operation between agricultural resources and industry is essential. The best and most profitable utilisation of raw materials can be made in the villages. That is why village industries' socities which take care of rural industries are advised to evolve ways and means to secure maximum co-operation between village capital and rural labour, Government has laid down that

(1) The centres of the industries listed in the plan should be located in agrarian areas, seaside villages, mountion side areas and the green valleys where raw materials are available.

(2) The capital for such enterprises must be raised co-operatively from the villagers alone,

(3) Tho labour as far as possible be recruited from the vicinity: exceptions may be made in certain cases.

(4) Raw materials should be locally available; exceptions are permitted because sometimes they are unavoidable. For instance, a noted village centre of bamboo industry relies on supply of bamboo from an area fifty miles off.

(5) There is no limit on the scale of an industry provided the manufactured articles are in demand in Japan or abroad.

(6) The manufactured goods must be of a high level and dificrent varieties should be encouraged to eater to different tastes.

(7) The village industries society will have full authority to supervise the rural industries.

(8) The society will help in raising capital, in organising industries, introducing new techniques supplying raw materials and the disposal of manufactured goods.

(9) The society will maintain strict watch on the quality

and quantity of manufactured articles and on the fixing of sale prices for local markets.

(10) The society must have close contacts with Agrarian, Marine or Forest Societies in the rural areas.

(11) Capital aid will be provided by the Central Agrarian Bank, when the village industries' societies submit a plan after a thorough survey of the industrial plan and the necessary statistics.

When thus the sanctity of the home is preserved, and the out-pouring of the human soul in the field of arts and crafts provides also the means of livelihood for people through the play of the hand and the eye, we shall have kept honour above life and spirit above matter, Latterly, the utilitarian ideal has been divorced from the aesthetic sense, but few realise,—all the less so under the influence of the mechanical West—**that the home is the abode of beauty and Art is the real handmaid of utility.** when the two befriend, employment rises on a colossal scale. Waste is converted into wealth. The debris of tailoring, and the scrap emerging out of woodwork become in turn the raw materials wrought into magnificent art curios with the aid of colour and design. It is thus that one-room and two-room factories multiply in every village and town and from the seashell to the cocoanut, from thrown-out pieces and broken fragments you get basic material for carving and colour-spirit. The assemblage of such articles and curios is effected by co-operatives which mobilize the wealth of rural and urban homes, organize the population, provide employment enrich society. enliven the people and open out a new era of artistic industry. They promote the country's reputation and the people's happiness alike.

Village crafts are but an extension of the Spinning Craft and Khaddar which forms the prince of village industries and constituted the very pivot of the Satyagraha movement in India It is no less the basis for India's economic reorganization and

it ill-behoves the nation to forget the very instruments by which it has wrought its own emancipation. There can be no better example before the Indian Union than that of Japan which, in spite of her defeat, is buzzing with work for her people and is well on its way to full prosperity.

Let us, therefore, concentrate our attention on Khaddar and cottage industries and see that the provinces advantageously pool their products and their expenditure and together organize their sales over the whole nation. Discharge of products is the best incentive to production and both demand our best attention through a well co-ordinated scheme of inter-provincial co-operation. They require depots and show rooms all over the country. but cannot bear the heavy expenditure incidental to individual effort. The detailed organization of Central and Provincial Boards in this behalf, inventories of the crafts all over, cen sus of qualified artisans and craftsmen. vocational school in districts, control and mobilization of raw materials, co-operative machinery to grant loans and promote production and distribution of goods, research Institutes, travelling exhibitions, deputation of students for study, invita tion of experts and technicians, museums central, provincial and district or even Taluk, preparation of samples and designs, publication of literature, light and heavy, libraries big and small, pilot machines, patent rights and tourist facilities—all this is the work of Government.

HEALTH

While some of the national problems look too abstruse, others are apt to be dismissed as too commonplace. Health is one such. Its scope is large in its modern connotation as it embraces many Social and Economic aspects of national life which have been sorely neglected. The health of the nation, rather, its ill health has been taken for granted and therefore has not been assigned any high priority in national affairs. How few are aware of the fact that all

the insects of the world weigh 9 times the weight of the earth and that two flies—a male and a female, produce in two years as many as 2 million flies, food and space being given. The mosquito that works by night has spread Malaria and that which works by day Filaria. It has been rightly observed that there is one (human) sleeper under each (iron) sleeper of the Railways in India, the former having fallen a victim to Malaria. Whater-works without drainage have minimized Cholera. Dysentery and Typhoid, but introduced Filaria and Malaria; Malaria which is more destructive of human life than powder and shot, and Filaria which is rapidly spreading in the country reducing the work co-efficient and the man-hours of the Nation There are whole areas of fertile land lying unexplored on account of these pests, which will be dealt with in connection with food. We live in the midst of numerous, enemies, at home, rats which eat away millions of lbs. of our grain, cats and dogs which spread rabies, flies which spread dysentery cholera and typhoid; mosquitoes responsible for malaria and filaria fleas for plague, bugs and lice, which infest our homes, crows and sparrows, pigs and stray cattle, insects invisidle, bacilli and bactria which are microscopic and dozens of other pests. A health programme must give attention to all these sources of waste and ill-health and we have so far allowed them to play havoc. There again is Beriberi which is spread by milled raw rice and immediate measures are necesary to cobat the evil by forbidding milling of raw rice and to add to this, we have Vanaspati in our midst.

For every 1,000 children born, 750 survive at the end of the first year and only 500 at the end of a decade. In other words we lose half the new births in 10 years. Our death rate is 24. I per mile against II.9, II.2, I0. 6 and 9.9. in the U.K. Australia, U, S. A. and New Zealand. Corresponding figures for infantile Death rate per 1, 000 live

births, are 169, 46, 36, 40 and 30. We lose 20 mothers out of 1000 confinements or 200,000 in all per annum against England's 4 per thousand and U.S.A.'s two; while 4 milion women suffer from the effects of child-bearing every year: out of 10 million confinements i.e., 40% of women suffer. It is considered that at least 50% of the existing mortality is preventible. Our doctors are but 1 to 6,300 and our nurses are but 1 to 43,000 whereas they must be 1 to 2,300 and 1 to 500 respectievly. Our midwives are 1: 60,00 while in U. K. they are 1. 618. About 75 % in rural. while the rural population is 8 to 10 times that of the urban. The beds in U. S. A. 1,100.

Malaria is the prime offender accounting as it does for a million deaths directly out of a total of eight million deaths, while another million, debilitated by malaria are finally returned under other heads so that really I out of 4 deaths is due to this fell disease. During 1944-45 the combined expenditure on 'medical and public health departments' in individual provinces varied from 2.8 annas to 10.9 annas and averaged 5.9 annas per capita of pupulation as against the required Rs. 3-3-0 per capita of our expenditure and as against the Bhore Committee's recommendation of 1-14-0. Filaria is neglected because the death rate arising from it is low. But disability and disfigurement, depression and distress caused by it have decreased the man-hours of work of the nation.

FOOD

It is a truism to say that life centers round food, and governments have the duty of ensuring the amenities of life to all—amenities in which food secures the highest priority. After a hundred and fifty years of British rule, we discover that India is not only not self-sufficient in food but deplorably legs behind the optimum. The food and population problem in India is intriguing and even baffling.

I (i) The total land growing food-grains in India is I60 million acres, (a) of which the irrigated extent comes roughly to 50 million acres (b) while that which is purely rain fed is I00 millon acres.

(ii) The multipurpose projects would add 27 million acres at the end of 15 years. This will be just sufficient to cover the needs of the increase in population durieng the period.

II Let us look at the problem from another angle : (a) The cultivated land worked out per capita today is 0 6 acres, (b) while that required for yielding a subsistence level of 1750 calories—is just less than an acre per capita.

III We have besides vast resources of fertile land lying waste on account of that fell disease malaria, 200,000 square miles or 120 milion or 12 crores of acres.

In effect then while we require for 30 crores of population slightly less than 30 crores or say 25 crores of acres of land, we have actually 16 crores of acres under cultivation, 2.7 crores potencially under multipurpose schemes, at the end of 15 years, and another 12 crores of acres under Malaria tracts. There is therefore but one forthright remedy namely securing an immediate increase in the fertility of the soil, three times over by manuring and intensive cultivation and another chance lies in crop rotation and in the manufacture of food yeast, which is protein food, such as has recently been manufactured from sawdust and husk in Germany. Still another device is to prohibit shelling and hulling of paddy on mills. This must in any case be adopted as a health measure also, so that we get more rice, and rice not divested of the vitamin content.

As things stand, we are regressing and not progressing. A target is fixed by a local Government, say, Madras. 6½ lakhs is apportioned to the Agricultural and 1 lakh to the

Public Works Departments so far as irrigated cultivation is concerned. The former is concerned with improved agronomic methods in use. Its concern is really mathematical, in terms of so many tons of grain, so many of compost and so many of chemical manures—so many bags of improved seed—all being equivalent to so many tons of rice and millet as apportioned to it. The P. W. D. is concerned with the 'cuseos' ofwater, but it throws the blame on silt which has to be removed, for it is choking the canals. In the dry districts the people are intently looking at the skies for the rain-god to smile and shower his waters on them. In the meantime the Board of Revenue issues the news of 'a withering crop report.' What is wanted for ordered and prompt prompt progress in regard to food or other amenities is co-ordination of departments and a human view of administration. For every three ministers there must be a co-ordinating minister.

Our sloution for the grow-more-food problem involves not an Agricultural issue merely, but it is inextricably coupled with the sanitary issne as well. Land and Water have to be married by the High Priest of Energy and then the culltivated land in our country which is but 10 p. c. of the whole can increase to the dimension of the uncultivated land which at present is 90 %.

A passing reference has been made to fertile tracts of land infested with Malaria so that the problem is a composite one relating to both health and food. If you solve it, you will be shooting two birds with one blow. The fact is that large tracts of land exist all over India today whose development is at a standstill owing to malaria. The story of Panama and its reclamation is well known. It was Sir Ronald Ross who, referring to these tracts, said that "the Treasures of the tropical forests are zealously guarded by the two-winged fairy, the mosquito". They

have a rainfall of 50 to 100 inches where the soil is fertile and soil erosion had not done its havoc and where the population is sparse and is composed of primitive tribes, being but 50 to 100 to the square mile, who lead a subhuman life. Three such chief tracts exist in India today, one along the Eastern Ghats, 60,000 square miles in area in the agency tracts of Ganjam, Vizagapatam and a second along the Western Ghats the farmer being more malarial than the latter. In the North, the Sub-Himalayan belt, the Terai land forms the third. The first of these has abundant water supply through rivers and waterfalls. The lands in such tracts become more malarious on account of cannals carrying water without proper drainage. Malaria is now brought under control, In Wynad in S. India, malaria is being controlled at a recurring cost of less than Re. 1 per capita per annum by cutting the contact between the man and the mosquito, by attacking the mosquito and attacking the malarial parasite. Colonization schemes have been thus made possible in two areas in S. India. By collating therefore, land, energy, water and man through proper organisation, we can promote health as well as food. The only fertile land available in the country in large blocks is in the malarilal tracts. Most of the Indian rivers pours 90% of their water into the seas as the rivers are in floods during the monsoon periods, while quite dry most time of the year. Only 5% of the total Hydro-Electric power of the country has so far been harnessed. India calls out from every corner—Health, food, rural reconstruction, and when the call is heard,—a new India will be coming into existence abounding in health and food. When Land and Water are properly harnessed they yield food, other wise they breed the mosquito and through it promote malaria and filaria.

REFUGEES

The difficulties of the new Government are not as yet at an end. Let us remember that we are still in the mist

of what is popularly called 'Refugee' work. May we not preferably call them evacuees, and in our own national language 'Paravasis' or better, 'Nirvasis' rather than 'Saranarthis.' They have not come here to seek shelter or to beg protection. It is the nation's approval of partition that has compelled this mass migration before which pale into insgnificance the movements of population in recent history between the Greeks and the Czechs or the revolt of the Tartars centuries ago and their march from Russia under the leadership of Zebech Derchi or even the Exodus of the Israelites from Missar to the land of Canaan flowing with milk and honey under the leadership of Moses and Aaron. Between East Punjab and West Punjab alone, four million people moved from West to East and five million from East to West—"all under emergency conditions" created by the fanatical communal outburst with its attendant attacks, reprisals and counter-reprisals. Even a normal process of migration or infiltration would be attended with risks and how arduous the journey should have been, how numerous the casualties ? Yet the East Punjab Government, barely one week old when called upon to face this crisis, had to cope with it and must have felt like a city with thousands of population submerged by a tidal wave one night. People. have been uprooted from their hearths and homes for no fault of theirs. It is true that we have waged a war with Britain and in this war of non-viloence, the post-war casualties and miseries have exceeded those during the war immeasurably. It is thus that millions have died and millons more have been dislocated. To open camps for the onrush of a whole population with tents and kitchens, stores and markets, food and clothing, lavataries and hospitals, maternity wards and infection camps, evacuation by trains and provision of transport, demanded enormous man-power, and money-power, initiative and resourcefulness, imagination, understanding, sympathy and patience, if one should combat the two evils of congestion and chaos. After relief comes rehabilitation, after the

needs of the body arise the requirements of mind and spirit.

While we are not out of the wood yet, there threatens in the East another disaster of mygration of Hindus from East to West Bengal, The latter has a density of population of 750 per mile. If we and an equal number or any thing like it from East Bengal another man-made famine will probably confront us. Apart from this, there are the harrowing scenes of migration with which we are familiar which will rapeat themselves with equal severity. But why should migration take place at all ? This must be investigated and prevented by all possible means and not suffered as we have suffered a similar disaster in the Noath West. for one thing the tarifficpolicy must not serve as a factor in the affair.

The remedy suggested of exchange of population and surrender of territory by East Bangal are factors that only encourage exodus. On an average it is estimated that the exodus does not exceed one thousand per diem. The tragedy is that in Dacca 1,000 houses are reported to have been requisi tioned by Government and 15.000 people have been displaced. This policy on the part of Pakisthan Government must be revised for it compels exodus and appears almost designed to bring it about. We can only wish that this exodus would come to a stop through the intervention of the Union Government, as the obvious result—apart from phychological and moral reactions, would be to create famine conditions affecting neighbouring areas.

The central Government's broad outlook embodied in the relief and rehabilitation administration with a capital of 10 crores came as a happy cover to the earnest and indefatigable labours of the Provincial Governmets in seeking to rehabilitate the evacuees as best they could at the time. But let it be remembered that what is reqired is not a short range relief but a long range rehabilitation based upon a due recognition of the character of the problem not merely as a national but as a psycho-ethical one. Unless the 'nirvasis' can feel that they

have somthing to call their own—a house, a kitchen garden, a cow or a buffalo, a pair of bulls and a plough a permanent abode provided with the amenities of social and cultural life, unless they can also feel that they have some initiative in promoting rehabilitation, they cannot reconcile themselves to theirnew lot. A town-ship alone provides such relief. New town-ships, if necessary, with prefabricated material for the time being, provide the only solution. After all in a town, we live upon each other's services to society while in villages in addition you have the produce of the home crafts. No other Government could have been more earnest and persevering in giving relief than those of the Indian Union and the Punjab and the several provinces that have received the 'nirvasis'. It may not have been possible with the petrified routine of department-alism which we have inherited, to satisfy everyone, but let us remember that we have yet to survive its cramping and cribbing illuence. I would earnestly place before Government the desirability of creating a High Power Authority like the T.V.A. which will be a complete government within Government and which is authorised to override wherever necessary the technical and departmental obstacles appropriate, doubtless, to normal conditions of civil Government, but ill-suited to emergency conditions such as we are passing through.

When all is said and done, the fact remains that the most harrowing experience is the abduction of women and on this issue we cannot afford to maintain the slight-est measuse of complacency. All honour to the disinter-ested and untiring labours of our sisters who are doing such magnificent work in this behalf at great risk and sacrifice. But alas, the social conscience is still doramant in many and morbid in not a few of the homes where these unfortunate sisters are srill being harassed and maltreated. It is no excuse for any one in the Indian Union to retain a single sister in India that the other side has retained two, three or even ten sisters. Moral actsl are not commodi-ties in barter. They are the expression of a superiorsoul

finement of culturue and constitute the real attributes of divinity in man.

SOCIAL JUSTICE

Politics, being the science and art of human well-being, and embracing as it does within its broadvinculum. the science of economics as well, has so far occupied the attention of Legislatures on the one hand and the press and platform on the other, that we witness little interest in the study of social problems—which really is a prime need of the hour. The fact is that our society has become effete altogether, and what is known as public opinion, which in the ultimate analysis, is the sanction--both intellectual and moral-behind all social organisation, has been for long dormant or even dead--thanks to centuries of foreign rule. Our newspapers have for decades devoted their columns to problems of political bondage and naturally not been able to give an adequate treatment to the subject of our social evils, Long, neglect of society under alien influence has impeded all such progress as under selfgovernment would have been effected imperceptibly through convention and change of custom. Custom has really become petrified where it should have been elastic. The steam-road roller of Bureaucracy which is the embodiment of Brute force,. had immobilised public opinion and dulled if not deadened individual conscience. Mothers maltreat children, group consciousness has remained undeveloped. A boat tragedy which ought not to take place in civilised life passes unnoticed and unremedied. Maternity-mortality and infantile disease devastate life. The spirit of the good Samaritan has been suppressed. Contract has yielded place to status. The time-honoured and traditional amenities of organised society have vanished. Duties have been forgotten and rights have come to rule. The ties of the joint family with its hoary implications hallowed by age and sanctified by custom and functioning in the village as a miniature Labour Union, Insurance trust

and co-operative society, are broken as under the impact of a civilization materialistic in outlook and individualistic in interest. Social evils have grown out of customs and manners have been divorced from the chastening influence of an acknowledged head of society. When Royalty has disappeared, the next tier of authority, namely the socioreligious heads have degenerated into priest craft with their threats of excommunication, but really they are afraid to strike though anxious to wound. The cement of sympathy that binds the bricks of the social structure has become decayed and the edifice of society has become a mass of debris.

Our task therefore is to replace this crumbling authority by a live, social headship through renovated public opinion and a rehabilitated social law duly enacted by the Legislatures in consultation as much with the progressive forces of the day as with the conservative elements that still survive the onslaughts of the West. Modern concepts under which Politics and Economics have become intertwined may choose to divorce the religious from the social and both from the Economic and the political in a framework in which all the four had long permeated each other; even so it is our duty to ensure free development to each of these forces so as to foster a healthy blend of both as against a mere juxtaposition much like the components of a mere mechanical mixture. Even the ideal of a secular nationalism, which we are seeking to establish, cannot place all the emphasis on the 'adjective to the detriment of the uplifting influence of there noun. The aroma of Hindusthan cannot be taken away from the sepals and the petals of the flower of Indian nationalism. Such an aroma is furnished by the social institutions. It may be that the flower has become dried but the elements of the aroma are still there and can yield their essenee under suitable treatment. It is true that we have different aromas in different categories, but when 'Chandan' and

'Karpur' mix, they only produce a reinforced sweetness. That is how we plead for the preservation and perpetuation of different cultures, even as you have different flowers... pink gulabi, white Mogra, and yellew chemali in the garland of Indian nationalism. Social jusitice demands protection to all, preservation of whatever is sweet and sustaining and improvement of each to the conjoint good of all.

Here it will become necessary to pay separate attention to each of the component factors that constitute Indian nationalism. The Muslim is in reality the Hindu of one or more generations ago, except in a small proportion of the population, and while his socio-religious customs and conventions have undergone some change, his manners and make-up, his economic interests and political well-being remain the same with those of the rest of the people in India. The eccentric' loyalty hitherto prevalent will soon yield place to a concentric fealty to the State and the Country where their lot is cast and a richer nationality must be the fruit of the recent commotions. A cocoanut garden vigerously shaken by a fierce storm may not bear fruit for a couple of years but the yield becomes trebled thereafter, on account of the aerating for the soil and the stirring of the roots.

Latterly we have had a new problem added to our Congress programme. The Sikh separatist movement in barely thirty years old. Starting at first as a protestant movement directed against Mahants and monopolies of Gurudwaras, it has like all sectarian and schismatic movements added a political wing to its range of interest. One should have thought that the Sikh was merely the contribution of the family to the military organisation of the Nation. The warrior has become the statesman and is only too conscious of his contribution to peace and prosperity. The five symbols of the Sikh cult are but the off-

shoot of such an idea. How else should a kirpan and kutch come to figure amongst the five. The Kadi is the age-long symbol of the challenge of resistance. The hair and the comb go together—the growth of the former being a traditional proof of a vow. The five have constituted a cult and soon developed into a culture. When between two brothers, between parents and childern, between husband and wife, one is a Sikh and the other is a Hindu, it becomes difficult for the uninitiated to understand how the Sikh and the Hindu can be regarded as belonging to different communities, constituting majorities and minorities. A fellow-traveller has narrated the story of how his grandfather, a 'kattar-sikh'. demanded of him that if he should get a son, the son should be made a Sikh. The traveller agreed and the position is that the grand father is a "Kattar Sikh" the father was a Hindu till 53, and then an innifferent Sikh, he himself is a 'Kattar Hindu' while his son. 17 years old, is a Sikh again. This state of things demand that we most reorganise our youthful training, that with the mother milk must be Infused a feeling of oneness—Hindus and Sikhs growing together as apostles of one culture. The Indian Christians have always been the apostles of composite nationalism. When to these the Muslims are added with a new Ideology, or the old revived of Common nationalism. India will become strong and compact like a granite rock.

Any civilized society must be composed of groups bound together by affinities of different kinds. Each such group is a community. To look after such communities cannot be communalism any more than the exercise of sentiment can be sentimentalism or reorganisation of Provinces in accordance with cultural, economic and linguistic affinities provincialism. The organisation of communities in order to safeguard their peculiar, notably, occupational interests is a legitimate public activity, springing from innate cultural sympathies, but affairs do not stop there. Sympa-

thies degenerate into prejudices and the community problem in to a communal one and the commenal is well-known is protean in shape and what is worse it is hydra-headed in character. When one head is taken away another sprouts forthwith. The problem creates schisms as a rule; concerning as it does the relation between the Muslims and the Sikhs between the Sikhs and the Hindus, between the Hindus and the Muslims, between the Brahmans and non-Brahmans, between the Bhumiyars and the Khatris, between Khatris and Kayasthas, between Kayasthas and Rajputs, between the Savarnas and the Avarnas. On the top of this you get those imperceptible and even insidious rivalries between the votaries of different languages in multilingual provinces. The Harijans themselves are divided into 84 divisions in Madras and all these divisions have been sedulously categorized and fostered under the benign rule of the British. These have been left to us by the British as a legacy and it is for us to evolve a basic unity founded upon goodwill and fellowship amongst these sects and school of thought.

RESERVATION OF SEATS

Before passing on to our next theme, we may advantageously turn to the inssue of minorities—an issue directly connected with the communal problem in India. At the first sight, reservation of seats may appear to be an intermediate step leading to full Joint Eilectorates—intended in the interests of Minorities. But rightly viewed, it is a concept meant to lighten the burden of the majorities who instead of undertaking the responsibility of providing for the minorities from abundance of their hearts, give it a legal boundenness, so lightening the burden which is legitmately their own. Reservation of seats gives a sense of false security to those enjoying it and lowers the standard of energy, effort and efficiency. It fills the recipients with a sense of inferiority and makes them feel like the poor relations at a rich man's feast. It prevents the growth of a towering personality which no one would or

should welcome and which alone would entitle the successful candidate to claim his full rights in an Elected House.

When thus communalism becomes a forgotten chapter of history, common citizenship and community of interest in economic and politcal affairs becomes the one cementing factor that binds different communities by one common tie of fealty to the nation, common respect for authority, common reverence for tradition and a common spirit of sympathy and fellowship towards all. When the Motherland becomes our own Goddess and service becomes the universal worship at her shrine, we shall have survived the acerbities of the day which will one day remain a curiosityof history and a fossil reminiscent of a past age. Such a new faith will not degenerate into fanaticism and it will remain for ever a vital and formative force operating on men's minds and chastening men's spirits.

HARIJANS

Within the range of Hindu society by itself, we have the Harijans constituting quite a fifth of the population. Theirs is an age-long problem and we owe it to ourselves to keep it ever fresh in our minds, remembering alike its essential nature and its neverfading urgency. For has it not been well said that 'it is the tendency of all creeds, opinions and political dogmas that have once defined themselves in institutions to become inoperative. The vital and formative principle which was active during the process of crystallization into sects or schools of thought or Government ceases to act and what was once a living emanation of the eternal mind organically operative in history becomes the dead formula on men's lips and the dry topic of annalists."

CATTLEWAETH

In India for centuries past the laws of health and of economics have been woven into the structure of religion. A daily bath before food is obligatory. Washing the legs and the hands on certain occasions is a religions injunction. The cow is a sacred trust of the Hindu which compels wor

ship. This leads us to the study of the cattle-wealth of the country. The one subject that has roused deep interest all over the land is the question of the slaughter of cattle—the approach being not merely economical but socio-religious sometimes. In this country the Hindus visualise three Mathas or Mothers, the Gomata or mother-cow the 'Ganga Matha' or Mother Ganges, and the 'Bhu Matha' or 'Mother-Earth' The Earth yields food, the water fertilizes the Earth and the cow feeds the babes and her progeny provides the bull-power and helps the soil being tilled, To slaughter such an innocent and useful animal is a tragedy. That is why the cow is described as a poem of pity. It may not be generally known that during the war the military were killing 30,000 calves a day because it was uneconomical to feed them by allowing them to feed on the dam's milk. After great pressure by one of our patriots in the Agricultural section, they were allowed to live for I4 days and were given away free to any one on the I5 th day and if not cleared, were put to death. In this matter we speak the sympathy and goodwill of those who have not inherited these traditions. as cow-protection can be successful only then, and it cannot be provided for by legislation. We live under conditions which guarantee freedom to all and one,s freedom always ends where others begins. Cow—protection constitutes a moral and humanitarian problem rather than one of fundamental rights, or directives from States or of special legislation. I say all this as one that holds the cow in the highest veneration as the proof of the economic—wealth of society.

The prosperity of cattle depends obviously upon the care and concern with which they are tended. And they are tended only in the measure in which the milk and milk products sell in the market. But the adulterated ghee (mixed with Dalda) sells cheaper in the bazars. Therefore genuine ghee cannot obtain proper prices. To produce such pure ghee has become uneconomic and just as com-

mercial crops drive out food crops and bad coin drives out good from circulation, so bad ghee is driving out pure ghee. Village cattle therefore suffer and ryots suffer because they are largely tended for ghee while town cattle which cater milk do not sufer. This adulteration can only stop when Vanaspati becomes liquid, not solid, for when liquid it cannot mix with ghee. It is only in the solid stare that it can be an adulterant. Therefore the hydrogeration of Vanaspathi must stop.

LANGUAGE

Our new-made freedom has brought in its train quite a few problems of importance for the nation to solve. problems which were never seriously raised while a foreign Government was ruling the cauntry. What shall be the State language and what the national language ? Perhaps both may be the same. Same or different, the question must be answered, The 'National' language is always the product of a natural evolution under the influence of haredity and environment. The Congress under Mahatmaji's guidance has all along accepted Hindusthani as it is spoken by the masses, as the national language. Here however are two difficulties. The masses always develop dialects and there are many such. Yet we all know,, the language of the bazars of the cities in the North. we know too the language that is understood, at public meetings by all and sundry. There is little doubt that this will be or become the national language and it is popularly known as Hindustani. We must evolve a laugnage which is midway between Sanskritized Hindi and Arabico-Persianized Urdu. We are speaking such a languauge as a matter of fact. Only we carry on an unnecessary dispute about the name. Hindi—pure or admixed-may be the language of U. P., but cannot be imposed as the national language of India, Such a langunge will evolvel in due course, indeed is evolving itself and it will differ from a purely provincial language.

Then arises the question of State language. There is an idea of reviuing 'a classical language of old if ever it existed as such,-abounding in Sanskrit terms, but to go back to a thousand years or more, ignoring the various influencor, etimological and cultural--which have played a notable. yea, a noble part in evolving modern composite Indian nationalisin, would savour of Atavism. The British may have left the country--but their century and a half's contribution is there to be seved and sifted and utilised. Back of the British era there was the Muslim culture extending over centuries, which is its own days enriched our culture, strengthened our administration and brought nearer distant parts of the country. It touched deeply the social life and the literature of the land. what really appears to be the vital point of difference on the subject is that we have raised controversies of classical vs. colloquial languages. In all such controeversies the latter has scored over the former. it is true that our Legislation should ultimately be authoritatively incorporated in the State language. But for the present we may have to be content with an authorised version in it of our Constitution written and passed however in English. In due course the technical language—unfamiliar and unavoidable---will become underatood and easy and acquire that measure of precision and dignity which the language of Law and Constitution demands. To precipitate matters in the meantime would be to see forcibly to ripen a raw fruit.

ASIATIC COUNTRIES

India's Independence has not been the sole end of the Indian National Congress. It is also a means to a larger end. Let us not forget what we stated on the 9th of August 1942 in Bombay when we demanded not merely a free and independent India, but demanded also that such a freedom and independence for India should only be a presage and proof of the independence and freedom of our neighbours to the East and the North and the West, who

are still in the grip of Western Powers and are fighting Imperialism so as to establish the triumph of democratic forces born with time and bred by tradition. All around us we witness the struggle of sister nations to be free and to rise to the full height of their stature. The new countries that have emerged after the war are Burma, India and Ceylon which have attaind their Independence, and the Philippines, likewise independent. In the Far East, Indonesia and Viet-Nam, Malaya and Siam have yet to emancipate themselves while Korera stands divided between Russia and America. In the Middle East, the acerbities of feelings between the Arabs and the Jews have not yet been softend. Indeed the blight of India's partition that overtook her on the 15th August, 1947, was an infection. The partition of India is the logical fulfilment in India of the policy of vivisection urged by the Peel Committee in the dispute over Palestine between the Arabs and the Jews in the year 1938-39. A 1,000 years ago the Arabs were pre-eminent in Astronomy, Mathematics and Medicine, though centuries of warfare have affected their standard of life and attainment. The Jews are likewise an ancient nation whose contributions old and new to the world's growth are inestimable. We look forwrrd therefore with eagerness to the day of fruitful co-operation between the Jews who have planted a modern Western culture on their essentially Eastern soil and the Arabs who must shake off their udal rule.

China is our near neighbour with whom India has many things in common. Our missionaries carried our culture centuries ago to China and brought theirs to India. Let us earnestly hope that China's troubles will soon be over and China will take her place in the comity of nations.

Asia is daily becoming more and more compact and close knit. Twenty-two nationalities gathered together in the Purana Qilla of Delhi in march 1947 and ever since

several Asisan conferences have met here such as the ECAFE and the Civil Aviation and the Meteorology conferences. India occupies a central place geographically and she has become the headquarters of the world's health organisation.

INDIANS ABROAD

The problem of Indians abroad has not been eased now in respect of those countries which have recently become indepenent like ourselves because of the reason that today two inpependent nations like India and Burma or India and Ceylon or India and Pakistan have to transact affairs on an equal level. Formerly we were looking up to Britain for securing relief but today we must depend upon our own power of negotiation, which should really be moral influence, not physical force Whether we have to deal with Burma in the East or Ceylon in the South or pakistan in the North-West and North-East we have tough problems to face. We have to reach agreements on compensations for landed property of Indians taken in Burma or citizen rights. and Labour problems in Ceylon or Civic and Economic rights in. Pakistan.

Then we have South Arfica. Our relations with South Africa have been strained during the last few years. In 1946, the U.N. Assembly in New York, passed by a two third majority a motion condemning the racial discrimination prevailing in South Africa and recommending a new phase of negotiation between the two countries. In 1947, the U.N. Assembly passed the same resolution by a majority but not a two third majority. Unfortunately the South African Govrnment has not openened negotiations with us for the solution of this matter. On the other hand, South Africa's policy has grown worse during the past year with the advent of the Malan Government. They have recently intoroduced racial legislation of a more drastic kind. So the conflict is much more bitter this year

than it has been in the past. The matter is again coming up before the the U,N. Assembly this very year. Let us hope the Assembly will pass the former resolution again by a two third majority and a proper solution found by either direct negotiation between the two countries or through arbitration by a third friendly power. The principle of racial discrimination is a serious matter and a potent cause of friction and even possibly war between countries.. In the interest of world peace, fair play and justice, the matter should be capable of a fair solution, satisfatory to both parties and there is no doubt that our delegation led by so capable a diplomat as Shrimati Vijaya lakshmi will succeed in persuading the U. N. O. and She South African Government of the justice of our cause and the need for a peaceful settlement.

We Cannot omit a reference here to our erstwhile comrades and colleagues,—the two great leaders of the N. W. Frontier Province Badshah Khan and Dr. Khan Saheb, who are lying behind the bars in Pakisthan. We have agreed to the secession from India of the areas since known by the name of Pakistan, and so had the Khan brothers. while we have no wish to interefere with the internal affairs of Pakistan, we cannot fail to state how deeply the whole of India is grieved over the treatment accorded to the men who have stood with them.

NEPAL.

We have, besides, a small but important area to our North which has to be duly located in relation to the orbit of the Indian Union. Nepal covers 500 miles of territory in the Central paortion of the Himalayas along with their extension from East to West, and has an area of 65,000 Sq. miles. It extends from the snowpeaked Himalayas to the level land of nearly 16 miles in width which forms a link with the great Indo-Gangetic plain. We cast no evil eye upon its navigable rivers, its forest wealth or its mineral resources,

its oranges or sugarcanes, its jute and hessian, its rice and millet, its rye and maize or its barley and potato. Its pure Aryan race and its glorious culture constitute an inseparable link between Nepal and India. Our interest in Nepal is identical with the internest of India in other Asiatic countries. It is our earaest hope that Nepal's system of Government will be reorganized are long so as to set up democracy and responsible Government on the lines adobted by India,

There are other areas in India which are integral geographical and historical parts thereof—the Portuguese and the French Settlments which are just no passing through the agony of a new birth. The Union Government is obviously engaged in delicate and difficult negotiations on the subject of their joining the Indian Union. They must join. India is not a meteor of which small bits can be detached. in order to become the playthings of outside forces.

THE CONGRESS, THE GOVERNMENT AND THE CONSTITUENT ASSEMBLY.

At this moment three great institutions are handling the destiny of our nation. The Congress, the Constituent Assembly and the Union Government. What relations must be maintained amongst these three is the immediate issue before us, The Congress has raised the nation to Liberty and the freedom so earned is being canalized into Constitutional channels by the Constituent Assembly. This is only a temporary institution. The Constitution improvised for the nonce is being worked by the Gevernment of the day. The body politic has its own physiology even as the human body has. In the latter the heart is the service reservoir of the blood (pure and impure) which it pumps—the pure to feed the body and the impure to be purified and returned to it. The Congress is the service station of the life-giving ideology of the nation. The life sustaining doctrines are pumped out from its chambers through the arteries of Government on to the nation where they become somewhat sullied in implementation and are returned to the

Congress for purification. The ideology constanty discussed by the populace and constantly renovated as public opinion is once again canalized by the Congress through Covernment in renovated form, That is how the Congress and the Government act and react upon eah other

Let us now consider the position of Government. A Government must govern and is therefore concerned with the problems of the day, and with the passions of the hour. Its work is concrete, its solutions must be immediate. The Congress has a wider jurisdiction and the more remote task of coordinating through a dispassionate criticism the achievements of the past, the endeavours of the present and the anticipation of the future. The Congress is really the Philospher while the Government is the Politician. The latter has power and the former influence Sometime influence which is moral overcomes power which is physical. Or shall we say, the Congress is like a benveolent and elderly mother-in law and the Government is like a tactful and young daughter-in-law. All the power is in reality vested in the latter through the husband. Yet she attempts—not merely affects—to obey her parents-in-Law, while ultimately carrying out her own will.

As the home presents conflicting authorities, the larger home, namely, the country presents conflicting forces and the great reconciliation must be on the one hand, between the Ministries, Central and provincial and their Legislative parties and on the other between these and the Central Parliamentary Board. Only broad sympathy, deep understanding and high courage can achieve such a reconcilaition. The problem largely centres round personal equation rather than rigid principles or inflexible policies. That is why the Government requires the aid of unencumbered and free thinking. The Secretariat is there doubtles but it is not the engine; it is only the steering wheel of the motor, the rudder of the boat of Government, and keeps the

vehicle to the centre of the canal or the road. Government is not a railiway train running on rails and requiring no steering, but a motor running on the road and always swerving to the right or the left. The function therefore of the Secertariat is limited, though indispensible and beneficent. The Engine must develop power through the accelerator and the Congress is the accelerator.

This Government is the fruit of the labours of the premier political organization of the country during the past three score and the three years. There have been other organizations equally sincere, enlightened and patriotic, but perhaps less endowed with vision, daring and dash, which pulled their weight in their own day, but which could not keep pace with the forces marching apace and ahead. The Congress itself had its own day of moderation and sobriety and the so-called moderates were only the Congress friends who had led the van of progress in their own day. They are the first coating of concrete quartz and laterite that lie embedded in the foundations of the national edifice and deserve to be remembered by posterity for the contribution they have made to national strength and the nation's emancipation. That is why we remember our forbears who should not be dismissed as back numbers. In the Valahalla of nations, the leaders of each generation have their due place. And it is our duty as wise men to foresee and formulate the needs of the hour to suit the changing temper of the nation. A nation acts under stress of emotion and exercises pressure on the Government of the day. The Congress is at once the "Thermometer" that measures the rise of "temperture" in its emotions and the "Barometer" that guages the fall in pressure of its actions. Or shall we say, varying the simile, the Congress represents the tentacles of the body politic, probing public opinion in the land. It is sometimes describedd also as the brain-trust of Government which ought to supplement and sublimate the ex-

periences of Ministers gatherd by them in their tours and talks. Our Ministers have to work under high pressure and tension, and are not able to take the all to desirable week-end holidays in which to think out the problems too knotty for quick or easy solution. Holidays are really meant for making possible high-level thinking during week days, and many not be grudged till sick leave is necessitated. That is why the Government of the day requires the aid of unencumbered thinking.

In addition, the Congress holds the balance even between, on the one hand the untutored laity—the masses whose sense of proportion, perspective and propriety is apt to be blurred by the projection into the picture of their immediate needs, and on the other, the Ministers that wear a crown of thorns on their heads and must take note of their own limitations in respect of a past that they have inherited, a present that is embarrasing and a future that is fugitive. While past commitments bind them, present difficulties are apt to puzzle them and future uncertainties confuse them. The public know no obstacles, they only know their needs. They see but one path to the mountain height,—the shortest and would negotiate it by the vertical route—like the helicopter. Government advises a foot-path or a bridle path which is of low gradient and safe like the route of the aeroplane. It is, therefore, the supreme task of the Congress to tone down the extravagant and idealistic demands of the people and tone up the measured and moderate, the realistic and restricted achievements of the Ministers. In the very nature of things, those in authority can only hold a candle in their hands in answer to the popular cry for the Moon.

All Government is Organization results in an automatic mechanism that must ever be fool-proof. Tyros in politics cannot affect to meddle with the hair spring and main-spring, the toothed wheel and the balanc-

ing rod, of the clock-work of Governments. At the same time, they cannot merely perpetuate what appears to them as petrified routine. That is why Governments the world over, being representative in structure and responsible in conduct, find themselves impaled on the horns of a dilemma. There is even an element of contradiction, not merely of competition, between the two concepts of Ministers being both representative and responsible. Their wise hesitation in counsel, their wise deserve in expression, their wise tardiness in action, are therefore apt to be misinterpreted as not merely callousness but positive betrayal of trust. At the same, time, there is abundant chance of a popular Government degenerating into the overbearing rule of a single individual and for democracy itself to become the autocracy of the chosen leader. Party Governments must govern no less than personal Governments With the latter the will of the ruler is the law for the day. With the former a whole Patrty must concur before a law can be enacted. But a Part y comprises many heads and many more hands and has leisure, for it is in a perpetual hurry. It cannot spare the time needed, for the leisurely examination of Bills and programmes. It can at the most but endorse principles or approve fo policies and leave the rest to its Executive. The Executive itself has little time and is enforced to entrst decision to a sub-committee. The chief Whip then steps into the arena, it is said, to implement the sub-committee's decisions. Thus does a popular institution, it may be thought, thud to become not a one-man show, but a one man,s direction. This argument is, however, only plausible. What is obvious is not always correct, any more than what is logical can be always reasonable. There is a corrective to all such degeneration. The Party has always the power to hold up the are at loggerheds with each other and both with the middle man. And the co operative movement alone represents

the great) reconciliation since it raises cash from pooled credit, eliminates the middle man, and distributes profits to the consumer, if it is a distributive society or to the producer if it is a producing society. This co-operative principle ensures equality of opportunity as well as of political, economic and social rights to all, for, authority is pooled and administration is as far as possible run by groups bound together by ties of co-operation. But the great feature of the new object is the aim at world peace and fellowship with which it appropriately concludes. It embodies in half-a-dozen words a summary of the ideals for which Mahatmaji lived and died. The plane of thought and work of the Congress is at once raised from the common level of its own emancipation to the higher altitudes of world peace. And it is a matter for rejoicing and satisfaction that our honoured Prime Minister should in his recent visit to London have been pointed to as the one man, who as "the head of the leading nation of Asia, can work for such world peace".

Man merely on accepting the object of the Congress which in the years past we were wont to call "creed". Today, "The object of the Indian National Congress is the well being and advancement of the people of India and the establishment in India by peaceful and legitimate means of a co-operative common-wealth based on equality of opportunity and of political, economic and social rights and aiming at world peace and fellowship". This objective had been debated long and deliberated upon gravely before it was finally adopted. It embodies a happy method of piecing in the new with the old, and reconciling the conflicts and contradictions with which life abounds. The contradictions when unreconciled result in conflict but when co-ordinated and in a way harmonized, give rise to compromises. A compromise is a surrender of rights by each of the parties concerned. The Federal Union is a compromise aris-

ing from the surrender of rights incidental to full provincial autonomy on the one hand and strict unitary government on the other. The Socialist and the capialist stand arrayed against one another. Their view-points must be reconciled, the former having really evolved as a protest against the latter. The producer and the consumer march, examine the "pass" and call back the caravan. The Congress has exercised such a right in the past and built up high traditions, so proving the integrity of its structure and the purity of its functioning. Democracy is a delicate chemical balance—highly sensitive to the smallest variation of weights in the pans and must see to it that the scales are held even between the deliberativeness of the Ministers and the hurry of the people, between the routine of Governments and the revolutionary spirit of the populace.

THE NEW CONGRESS CONSTITUTION

It is to ensure these happy results that after several patterns have been tried and rejected, the Congress Constitution has emerged from the crucible of public opinion and from out of the moulds of past experience, and is now in the shape of crude castings which await the polish of machinery in the work-shops of its annual session where it must undergo planning and shaping, boring and drilling. rolling and fitting. It is for us to work this new Constitution in the ensuing years. The Congress, notwithstanding its acting as a Party in the councils of the Union, has taken the daring step of regarding every son and daughter of India as a primary member of the body and taking courage in both hands, has evolved a constitution in which if is open to any major aged 21 years to enrol himself as a Congress.

For the Congress to play its part in international politics, it must make its position strong and unassailable. We know however how in recent years forces once connected with the congress have chosen to separate. It is not for us to apportion blame between one or the other. The fact however remains that no school of thought however pat-

riotic its votaries, and however up lifting its ideals, can remain within an organization and carry on propaganda against its tenets and its policy. It pains us to recall how our Socialist friends——while being intimately connected with the parent organization, have condemened our principle of non-violence, our approach to the solution of India's problems throrgh the Cabinet Mission and our formation of an Interim Government. This knocked down the very basis of the approach and the attitude of the Congress in regard to its political problem and a natural result was a separation of the Socialist friends from the Congreress. It is inevitable that during periods of transition viewpoints differ, but an undue emphasis on them is apt to promote schisms where concerted action and co-ordinated thought ought to hold all groups to gether. Institutions having their own roll of membership their own constitutions and programmes have a tendency to drift from parent institutions. The Kisan organizations while being free to pursue their occupational problems, cannot while their leaders are in the Congress Executives and their links are with the Congress, function as a parallel body to the Congress without weakening the latter.

When we realize the magnificent work before the Congress we readily admit that for its achievement it must first consolidate and purify itself. Is it then too much to demand that the members of a body working with such a high and uplifting oject, should in order to be declared "qualified" members of the Congress, be habitual wearers of Khaddar, and advocates of the removal of untouchability and teetotallers so carrying proofs in their person, and conduct, of their appreciation of the economic needs of the country and its moral standards ? In asking you to wear Khaddar it lays the foundations of a new economic set-up, in enjoining prohibition, it rears Indian Nationalism on a new moral plinth, in calling upon you to abjure untouchability in any shape or form, it levels up the floor, in pleading for inter-communal unity and in demanding respect for the faiths of other people it raises

the protecting walls of the edifice. Finally economic and social equality ageendquality of opportunity and of status for all irres pective of race, creed or sex constitute the roofing of the man sion. In effect then the object and conditions of membership constitutue the complete mansion of Swaraj endowed with the great charter of a chastened and purified political economic and social programme based upon self reliance, social equality and moral uplift, so qualifying the members of the Congress to strive sincerely and sedulously for world peace and fellowship. It is further enjoined on every qualified member, that in order to become an effective member, he should devote regularly a part of his time to some form of national or constructive activity, as laid down from time to time by the Congress and also sign a declaration to that effect The range of choice is wide, the time-measure prescribed for such activity is voluntary. All that is required is the will to be active. The will finds its own way. Once the way is found, the mind is not content to do the bare minimum. A goodengage ment becomes an in to xication asmuchas bad habit. Man often becomes what he avows himself to be. The signature affixed to the form is such an avowal and serves as a perpetual mentor and monitor. The thousands of workers who are patriotic and thirsting for a programme, should not wait for external guidance, but choose their favourite field from out of the 18 points in it. The sum total of work so achieved would shortly beco me immeasurable and invaluable. That way lies the route to real Swaraj, and thereinlies the helpfulness and therein reside the potentialities of the new Constitution. When thus the new set-up will have been in full force, we shall have organized not merelv the seventeen crores of voters oftomorrow, as against the 3½ crores of yestrday, but the full 30 crores of brains for enabling India to take a foremost place in the comity of nations, and their sixty crores of hands to make India self-sufficient and self-respecting.

A PEEP INTO THE FUTURE

Shall we visualise for a moment what would be the position of India ten years hence. ? A decade as not too long a period for such a pastime. In traversing the future we shall pass many landmarks. We shall then have to recall how the English had once ruled our country, how we had no foreign politics, no defence problems, no Indian Army at all, how railways and ships were owned by foreigners, now telephones and telegraphs came from abroad, how every one of the consumers' goods was exported across the seas, and how a student from his alphabet to his university undertook to buy foreign articles for his dress, sports and studies worth over Rs 10,000, how our coinage was tied up to the sterling,

how our Railway-rates were to be fixed by a Board under a Parliamentary Act, how imports Act, how imports in-cluding salt, porcelain chips, old newspaper bales, marbles, potatoes and apples were dumped on us as keel ballast, how verseas tariffs were planned in British interests and how our trade was designed to raised the standard of life of the British, how English was the vehicle of thought in colleges, courts and councils, how the foreign ruler chose to think and act, rule administer. fight and defend for us. All this is gone and remains in memory only as a bad dream. We are masters of our own country and the progress we have achieved in a year has staggered the imagination of those who were fondly expecting disaster. The nascent nationalism of an emancipated country offers a fertile soil for all good seed to sprout from and grow on. Yet it must be admitted that the sunlight may illumine the world but cannot light a lamp unless people know how to harness it. Every one must exercise his or her energies to secure its full benefits. Imagine how much of agony and anguish the English women had passed through for over a decade before they were admitted to franchise. In India, they got it for the asking. One resolution in the Madras Legislature paved the way for votes for women all over India, Again where have you a country which has a daughter of hers as an Ambassador, another as a member of the Central Government and a third as the Governor of a province, a fourth as a member of several deputations abroad ? Where have you a Government which has sought to abolish the feudal system from its socio-economic organization by peaceful and legislative means, which is attempting a rapid nationalization of its shipping industry and electric supply, its air-lines and tele-machinery and an equally rapid reform of its labour organization ? Well may we expect at the rate at which we are progressing, nationalization of land and of select key industries, food and clothing and houses for all, universal education and facilities for medicament so that our Swaraj may fill the pride of the common man, equally with the uncommon.

Only thus you can keep up the spirit of the Congress which has promised Ram Rajya which Gandhiji defined as follows:—

> "Ram Rajya can be religiously translated as Kingdom of God on Earth; politically translated it is perfect democracy in which inequalities based on possession and non—possession, colour, race, or creed vanish. In it, land and State belong to the people; justice is prompt, perfect and cheap; and therefore there

is freedom of worship, speech and the press,—all this because of the reign of the self-imposed law of moral sertraint". He said further: "My conception of Swaraj is not one of political indence. I want to see Dharmaraj (the Kingdom of heaven on earth) the reign of Truth and Non-violence in every walk of life......To remain a slave is beneath the dignity of man'. He said also: "For me patriotism is the same as humanity. Imperialism has no place in my scheme of life. Isolated independence is not the goal of States. It is voluntary inter dependence. I believe in Adwaita. I believe in the essential unity of man, for that matter, of all that lives. I believe that if one man gains spiritually, the whole world gains with him; and if one man falls the whole world falls to that extent." He said again, 'I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony......There can be no room in such India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks or drugs. Women will enjoy the same rights as men. This is the India of my dreams.

But let us be humble in prosperity for it behoves those who are successful not to be infatuated with the wine of their early triumphs. We have yet a long way to traverse to reach that steadiness and balance which modern independent nationalities of longer standing claim to enjoy. But, then, the thourght occurs – where lies all balance—we are all familiar with the two opposite views on the question. "It is true on the one hand that there is a period of youthful enthusiasm when we imagined that society could proceed without the spur of self-interest. The world of facts on the other has proved to us that an enlightened but staunch self-interest is and must ever remain the mainspring of human endeavour. The explosive reformer refused to profit by his experience. He is too proud in his concept to learn from life. He idly fancies that by enlisting all men as servants of an octopus State, he can solve the problems which have baffled political philosophers like Plato and Aristotle. He is deluded enough to believe that in the abolition of prizes which stimulate ambition lies the cure for all social evils". Does not all balance really lie in the equipoise between greed and satisfaction ? Whatever be the standing and stability of a nation, aggressive ambition, better known as greed, is the source of all imbalance whether in individuals or nations, whether in socio-economic or political life. We have repeatedly said, we

have no designs upon our neighbours, far or near, Asiatic or European. That guarantees not only our blance but also our spiritual exaltation. Having ensured to ourselves such equanimity and equipoise, it must be our concern to ensure all modern amenities to the less well placed brothers and sisters of our nation. England whose contact with us has borne abiding results—some good, others bad, has worked its way from its clanish and tribal stages to feudalism and capitalism and has sought to neutralise the evils it has created by takinig care to round off the angularities and soften the acerbities incidental to unequal fortunes in life. Her old age pensions, accident and sickness' insurance, unemployment doles, orphanages, workmens' homes, asylums for waifs and strays, her Church organisation and organized charities—all these have proved t me y correctives to the vast and almost unbridgeable chasm between her "haves" and her "have-nots". Yet these bridges are not a connected link for they have numerous gaps in them so much so that society yearns for a new alignment of conditions ensuring edequate means not merely "to each according to his capacity"—but "to each according to his need".

Western civilization based upon competition and hurry and with its emphasis on natural wealth and machine culture is a process of creating evils and finding remedies for them. Ours has always been rooted in co-operation and we have striven to solve the problem of life in our own way in this country without those violent commotions in soc tey which have disturbed elsewhere their peaceful progress. That way alone lies the route, unerring and safe, to the concept of a world State. There are deep-seated errors and emotional aberrations in men's minds which account for the prevailing malady and war mania, and these must be discovered and cured. The child is trudly the father of man and peace ideas like diet propensities must be infused into the new-born babe with the mother's milk and the nursery song. This is what the teaching of non-violence has done. Its achievement has been exemplary as can be seen by a contrast with the effect of the two Great World Wars that occurred in an interval of thirty-five years. Even these have paved the way to the world State. The first World War had changed the map of of Europe, and Russia had emerged with its new cult of equality sought to be eastablishd by wading through rivers of blood. The second world war has changed the map of Asia. Half the World's population lives in Asia, and Asia except Japan had been under subjection before it. These wars are like the flood of a river which carry the sandsfrom place to

place and form new islands, obliterating old ones. They do not make for ordered peace as non-violence alone can. A third World War—which Heaven forbid—may change the map of the world and demolish half of it for want of food. Let us no more dream of wars—even to fear them It is not merely hopes that come true, even fears may be realized.

Madhatma Gardhi's great achievement leaves no room for either, for he has woven the fabric of socieidty anew by piecing in the woof of modern ideology into the warp of ancient tradition, replacing each of the effete institutions of society by others that are alive and animating, infusing new life into old forms and reading a new meaning into ancient formulae. In each era it is one man that is able to achievesuch a result and in this era of centuries Gandhi is that man. Mahatmaji was the prophet of the great reconciliation not only between the Varnas and the Asramas, but between the past and the future and between youth and age. There are some passionately clinging to the past while others are seeking to catch at the future. But the wise man standing midway between both parties and sympathising with both knows that we are in the stage of eternal transition. The present is in every age merely the shifting point at which past and future meet. And we have no quarrel with either. There can be no world without traditions or without movement. We cannot bathe twice in the same stream though the stream flows in an unending circle.

"There is never a moment when the new dawn is not breaking over the earth and never a moment when the sun-set ceases to die. Let us not hasten towards the dawn with undue speed nor leave the sun set withont gratitude for the dying light that once was dawn. In the moral world, we are ourselves the light-bearers and the cosmic process is in us made flesh. We press forward, torch in hand, along our course in life and are soon outpaced by those behind us." Let us skilfully pass the living torch—bright and unflickered, as we ourselves disappear, to the hands of our juniors and help to make them the elders of the race in turn.

The youth represents the future and are the heirs to our ancient estate. The elders represent the past and are in possession of it now. It is no longer possible for them to ignore one another any more than the sunset of yester-eve can be forgotten in tne sunrise of this morn. Age represents the waters of the well eternally drawn and ever replinshed by the springs of youth all round. It is the youth that attains age and age that begets youth. Life is a happy blend of both.

SUMMARY OF THE PROCEEDINGS OF THE WORKING COMMITTEE

Gandhinagar (Jaipur), December 16—19, 1948.

The Working Committee met 11-30 a. m. on 16-12-1948.

Dr. Rajendra Prasad was in Wardha and could not attend the meeting. Pandit Govind Ballabh Pant was also absent. All other members were present.

The following time-table for the Working Committee, A. I. C. C., Subjects Committee and the Open Session of the Congress was fixed.

16-12-48	A.I.C.C. & Subjects Committee	...	2 p.m. to 7-30 p.m.
17-12-48	Working Committee	... ...	7-30 a.m.
	Subjects Committee	... ...	8-30 a.m
	„ „	... ...	2 a.m.
18-12-48	Working Committee	... ...	7-30 a.m.
	Subjects Committee	... ...	8-30 a.m.
	Open Session	...	3 p m. to 5 p.m. (Address)
	„ „	...	5 p.m. to 8-30 p.m. (Resolutions)
19-12-48	Open Session	... ...	8-30 a.m. to 12 Noon
	„ „	...	3 p m. to 8 p.m.

The Working Committee met at 7-30 a.m. on 17-12-48. Dr. Pattabhi was in the Chair. All members except Dr. Rajendra Prasad attended the meeting. The Working Committee passed the draft resolution for the Subjects Committee meeting on **"Standards of Public Conduct"**,

The Working Committee met again at 7-30 a.m. on 18th Dec. 1948. Dr. Pattabhi Sitaramayya was in the Chair. All the members were present except Dr. Rajendra Prasad. The Working Committee received a deputation of labour leaders, (Shri Gulzari Lal Nanda, Shri Hariharnath Sastri, and Shri Khandubhai Desai) associated with the H.M.S.S. and the INTUC. The deputationists placed before the Working Cammittee the difficulties they had to undergo in working in the Labours field as against the propaganda of other Party organisations. It was suggested that there must be a speedy process for the settlement of disputes by automatic reference for arbitration. They laid special emphasis on the economic distress caused by the abnormally high price level and wanted the Governments to take special notice of the same and promptly deal with the situation as otherwise, they felt, it would endanger the truce.

The Working Committee accepted the draft resolution on **"Linguistic Provinces"** to be placed before the Subjects Committee.

SUMMARY OF THE PROCEEDINGS OF THE ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE MEETING

Jaipur (Gandi Nagar), December 16, 1948,

The All India Congress Committee meeting started at 2 p.m. with Sardar Vallabhbhai Patel in the chair. Dr. Rajendra Prasad was absent. At the opening, "Vande Mataram" was sung. The proceedings of the A. I. C. C. meeting held in Bombay on April 24, 25 & 26, 1948, were confirmed.

The report of the General Secretaries for the period November 1946 to December 1948 was submitted and approved. The audited report of accounts for the period October, 1945 to September, 1947 was placed before the meeting and was accepted.

The A. I. C. C. then met as the Subjects Committee.

Sardar Vallabhbhai Patel invited Dr. Pattabhi Sitaramayya, President-elect of the Session, to take the chair. Dr. Pattabhi started the proceedings with an opening speech,

The Resolution on **"In Memoriam"** was moved from the Chair and was accepted, all standing.

The Resolution on **"Homage to Martyrs"** was moved from the Chair and was accepted, all standing.

The Resolution on **"General Condolence"** was also moved from the Chair and was passed unanimously.

The Resolution on **"The Message"** was moved by Shri Shankarrao Deo and seconded by Dr. P. C. Ghosh. Amendments were moved by (1) Dr. Choitram Gidwani, (2) Shri Johari Lal Jhanjaria, (3) Shri Abdul Ghani, (5) Shri Ansar Harvani, (5) Shri Algurai Shastri, (6) Shri Babubhai Patel, (7) Shri Mataprasad, (8) Shri Onkarnath, and (9) Shri Kannamwar. Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel next addressed the meeting in support of the resolution. Shri Shankarrao Deo accepted the amendment of Shri Onkarnath with slight changes. As a result the last para of the resolution was changed to read as follows :—

"The Congress urges all Congressmen with all earnestness to face the difficulties and crises of to-day, both national and international, in the light of that message so that India may grow in freedom and moral stature and the great objectives for which this Congress has stood may be fulfilled.".

The resolution was then placed before the House and passed unanimously.

The Resolution on **"Foreign Policy"** was moved by Shri Shankarrao Deo and seconded by Shri Jugal Kishore. Amendments were moved by (1) Shri Jagannathrao, (2) Shri Mahesh Dutt Misra; (3) Shri Mohan Singh Sahney, (4) Shri Ansar Harvani, (5) Shri Algurai Shastri, (6) Shri Shibbanlal Saxena, (7) Shri Joharilal Jhanjaria (8) Shri Mahabir Singh, (9) Shri Deen Dayal Khanna,

---

N B.—For text of resolutions see proceedings of the Congress Session (Page).

मंच--विषय-निर्वाचनी--(Subject Committee Dais)

(10) Shri Biswanath Das and (11) Shri Hirasingh Chineria. Shri Govind Ballabh Pant addressed the meeting in support of the resolution. He was followed by (1) Shri Nathulal Singh, (2) Dr. Jetley, and (3) Shri Vijaya Vargiya.

Pandit Nehru next spoke on the resolution. The amendments were either withdrawn or lost when put to vote. The resolution was accepted by an overwhelming majority.

The meeting terminated at 7-45 p.m.

SUBJECTS COMMITTEE MEETING

Gandhinagar, December 17—18, 1948.

The Subjects Committee met under the Chair-Manship of Dr. Pattabhi Sitaramyya at 8-30 a m.

Shri Shankrrrao Deo moved the Resolution on "**Foreign Possessions in India**". It was seconded by Shri Jugal Kishore. Amendments were moved by (1) Shri K. Kelappan, (2) Shri Algurai Shastri, Shri R. K. Sidhwa, (3) Dr. Jetley and (4) Shri Sivan Pillay. Shri S. K. Patil addressed the meeting in support of the Resolution. Pandit Nehru spoke on the resolution. The amendments were all withdrawn and the resolution was accepted unanimously.

Shri Shankarro Deo moved the Resolution on "**Indians in South Africa**". It was seconded by Shri Jugal Kishore. Amendments were moved by (1) Shris Shibbanlal Saxena, (2) Mata Prasad, and (3) Algurai Shastri.

Seth Govind Das and Shri Babubhai Patel spoke in favour of the resolution. All the amendments were later withdrawn or lost. The resolution was passed unanimously.

Shri Shankarrao Deo moved the Resolution on "**Indonesia**" It was seconded by Shri Jugal Kishore.

An amendment was moved by Shri Ansar Harwani. It wes lost by a large number of votes. The Resolution was passed unaimously.

Shri Shankarrao Deo then moved the Resolution on "**Sufferers from the Partition**". It was seconded by Shri Jugal Kishore.

Some amendments were moved to the Resolution by (1) Sardar Gurumukh Singh, (2) Shris Ajit Prasad Jain, (3) Shibbanlal Saxena, (4) Narendra Sen, (5) Dr. Choitram Gidwani, (6) Ruplal Mehta, (7) Nandlal, (8) Lehna Sing Sethi, (9) Algurai Shastri, (10) R. K. Sidhwa, (11) Abdul Ghani, (12) Jagat Narain Lal, (13) Nathulal Jain, and (14) Zail Singh. Sardar Pratap Singh, Smt. Sucheta Kripalani and Sardar Patel addressed the meeting in Support of the resolution. The mover accepted the amendments of Shri Nathulal Jain and Dr. Choitram Gidwani. All the other amendments were either withdrawn or lost. The Resolution as amended was passed by an overwhelming majority.

The meeting then adjourned.

The Subjects Committee resumed its sitting at 3 p. m. with Dr. Pattabhi Sitaramayya in the Chair.

Shri Shankarrao Deo moved the Resolution on '**Labour**" It was seconded by Shri Jugal Kishore.

Amendments to the resolution were moved by the following :—

(1) Shri Nathulal Jain,
(2) Shri Jagannath Rao,
(3) Shri Shibbanlal Saxena, and
(4) Shri Jogeswar Mandal.

Shri Jagjiwan Ram addressed the meeting. The amendment were all either withdrawn or lost. The Rosolution was accepted.

Shri Shankarrao Deo then moved the Resolution on "**States**". It was seconded by Shri Jugal Keshore.

Amendments to the resolution were moved by the following:—

(1) Shri Ratnappa Kumbhar,
(2) Shri Shatrughna Sharan Sinha,
(3) Shri Balkrishna Sharma,
(4) Shri Rânjit Singh,
(5) Shri Joharilal Jhanjaria,
(6) Shri Shibbanlal Saxena,
(7) Shri Ansar Harvani,
(8) Shri Nathulal Jain,
(9) Shri Jwala Prasad,
(10) Shri R. K. Sidhwa,
(11) Shri B. N. Sharma,
(12) Shri Sundarlal,
(13) Shri Bansilal Lohadia, and
(14) Shri Govind Prasad Srivastava.

Sardar Patel addressed the meeting. The amendments were all either withdrawn or lost. The resolution was accepted.

Shri Shankarrao Deo moved the Resolution on **"Gandhi National Memorial Fund"**.

Amendments were moved by Shri Raghavdas and Shri Mahabir Singh. Acharya Kripalani addressed the meeting. The amendments were withdrawn or lost. The Resolution was passed unanimously.

Shri Shankarrao Deo then moved the esolution on **"Communalism"**

Amendments were moved by the following:—

(1) Shri Jagat Narain Lal,
(2) Shri Mohan Singh Sahney,
(3) Shri Mahesh Dutt Mishra,
(4) Shri Algurai Shastri,
(5) Shri Nandlal,
(6) Shri Shibbanlal Saxena,
(7) Shri Onkarnath,
(8) Shri Din Dayal Khanna,
(9) Shri Yash Pal,
(10) Shri Roshanlal Vyas,
(11) Shri R. K. Sidhwa, and
(12) Shri Ansar Harvani,

Seth Govind Das addressed the meeting. The amendments were all withdrawn or lost when put to vote. The Resolution was passed unanimously.

The Subjects Committee met again at 8-30 a. m. on 18 Dec. 1948 in the Subjects Committee Pandal. Dr. Pattabhi Sitaramayya presided.

Shri Shankarrao Deo moved the resolution on **"Economic Programme"** which was seconded by Shri Jugal Kishore. Amendments were moved by Shri Joharilal Jhanjaria, Baba Raghav Das, Shri S. Nija-

lingappa, Shri Algurai Sastri, Sardar Ranjit Singh, Shri Jogesar Mandal, Dr. G. K. Jetley, Babubhai Patel, Nathulal Jain, M. Jaganathrao, Hirasingh Chineria, Abdul Ghani. Shatrughna Saran Singh, Shibbalal Saxena. The mover accepted the amendments of Shri Nijalingappa, Shri Algurai Shastri and Shri Ranjit Singh. The resolution as amended was placed before the House and was passed unanimously.

Shri Shankarrao Deo moved the resolution on "**Standards of Public Conluct**". Io was seconded by Shri Jugal Kishore. Amendments were moved by Shris Biswanath Das, Shri Rohini Choudhury. Shri Mahesh Dutt misra. Abdul Ghani, K. Subbaraju, K. P. Tripathi, B. N. Sharma, R. P. Sharma, Jwala Prasad, J. Jhanjaria, Gyani Zial Singh, Yash Pal, J. Mandal, Shibbanlal Saxena, Ranjit Singh, Niranjan Singh. The following amendment of Shri Mahesh Dutta Misra was passed by I07 votes against 52: In para 4. delete the words "and more specially" in the first line, and after the words 'provincial legislatures' add "and more especially members of the Cabinets." The following amendment of Shri Bansilal Lohadia Was lost by 9I votes against I04: "In para. 7 after the words 'Government activities', the following words be added, "and it is desirable that Congressmen holding ministerial posts should not be office-bearers in the Congress Committees and particularly members of the Parliamentary Board". All other amendments were lost or withdrawn. The resolution as amended was passed unanimously.

Pandit Govind Ballbh Pant moved the resolution on "**Linguistic Provinces**" It was seconded by Shri Jugal Kishore. The resolution was passed unanimously.

The Subjects Committee met again at 8-30 a. m. on 19th Dec. 1948. Dr. Pattabhi Sitaramayya presided. The following amendments to the Congress Constitution were moved from the Chair and accepted unanimously -

Article III : (a) Include the 5 new P. C. Cs set up in States : Rajputana, Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Himachal and Patiala and East Punjab States Union.

Article IV : (c) Certified Khadi—Certified through the agencies approved by the Working Committee.

(f) The portion of the sentence after the Working Committee in the 7th line should read as follows : "provided his name has been on the list of qualified members for at least one year."

Article IX : (d) Add at the end "Such constituencies shall consist only of contiguous areas."

(e) Delete "in a contiguous area" in line 3, and add at the end after 'five panchayats'—"in the constituency."

(f) "full term" in the third line shall be explained by the Working Committee.

(h) The P. C. C. shall intimate to the A. I. C. C. Office within two week after the delegates are elected.

(k) Separate clause 'k' has to read as follows:
"The delegates shall be elected for a term of three years."

Article XI: (b) After 'ex-Presidents of the P. C. C.s' in the second line add "as referred to in Article IX Clause (f)".

(c) iv: Second line—add "delegates" before 'fees and subscriptions'.

(d) ii: Fourth Line: delete "one" after 'and form' and add: "an ad-hoc committee".

Article XX: (f) Second line—Substitute for 'qulified and effective membership of the Congress'—"effective and qualified membership of the Congress respectively."

Pandit Jawaharlal Nehru then moved that discussion on the resolution on "**Standards of Public Conduct**" accepted in the amended form on 18th *December 1948 by the Subjects Committee* be reopened. The President sought the opinion of the House on it and by a majority of votes the House decided to reopen the question.

Pandit Jawaharlal Nehru then moved an amendment to delete in the penultimate para after the word 'Congressmen' "members of Central and Provincial Legislatures, more especially members of Cabinets". Shri S. K. Patil Seconded the resolution. Sardar Vallabhbhai Patel and Pandit Govind Ballabh Pant spoke in support of the amendment. The resolution as amended was passed by an overwhelming majority.

Non-Official Resolutions

The A. I. C. C. Office received notice of over one hundread and fifty non-official resolutions which the A. I. C. C. members wished to move at the Subjects Committee meeting. Most of these resolutions were covered by the official resolutions. As sufficient time was not left for their consideration, it was decided that the remaining resolutions be referred to the working Committee for consideration and disposal.

CONGRESS SESSION

The Jaipur Session of the Congress met under the Presidentship of Dr. Pattabhi Sitaramayya on I8th December I948. The proceedings started at 2 p. m. with 'Vende Mataram' which was followed by another national song.

Shri Gokulbai Bhatt, Chairman, Reception Committee, read his address. Acharya Jugal Kishore read the messages raceived from Dr. Rajendra

Prasad and others. He was followed by representatives of Indians Overseas their fraternal Greetings to the Congress. amongust them were (I) Dr. Anup Singh from America (2) Sardar Budh Singh from Ceylon, (3)Dr. Kapila from East Africe and (4) Shri Regmi from Nepal.

Dr. Pattabhi Sitaramyya then delivered his presidential address both in English and Hindustani.

The resolutions accepted by the Subjects Committee were then placed before the Open Session. The following Resolutions on **"In Memoriam"**, **"Homage to Martyrs"** and **"General Condolence"** were moved from the Chair and passed unanimously, all standing.

IN MEMORIAM

This Congress places on record its sense of profound sorrow and shame at the assassination of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation.

HOMAGE TO MARTYRS

The Congress offers its homage to all those martyts who have laid down their lives in the country's struggle for independence.

GENERAL CONDOLENCE

The Congress expresses its deep sense of sorrow and loss at the deaths of :—

1. Shri N. C. Kelkar,
2. Shri K. F. Nariman,
3. Shri B. G. Horniman,
4. Shri M. A. Jinnah,

5. Shri B. S. Moonjee,
6. Shrimati Pramilabai Oke,
7. Shri K. Pt Khadikar,
8. Shri R. S. Nimbkar,
9. Shri Smritis Bannerji,
10. Shri Sachindranth Mitra,
11. Shri Sushil Das Gupta,
12. Shri Mani Das.

Pandit Jawaharlal Nehru, then moved the following Resolution on "**The Message**". It was seconded by Maulana Abul Kalam **A**zad. The Resolution was passed unanimously.

THE MESSAGE

"During its long history of struggle for India's freedom, carried on from generation, to generation, the Congress experienced both sorrow and fulfilment and many triumphs and defeats. But under the superb leadership of the Father of the Nation, sorrow was made to chasten and purify the people and every defeat was turned into an incentive for redoubled effort and a prelude to victory.

Two years ago the Congress met in Meerut City at a time of trial and difficulty and again under inspiration of Gandhiji gave a lead to the nation. These two years have brought fulfilment in a measure, and the independence, for which generations had struggled and suffered, has been achieved. But the cost of that achievement has been heavy indeed, for the Motherland has been cut in two, and following this ill-fated partition, madness descended upon the people and all the

great ideals for which the Congress stood seemed for a moment to be eclipsed. The darkness was illumined by the heartening message of Gandhiji, and innumerable sorrowing hearts drew strength and solace from it.

Then came the greatest blow of all, the assassination of him who was the embodiment of love and the gentle uncoquerable spirit of India.

Thus the very achievement for which the Congress had laboured and which was a culmination of long struggle, brought no glow of freedom but sorrow and dismay.

In reverent memory of Gandhiji and in homage to his teaching, the country faced these terrible crises, the greatest of which was the crisis of the spirit which had clouded India's mind and made her forget for a while the great lesson which the Master had taught.

This Congress, meeting sixteen months after the attainment of independence and nearly eleven months after the passing away of him who fashiond it and gave it life, pays its homage to that great spirit and to his great message, and resolves to continue the service of the people of India and humanity in the light of that life-giving message.

Political freedom having been attained through non-violent action under the leadership of Gandhiji, the National Congress has now to labour for the attainment of social and economic freedom so that progress and equal opportunity may come to all

the people of India without any distinction of race or religion. This task requires and a dedication to the service of the Motherland in a constructive spirit.

The people of India have achieved independence: but to enjoy its fruits, they must discharge their responsibilities and obligations. Congressmen must remember that it has been and should continue to be their highest privilege to serve the people and to shoulder these responsibilities and obligations, and those who hanker after office or power, forgetting their obligations, do an ill-service to the country.

It was the particular teaching of Gandhiji that service should be directed more specially towards promoting unity and goodwill between all the people of India, abolishing class distinctions and those based on birth or caste or religion, and working for a classless democratic society in a peaceful manner. Above all, the lesson he taught was the adherence, at all costs and in all circumstances, to the moral values which give meaning to life.

This Congress urges all Congressmen with all earnestness to face the difficulties and crises of today, both national and international, in the light of that message so that India may grow in freedom and the great objectives for which this Congress has stood may be fulfilled."

Pandit Govind Ballabh Pant then moved the following Resolution on "**Foreign Policy**". It was

seconded by Shri Harekrishna Mehtab. The resolution was passed unanimously. The meeting adjourned at 8-30 P. M.

FOREIGN POLICY

"The National Congress has, even while it was struggling for the freedom of India, associated itself with progressive movements and struggles for freedom in other countries. India's liberation was viewed as a part of the larger freedom of all the countiries and peoples of the world, In particular, the Congress has stood in the past for the ending of all imperialist domination and colonial exploitation of any country or people, and has opposed Fascism and all other tendencies which suppress human spirit.

The achievement of independence brought new responsibilities to India in international affairs and it became necessary to develop direct and closer contacts with other nations, The Congress welcome these contacts and trusts that these will lead to mutual understanding and cooperation and the promotion of world peace.

The foreign policy of India must necessarily be based on the principles that have guided the Congress in past years. These principles are the promotion of world peace, the freedom of all nations, racial equality, and the ending of Imperialism and Colonialism. In particular, the Congress is interested in the freedom of the nations and peoples of Asia and Africa who have suffered

under various forms of colonialism for many generations.

with a view to advance the cause of world peace and coopertaion, India associated herself with the United Nations. This Congress declares its full adherence to the principles underlying the charter of the United Nations.

It should be the constant rim of the foreign policy of India to maintain friendly and cooperative relations with all nations and to avoid entanglement in military or similar alliances which tend to divide up the world in rival groups and thus endanger world peace. Maintaining her freedom of action in foreign affairs and in the economic development of the country, India should continue to function as a member state of the United Nations, cooperating with other States in the maintenance of peace and freedom.

In view of the attainment of complete independence and the establishment of the Republic of India, wchih will symbolice that independence and give to India the status among the nations of the world that is her rightful due, her present associations with the United Kingdom and the Commonwealth of Nations will necessarily have to change. India, however, desires to maintain all such links with other countries as do not come in the way of action and independence, and the Congress would welcome her free association with the independent nations of the Commonwealth for their commonweal and the promotion of world peace.

India is especially concerned with her neighbour countries of Asia and the Congress trusts that closer bonds of fellowship and cooperative effort for the maintenance of freedom of Asian nations and their progress will be developed."

The Session started at 2 p. m. on I9-I2-I948. Dr. Pattabhi Sitaramayya presided.

Shri S. K. patil moved the following Resolution on "**Foreign Possessions in India**". It was seconded by Shri R. K. Sidhwa. The resolution was passed unanimously.

FOREIGN POSSESSIONS IN INDIA

"The chequered course of India's history during the last two hundred years or more has left certain foreign possessions in various parts of the country. These foreign possessions continued for this long period because India herself was under alien domination.

With the establishment of independence in India the continued existence of any fereign possession in India becomes anomalous and opposed to the conception of India's unity and freedom. Therefore it has become necessaay for these possessions to be politically incorporated in India and no other solution can be stable or lasting or in conformity with the will of the people. The Congress trusts that this change will be brought about soon by peaceful methods and the friendly cooperation of the Gevernments concernd. The Congress realises that during this long period administrative, cultural, educational and judicial systems have grown up in these foreign

possessions, which are different from those prevailing in the rest of India. Any change-over therefore must take these factors into consideration and allow for a gradual adjustment which will not interfere with the life of the people of the areas concerned. The Congress would welcome the present cultural heritage of these possessions to be continued, in so far as the people of those possessions desire and for a measure of autonomy to be granted, wherever possible, so as to enable the people of those possessions to maintain their culture and institutions within the larger frame-work of free India."

Seth Govind Das moved the following Resolution on "**Indians in South Africa**" which was seconded by Shri Raoji Bhai Patel. Shri Mata Prasad also addressed the Session. The resolution was passed unanimously.

INDIANS IN SOUTH AFRICA

"This Congress has noted with deep regret that the Government of the Union of South Africa continues to treat its Indian citizens in disregard of acknowledged human rights and of the principles laid down in the Charter of the United Nations. That Government has ignored the wishes of the General Assembly of the United Nations and even challanged the fundamental principles on which the United Nations Organisation is founded. This repudiation of a vital principle, if persisted in, can only lead to bitter and far-reaching racial

conflicts and may even result in the break-up of the United Nations Orgnization.

The Congress expresses its full sympathy with all those who have *suffered by the policy of* racial discrimination of the Government of the Union of South Africa."

Acharya Jugal Kishore then moved the Resolution on **"Indonesia"** which was seconded by Shri Deshpande. The resolution was passed unanimously.

INDONESIA

"The Congress sends its greetings to the leaders and people of the Indonesian Rebublic, who have struggled for their freedom against difficulties during the past three years. It assures them of its complete sympathy for their cause. The people of Indonesia have been culturally associated with the people of India for ages past and it is a matter of the utmost concern to India that Indonesia should attain her full freedom and take her rightful part in Asian and international affairs."

Shri Balwantrai Mehta moved the following resolution on **"States"**. He was seconded by Shri Shanti Saran (Rampur State). Shri Harbans Lal (East Punjab States), Shri Dulichand Trivedi (Rajasthan Union), Shri Kulwantrai (Patiala & East Punjab States), Shri Y. S. Parmar, Shri Gian Chand (Patiala & East Punjab states) Shri

Gunanond Sharma (Tehri State), Shri Satya Dev Busbari (Himachal) and Shri Sitaram Dwivedi (Banares State) spoke on the Resolution. Sardar Vallabhbhai Patel also addressed the Session. The Resolution was passed unanimously.

STATES

"The Congress welcomes the developments that have taken place in regard to the States in India, resulting in the ending of the Indian States system which the British Government had built up early in the 19th century. While welcoming this process of integration, merger and union, so as to make the States approximate to the Provinces, the Congress trusts that all Feudal relics and impediments to the free development of the people will be removed".

———

Sardar Pratap Singh then moved the following Resolution on **"Sufferers from the Partition"**. It was seconded by Shri N. V. Gadgil. Smt Sharda Bhargava (Jaipur), Shri Roshanlal Vyas (E. Punjab), Shri Bhalchandra Sharma (Bengal), Shri N. Sanyal (Bengal), Shri Narendra Nath Sen (Bengal), Shri Ranbir Singh Mehta (Punjab), Smt. Sucheta Kripalani and Smt. Mridula Sarabbai also addressed the gathering.

On the suggestion of the President, the amendment of Shri Tulsiram Sarogi to the effect that the words "and the non-official organisations" should be added after 'Central, Provincial and State Governments', was incorporated in the

resolution. The resolution was passed unanimously.

SUFERERS FROM THE PARTITION

"This Congress records its deep sorrow at the death, by internecine conflicts, of vast numbers of the people of this country belonging to every religion, during the disturbances that preceded the Partition. The Congress extends its heartfelt sympathy to all their relative and to all the refugees who have suffered untold misery and lost all they possessed, and borne their sufferings with fortitude. While appreciating the work that the Central, Provincial and State Governments and the non-official orgonisations have done to give relief to and rehabilitate there refugees, the Congress, trusts that every effort will be made both by Government, Congress organisation and people to expedite this work and more particularly that children and young people will be specially cared for and given opportunities of education and development".

Pandit Jawaharlal Nehru addressed the Session and dwelt at length on the problem of refugees.

Shri Govind Ballabh Pant then moved the following resolution on "**Communalism**" which was seconded by Shri Purshottam Das Tandon. Among others who spoke on the resolution were Shri Anantasayanam Ayyangar, Sardar Zail Singh, Shri Harihar Lal Bhargava, Sardar Mohan Singh Sahney and Shri Ansar Harwani. The resolution was passed unanimously.

COMNUNALISM

"Ever since its inception, the National Congress has conceived and striven for a nation where the peeple of all religions and races should have equal rights and opportunities and should function together as citizens of India. It has opposed communalism and separatism which weaken the nation and come in the way of all progress and cooperative effort. Keeping this ideal in view, it has nevertheless, by stress of circumstances, and by the pressure of the dominating power at the time, accepted certain compromises, which introduced an element of communalism in the public life of the country. In spite of the efforts of the Congress, communal forces, exploiting the name of religion grew in strength and resulted not only in the partition of the country, but also in the foul assassination of Mahatma Gandhi.

The terrible experiences through which the country has passed have demonstrated the evil that communalism brings in its train and have shown that the freedom of the Indian nation, as of every componant part of it, is imperilled by these communal and separatist tendencies. In order, therefore, to preserve the hard won freedom of the country and for the nation to grow and prosper and enjoy the fruits of this Freedom, it has become essential to put an end to the spirit of communalism which has already caused so much grievous injury.

The long past of India is evidence of the spirit of tolerance which was the basis of life and culture in

this country. India has been and is a land of many religions and many races and must remain so. The freedom of India can only be based on a recognition of an over-riding unity binding together the richly varied cultutral life of the country, which should have full play. The aim of the Congress has therefore been to develop this great country as a democratic secular State which neither favours nor discriminates against any particular religion.

This Congress reiterates this objective and declares its firm resolve not to permit communalism or the misuse of religion as a political weapon for anti-national and socially reactionary purposes. The Congress calls upon the country to make a supreme effort to restore good will, peace and harmony among the various communities that from the nation.

It is for this that Mahatma Gandhi laboured, and it was for this that he ultimately sacrificed his precious life. To every Indian, and more particularly to every Congressman, he has left this great legacy and example."

Shri Jagjiwan Ram, then, moved the following resolution on "**Labour**". It was seconded by Shri Shankarrao Deo. Other speakers on the resolution were General Awari, Shri Algurai Shastri, Shri Satyanarayan Raju, Smt, Ram Dulari Sinha, and Shri M. C. Tapde (Vidarbha). The resolution was passed unanimously.

The National Congress has always stood for the rights of the working class and for ending exploitation in every shape or form. Even while engaged in a life and death struggle to achieve the freedom of the country, it never lost sight of its essential duty of protecting and advancing the vital interests of the worker, whether in the field or in the factory. Mahatma Gandhi's successful intervention in the Ahmedabad Textile Labour Dispute in 1918 ushered a new era in the peaceful settlements of industrial disputes between organised labour and capital. Congress Committees as well as individual Congressmen have worked ceaselessly in the service of the working class and have held a loft the ideal of securing social justice to the worker. The growth and development of Trade Unionism in this country owes much to the active sympathy, support and guidance of leading Congressmen and the Congress organisation.

With the achievement of independence, the task of more direct and active participation in the programme of ameliorating the condition of the working class devolves more squarely on this great national organisation. Believing that political freedom is the fountain-head of all other freedoms, social and economic, the Congress concentrated the bulk of its energies on the elimination of imperialistic exploitation. Now that independence has been achieved the Congress calls upon its members and its constituent bodies to take more active interest in the labourfield, to strengthen their

links with the workers in fields and factories and to promote just relations between labour and management.

This Congress appreciates the progressive policy of labour legislation undertaken by the Central and Provincial Governments laying the foundations of social security and adopting other measures calculated to safeguard and promote the interests of industrial labour. It calls upon the Provincial Governments to pursue with vigour, and complete within the shortest possible time the programme of improving the lot of the agricultural labour already initiated by the Central Government through the Minimum Wages Act.

The Congress is aware of and fully sympathises with the difficulties and hardships of the workers due to various causes and yet appeals to them to take a realistic and responsible view of the critical situation through which the country is passing and not to be swayed by destructive ideologies leading to greater strife, chaos and discord. The Congress further warns the workers against the organised attempts to exploit the working classes for narrow political ends in the utter disregard of the vital needs and basic interests of the country.

While appreciating the timely move of the Central Government to establish Industrial Truce this Congress asks both capital and labour to work whole-heartedly in the maintenance of peace and good relations in industry. This Congress is of the opinion that uninterrupted and expanding production is a

vital and indispensable pre-condition for relieving the present hardship of the people and for raising the standard of livng of the workers. Any slowing down or suspension of work for even a short period in industry or transport anywhere in the country would greatly hamper recovery, add to the already heavy burden of miseries of the people and prove exceedingly detrimental to the interests of the workers themselves.

The Congress fully admits that adequate incentives must be offered to the workers so that they can fully cooperate with the nation's drive for increased production. In this connection this Congress approves of the recommendation of the Economic Progamme Committee of the A.I.C.C. on fixation of fair wages and fair profits and the scheme of profit-sharing for labour in industry and calls upon the Central and Provincial Governments to take effective and early steps to implement these recommedation.

Acharya J. B. Kripalani then moved the following resolution on "**Gandhi National Memorial Fund**" which was seconded by Shri Basantlal Murarka (Bengal). The resolution was passed unanimously.

GANDHI NATIONAL MEMORIL FUND

This Congress endorses the appeal and approves of the action taken by the A.I.C.C. to raise a National Memorial to Mahatma Gandhi and to start a National Memorial Fund with the object

of furthering the constructive, educational, social and cultural ideals and activities with which Mahatma Gandhi was so intimately connected during his life time, and through the implementation of which he hoped to make India a just, healthy, self-reliant, united and democratic nation, as well as to further the cause of world peace and fellowship, and of collecting, preserving and publishing his writings and teachings in various languages.

Prof. N. G. Ranga moved resolution on "**Economic Programme**", which was seconded by Dr. P. C. Ghosh. The resolution was passed unanimously.

ECONOMIC PROGRAMME

This Congress generally approves the report and recommendations of the Economic Programme Committee of the All India Congress Committee.

In view of the economic crisis through which the country is passing, it is the duty of the Government as also of the people to further the objectives that the Congress has laid down and in so spreading the burden of today that it may be shared by all and that none may escape it while others are crushed by it. The nation must undergo a period of austerity and must avoid all wasteful expenditure. Conscious and concerted effort must be made on national scale to meet this crisis in production and price inflation. All the

nation's resources, human and material, should be utilised to increase production. While the people must produce more, they must consume less and invest their savings in Gouernment Securities and undertakings. There must be economy all ronnd. Government must ruthlessly cut down their expenditure consistently with the efficiency of administration and the safety of the State.

While it is essential to press forward large scale projects in order to increase the food supply and the power resources of the nation so that the nation may be self-sufficient in regard to food and other essential commodities, small scale projects should be particulary undertaken as they yield quicker results. This must be done in a planned manner. Attention must be specially directed to the rapid development of cottage and small scale industries, preferably on a cooperative basis, which will provide employment to many and will immediately produce more consumers' goods. This plan of decentralised production should form part of the permanent economy of the country.

To assure the urban population, specially industrial workers a regular supply of food grains at the controlled rate during this period of shortage, food-grains should be procured from the cultivator at a price remunerative to the cultivator and fair to the consumer after leaving enough for the peasant and his family. Peasants should cooperate with the Governments in making the procurments of food grains a success. This Congress endorses the textile

policy of the Government of India and calls upon the Provincial Government to see that a fair quota of mill-cloth and other essential goods necessary for a minimum standard of living be made available at controlled rates, preferably through cooperatives, to the villagers. The services of the A. I. S. A. and A.I,V.I.A. should be enlisted to organise an intensive campaign throughout the country for production of Khadi and other commodities.

In order to put forth the utmost effort in production, it is essential that industrial and agrarian conflict should be avoided, for each such conflict means loss in production and a set-back to the nation. The Congress congratulates the Central Government on its efforts in the interest of industrial truce and social insurance and recommends early establishment in all the Provinces States and Unions on a uniform basis, of statutory machinery for the resolution of industrial disputes in a just and peaceful manner, and also the establishment of machinery, Central, regional and functional, for the study and determination of fair wages and conditions of labour and fair remuneration of capital, and methods for the association of labour in all matters concerning industrial production such as formation of Central, regional and unit production committees.

The Congress further appeals to all who are concerned in production to try their utmost to make every effort to this end. The proprietors of industry

should bring down their profits and help in raising production. Labour must realise that every strike and lock out at this stage is a grave ill-service to the general community.

The Government of India have announced their Industrial Policy favouring a Mixed Economy and leaving a very large sector for development and expansion by private enterprise. The industrialists in this hour of crisis must do their duty-by the nation. Ohile it is the policy of the Congress to see that the industries are operated in the interest of the nation and the key industries are progressively brought under State control and ownership, it is not its intention to injure the legitimate interests of the industrialists.

The Central, Provincial, States and Union Governments are further requested to take steps to have adequate housing facilities porvided for industrial labour. Locally available materials should be used to the largest possible extent in order to lesson cost and expedite construction.

The Congress is fully aware of the hardships due to the rising cost of living and the defective system of settlement of disputes and is anxious to find effective remedies for both. At the same time the Congress would like to place the working class on its guard against the disruptive forces which want to exploit the working class for the fulfilment of their political aims. There is no better and greater duty today for all those engaged in industry in

whatever capacity than to keep the wheels of production constantly going.

Shri Shankarrao Deo then moved the following Resolution on "**Standards of Public Conduct**". It was seconded by Shri Jagat Narain Lal. Shri Rajendra Dube also spoke on the resolution. The resolution was passed unanimously.

STANDARDS OF PUBLIC CONDUCT

The Congress, under Gandhiji's leadership, become not only a powerful instrument for gaining India's freedom, but also an organisation in intimate contact with the masses and attracting their goodwill and loyalty and exercising a moral authority over them. Gandhiji's conception of politics and public life was inextricably connected with high moral standards and sacrifice and service of the people irrespective of caste or creed. This conception influenced the Congress, which he shaped, and Congressmen came to be judged not by their wealth or status in society but by their public service and sacrifice and their individual conduct. Thus the Congress attained a supreme position in the life of the country and public standards rose to a high level. Because of this India not only achieved independence but also gained the respect and admiration of other nations.

It is this precious heritage that the present and succeeding generations have to preserve. If this hard-won freedom is to be maintained and utilised

for the creation of a new society based on social justice and equality of opportunity for all, it is essential that the Congress and Congressmen should keep intact these great ideals and should continue to serve the people without becoming victims to the lure of power, wealth or privilege.

Unfortunately, contact with power has affected many Congressmen and there is a tendency to use this power and position for self-interest. The spirit of disinterested service and of constructive work for the public cause gradually ceases to be the motive power which moves large numbers of people. It is essential, from the point of view of the individual as will as of the nations, that this tendency should be arrested and every Congressman and Congres-woman has a duty and obligation to work to this end.

Gandhiji combined political work with constructive and productive activity and placed a varied programme of constructive work before the country in which every Congressman, and indeed every Indian, was expected to take part. It was by this service that the Congress organisation grew in influence and the nation become strong. Political activity must necessarily deconfined to a few, but national activity and service must be the privilege and obligation of every individual.

In order to renew and revitalise itself, the Congress must devote itself to renewing this service in some form of the constructive programme. Unity among the various communities in the country is

the first essential, and the removal of all forms of untouchability and the like is equally important. Other important activities are, social education of the masses in towns and villages, and a country-wide campaign for increasing production in every way and, more espesially, through the agency of cooperatives and village industries, including Khadi, association with the "Grow More Food" campaign, and organisation and service of workers in field and factory. It should be the special privilege of young men and young women to undertake these various activities in the service of the contry.

Owing to the widespread reintroduction of controls, it is necessary that congressmen should cooperate with others in making these controls a success and in checking corruption and breaches of the regulations.

The success of the Central and Provincial Governments, controlled by the Congress, depends to a large extent on full cooperation between the Governments and the Congress organisation. This cooperation should be evolved in each Province, subject to broad principles being laid down in regard to it by the working Committee of the congress or the Central Parliamentary Board. It is not possible or desirable for individual Congressmen to interfere in Government's activities. Complaints of Governmental activity or abuse of authority should be dealt with by the provincial Congress Committee alone who should approach Government for redress. In particular Congressmen must always bewere of

getting any special facilities, financial or other, for themselves or for there friends and relatives.

All Congressmen must set an exapmple in all such matters and maintain a high standard of conduct.

In these days of world crises and national difficulty a burdan is cast on the Congress which it must shoulder. Crises are not resolved or diffiicul-ties removed by patchwork remedies or opportunist methods. They are only finally resolved by removing the root cause of trouble end by maintaining always a high moral standard. The Congress there fore calls upon all Congressmen and the Nation generally to apply themselves to these great tasks in the sprit which enabled them to achieve freedom for this country.

The folowing resolutions on **"Linguistic Provinces"** and on **"Congress Constitution"** were moved from the Chair and passd unanimously.

LINGUISTIC PROVINCES

The question of the formation of new provinces on a unilingual basis and the re-distribution of the existing provinces for this purpose, wherever necessary, has engaged public attention for a considerable period. The Congress is aware of the strong desire for the formation of separate provinces on as linguistic basis and it has accepted the priniicple. In view, however, of the report of the Linguistic Provinces Commission appointed by the President of the Constituent Assembly and the new problems that have arisen out of the achievement

of independence, this Congress appoints a committee of the following three members, namely:

1. Dr. Pattabhi Sitaramayya
2. Pandit Jawaharlal Nehru
3. Sardar Vallabhbhai Patel

to review the position and to examine the question in the light of the decisions taken by the Congress in the past and the raquirements of the existing situation. The Committee will submit its report to the Woıking Committee within three months.

AMENDMENTS IN CONGRESS CONSTITUTION

Article III: Include the 5 New P. C. C's. set up in

(a) States : Rajputana, Madhyabharat, Vindhya Pradesh, Himachal and Patiala & East Punjab States' Union.

Article IV : Certified Khadi—Certified through the

(c) agencies approved by the Working Committee.

(f) The portion of the sentence after the Working Committee in the 8th line should read as follows : "provided his name has been on the list of qualified members for at least one year".

Aricle IX : (d) Add at the end "Such constituencies shall consist only of contiguous areas"-

(e) Delete "in a contiguous area in line 3, and add at the end after 'five panchayats'—"in the constituency."

(f) "full term" in the third line shall be explained by the Working Committee.

(h) The P. C. C. shall intimate to the A.I.C.C. Office within two weeks after the delegates are elected.

(k) A separate clause 'k' has to be added to read as follows:

"The delegates shall be elected for a term of three years".

Article XI: (b) After 'ex-Presidents of the P. C. C's.' in the second line, Add "as referred to in Article IX clause (f)."

(c) iv Second line—add "delegates" before 'fees and subscription.'

(d) ii Fourth line: delete "one" after 'and form' and add: "an ad-hoc committee".

Article XX: (f) Second line—substitute for qualified and effective membership of the Congress"—effective and qualified membership of the Congress respectively."

Pandit Jawaharlal Nehru also addressed the gathering and the session came to an end at 9 p.m. with the singing of "Jana Gana Mana."

Shri Hiralal Shastri, on behalf of the Reception Committee, made a short speech.

परिशिष्टों की सूची

रिपोर्ट पृष्ठ संख्या	परिशिष्ट	विषय
५	१	स्वागत समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची
६	२	संचालन समिति के सदस्यों की सूची
,,	३	समितियों के सदस्यों संयोजकों की सूची
१५	४	अधिवेशन सम्बन्धी कार्यक्रम की सूची
१८	५	द्वारों के नाम
३६	६	आय व्यय का तलपट

स्वागत समिति की कार्य-कारिणि के

सदस्यों की सूची

परिशिष्ट १

१. श्री गोकुलभाई भट्ट
२. श्री हीरालाल शास्त्री
३. श्री जयनारायण व्यास
४. श्री श्रीकृष्णदास जाजू
५. श्री माणिक्यलाल वर्मा
६. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
७. श्रीमती जानकीदेवी बजाज
८. श्री भागीरथ कानोडिया
९. श्री कमलनयन बजाज
१०. श्री सिद्धराज ढड्ढा
११. श्री दौलतमल भण्डारी
१२. श्री रघुवरदयाल गोयल
१३. श्री बलवन्तसिंह मेहता
१४. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
१५. श्री कृष्णगोपाल गर्ग
१६. श्री मुकटविहारी भार्गव
१७. श्री पूर्णचन्द जैन
१८. श्री शिवविहारी तिवाडी
१९. श्री रामेश्वर अग्रवाल
२०. श्री शोभाराम

२१. श्री आदित्येन्द्र
२२. श्री भोलानाथ
२३. श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी
२४. श्री रूपलाल सोमाणी
२५. श्री नाथूलाल जैन
२६. श्री गोकुललाल असावा
२७. श्री प्रेमनारायण माथुर
२८. श्रीमती रतनदेवी शास्त्री
२९. श्री चिरंजी लाल शर्मा
३०. सरदार हरलाल सिंह
३१. श्री मीठालाल त्रिवेदी
३२. श्री बाबूलाल कपूरचन्द
३३. श्री चौधरी रामचन्द्र
३४. श्री रमेशचन्द व्यास
३५. श्री भँवरलाल आचार्य
३६. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
३७. श्री वंशीलाल लुहाडिया
३८. श्री देवीशंकर तिवाडी
३९. श्री टीकाराम पालीवाल
४०. डा० मंगलसिंह
४१. श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय
४२. श्री सुमनेश जोशी
४३. श्रीमती शारदा भार्गव
४४. श्री मांगीलाल भव्य
४५. श्री भागचन्द सोनी
४६. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

४७. श्रीमती गोमतीदेवी भार्गव
४८. श्री बालकृष्ण कौल
४९. श्री सोहनलाल दूगड़
५०. श्री अमृतलाल पायक
५१. श्री मातादीन भगेरिया
५२. श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा
५३. श्री जियचन्द जैन
५४. श्री सुभद्र कुमार पाटनी
५५. श्री लादूराम जोशी
५६. श्री नेमीचन्द कासलीवाल
५७. श्री भोगीलाल पांड्या
५८. श्री रामानन्द अग्रवाल
५९. श्री भीमसेन वेदालंकार
६०. श्री नजीर अहमद
६१. श्री अमृतलाल यादव
६२. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
६३. श्री सादिक अली
६४. श्रीमती सज्जनदेवी
६५. श्री कुशलचन्द डागा
६६. श्री अब्बासअली
६७. श्री तुलसीराम सरावगी
६८. श्री रामेश्वर टांटिया
६९. डा० जी. एस. महाजनी
७०. श्री चम्पालाल बांठिया
७१. श्री मस्तानसिंह
७२. श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी

७३. श्री सन्तोषचन्द्र वरदिया
७४. श्री विशंभरनाथ भार्गव
७५. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा
७६. श्री केदारमल परसरामपुरिया
७७. श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णिय
७८. श्री गोविन्दनारायण झालानी
७९. श्री नरोत्तमलाल जोशी
८०. श्री राजवहादुर
८१. श्री रूपचन्द सोगाणी
८२. डा० राजमल कासलीवाल
८३. श्री देवीलाल सामर
८४. श्री भगवानदास भार्गव
८५. श्री महावीर प्रसाद भार्गव
८६. श्री वी. एन, काक

५५ वां कांग्रेस अधिवेशन स्वागत समिति

संचालन समिति की सूची

१. श्री गोकुलभाई भट्ट	अध्यक्ष, स्वागत समिति
२. श्री श्रीकृष्णदास जाजू	उपाध्यक्ष ,, ,,
३. श्री हरिभाऊ उपाध्याय	,, ,, ,,
४. श्रीमती जानकीदेवी बजाज	,, ,, ,,
५. श्री माणिक्यलाल वर्मा	,, ,, ,,
६. श्री भागीरथ कानोडिया	,, ,, ,,
७. श्री हीरालाल शास्त्री	प्रधान मंत्री ,, ,,
८. श्री जयनारायण व्यास	दलपति, स्वयंसेवक दल
९. श्री कमलनयन बजाज	कोषाध्यक्ष
१०. श्री सिद्धराज ढड्ढा	संयुक्त मंत्री, स्वागत समिति
११. श्री दौलतमल भंडारी	संयोजक, निर्माण समिति
१२. श्री रामेश्वर अग्रवाल	,, भोजन समिति
१३. श्री विजयचन्द जैन	,, सामग्री संग्रह समिति
१४. श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय	,, प्रचार प्रकाशन समिति
१५. श्री रघुवरदयाल गोयल	,, निवास समिति
१६. श्री सरदार हरलालसिंह	,, पंडाल व्यवस्था समिति
१७. श्री देवीलाल सामर	,, सजावट समिति
१८. श्री सुभद्रकुमार पाटनी	,, बाजार विज्ञापन समिति
१९. श्री पूर्णचन्द जैन	,, प्रदेश नियंत्रण समिति
२०. श्री लादूराम जोशी	,, सफाई समिति
२१. श्री डा० राजमल कासलीवाल	,, रोगोपचार समिति
२२. श्री राजबहादुर	,, रेल्वे यातायात समिति
२३. श्री रूपचन्द सोगाणी	,, जुलूस समिति
२४. श्री टीकाराम पालीवाल	,, स्वागत सत्कार समिति
२५. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	,, सवारी समिति
२६. श्री कृष्णदासभाई गांधी	,, प्रदर्शनी समिति
२७. श्री नेमीचन्द कासलीवाल	कानूनी सलाहकार

परिशिष्ट नं० ३

समितियों के नाम तथा उनके संयोजक

क्रम संख्या	समिति	संयोजक
१.	निर्माण समिति	श्री दौलतमल भंडारी
२.	सामग्री संग्रह समिति	श्री विनयचन्द जैन
३.	भोजन समिति	श्री रामेश्वर अग्रवाल
४.	प्रचार प्रकाशन समिति	श्री चन्द्रगुप्तवार्ष्णेय
५.	स्वयंसेवक समिति	श्री जयनारायण व्यास
६.	निवास समिति	श्री रघुवरदयाल गोयल
७.	प्रवेश नियंत्रण समिति	श्री पूर्णचन्द्र जैन
८.	सजावट समिति	श्री देवीलाल सामर
९.	प्रदर्शिनी समिति	श्री कृष्णदास गांधी
१०.	रेलवे यातायात समिति	श्री राजबहादुर
११.	सफाई समिति	श्री लादूराम जोशी
१२.	बाजार विज्ञापन समिति	श्री सुभद्रकुमार पाटनी
१३.	रोगोपचार समिति	श्री डा० राजमल कासलीवाल
१४.	पंडाल समिति	सरदार हरलालसिंह
१५.	सवारी समिति	श्री गुलाबचन्द कासली वाल
१६.	स्वागत सत्कार समिति	श्री टीकाराम पालीवाल
१७,	अर्थ व्यवस्था समिति	श्री कमलनयन बजाज
१८,	जलूस समिति	श्री रूपचन्द सौगाणी
१९.	सामान समेट समिति.	श्री हरलाल सिंह
२०,	कलकत्ता समिति	श्री भंवरमल सिंघी

५५वें कांग्रेस अधिवेशन का

मुख्य कार्यक्रम

	दिसम्बर १९४८ ता०	समय
१. सर्वोदय प्रदर्शिनी का आचार्य विनोवा द्वारा उद्घाटन	ता० १४	३ बजे
२. दिल्ली से मनोनीत अध्यक्ष का स्पेशल ट्रेन से आगमन	१५	२ बजे
३. महात्माजी की मूर्ति का अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन	१५	२। बजे
४, अध्यक्ष का जुलूस चांदपोल और जोहरी बाजार से म्यूजिम तक	१५	३ से ५॥
५. अध्यक्ष को जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल द्वारा मानपत्र भेंट	१५	५॥ बजे
६. झंडारोहण	१६	८॥ बजे
७. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक	१६	१० बजे
८, अ. भा. कांग्रेस समिति की बैठक	१६	२ से ३
९. विषय निर्वाचिनी समिति की बैठक	१६	३ से ४
		४॥ से ६
	और	
	१७	८॥ से ११॥
		२ से ४
१०. खुला अधिवेशन	१८ और १९	२ से ७

परिशिष्ट नं० ५

राजस्थान के शहीदों के नाम पर बनाये गये

द्वारों की सूची

१. मुख्य द्वार	जमनालाल बजाज द्वार
२. उत्तर का द्वार	बीरबल मोची द्वार
३. पूर्व का द्वार	रमेश स्वामी द्वार
४. दक्षिण का द्वार	प्रतापजी बारहठ द्वार
५. पश्चिम का द्वार	बालमुकन्द बिस्सा द्वार
६. उत्तर से पूर्व की ओर नं० १	चुन्नीलाल द्वार
७. " नं० २	पापणी द्वार
८. " नं० ३	रूपाजी करपाजी द्वार
९. पूर्व से दक्षिण की ओर नं० १	शांतिलाल वैद्य द्वार
१०. " नं० २	रामचरणसिंह द्वार
११. " नं० ३	हरिनारायण शर्मा द्वार
१२. पंडाल से मानसिंह हाईवे नं० १ की तरफ	शांतिलाल आनन्दीलाल द्वार
१३. " नं० २	मौलाना मोहनुद्दीन द्वार
१४. विषय निर्वाचिनी की ओट में	भीमशंकर शर्मा द्वार
१५. " की बगल में	अभयमल द्वार
१६. " "	अर्जुनलाल सेठी द्वार
१७. अन्य स्थानों पर	गोरीशंकर भार्गव द्वार
१८. "	नयनुराम द्वार
१९. "	केसरीसिंह बारहठ द्वार
२०. "	सागरमल गोपा द्वार
२१. "	मीठालाल व्यास द्वार
२२. "	खूबराम सर्राफ द्वार

AUDITORS REPORT

From

15 th July 1948 to 31 st July 1950

BY K. N. GUTGUTIA & CO.

Chartered Accountants

Hony. Auditors

K. N. GUTGUTIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Jaipur:
Dated the 11th August. 1950

To,

The Members of the Reception Comittee
55th session of the All India Congress,
held at Jaipur

Gentelemen,

We have audited the annexed Balance Sheet of the 55th Session of the all India Congress held at Jaipur in December, 1948 as at 31st July, 1150 and the relative Income and Expenditure Account thereof with the books of accounts and papers produced to us and have to observe thereon as follows:—

1. PERIOD:—The books of account started from 15th July. 1948 and the above accounts have been drawn upto 31st day of July, 1950.

2 INTERNAL CHECKING, AND QUANTITATIVE RECONCILIATION:—

Speaking generally there was no internal checking of the accounts in any of the departments—better known as "Samities". No quantitative register were maintained for recording receipts and issues of stores and other meterials—heavy or light—such that quantitative reconciliation could be made in any of the—Samities.

(a) SAWARI SAMITI (TRANSPORT DEPARTMENT) Consumption of petrol, payments for trucks hired and the utilities thereof have not heen substantiated nor accounted for.

(b) BHOJAN SAMITI (KITCHEN;—

Detailed account of Bhojan 'Coupons' was not available. Total amounts paid for purchases of Food grains etc, less the proceeds of sales credited in the books have been shown as consumption.

(c) NIRMAN SAMITI (CONSTRUCTION):—

Issue of construction material and subsequent disposal thereof have not been properly accounted for and hence proper verification of the construction accouut was not possible.

(d) VIKRAY SAMITI (SALES):—

No detailed account of stores and other articles—collected from the different Samities and transferred to—the 'Vikray' Samity was maintained and as such save and except checking the sale proceeds as credited in the books with the counterparts of bills, cash memos and other receipts issued no other verification was possible.

(e) SWAYAM SEWAK SAMITI:—

The detailed Account of Volunteers dress putchased, sold or distributed are not available. In short. besides checking the receipts and payments of money as recorded in the books of accounts with the vouchers and papers—available to us—no quantitative verification was possible for reasons mentioned hereinbefore.

Subject to the foregoing observations. the above accounts have been properly drawn up and the same are correct to the best of our information and fhe explanations given to us and as shown by the books of accounts.

Yours faithfully.
Sd/—K. N. Gutgutia & Co
CHARTERED ACCOUNTANTS
HONY AUDITORS

RECEPTION

55TA INDIAN NATIONAL

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE

EXPENDITURE	Rs.	as.	p.	Rs.	as.	ps.
To Salaries				213627	15	0
,, Postage & Telegram				7156	9	0
,, Stationery				21698	8	9
,, Loud-Speaker Expenses				10550	8	0
,, Kent				5913	10	6
,, Travelling Expenses				73697	3	3
,, Conveyance				1601	9	3
,, Petrol Expenses				87180	13	0
,, Insurance				46023	4	0
,, Meeting Expenses				206	2	0
,, Printing Expenses				21007	0	6
,, Special Bonus				13802	8	0
,, Miscellaneous Expenses				44524	13	0
,, Newspapers				546	5	6
,, Guests' Expenses				3192	9	6
,, Medicines				22	7	0
,, Bhojan				52257	9	9
,, Gandhinagar Pravaish Dwar				25774	0	0
,, Electric & water				14286	15	0
,, Exhibition Fund				2712	7	6
,, Decoration Expenses				1929	0	0
,, Wages				444218	13	6
,, Publicity Expenses				1276	3	9
,, Light Charges				755	11	9
,, Railway Freight				150237	1	0
,, Chitra Pradrashni				9336	10	0
,, Gramodyog				821	14	6
,, Gau Sheva Sangh				3590	0	9
,, Telephone				14729	9	6
,, Nature Cure				1500	0	0
,, Bad-Debts				1002	14	9
,, Photos (Chitra)				5513	0	0
,, Advertisement				2933	13	0
,, Rajasthan Digdarshan				12633	1	0
,, Saman Kharach (*Misc. Materials Consumed*)				1703	13	6
,, Diesel Oil				187	8	0
,, Exhibition Construction				56077	4	6
,, Cartage (Transport)				1788[illegible]8	8	6
,, Mobil Oil				3586	11	0
,, Custom Duty				70933	3	6
,, Commission				1146	7	3
,, Saman Kiraya				67719	14	0
,, Gandhinagar Construction (*Including Electric & Water*)				373240	0	6

K. N. Gutgutia & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS.
AUDITORS

COMMITTEE
CONGRESS JAIPUR
PERIOD FROM 15th JULY, 1948 TO 31st JULY 1950

INCOME	Rs	as	p.	Rs.	as.	p.
BY Sale of Tickets:—						
Reception Committee	190150	0	0			
Entrance Fee	500210	8	0	690360	8	0
,, Exhibition Ticket Sale				27124	12	0
,, Accommodation Fees				111333	2	0
,, Rent of Stalls				62233	14	0
,, Advertisement Charges (Realised)				17702	0	0
,, Sale of Bus Tickets				50265	15	0
,, Sale of Rajasthan Digdarshan				2503	11	0
,, Miscellaneous Income:—						
Earnest Money Forfeited	3580	0	0			
Hindustan Information Bureau for Propaganda	5000	0	0			
Sundry Credit Balance w/o						
Other Income	2195	10	3	13273	10	3
,, Interest From Banks	2498	0	0	77	8	0
,, Donations:—						
Jodhpur Government	500000	0	0			
Bikaner Government	400000	0	0			
United State of Rajasthan	200000	0	0			
Jaipur Government	100000	0	0			
Matsya Union	25000	0	0			
Sirohi	11000	0	0			
Sundries	10107	0	0	1246107	0	0

Continued From A & B.

EXPENDITURE	Rs.	as	p.	Rs.	as.	p.
,, Goods Account—						
Purchases	3749375	2	0			
Less Sales	3349435	5	0	399939	13	0
,, Provision for Contingent Expenses				3346	9	6
				2452970	9	3
,, Balance B/F				231988	9	0
,, Balance (Cr.) carried to Balance Sheet				21011	7	0
				253000	0	0

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES :	Rs.	as,	p.	Rs.	as.	p
Liabilities:—						
Provision for contingent expense	3346	9	6			
For Bonus	1005	0	0			
Others	272	3	0	4623	12	6
Income & Expenditure Account						
Balance (Cr.) as per Income & Expenditure Account				21011	7	0
				25635	3	6

Sd. Gokul bhai Bhatt(Chairman)
Sd. Hirlal Shastri (Genral Secretary)
Sd. Siddharaj Dhaddha (Joint Secretary)
Sd, Kamal Nayan Bajaj (Treasurer)

Continued From A & B.

INCOME	Rs.	as	ps.	Rs.	as	ps.
,, Balance, excess of (expenditure over Income carried down)				231988	9	0
				2452970	9	3
,, Special Donation (Amount retained to meet out deficit Out of Provisional Donation of Rs. 600000/-advanced by the Jaipur Government)				253000	0	0
				253000	0	0

AT 31ST JULY, 1950.

ASSETS	Rs.	as.	ps.	Rs.	as.	ps.
<u>Book Debts (Doubtful)</u>				21011	7	0
<u>Cash & Bank Balances:--</u>						
With Bank of Jaipur Ltd., Jaipur in C/A.	3322	15	3			
With United Commercial Bank Ltd., Jaipur in C/A	8	12	6			
In Hand (as per cash book)	1292	0	9	4623	12	[illegible]
				25635	3	6

Examined and found correct subject to our separate report of even date

Mirza Ismail Road,
Jaipur, the 11th August, 1950.

Sd/- K. N. Gutgutia & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
HON. AUDITORS

ALL INDIA GONGRESS 55th

	Main Office			Medical Relief			Railway Transport			Reception		
Salaries	45,664	2	9	63	0	0	71	0	0	216	10	0
Postage & Telegram	3636	7	6	25	6	0	240	10	0			
Stationery	17127	2	9	59	7	0						
Loudspeaker Exp.	10466	8	0							84	0	0
Rent	5207	6	0									
Travelling Exp.	5899	1	9				323	11	0	56	5	0
Conveyance	872	13	3	36	3	0	37	0	0	25	12	0
Petrol Exp.	1418	13	6							52	12	0
Insurance	42001	0	0									
Meetings Exp.	206	2	0									
Printing Exp.	8437	15	6				37	0	0	108	0	0
Special Bonus	8970	5	6									
Miscellaneous Exp.	12245	14	3	10	1	0	8	6	0	401	15	6
Newspapers	473	7	0	3	14	0						
Guests Expences	2332	4	0							300	0	0
Medicines				22	7	0						
Bhojan	401	14	0				25	8	0	505	11	6
Gandhinagar Entrance				377	0	0						
Electric & Water	14207	3	0									
Exhibition Fund	2712	7	6									
Decoration Exp.							77	12	0			
Wages												
Publicity Expences												
Light Charges												
Railway Freight	699	7	0									
Chita Pradarsani												
Gramodyog												
Goe Seva Sangh												
Telephone	14675	8	6				38	15	0			
Natural Treatment												
Bad Debts	360	0	0									
Pictures (Chitra)	263	0	0									
Advertisement	486	14	0									
Rajasthan Digdarshan												
Saman Kharch	155	11	0									
Diesel. Oil.	187	8	0									
Exhibition Construction												
Cartage Transpurt												
Mobil oil												
Custom Duty												
Commission												
Saman Kiraya												
Gandhinagar Construction (Including Electric & Water)												
	199109	0	9	597	6	0	822	14	0	1751	2	0

SESSION HELD IN 1948.

Pandal	Sanitation	Decoration	Exhibition	Publicity	Procession	Wi…
472 3 3	615 3 6	208 5 0	2192 1 9	330 0 0	155 0 0	
5 15 0	6 1 6	15 1 6	699 12 0	116 12 0		
			1603 9 9			
3400 4 0	466 10 6	502 15 0	32240 15 9	1895 7 6		
63 1 0		87 7 0		90 0 0		
			3000 0 0			44 [illegible]
75 0 0	294 0 0		1811 2 0			
	57 8 0			1870 0 6	142 8 0	
362 9 6	399 4 6	54 2 6		510 0 0	376 0 0	
			2256 14 9	421 14 0	3162 12 6	
				27 12 0		36 1…
						23 7…
325 8 6	175 15 0	211 13 0	14518 6 0	217 12 0		
		25397 0 0				2109 8…
96 0 0	11206 6 0	2395 4 0	1851 4 0			
			1080 11 3	62 14 8	131 10 0	33596 6 0
			755 11 9			
			1750 1 3	105 0 0		
			9336 10 0			
			821 14 6			
			3590 0 9			
			1500 0 0	15 2 0		
			5 1 0			
				5250 0 0		
				159 7 0		
85 3 0		1462 15 6		12633 1 0		
			56077 4 6			
						5057 4 0
4975 12 3	13221 1 0	30334 15 6	100[illegible]	90[illegible]		

ALL INDIA CONGRESS 55th

	Volunteer			Food			Sawari		
Salaries ...	767	9	3	62735	5	0	24082	12	3
Postage & Telegram ...	84	1	0	201	7	3	82	5	0
Stationery ...				552	10	0			
Loudspeaker Exp. ...									
Rent ...				210	11	0			
Travelling Exp. ...	1686	9	0	15175	8	3	1075	2	9
Conveyance ...	74	9	0						
Petrol Exp. ...							85709	3	6
Insurance ...							1022	4	0
Meetings Exp. ...									
Printing Exp. ...	134	9	0	1793	12	0	2527	13	0
Special Bonus ...							273	0	0
Miscellaneous Exp, ...	6905	13	6	4375	13	3	894	8	3
Newspapers ...	17	13	0						
Guests Expenses ...	6	4	0						
Medicines ...									
Bhojan ...	7167	1	9				4486	9	0
Gandhinagar Entrance ...									
Electric & Water ...									
Exhibition Fund ...									
Decoration Exp. ...									
Wages ...	1263	2	0	35754	9	6	2346	15	6
Publicity Expenses ...				88	10	0			
Light Charges ...									
Railway Freight ...							2774	15	9
Chitra Pradarshni ...									
Gramodyog ...									
Gow Seva Sangh ...									
Telephone ...									
Natural Treatment ...									
Bad Debts ...				47	6	6	11	6	0
Pictures (Chitra) ...									
Advertisement ...									
Rajasthan Digdarshan ...									
Saman Kharch ...									
Diesel Oil ...									
Exhibition Construction ...									
Cartage Transpurt ...							130640	2	0
Mobil Oil ...				6321	13	3	3586	11	0
Custom Duty ...							737	8	0
Commission ...									
Saman Kiraya ...									
Gandhinagar Construction (Including Electric & Water) ...									
	18107	7	6	127257	10	0	260251	4	0

SESSION HELDIN 1489

Construction	Procurement	Sales	Admission	Accommodation	Marketing & Advt.	Total
33534 5 0	9958 6 9	30457 10 9	1173 6 6	242 2 6	688 10 9	213627 15 0
1525 0 8	431 14 0		4 1 0	51 2 0	30 9 0	7156 9 0
774 8 3	194 6 0		1222 3 0	7 10 0	157 0 0	21698 8 9
						10550 8 0
		495 9 6				5913 10 6
7354 15 9	2726 9 0		81 12 0	257 12 0	463 8 0	73697 3 3
	209 2 0			60 8 0		1601 9 3
						87180 13 0
						46023 4 0
						206 2 0
			3005 14 0	579 2 0	227 4 6	21007 0 6
3561 8 0						13802 8 0
6355 7 0	1792 2 0	954 3 3	3573 7 9	211 3 0	156 6 0	44524 13 0
						546 5 6
554 1 6						3192 9 6
						22 7 0
21912 2 9				200 0 0		52257 9 9
						25774 0 0
79 12 0						14286 15 0
						2712 7 6
						1929 0 0
333981 3 9	19106 14 6			4340 5 9		444218 13 6
					44 0 0	1276 3 9
						755 11 9
	144907 9 0					150237 1 0
						9336 10 0
						821 14 6
						3590 0 9
						14729 9 6
						1500 0 0
3 0 0	558 10 6	17 6 9				1002 14 9
						5513 0 0
	178 8 0	2109 0 0				2933 13 0
						12633 1 0
						1703 13 6
						187 8 0
36809 5 3						56077 4 6
						17828 8 6
						3586 11 0
	70195 11 6					70933 3 6
	176 4 0	970 3 3				1146 7 3
66648 9 0	1071 5 0					67719 14 0
373240 0 6						373240 0 6
886333 15 0	251507 6 3	35004 1 6	9060 12 [illegible]	5949 13 3	1767 0 3	2409684 2 9

संयुक्त मंत्री का निवेदन

(आडिटरों की रिपोर्ट के बारे में)

जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के हिसाब के सिलसिले में आडिटरों की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कुछ उप समितियों में सामान के उपयोग में तथा उसके आंतरिक देन लेन के सम्बन्ध में मीलान करने के लिये ब्यौरे वार रेकार्ड रखे जाने की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस सिलसिले में इतना कहना पर्याप्त होगा कि जितने बड़े पैमाने पर जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी करनी पडी थी उसके लिए स्वागत समिति को ३, ४ महिने का जो समय मिला वह बहुत कम था। समितियों का निर्माण होते २ उन्हें और भी कम समय मिला। अधिवेशन की जो जिम्मेदारी उठाई गई थी उसे समय के अन्दर ज्यों त्यों पूरा करने के लिये प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों के वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यकताओं ने समय समय पर जितने भी दिनों के लिये काम में हाथ बटाने की इच्छा जाहिर की उसका स्वागत करना भी अनिवार्य था।

अधिवेशन की अवधि के भीतर २ तैयारी करने को दृष्टि से दिन रात तेजी से चलने वाले अनेक प्रकार के कामों के लिए कई कार्यकर्ताओं की टोलियों को वारी २ से जुटना पडा। अतः स्पष्ट है कि सामान के उपयोग और देन लेन का मीलान करने योग्य व्यौपारिक तरीके से पूरा विवरण रख सकना अधिकतर अंशों में सम्भव नहीं था। इतने बडे और जल्दी के काम में इस प्रकार की कमी रह जाना स्वाभाविक था।

व्यवसायिक हिसाबी परम्परा के पालन में जहां तक सामान के मिलान का सवाल है कुछ कमी भले ही रही हो पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि प्रान्त पर आई हुई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिये सम्बन्धित कार्यकर्ताओं ने कुल मिलाकर बडे परिश्रम व लगन से कार्य किया।

सिद्धराजढड्ढा
(संयुक्त मंत्री)

परिशिष्ट ६ (३)

(क) स्वागत समिति की कार्यकारिणी की ता० १३-८-५० की बैठक की कार्यवाही का सार

स्वागत समिति की कार्यकारिणी की अन्तिम बैठक ता० १३-८-५० को राजस्थान ज्ञान मन्दिर में श्री गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में हुई।

१—हिसाब की स्वीकृति

पिछली बैठक की कार्यवाही के बाद स्वागतसमिति की रिपोर्ट तथा आडीटर द्वारा जांच किया हुआ ता० ३१-७-५० तक का हिसाब पेश किया गया चर्चा के बाद आडिटर्स की रिपोर्ट के बारे में संयुक्त मंत्री द्वारा किये गये निवेदन (परिशिष्ट नं० ६ में प्रकाशित) के साथ स्वागत समिति का हिसाब तथा तत्सं-बन्धी आडिटर्स की रिपोर्ट सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गये।

२. स्वागतसमिति की रिपोर्ट की स्वीकृति

संयुक्तमंत्री द्वारा रिपोर्ट का मसविदा पेश हुआ। चर्चा के बाद रिपोर्ट का मसविदा पढ़ा जाकर प्राप्त संशोधनों के साथ सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। यह निश्चय किया गया कि रिपोर्ट तथा स्वागतसमिति का हिसाब स्वागत-समिति की साधारण सभा में स्वीकृति के लिये पेश किये जांय।

३—आभार प्रदर्शन

उपस्थित सदस्यों ने भावना प्रकट की कि स्वागत समिति के प्रधान मंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री ने स्वागत समिति के लिये लाखों रुपये की अर्थ व्यवस्था तथा संभावित घाटे की पूर्ति के लिये जो प्रयत्न किये उसके लिये कार्यकारिणी की ओर से उनके प्रति आभार प्रदर्शन किया जाय। इस सिलसिले में नीचे लिखा प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव

"स्वागत समिति के प्रधान मंत्री पं० हीरालाल शास्त्री ने आवश्यक जिस बड़े पैमाने पर अर्थ व्यवस्था की तथा अधिवेशन के तुरन्त बाद स्वागत समिति

के संभावित लाखों रुपये के घाटे की पूर्ति के लिये कायकारिणी द्वारा उन अकेले पर डाली गई जिम्मेदारी को जिस सफलता के साथ पूरा किया और इस प्रकार स्वागत समिति को असाधारण कठिनाई से बचा लिया उसके लिये यह कार्यकारिणी उनको हार्दिक धन्यवाद देती है।

स्वागत समिति के आडिटर्स द्वारा हिसाब के सिलसिले में की गई उनकी अवैतनिक सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव

"स्वागत समिति के आडीटर्स श्री के० एन० गुटगुटिया एन्ड कम्पनी, कलकत्ता, तथा उनके स्थानीय शाखा संचालक श्री मदनलाल शर्मा ने स्वागत-समिति के हिसाब की जांच का कठिन कार्य जिस परिश्रम के साथ अवैतनिक रूप में किया उनका आभार मानती है और उनकी सेवाओं के लिये धन्यवाद देती है।"

शेष सामान

स्वागत समिति की बची हुई चीजों की सूची पेश हुई। निर्णय हुआ कि—

१. आचार्य श्री विनोबाभावे द्वारा गांधीनगर के शिलान्यास के लिये उपयोग में आई हुई चांदी की करणी तथा अधिवेशन के लिये विशेषतौर पर बुनवाया गया झंडा राजस्थान संग्रहालय "म्यूजियम" को तथा फोटो अल्बम व टिकटों के लिये बनवाये गये मूल चित्र आदि राजस्थान ज्ञान मन्दिर को अधिवेशन की स्थाई यादगार के तौत पर प्रदर्शित करने के लिये भेंट कर दिये जांय।

२. फिल्म तथा दिग्दर्शन की बची हुई प्रतियां सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से डाईरेक्टर पब्लिक रिलेशन के दफ्तर में भेज दी जाय।

३. झंडे, वायर रेकार्डस मशीन मय कार्ट्रिज तथा सरदार हरलालसिंह की मोटर आदि शेष चीजें राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सुपुर्द कर दी जाय।

निश्चय हुआ की रिपोर्ट तथा हिसाव स्वीकार करने के लिये स्वागत समिति की साधारण सभा की बैठक ता० ३ सितम्बर को दोपहर के २ बजे राजस्थान ज्ञान मन्दिर में बुलाई जाय।

परिशिष्ट ६ (४)

(ख) स्वागत समिति की अन्तिम सभा की कार्यवाही का सार

पूर्व निश्चय तथा सूचना के अनुसार स्वागत समिति की अन्तिम बैठक ता० ३ सितम्बर, १९५० को राजस्थान ज्ञान मन्दिर, जयपुर में हुई उसमें नीचे लिखे अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

१—अ० भा० कांग्रेस के ५वें अधिवेशन की स्वागत समिति की यह सभा कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रधान मन्त्री की रिपोर्ट तथा हिसाब निरीक्षकों द्वारा जांच हुए स्वागत समिति के हिसाब को स्वीकार करती है। यह सभा यह भी निश्चय करती है कि रिपोर्ट तथा हिसाब, व बचा हुआ सामान, फाईलें तथा रेकार्ड (सूची के अनुसार) राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सुपुर्द कर दिये जायं और इसकी सूचना अ० भा० कांग्रेस कमेटी को मय हिसाब तथा रिपोर्ट की प्रतिलिपियों आदि के भेजी जाय।

२—अ० भा० कांग्रेस के ५५वें अधिवेशन के लिए आवश्यक अर्थ व्यवस्था के सिलसिले में राजस्थान की रियासती सरकारों, विभिन्न बेंकों, तथा अन्य महानुभावों ने समय २ पर जो विशेष सहायता एवं सहूलियतें दी उसके लिए स्वागत समिति की यह सब उनका आभार मानती है और उन्हें हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती है।

३—अ० भा० कांग्रेस के ५५वें अधिवेशन की स्वागत समिति की यह सभा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राजस्थान की रियासतों, के शासकों तथा मन्त्रि मण्डलों तथा समिति के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी तथा संचालन समिति के सदस्यों, समितियों के संयोजकों, सदस्यों एवं स्वयंसेवक, स्वयं-सेविकाओं, सार्वजनिक संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अधिवेशन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए की गई सेवाओं के लिए सबका आभार मानती है। स्वागत समिति इन सबकी कृतज्ञ है।

४—अ० भा० कांग्रेस के ५५वें अधिवेशन की स्वागत समिति की यह सभा स्वागत समिति के आडीटर श्री के० एन० गुटगुटिया एण्ड को० तथा

जयपुर शाखा के संचालक श्री मदनलाल शर्मा का स्वागत समिति के हिसाब की जांच का कठिन कार्य अवैतनिक रूप से तथा बडे परिश्रम के साथ पूरा करने के लिए आभार मानी हुई उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देती है।

५–स्वागत समिति के प्रधान मन्त्री पं० हीरालाल शास्त्री ने अधिवेशन के लिए आवश्यक जिस पैमाने पर अर्थ व्यवस्था की तथा अधिवेशन के तुरन्त वाद स्वागत समिति के सम्भावित लाखों रुपये के घाटे की पूर्ति के लिए साथ पूरा किया उसके लिए यह कार्यकारिणी उनको हार्दिक धन्यवाद देती हैं।

६–स्वागत समिति के संयुक्त मन्त्री श्री सिद्धराज ढड्ढा ने समिति के कार्यालय का संचालन करने, समितियों का मार्ग दर्शन करने तथा सारे कान सामन्जस्य विठाने और अधिवेशन के वाद के शेष कार्य को निपटाने में जो परिश्रम किया है उसके लिए यह सभा उनके तथा कार्यालय सहायक श्री छीतरमल गोयल व अन्य कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है।

७–स्वागताध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट के अधिक परिश्रम व मार्ग दर्शन के लिए स्वागत समिति उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रदर्शित करती है।